



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 26, 2016/वैशाख 6, 1938

No. 121]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 26, 2016/VAISAKHA 6, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

अंतिम जांच परिणाम

**विषय :** कोरिया जनवादी गणराज्य, ताईवान, चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड, रूस और यूरोपीय यूनियन के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "पोली विनायल क्लोरोराईड (पीवीसी) पेस्ट/इमलशन रेसिन" के आयातों पर पाटन-रोधी जांच की निर्णयिक समीक्षा (एस एस आर)।

**सं. 15/19/2014-डीजीएडी :-** समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

### क. मामले की पृष्ठभूमि

1. यतः कोरिया जनवादी गणराज्य, ताईवान, चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड, रूस और यूरोपीय यूनियन मूल की अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित पोली विनायल क्लोरोराईड पेस्ट रेसिन जिसे इमलशन पीवीसी रेसिन भी कहा जाता है (जिसे आगे संबद्ध वस्तुएं कहा गया है) जो कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उप-शीर्ष 3904 2210 के अंतर्गत आती हैं, के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 11 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या 14/36/2009-

डीजीएडी द्वारा अपने प्रारंभिक परिणाम में संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनन्तिम पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपरोक्त परिणामों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 26 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्या 77/2010-सीमा शुल्क द्वारा संबद्ध वस्तुओं पर अनन्तिम पाटन-रोधी शुल्क लगाया था। और यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 2 मई, 2011 की अधिसूचना संख्या 14/36/2009-डीजीएडी द्वारा अपने अंतिम परिणाम जारी किए थे तथा वित्त मंत्रालय ने दिनांक 26 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 66/2011-सीमा शुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाए थे।

2. इससे पृथक अन्य जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 31 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या 15/27/2008-डीजीएडी द्वारा यूरोपीय यूनियन के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क के मामले की निर्णयिक समीक्षा शुरू की थी और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने दिनांक 7 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या 104/2004-सीमा शुल्क द्वारा पाटन-रोधी शुल्क लगाए थे और दिनांक 6 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या 115/2009-सीमा शुल्क द्वारा उन्हें आगे बढ़ाया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निर्णयिक समीक्षा करने के बाद दिनांक 26 अप्रैल, 2010 अधिसूचना संख्या 15/27/2008-डीजीएडी द्वारा यूरोपीय यूनियन मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर लागू रखे जाने की सिफारिश की थी, जिसे वित्त मंत्रालय की दिनांक 25 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या 70/2010-सीमा शुल्क द्वारा लगाया गया था और उसमें दिनांक 20.01.2012 की अधिसूचना संख्या 8/2012-सीमा शुल्क द्वारा संशोधन किया गया था।

3. और यतः लेदर क्लॉथ एंड प्लास्टिक मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन (एलसीएमपीए) ने सीईएसटीएटी के समक्ष एक अपील दायर की थी जिसमें उसने दिनांक 26 अप्रैल, 2010 के अंतिम परिणामों द्वारा की गई सिफारिशों पर विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर लागू रखने और दिनांक 25 जून, 2010 की सीमा शुल्क विभाग की अधिसूचना संख्या 70/2010-सीमा शुल्क द्वारा लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क और दिनांक 16012010 की अधिसूचना संख्या 8/2012-सीमा द्वारा ऐसे शुल्कों में किए गए संशोधन को चुनौती दी थी।

4. और यतः माननीय सीईएसटीएटी ने दिनांक 6 जुलाई, 2012 के अपने आदेश द्वारा दिनांक 26 अप्रैल, 2012 के अंतिम परिणाम, दिनांक 25 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्या 70/2010-सीमा शुल्क को खारिज कर दिया तथा मामले को हितवद्ध पक्षकारों को सुनवाई के लिए अवसर प्रदान करने के बाद नया निर्णय लेने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को वापिस भेज दिया।

5. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 4 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना संख्या 15/21/2008-डीजीएडी द्वारा हितवद्ध पक्षकारों को सुनवाई के लिए अवसर प्रदान करने के बाद यूरोपीय यूनियन के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर लागू रखे जाने की सिफारिश की थी और ऐसा शुल्क, वित्त मंत्रालय की दिनांक 3 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या 15/2013-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा लगाया गया था।

6. और यतः मेसर्ज केमप्लास्ट सन्मार लिमिटेड ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष विधिवत् पर्याप्त प्रमाण युक्त एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें उसने यह तर्क दिया था कि कोरिया जनवादी गणराज्य, ताईवान, चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड, रूस और यूरोपीय यूनियन के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन होने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तथा यह अनुरोध किया था कि इसकी समीक्षा की जाए, अवधि को बढ़ाया जाए और संबद्ध देशों की मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क में संशोधन किया जाए।

7. यतः विधिवत् पर्याप्त प्रमाण युक्त प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र को ध्यान में रखते हुए तथा पाटन-रोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को निरंतर जारी रखने और इसकी जांच करने के लिए कि ऐसे शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को उससे

क्षति होने की संभावना है, दिनांक 27 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या 15/219/2014-डीजीएडी द्वारा निर्णयिक समीक्षा जांच शुरू की है।

8. वर्तमान निर्णयिक समीक्षा जांच, उपरोक्त पैरा (1) और (2) में उल्लिखित निर्यातिक देशों नामतः कोरिया जनवादी गणराज्य, ताईवान, चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड, रूस और यूरोपीय यूनियन (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर की गई है।

9. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त नियमावली के नियम 23 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने यूरोपीय यूनियन से आयातों के खिलाफ अधिसूचना संख्या 15/2013-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा प्रभारित “पोली विनायल क्लोराईड पेस्ट रेसिन” पर मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क को भारत सरकार में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 1 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या 26/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा दिनांक 3 जुलाई, 2013 से 25 जुलाई, 2016 तक आगे बढ़ा दिया है। पृथक रूप से वित्त मंत्रालय ने दिनांक 26 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 66/2011-सीमा शुल्क द्वारा कोरिया जनवादी गणराज्य, ताईवान, चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड और रूस से “पोली विनायल क्लोराईड पेस्ट रेसिन” के आयातों के खिलाफ लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क को दिनांक 1 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या 25/2015-सीमा शुल्क द्वारा आगे बढ़ा कर 25 जुलाई, 2016 तक कर दिया था।

## **ख. क्रिया विधि**

10. इस जांच के संबंध में निम्नोक्त क्रिया-विधि का अनुसरण किया गया है:-

- (i) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, उपलब्ध सूचना के अनुसार संबद्ध देशों से ज्ञात निर्यातिकों और आयातों को दिनांक 27 अप्रैल, 2015 की जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना की प्रति भेज दी थी। ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत कर दें और अपने लिखित विचारों से अवगत करा दें। निर्यातिकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रतियां, ज्ञात निर्यातिकों/उत्पादकों की एक सूची के साथ संबद्ध देशों के दूतावासों को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थीं कि वे संबद्ध देशों के निर्यातिकों/उत्पादकों को यह सलाह दें कि वे अपने उत्तर निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर दें।
- (ii) नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार आवेदक की ओर से प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र को अगोपनीय वृतान्त की प्रति ज्ञात निर्यातिकों और संबद्ध देशों के दूतावासों को उपलब्ध करा दी गई थी।
- (iii) प्राधिकारी ने निर्णयिक समीक्षा शुरू करने की सार्वजनिक सूचना की एक प्रति संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातिकों को अग्रेषित कर दी थी और उन्हें नियमावली के अनुसार पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने लिखित विचारों से अवगत कराने का अवसर दिया गया था :-

  - (क) तिआन्जिन केमिकल प्लांट, चीन जनवादी गणराज्य
  - (ख) तिआन्जिन बोहाई केमिकल इंडस्ट्रीज, चीन जनवादी गणराज्य
  - (ग) शेन्यांग केमिकल्स कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य
  - (घ) फोरमोसा प्लास्टिक कारपोरेशन, ताईवान
  - (ङ) एलजी केम लिमिटेड, कोरिया जनवादी गणराज्य
  - (च) हानवाह केमिकल्स, कोरिया जनवादी गणराज्य

(छ) कनेका पेस्ट पोलीमर्स एसडीएन, मलेशिया

(ज) विनथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड

(झ) ओओओ पोलीमर – केमी, रूस

(ञ) विस्टोलिट जीएमबीएच एंड कंपनी, डेन्मार्क

(ट) ईवीसी बिजनिस सेन्टर, यू.के.

(ठ) वास्टोलाईट जीएमबीएच एंड कंपनी, जर्मनी

(ड) सोल्विन एसए, बेल्जियम

(ढ) विन्नोलिट जीएमबीएच एंड कंपनी, जर्मनी

(ण) अल्सकोंडिड, स्पेन

(iv) जांच शुरू करने की अधिसूचना के प्रत्युत्तर में संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं :-

(क) मेसर्ज एलजी केम, कोरिया जनवादी गणराज्य (“मेसर्ज एलजी”)

(ख) मेसर्ज हानवा केमिकल्स, कोरिया जनवादी गणराज्य (“मेसर्ज एचसीजी”)

(v) इनके अतिरिक्त रूस के उत्पादक, मेसर्ज रस विनायल ने दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अपने पत्र में जांच से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए हैं। तथापि, इस कंपनी ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। लेकिन वर्तमान जांच में कंपनी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जितना उपयुक्त पाया गया है, विचार किया गया है। जांच के विलंबित चरण में एससीजी परफोर्मेंस केमिकल्स कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड (“मेसर्ज एससीजी”) जो कि संबद्ध वस्तुओं की निर्यातिक है और जिसकी 100% सहायक कंपनी नामतः मेसर्ज टीपीसी पेस्ट रेसिन कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करती है, के अक्टूबर, 2016 के ई मेल के अनुसरण में दिनांक 21 जनवरी, 2016 का ई मेल प्राप्त हुआ था, जिसमें उसने जांच में संभावित रूप से भाग लेने का अनुरोध किया था। प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में यह बताया है कि संबद्ध वस्तुओं के उपरोक्त उत्पादक और निर्यातिक ने हितबद्ध पक्षकार के रूप में स्वयं को पंजीकृत नहीं कराया है, जैसा कि जांच के लिए किया जाना अपेक्षित है। बाणिज्य मंत्रालय के बेवसाईट पर उपलब्ध कराई गई समय बढ़ाए जाने की सूचना के बावजूद न ही उन्होंने कोई निवेदन किया है/सामान्य मूल्य के आंकडे और उनके द्वारा किए गए निर्यात के आंकडे प्रस्तुत किए हैं। इसलिए निर्यातिक ने उसको प्रदान किए गए अवसरों का समयबद्ध तरीके से कोई लाभ नहीं उठाया है। तथापि, प्राधिकारी ने निर्यातिकों को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए प्रकटन विवरण प्रदान किया है।

(vi) बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण (एमईटी) की प्रश्नावली चीन जनवादी गणराज्य में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातिकों और भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी को संबद्ध सूचना उपलब्ध करा दें। जांच शुरू करने के प्रयोजनार्थ चीन जनवादी गणराज्य में प्रचलित सामान्य मूल्य पर भारत में संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन की लागत के आधार पर विचार किया गया था जिसमें विधिवत समायोजन किया गया था। प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में ज्ञात निर्यातिकों/उत्पादकों को सूचित किया था कि उनका यथा संशोधित पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और पैरा 8 में उल्लिखित प्रावधान के आलोक में आवेदक के दावे की जांच करने का प्रस्ताव है। इसलिए चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध

वस्तुओं के उत्पादकों/नियर्यातकों से अनुरोध किया गया था कि वे यथा उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करें ताकि प्राधिकारी इस पर विचार करने में सक्षम हो सकें कि क्या चीन जनवादी गणराज्य में सहयोगी उत्पादकों/नियर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण का दर्जा स्वीकृत कर सकते हैं। तथापि, चीन जनवादी गणराज्य से किसी भी उत्पादक/नियर्यातक ने चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण का खंडन करने के उत्तर में एमईटी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

(vii) नियमावली के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/एसोसिएशनों को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं :-

एकजो नोबल कोटिंग्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, 62-पी होसकोटे इंडस्ट्रियल एरिया, पिलगुम्पा, कर्नाटक - 562 114.	एल्लेप्पी कंपनी लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नंबर 2602, टेक हाऊस, एल्लेप्पी, केरल.
एनाबोंड इस्सेक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, 1 एफ देव रिजेंसी, पहला मेन रोड गांधी नगर, चेन्नई-20.	क्रिएटिव बर्ल्ड, 11-12, दूसरा तल, नरीमन इंडस्ट्रियल इस्टेट, न्यू लिंक रोड, विलेज चिंचोली मलाड (वेस्ट), मुंबई.
डीसी मिल्स (प्राईवेट) लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नंबर 160, कालावूर, एल्लेप्पी, केरल.	डीआरजी लेदर प्राईवेट लिमिटेड, कराई पुदुर, ग्रिस्सुर.
एफटेक शरॉफ इंडिया लिमिटेड एक्सिल ईस्ट, एस. विवेकानंद रोड, गोरे गांव, मुंबई -400 062	फेनर कन्वेयन बेलिंग प्राईवेट लिमिटेड मदुरै-डिंडीगुल रोड, नगरी, वाडीपट्टी तालुक, मदुरै - 625 221, तमिलनाडु
फेनाप्लास्ट लिमिटेड 165 -166 नन्दीगांव ग्राम, मेडक जिला, आन्ध्र प्रदेश	हलोल लेदर क्लॉथ लिमिटेड, 7-ए, धर्मसी क्रोस स्ट्रीट, भिंडी बाजार, मुंबई - 400003
हैंकेल टेरोसोन इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड 74, इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कालोनी महरोली रोड, गुडगांव, हरियाणा.	हिन्दुस्तान सील्स लिमिटेड, बीकानेर बिलिंग, तीसरा तल, 8/1, लाल बाजार स्ट्रीट, कोलकाता
इंटरनेशनल कन्वेयर लिमिटेड ई-39, एमआईडीसी, इंडस्ट्रियल एरिया, चिकाथाना, औरंगाबाद-431210	जास्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड 5105 ब्लॉक -डी, गली 1, कृष्णा नगर, करोल बाग, नई दिल्ली 110 005

केराफीबेरटेक्स इंटरेशनल प्राईवेट लिमिटेड, 53-57 किनफरा इंडस्ट्रियल पार्क, किसुमागिरी, डाक घर – कक्कांडु, कोचीन- 682030	केरल बेलर्स लिमिटेड पोस्ट बॉक्स 28 3, एल्लप्पी, केरल
मयूर यूनीकोर्ट्स लिमिटेड, रोटरी भवन, चर्च रोड, जयपुर.	ऑसबाल केबिल प्रोडक्ट्स, ए 93/1 वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, 52 वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110 052.
फिरोज सेथना प्राईवेट लिमिटेड 101-ए, रोड, नंबर 16, वागले इंडस्ट्रियल इस्टेट, थाणे.	पोलमान इंडिया लिमिटेड, मेकर चेम्बर – V, नरीमन प्लाईट, मुंबई- 400 021
पोलीनोवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड 92-101, कुन्डेईम इंडस्ट्रियल इस्टेट, पणजी पोंडा रोड, कुन्डेईम, गोवा-403110	प्रीमियर पोलीफिल्म लिमिटेड, 305 इलाईट हाउस, 36 कम्युनिटी सेंटर, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली
रोटा स्क्रीनटेक लिमिटेड 301, सिल्वर चेंबर टेगोर रोड, राजकोट- 360002.	शिवम टेक्सटार्डल्स, ए 1/126 जनकपुरी, नई दिल्ली-110 058.
सिएल टिजिट लिमिटेड, 58 मोतीलाल गुप्ता रोड, बारिशा इंडस्ट्रियल- 700008, कोलकाता	स्नेह विनायल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट एरिया, रेनीगुन्टा- 517520 आंध्र प्रदेश
एसआरएफ लिमिटेड, विरालीमलई - 621316, तमில்நாடு, இங்கியா	टेक்ஸोன इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, 19 மார்லஸ் ரோட், எगமோர், சென்னை - 8
ट्रावनகोर कोकोटफ्ट प्राईवेट लिमिटेड, கோயர பார்க், பிரூவிஜா, செர்தாலா-688 539, கேரள	யश மார்க்டிங் எஜேஸீஜ, 1/2 சித்ராமி அபார்ட்மெண்ட், ஆಶ்ரம ரோட், அஹம்஦ாබாத்- 380009
வெலி வெலவெட் (ப்ராईவெட்) லிமிடெட் 1/2 சித்ராமி அபார்ட்மெண்ட், ஆಶ்ரம ரோட், அஹம்஦ாබாத்-380009.	ஓம் விநாயல்ஸ் ப்ராईவெட் லிமிடெட், 4- மூதல், வ்யாபார ஭வன 49, பி.டிமேலோ ரோட், கர்நாக வாங்கி, முங்கூட்டு-400009

गोमती एक्सपोर्ट्स, 410, 121/127 – मंडवी नवजीव, मुंबई -400003.	आरएमजी पोलीविनायल इंडिया लिमिटेड 302, ईलीट हाऊस, 36, कम्युनिटी सेंटर, जमरूदपुर, नई दिल्ली 110048.
वीके विनायल 4283 (ए) / 4 जय माता मार्किट, त्रिनगर, नई दिल्ली -110035	यूनाईटेड डेकोरेटिव प्राईवेट लिमिटेड 46/3, साईट-IV, यूपीएसडीआईसी इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद -201010, गाजियाबाद.
बी. बी. ट्रेडिंग कंपनी, बी -10, शू मार्किट, दिल्ली -110035.	इंकम केबिल्स प्राईवेट लिमिटेड ए-1/73 सफदरजंग इन्क्लेव, नई दिल्ली 110029
कुंदन राईस मिल्स लिमिटेड, डी-16, सिटी चेम्बर्स, प्रशांत विहार, दिल्ली 110085	लकी प्लास्ट लिमिटेड . 6-बी/3 एन.ई.ए., ओल्ड राजिन्द्र नगर, नई दिल्ली
मेन्सफाइल्ड केबिल कंपनी, बी 41, सेक्टर-6, नोएडा- 201301.	मार्बल विनायल्स लिमिटेड जी-73, कनाट सर्किस, नई दिल्ली 110001
नोविले क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड, 4316/17- तीसरा तल, सैनी मार्किट, बहादुरगढ़ रोड, नई दिल्ली-110006	'ओरियंट ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड, सी-15, शमा कोपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, जी. टी. करनाल रोड, नई दिल्ली- 110033
ओस्बाल विनायल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2/49, रूप नगर, दिल्ली 110007	पेरामाउन्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, एम- 4, बहुबली, 59/17, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली
पूनम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, 76, शाहजादा बाग एक्सटेंशन, ओल्ड रोहतक रोड, दिल्ली-110035	आर. के. इंडस्ट्रीज सी-595, डीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल पार्क, नरेला, दिल्ली 110040
आर. के. ट्रेडिंग कंपनी, दूसरा तल, सैनी मार्किट, 3007, बहादुरगढ़ रोड, दिल्ली 110006	आर. एम. ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड, एफ-31 – भगवंत सिंह मार्किट, बहादुरगढ़ रोड, दिल्ली

रेल्लीसन्स प्राईवेट. लिमिटेड . प्लॉट नंबर 164 (1310), वीपीओ मनपुरा, तहसील नलगढ़, जिला – सोलन.	रिसपोंसिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड महागांव रोड, बेटेगांव, बोईसर ईस्ट, ताल-पालधार, जिला – थाणे, महाराष्ट्र.
रिटजी इंटरनेशनल प्राईवेट.लिमिटेड . डी -832, न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली-110065.	रोयल इंडस्ट्रीज जी-1085, डीएसंआईडीसी इंडस्ट्रियल काम्पलेक्स, नरेला, दिल्ली
एस. के. ट्रेडर्स, के. संख्या 358, स्ट्रीट नंबर 2, कुशक रोड -2, स्वरूप नगर, दिल्ली	एस.एल.एफ. (इंडिया )लिमिटेड, 6, सहगल कालोनी, कोर्ट लेन, दिल्ली 110054.
एस. आर. पोलीकेम, 4311/5-जय माता मार्किट, त्रिनगर, दिल्ली 110035	शील पोलीटेक्स, 10761-62, झंडेवालान रोड, नवीं करीम, नई दिल्ली 110055
शील विनायल्स, एच-41, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110016	शिव शक्ति इंडस्ट्रीज, डी-7, खसरा नंबर 30/23, नांगली पूना एक्सटेंशन, दिल्ली 110036
सन्नी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, सी-151, प्रीत विहार, दिल्ली	सुप्रीम इलेक्ट्रिकल्स, डी-33, बाली नगर, नई दिल्ली
सुशी केम प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज, 72-वी, शाहजादा बाग एक्सटेंशन, ओल्ड रोहतक रोड, दिल्ली	टेररा इंडिया एफ -118, अशोक विहार, फेज-1, दिल्ली-110052.
त्रिशला विनायल घूब्स लिमिटेड, 4. ए रेस कोर्स, त्रिशला हाऊस, देहरादून- 248001	अल्टीमेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ई-260, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली
वी के पोलीकोट्स लिमिटेड, फ्लेट नंबर 7 डी, सातवां तल, हंसालय भवन, 15 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली	विमला इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, 307/3 शाहजादा बाग, ओल्ड रोहतक रोड, दिल्ली 110035
अक्षत प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड, 4648/15, जय माता मार्किट, त्रिनगर, नई दिल्ली-110035	विपिन पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड, . 193, भागीरथी अपार्टमेंट्स, सेक्टर-9 रोहिणी, दिल्ली.
अरिनीतिज सेल्स प्राईवेट. लिमिटेड, 603, निर्मल टॉवर, 26, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली 110001	बंसल केमिकल्स (इंडिया) एफ/14, महावीर चेम्बर्स, 103, नयनीअप्पा नाइकेन स्ट्रीट, चेन्नई- 600003.

(viii) उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं/निवेदन किए हैं:-

- (क) मेसर्ज मयूर यूनीकोटर्स लिमिटेड
- (ख) मेसर्ज पोलीनोवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- (ग) मेसर्ज जस्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(ix) इनके अतिरिक्त मेसर्ज लेदर क्लॉथ एंड प्लास्टिक्स मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन (एलसीएमपीए) ने याचिका के उत्तर प्रस्तुत किए हैं।

(x) मेसर्ज अथेना एसोसिएट्स ने भी 02.02.2016 की सुनवाई के बाद मेसर्ज मयूर यूनीकोटर्स लिमिटेड, मेसर्ज पोलीनोवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्ज जस्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (एलसीएमपीए), मेसर्ज केपीएल इंटरनेशनल लिमिटेड और मेसर्ज जस्क प्लास्टिक्स इंडिया लिमिटेड की ओर से निवेदन किए हैं।

(xi) एक आयातक, मेसर्ज क्लासिक लेमीटेक्स प्राईवेट लिमिटेड ("मेसर्ज क्लासिक") ने कार्रवाई के विश्व स्तर पर अपने उत्तर प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की याचिका में उल्लिखित सभी ज्ञात आयातकों को यह सूचित किया है कि वे प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत कर दें। इसके अतिरिक्त प्रश्नावलियां और जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचनाएं वेवसाईट पर उपलब्ध हैं। जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना के अनुसार जांच में भाग लेने का इच्छुक कोई भी पक्षकार स्वयं को एक हितवद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत करा सकता है।

(xii) मेसर्ज क्लासिक लेमीटेक्स प्राईवेट लिमिटेड ने अपने दिनांक 18.03.2016 के पत्र द्वारा यह अनुरोध किया है कि निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने से पहले पीवीसी रेसिन पर मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क को जून, 2015 में उसकी समाप्ति पर इस आधार पर नहीं लगाया जाए कि विश्व भर में वीसीएम की कीमतों में गिरावट आने के बावजूद भारत में वीसीएम रेसिन की अधिक कीमतें प्रचलित हैं। विश्व भर में उत्पादों के गतिशील लागत ढांचे पर विचार नहीं किया जाए, विदेशी विनमय दर कारकों जिनमें क्रोस मुद्रा दरें, प्रयोक्ता उद्योग पर विशेष कर रोजगार पर अग्रिम प्रभाव, कुछ उत्पादकों के लिए एकाधिकार संरक्षण, उलटे शुल्क ढांचे का उद्भव, प्राप्तकर्ता उद्योग द्वारा आयातों की कम बीजक बनाना आदि शामिल हैं।

(xiii) 0.2.02.2016 को हुई सौखिक सुनवाई में आयातक ने भाग लिया था और प्रश्नावली के अनुसार आयातों के आंकड़े प्रस्तुत किए थे और निवेदन किए थे, जिनको दक्षिण कोरिया से उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रदत्त आंकड़े और डीजीसीआईएंड एस के आंकड़ों के साथ सहयोगित किया गया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, आयातक ने दिनांक 18.03.2015 के अपने पहले पत्र में किए गए निवेदनों को व्यापक रूप से दोहराया है और आग्रह किया है कि घरेलू उद्योग को दिया गया संरक्षण विश्व के कीमत आंकड़ों पर आधारित नहीं है, देश में मांग और पूर्ति के बीच व्यापक अंतर है, मेसर्ज केमप्लास्ट की गैर-एकीकृत सुविधा दी गई है जिसके फलस्वरूप उच्च लागत है और अनुचित मात्रा में पाटन-रोधी शुल्क लगाया गया है, यदि ये सभी तथ्य सही होते तो इनसे मेसर्ज केमप्लास्ट उन देशों को निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित होता जिनकी घरेलू कीमतें अधिक हैं। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है।

(xiv) प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने से पहले आयातक के दिनांक 18.03.2015 के अपने पत्र में किए गए निवेदनों से भावी निर्णायक समीक्षा जांच के बारे में उसे जानकारी होने का पता चलता है। इसके अतिरिक्त प्रश्नावलियों और जांच शुरू करने की राजपत्रित अधिसूचनाओं के वाणिज्य विभाग की वेवसाईट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने को ध्यान में रखते हुए आयातक वर्तमान सतत निर्णायक समीक्षा के बारे में निर्धारित समय सीमा के भीतर निवेदन कर सकता था/आंकड़े प्रस्तुत कर सकता था।

(xv) इसके अतिरिक्त मेसर्ज बंसल केमिकल लिमिटेड ने दिनांक 8 जून, 2015 के अपने पत्र में यह बताया है कि उसने वर्ष 2008 से विचाराधीन उत्पाद के कोई आयात नहीं किए हैं और वह भिवष्य में भी वह इनके आयात नहीं करेगा और इसलिए उसे विचाराधीन उत्पाद का एक प्रमुख निर्यातक नहीं माना जाना चाहिए।

(xvi) जिन निर्यातिकों, उत्पादकों और हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी को अपने उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं और न ही इस जांच से संबद्ध कोई सूचना प्रदान की है, उनको असहयोगी माना गया है।

(xvii) जांच शुरू करने के पश्चात् जांच की अवधि सहित विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के ब्यौरे प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक आसूचना और सांचियकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएडएस) से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को ऐसी सूचना प्राप्त हो गई है।

(xviii) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की अनुकूलतम लागत और निर्माण की लागत तथा विक्री की लागत का आकलन, सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएपीपी) के आधार पर किया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटन-रोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। प्राधिकारी द्वारा पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-2 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों के लिए एनआईपी का निर्धारण किया गया है।

(xix) वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि, 1 अक्टूबर, 2013 से 30 सितंबर, 2014 (12 महीनों) तक है। तथापि, क्षति का विश्लेषण करने के लिए जांच की अवधि में अप्रैल 2011-12, 2012-13, 2013-14 तथा जांच की अवधि (पीओआई) भी शामिल है।

(xx) पाटन-रोधी शुल्क नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 2 फरवरी, 2016 को हुई मौखिक सुनवाई के दौरान अपने विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया था। इस मौखिक सुनवाई में उपस्थित पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें और अपने प्रत्युत्तर दें।

(xxi) इस जांच की कार्रवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को जहां कहीं भी प्रासंगिक पाया गया है, उन पर प्राधिकारी द्वारा इस परिणाम में विचार किया गया है।

(xxii) घरेलू उद्योग, सहयोगी निर्यातिकों और एक आयातक/प्रयोक्ता उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना और आंकड़ों के संबंध में जितना आवश्यक समझा गया है, उनकी उतनी जांच की गई है।

(xxiii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की प्राधिकारी द्वारा उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक समझा है, संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है तथा उसे गोपनीय सूचना माना है और उसे प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के पर्याप्त अगोपनीय वृतान्त प्रदान करें।

(xxiv) जहां कहीं भी यदि किसी हितबद्ध पक्षकार ने मौजूदा जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना का अभिगमन करने अथवा उसे अन्यथा प्रदान नहीं करने से मनाही की है अथवा जांच में विशेष रूप से अडचन पैदा की है, प्राधिकारी ने उसे असहयोगी माना है और "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर इस अंतिम निर्णय में उसे रिकार्ड किया है।

(xxv) उपरोक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा जात हितबद्ध पक्षकारों को अनिवार्य तथ्यों की व्योषणा की गई थी। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे 20.4.2016 तक प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर दें। तथापि, मै0 क्लासिक लेमिटेक्स और मै0 एस सी जी परफोरमेंस कैमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा किए गए निवेदनों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए एक दिन का अतिरिक्त समय दिया था अर्थात् ये टिप्पणियां 21.04.2016 तक अवश्य

प्रस्तुत कर दी जाएं। इसके अतिरिक्त प्रकटन विवरण पर प्राप्त हुई टिप्पणियों पर जितना प्रासंगिक पाया गया है प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।

(xxvi) इस परिणाम में जांच अवधि के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई औसत विनिमय दर, 1 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर = 61.65 रुपए है।

(xxvii) “\*\*\*\*” हितबद्ध पक्षकार/अन्य पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का परिचायक है और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इसे गोपनीय माना गया है।

#### **ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

11. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद “पोली विनायल क्लोराईड पेस्ट रेसिन” है जिसे “इमलशन पीवीसी रेसिन” और “पीवीसी पेस्ट रेसिन” (जिसे आगे संबद्ध उत्पाद अथवा संबद्ध वस्तुएं कहा गया है) भी कहा जाता है। मुख्यतया दो प्रकार के पीवीसी रेसिन होते हैं, नामतः पीवीसी पेस्ट रेसिन और पीवीसी सस्पेंशन रेसिन। जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना में स्वतः यह स्पष्ट किया गया है कि पीवीसी सस्पेंशन रेसिन को इस जांच के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। पीवीसी पेस्ट रेसिन का उत्पादन विनायल क्लोराईड मोनोमेर (वीसीएम) द्वारा किया जाता है। वीसीएम का उत्पादन, ईडीसी का प्रयोग करके किया जाता है, जिसके लिए एक प्रमुख उत्पाद के रूप क्लोरीन की आवश्यकता होती है। सफेद/धूंधले सफेद पाउडर के रूप में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और विक्री की जाती है। संबद्ध वस्तुओं की गुण क्षमताओं का वर्णन, के मूल्य, अंतर्रूभूत चिपचिपाहट, अंशों को बनाए रखने की क्षमता, ऊष्म की क्षमति, प्रारंभिक बीएफबी आदि के रूप में किया जाता है।

12. संबद्ध वस्तुएं अधिनियम के अध्याय 34 में उप-शीर्ष 3904 के अंतर्गत आती हैं। तथापि, सीमा शुल्क का यह वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरीके से वर्तमान जांच पर बाध्यकारी नहीं है।

#### **ग. 1 निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

13. निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं, उपभोक्ताओं, अन्य हितबद्ध पक्षकारों और अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) प्राधिकारी को मूल जांच के एक भाग के रूप में वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के कार्य-क्षेत्र पर पुनःविचार करना चाहिए और ऐसी कुछ मदों को हटा लेना चाहिए जो कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्राधिकार के भीतर नहीं आती हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी के विशेषाधिकार के अंदर निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद की पुनःजांच करना शामिल है।
- (ख) घरेलू उद्योग मिश्रण प्रक्रिया से किसी भी प्रकार का रेसिन नहीं बनाता है, लेकिन यह संस्पेंशन और माईक्रो-सस्पेंशन प्रक्रिया से रेसिन बनाता है। चूंकि ऐसा स्वीकार किया गया है कि संस्पेंशन प्रक्रिया से विनिर्मित किया गया रेसिन, विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर है, इसलिए माईक्रो-सस्पेंशन प्रक्रिया से बनाया जाने वाला रेसिन ही बचता है और न कि मिश्रण प्रक्रियासे बनाया गया रेसिन। घरेलू उद्योग एक उत्पाद को इमलशन ग्रेड और पेस्ट रेसिन जैसे बहुविध नामों से प्राधिकारियों को भ्रमित कर रहा है।
- (ग) घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तुएं, उत्पादों का केवल एक छोटा उप-सेट मात्र है, जिनके संबंध में शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया गया है। घरेलू उद्योग केवल ग्रेड 124 (के मूल्य 65), 120 (के मूल्य 68) और 121 (के मूल्य 77) विनिर्मित करता है। घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित कोई भी ग्रेड कम फोरिंग रेसिन के रूप में योग्य नहीं है। उत्पादों के विनिर्देशन भागों में केमपास्ट, फोरिंग गुणक्षमताओं के बारे में विल्कुल भी बात नहीं करता है।

(इ) घरेलू उद्योग ने अपनी बेवसाईट पर स्वतः और साथ ही अपनी याचिका में तथा अपने उत्पाद केटेलोग में उसके द्वारा विनिर्मित विभिन्न ग्रेडों के पीवीसी पेस्ट रेसिन का उल्लेख किया है, जिनकी भिन्न गुणक्षमताएं हैं और वे विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए उपयुक्त हैं तथा किसी एक ग्रेड के बदले किसी दूसरे ग्रेड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह इस तथ्य का स्वतः पर्याप्त प्रमाण है, जिसका घरेलू उद्योग खंडन नहीं कर सकता है कि विभिन्न ग्रेड, विभिन्न उत्पाद हैं और वे तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं।

(च) घरेलू उद्योग (1) उच्च के-मूल्य के पीवीसी पेस्ट रेसिन और (2) विशेषकर ऑटोमेटिव अनुप्रयोग के लिए कम फोगिंग के पीवीसी पेस्ट रेसिन विनिर्मित नहीं करता है।

(छ) केमप्लास्ट द्वारा विनिर्मित रेसिन से विनिर्मित चमड़े के कपड़ा, कभी भी फोग परीक्षण में सफल नहीं रहा है। केमप्लास्ट के सभी ग्रेड के रेसिन, फोग के परीक्षण में विफल पाए गए हैं और वे मानकों को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि उनसे ग्लास प्लेटों पर तेल के बड़े बिन्दु बन जाते हैं और इसलिए वे ऑटोमेटिव उद्योग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए कम फोग गुणक्षमता वाले पीवीसी रेसिन का आयात करना एलसीएमपीए के सदस्यों के लिए अनिवार्य हो गया है, जिसके बिना समग्र ऑटोमेटिव उद्योग के लिए घरेलू आपूर्ति पूरी नहीं हो पाएगी।

(ज) कृपया इसकी तुलना यूरोपीय यूनियन से आयातित 373 एनडी और 375 एमडी जैसे विशेष ग्रेड के साथ करें, जिससे स्पष्ट पता चलेगा कि केमप्लास्ट द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुएं, यूरोपीय यूनियन सहित संबद्ध देशों से आयातित 373 एनडी और 375 एमडी, जैसे विशेष ग्रेड की समान वस्तुएं नहीं हैं और विचाराधीन उत्पाद के अधिकार-क्षेत्र के भीतर कम फोगिंग ग्रेडों को अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं है। प्राधिकारी नोट कर सकते हैं कि विशिष्ट ग्रेड में कीमत में अंतर और पीवीसी का सामान्य प्रयोजन, 20% और 28% की सीमा में है, जिससे पता चलता है कि विचाराधीन उत्पाद में इन ग्रेडों पर निरंतर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है। ऑटोमेटिव अनुप्रयोग, विशेषकर आयातित ग्रेड के लिए कम फोग के रेसिन्स, घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित पीवीसी ग्रेड के लिए न तो तकनीकी और न ही वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और कम फोग के रेसिन्स को विचाराधीन उत्पाद के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखे जाने की आवश्यकता है।

(झ) घरेलू उद्योग 65 और 77 के बीच के के-मूल्य के प्लास्टिकीकृत पीवीसी पेस्ट रेसिन विनिर्मित कर रहा है जैसा कि उनके निजी उत्पाद केटेलोग से पता चलता है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग अपने उत्पाद को 39042110 उप-शीर्ष और न कि किसी अन्य वर्गीकरण के अंतर्गत कलीयर कर रहा है। इसलिए समीक्षा के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद, सीटीएच 39042110 के अंतर्गत आने वाले 65 और 77 के बीच के के-मूल्य के प्लास्टिकीकृत पीवीसी पेस्ट रेसिन होने चाहिए।

(ज) ऑटोमेटिव कंपनियों ने फोगिंग गुणक्षमता के परीक्षण में सफल होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक एसएई जे-1756 को अपनाया है। घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित पेस्ट रेसिन सभी फोगिंग परीक्षणों में विफल रहता है और यह ऑटोमेटिव विनिर्माताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में अनुपयुक्त है। इसलिए उसकी तुलना, यूरोपीय यूनियन के विशेष ग्रेडों के साथ करने का अनुरोध किया जाता है।

(झ) घरेलू उद्योग 65 और 77 के बीच के के-मूल्य के पीवीसी पेस्ट रेसिन विनिर्मित कर रहा है। उच्च के-मूल्य के रेसिन को कम के-मूल्य के रेसिन से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। 77 से अधिक के-मूल्य के पीवीसी पेस्ट रेसिन को विचाराधीन उत्पाद के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

(झ) एलसीपीएमए के सदस्य, घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित पीवीसी पेस्ट रेसिन प्रयुक्त विनिर्देशनों से चमड़े के कपड़े के आर्डरों को निष्पादित नहीं कर सकते हैं।

(झ) जांच से पहले और जांच अवधि के बाद एलसीपीएमए के सदस्यों ने घरेलू उद्योग को उच्च के-मूल्य के कम फोगिंग पेस्ट रेसिन के आर्डर दिए थे जिनकी आपूर्ति करने में घरेलू उद्योग असमर्थ था। हमने घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेडों और आयातित ग्रेडों के साथ चमड़े के कपड़े बनाने और उनका परीक्षण करवाने का प्रयास किया

है। उच्चतर के-मूल्य के आयातित पीवीसी से निर्मित टॉप कोट, कम फोगिंग के परीक्षण में सफल रहा और केम्प्लास्ट पीवीसी रेसिन से विनिर्मित टॉप कोट, ऐसे परीक्षण में विफल रहा है।

- (द) प्राधिकारी का यह विवेक है कि प्राधिकारी की पसंद से किसी भी मान्यता प्राप्त और स्वतंत्र एजेंसी से नमूने का संग्रहण करने से लेकर उपयुक्त नमूना परीक्षण की विश्वसनीयता और आवश्यक परीक्षण करने के लिए सुविधाओं की उपलब्धता पर बल देते हुए ऐसा परीक्षण करवा सकते हैं। हम ऐसे परीक्षण पर होने वाले व्यय का वहन करने के लिए भी तैयार हैं।
- (ग) एलसीपीएमए के सदस्यों ने (1) उच्च के-मूल्य के पीवीसी पेस्ट रेसिन और (2) कम फोगिंग के पीवीसी पेस्ट रेसिन के आर्डर दिए हैं, जिनकी आपूर्ति करने में केम्प्लास्ट असमर्थ रहा है और उसने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है। यह पहले स्पष्ट कर दिया गया है कि एलसीपीएमए के सदस्य, केम्प्लास्ट द्वारा विनिर्मित मौजूदा ग्रेडों से ऑटोमेटिव उद्योग के लिए आर्डर निष्पादित नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार वे आयात करने के लिए विवश हैं।
- (ह) घरेलू उद्योग को कहा जाए कि वह के-मूल्य वार उत्पादन और बिक्री के ब्यौरे प्रदान करें, क्योंकि हितवद्ध पक्षकारों को घरेलू उद्योग द्वारा वास्तव में विनिर्मित किए जा सकने और बेचे जाने वाले ग्रेडों की जानकारी नहीं है।
- (थ) कुछ ग्रेडों की आपूर्ति के खिलाफ मामूली आवश्यकताएं अथवा वाणिज्यिक मात्रा की कमी कोई तर्क नहीं है। यह स्वीकार किया जाता है कि विशिष्ट ग्रेडों की मांग बहुत कम है, लेकिन निचले स्तर के प्रयोक्ताओं के लिए वह पर्याप्त है।
- (द) घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद आयातित उत्पाद के समान बस्तु नहीं है।
- (ध) विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्राधिकार की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि उच्च के-मूल्य के रेसिन्स और विशेष कर ऑटोमेटिव क्षेत्र में कम फोगिंग रेसिन्स को, जिन्हें घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित नहीं किया जाता है और न ही उसकी आपूर्ति की जाती है, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्राधिकार में निरंतर शामिल किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी को कम फोगिंग परीक्षण को वाष्पशील परीक्षण के समान बताते हुए गुमराह करने का प्रयास किया है, जब कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित रेसिन कम फोगिंग परीक्षण में कभी सफल नहीं रहा है और दुर्भाग्यवश आईआईटी, दिल्ली में किए गए परीक्षण में भी वाष्पशील और न कि कम फोगिंग गुणक्षमताओं का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार यह मामला विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र पर पुनर्विचार किए जाने का है और नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि प्राधिकारी को ऐसा विचार करने से रोके।
- (न) वाष्पशील परीक्षण और कम फोगिंग परीक्षण, एक जैसे और समान परीक्षण नहीं हैं। ऑटोमोबाईल इंटीरियरों के लिए निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कम फोगिंग परीक्षण नितांत भिन्न किस्म का परीक्षण है और आईआईटी, दिल्ली के पास कम फोगिंग गुणक्षमताओं का परीक्षण करने की सुविधाएं नहीं हैं।
- (प) 09-10 अप्रैल, 2016 को मयूर यूनीकोटर्स नामक एक प्रयोक्ता/आयातक के जयपुर परिसर का जांच दौरा किया गया था, ताकि उनके निवेदनों में दिए गए आंकड़ों/आधार की मौके पर जांच की जा सके। यह दोहराया जाता है कि पीवीसी रेसिन की वाष्पशीलता युक्त मात्रा और फोग गुणक्षमता दो भिन्न गुणक्षमताएं हैं और यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि 0.5% से कम वाष्पशीलता युक्त मात्रा वाली पीवीसी रेसिन में कम फोगिंग के विशेष लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख किया गया है कि विभिन्न के-मूल्यों की पीवीसी के विभिन्न ग्रेडों का उपयोग फुटवीयर, ऑटोमेटिक और सामान्य अनुप्रयोगों में विभिन्न परतों की कोटिंग करने में किया जाता है। ऐसा कोई ज्ञात एडिटिव नहीं है, जो कि के-मूल्य अथवा फोग के विशेष लक्षणों में कोई परिवर्तन कर सके। यदि के-मूल्य बढ़ाने के लिए पीवीसी पेस्ट रेसिन में लगाए गए प्लास्टिसाईजर को कम किया जाता है, तो इससे उसकी चमक/लोचशीलता भी कम हो जाती है।

(फ) भारत गणराज्य में रूस के परिसंघ की व्यापारिक प्रतिनिधि ने यह निवेदन किया है कि वर्ष 2011-2014 तक की जांच अवधि के दौरान भारत में रूस से विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं हुआ है। रूस में "जेएससी चिम्परोम", वोलगोगराड और "यूसोलीचिम्परोम लिमिटेड" नामक दो कंपनियां हैं, जो संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। यूसोलीचिम्परोम लिमिटेड ने भारत को संबद्ध वस्तुएं संप्रेषित की हैं। इन दोनों कंपनियों ने क्रमशः वर्ष 2009 और 2014 से अपने वाणिज्यिक क्रियाकलाप समाप्त कर दिए हैं। इसलिए पीवीसी उत्पादन की रूस की क्षमताओं के परिणाम अप्रासंगिक हैं, क्योंकि रूस की कंपनियां, उप-शीर्ष 3904 के अंतर्गत शामिल पीवीसी उत्पादों के उत्पादन और निर्यात से संबंधित हैं। तथापि, जांच का विषय, केवल पीवीसी पेस्ट/इमलशन रेसिन है, इसलिए क्षमताओं के परिणाम भासक हो सकते हैं और उसके फलस्वरूप भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं के लदानों के पुनः शुरू होने की संभावना पर गलत निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पीवीसी संसर्पेशन रेसिन जो कि वर्तमान जांच के कार्य-क्षेत्र से बाहर हैं, के रूस के उत्पादक, मुख्यतया सीआईएस क्षेत्र, मध्य-पूर्व, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीका के बाजारों पर अपना ध्यान संकेन्द्रित करते हैं।

## ग. 2 घरेलू उद्योग के विचार

14. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

(क) चूंकि वर्तमान जांच निर्णयिक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र वही है जो कि मूल जांच में था।

(ख) पीवीसी रेसिन को मुख्यतया दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है – पीवीसी पेस्ट रेसिन और पीवीसी संसर्पेशन रेसिन। पीवीसी पेस्ट रेसिन का उत्पादन विनायल क्लोरोराईड मोनोमेर (वीसीएम) से किया जाता है। सफेद पाउडर के रूप में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री की जाती है। घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादकों द्वारा इसकी पेशकश विभिन्न ग्रेडों में की जाती है, जो कि सहयोजित गुणक्षमताओं की दृष्टि से भिन्न मात्र होती हैं, जिन्हें प्रक्रिया के प्राचलों पर नियंत्रण रख कर और विनिश्चित संयोजियों के प्रयोग से प्राप्त किया जाता है। ऐसे विभिन्न ग्रेडों का यह अभिप्राय नहीं है कि ये विभिन्न उत्पाद हैं। पीवीसी पेस्ट रेसिन के सभी ग्रेड, विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के भीतर आते हैं।

(ग) घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तुएं, संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के समान वस्तुएं हैं। विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त उत्पादन प्रक्रिया और घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त उत्पादन प्रक्रिया के बीच कोई वास्तिवक अंतर नहीं है। तथापि, प्रत्येक विनिर्माता आवश्यकताओं और उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार अपनी उत्पादन प्रक्रिया के बेहतर उपयोग करता है।

(घ) घरेलू उद्योग 61 से कम और 85 जितने उच्च के-मूल्य वाली संबद्ध वस्तुएं विनिर्मित करता है, जैसा कि उसके उत्पाद ब्रोशर से स्पष्ट पता चलता है। उचित जांच करने के बाद प्राधिकारी ने विगत जांच में यह निर्णय दिया था कि घरेलू उद्योग उच्च, कम और मध्यम के-मूल्य के विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने में सक्षम है।

(ङ) घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और प्रयोक्ता एसोसिएशन, एलसीपीएमए द्वारा आयातित विचाराधीन उत्पाद की वाष्पशीलता मात्रा की आई.आई.टी, दिल्ली में परीक्षण करने के बाद प्राधिकारी ने यह निर्णय दिया है कि दोनों उत्पाद समान वाष्पशीलता मात्रा युक्त हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आंतरिक प्रयोगशाला के परीक्षण से यह पता चला है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद के नमूने का के-मूल्य कम से कम 61 और अधिकतम 82 है। इसलिए घरेलू उद्योग, अत्यधिक भिन्नता युक्त के-मूल्य की व्यापक श्रृंखला की संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है।

(च) घरेलू उद्योग ने निर्णयिक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद के उसी कार्य-क्षेत्र को सुसंगत रूप से अपनाया है, जब तक कि हितवद्ध पक्षकारों द्वारा उसमें संशोधन करने के लिए ठोस कारण नहीं बताए जाएं जिनके साथ

उनको सिद्ध करने के लिए विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर दिए जाएं। मौजूदा सामले में चार जांच की गई हैं जिनमें विचाराधीन उत्पाद समान रहा है। इसलिए जब तक कि हितवद्ध पक्षकार ऐसे प्रमाणों के अतिरिक्त जिनकी प्राधिकारी द्वारा विगत जांच में पहले से ही जांच कर ली गई है, कोई और विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर देते, तब तक विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हितवद्ध पक्षकारों द्वारा कोई भी नया तथ्य सामने नहीं लाया गया है, इसलिए पहले से किए गए निर्धारण में परिवर्तन करने का कोई कारण नहीं है।

- (द) विनिर्माण प्रक्रिया में अंतर होने से दो भिन्न प्रक्रियाओं से निर्मित दो उत्पाद, दो भिन्न वस्तुएं नहीं हो जाती हैं। घरेलू उद्योग द्वारा अपनी प्रक्रिया से निर्मित रेसिन और एमलसन प्रक्रिया से निर्मित रेसिन का परस्पर रूप से प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद पीवीसी पेस्ट रेसिन है, जिसे एमलसन प्रक्रिया से अथवा माईक्रो ससपेंशन प्रक्रिया से निर्मित किया जा सकता है। इसलिए पीवीसी रेसिन को एमलसन रेसिन अथवा माईक्रो ससपेंशन अथवा डिसपर्शन रेसिन भी कहा जाता है। इस प्रकार चार विभिन्न नामों से जाना जाने वाला उत्पाद, चार विभिन्न उत्पाद नहीं हो सकते हैं।
- (ज) घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित ग्रेडों में 120, 121, 123, 124 और 128 हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूर्व जांच में कम फोगिंग अनुप्रयोग की जांच की है और यह निर्णय दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित ग्रेड, कम फोगिंग रेसिन के बतौर योग्य हैं।
- (झ) विचाराधीन उत्पाद में अनेक प्रकार के उत्पाद शामिल हैं जो कि सहयोजित गुणक्षमताओं के रूप में विशेष रूप से भिन्न होते हैं। विश्व व्यापार संगठन के करारों में अथवा भारतीय कानूनों के अंतर्गत ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि विचाराधीन उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय रूप से सदृश उत्पाद होना चाहिए। विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न प्रकार, ग्रेड और रूप हो सकते हैं, जिनमें सहयोजित लागत और कीमत के रूप में विशेष अंतर हो सकता है। विभिन्न ग्रेडों/रूप/प्रकार के उत्पाद होने का यह अभिप्राय नहीं है कि वे विभिन्न उत्पाद हैं। विभिन्न ग्रेड के उत्पाद, उनके कार्यों और प्रयोगों के लिए एक समान होते हैं। यह तथ्य कि विभिन्न प्रकार के उत्पाद विभिन्न अंत प्रयोगों के निर्मित होते हैं, का यह अभिप्राय नहीं है कि वे विभिन्न वस्तु बनते हैं, विशेष रूप से जब विभिन्न प्रकार के उत्पाद समान कार्य करते हैं।
- (ज) बारंबार की गई जांच से यह पता चला है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुएं, आयातित उत्पादों के समान वस्तु हैं।
- (ट) घरेलू उद्योग ने कभी भी विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति करने से मना नहीं किया है, यदि उनका आर्डर नियमित आधार पर दिया जाता है। यदि विचाराधीन उत्पाद की मांग बहुत कम होती है और उसे पूरा करना आवश्यक होता है, तो उपभोक्ता उत्पाद का आयात कर सकते हैं। आयातों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

### ग. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. प्राधिकारी किए गए निवेदनों को नोट करते हैं और उनका यह मानना है कि विचाराधीन उत्पाद “पोली विनायल क्लोरोआईड पेस्ट रेसिन” है, जिसे “इमल्सन पीवीसी रेसिन” भी कहा जाता है और जो पीवीसी पेस्ट रेसिन के नाम से जाना जाता है (जिसे आगे संबद्ध उत्पाद अथवा संबद्ध वस्तुएं कहा गया है)। मुख्यतया दो प्रकार के पीवीसी रेसिन होते हैं, नाम: पीवीसी पेस्ट रेसिन और पीवीसी ससपेंशन रेसिन। सभी ग्रेड के “पोली विनायल क्लोरोआईड पेस्ट रेसिन” को “इमल्सन पीवीसी रेसिन” भी कहा जाता है और इन्हें पीवीसी पेस्ट रेसिन के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान जांच की विषय वस्तु है तथा जिसे विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के भीतर विचार करने का प्रस्ताव है। तथापि, मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद के अनुसार इस जांच के कार्य-क्षेत्र और परिधि में से ससपेंशन रेसिन, पीवीसी ब्लेंडिंग रेसिन इमल्सन, पीवीसी पेस्ट रेसिन के को-पोल्यूर्स और बैटरी सेपरेटर रेसिन को बाहर रखा गया है।

16. पेस्ट रेसिन और इमल्सन रेसिन जो कि विभिन्न उत्पाद हैं, के संबंध में यह नोट किया जाता है कि पीवीसी पेस्ट/इमल्सन रेसिन का उत्पादन दो प्रक्रियाओं अर्थात् माईक्रो स्स्पेंशन और इमल्सन पोलीमेराईजेशन से किया जा सकता है। जबकि इन दोनों प्रक्रियाओं से विनिर्मित वस्तुएं समान होती हैं, फिर भी उनमें विभिन्न ग्रेडों की भौतिक और रसायनिक विशेषताओं में कुछ अंतर होता है। यह अवधारणा कि विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र, विशेष प्रक्रिया से विनिर्मित पीवीसी पेस्ट रेसिन तक ही सीमित है, सही नहीं है। हालांकि पीवीसी पेस्ट रेसिन को दो विभिन्न प्रक्रियाओं से विनिर्मित किया जाता है, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि परिणामी उत्पाद, विचाराधीन उत्पाद से भिन्न है। घरेलू उद्योग माइक्रो स्स्पेंशन प्रक्रिया को अपना कर संबद्ध वस्तुएं विनिर्मित करता है। ऐसी प्रयुक्त प्रक्रिया में भिन्नता होने के फलस्वरूप उत्पाद तब तक भिन्न नहीं होता है, जब तक कि उत्पादों के परिणामी ग्रेड, अनिवार्य उत्पाद गुणक्षमताओं के रूप में स्वतः भिन्न नहीं होते हैं। ऐसा संभव है कि प्रत्येक उत्पादक की उत्पाद विनिर्माण करने की अपनी निजी प्रक्रिया हो, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया में भिन्नता तब तक कोई मायने नहीं रखती, जब तक कि विभिन्न ग्रेडों के परिणामी उत्पाद (विभिन्न ग्रेडों सहित) की गुणक्षमताएं समान होती हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह मानना है कि वर्तमान जांच में पीवीसी पेस्ट रेसिन और पीवीसी इमल्सन रेसिन दोनों विचाराधीन उत्पाद में शामिल हैं तथा दोनों विचाराधीन उत्पाद और उत्पादों के कार्य-क्षेत्र के भीतर आते हैं। पाटन और क्षति का मूल्यांकन करने के लिए तुलना करते समय ग्रेड स्तर पर गुणक्षमताओं में अंतर होने के पहलु पर यथा संभव उपयुक्त रूप से विचार किया जाता है।

17. एलसीपीएमए के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित कोई भी ग्रेड कम फोगिंग रेसिन के रूप में योग्य नहीं है, विगत जांच में इस मामले की जांच की गई थी और विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों जिनमें घरेलू उद्योग और एलसीपीएमए शामिल हैं, के तर्क को ध्यान में रखने के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पहले यह निर्णय लिया गया था कि उनके नमूनों की जांच आईआईटी, दिल्ली से कराई जाए, विशेष रूप से इस तथ्य की कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद, 78 से अधिक के-मूल्य से संबंधित हैं और साथ ही क्या उनके उत्पादों के लक्षण, कम फोगिंग के हैं।

18. दोनों पक्षकारों से कहा गया था कि वे अपने नमूने भेजें और दोनों पक्षकारों को नमूनों के परिणामों की सूचना विधिवत दे दी गई थी, जिसके आधार पर विगत जांच में नमूनों की रिपोर्टें (जिनमें उपरोक्त संस्थान द्वारा दिए गए निष्कर्ष शामिल हैं) की जांच करने के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया था कि पीवीसी पेस्ट रेसिन सहित संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उद्योग के नमूनों में उच्चतर के-मूल्य निहित था (जो कि 78 से अधिक था), जबकि एलसीपीएमए के किसी भी नमूने में के-मूल्य 78 से अधिक नहीं था और सभी नमूनों (दोनों पक्षकारों के नमूनों) में कम फोगिंग के लक्षण थे।

19. उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने विगत जांच में यह निर्णय दिया था कि एलसीपीएमए का यह तर्क कि घरेलू उद्योग उन ग्रेडों के पीवीसी पेस्ट रेसिन का उत्पादन नहीं करता है, जिनका के-मूल्य 78 से अधिक होता है और कम फोगिंग लक्षण होते हैं, सही नहीं है। आईआईटी, दिल्ली ने अपने परीक्षण परिणामों के माध्यम से तथा बाद में दिए गए स्पष्टीकरण से इसकी संपुष्टि की है कि घरेलू उद्योग ने ऐसे ग्रेडों के पीवीसी पेस्ट रेसिन विनिर्मित किए हैं, जिनमें कम फोगिंग विशेषताएं हैं और जिनका के-मूल्य 78 से अधिक है।

20. प्रतिवादी पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि वाष्पशीलता और फोगिंग भिन्न परीक्षण होते हैं और आईआईटी, दिल्ली द्वारा किए गए परीक्षण में कम फोगिंग गुणक्षमता का परीक्षण शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भी प्रयोक्ता पाटन रोधी शुल्क का भुगतान करके काफी अधिक कीमतों पर यूरोपीय यूनियन से कम फोगिंग ग्रेड के विचाराधीन उत्पाद का निरंतर आयात कर रहे हैं, क्योंकि ऑटोमेटिव क्षेत्र के विनिर्देशनों के अनुसार इस ग्रेड की आवश्यकता होती है। इस संबंध में यूरोपीय यूनियन में उत्पादकों ने ऐसे ग्रेडों की परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने दिसंबर, 2015 में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आंतरिक प्रयोगशाला परीक्षणों की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं, जिनसे पता चलता है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं के नमूनों में के-मूल्य न्यूनतम 61 और अधिकतम 82 था।

22. चूंकि प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आईआईटी, दिल्ली का ऐसा कोई नया परिणाम निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कि उसकी पहली रिपोर्टों के संशोधन में हो, इसलिए प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे पर विचार नहीं किया है कि 78 से अधिक के के-मूल्य वाले पीवीसी पेस्ट रेसिन और कम फोगिंग वाले रेसिन को विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा जाए। तथापि, विभिन्न अंतरभूत गुणक्षमताओं को ध्यान में रखते हुए प्रयोक्ता द्वारा प्लास्टिसाइजर आदि जैसे कुछ एडीटिप्स का इस्तेमाल करके किसी ग्रेड में अत्यधिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसलिए अलग अलग ग्रेड की तुलना करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है।

23. घरेलू उद्योग के इस दावे के संबंध में कि उसके द्वारा विनिर्मित पीवीसी पेस्ट रेसिन के विभिन्न ग्रेडों की विभिन्न गुणक्षमताएं हैं और वे विभिन्न प्रयोग करने के लिए उपयुक्त हैं, जो कि उसकी वेवसाईट पर स्वतः उपलब्ध कराए गए केटेलॉग में दर्शाया गया है, प्राधिकारी मेसर्ज केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड द्वारा विनिर्मित की जा रहीं तीन पीवीसी पेस्ट रेसिन नामतः 120, 121 और 124 का अनुशीलन करने पर नोट करते हैं कि केटेलॉग से यह पता चलता है कि ये तीनों ग्रेड चमड़े का कपड़ा बनाने के लिए उपयुक्त हैं। हालांकि इन ग्रेडों की विभिन्न गुणक्षमताएं हैं, लेकिन वे धारा 9 के (1) में उल्लिखित परिभाषा के भीतर विभिन्न वस्तुएं नहीं बनती हैं। इसलिए यह संपुष्टि की जाती है कि ये तीन ग्रेड, उत्पाद की गुणक्षमताओं के सहयोजित तकनीकी (रसायनिक/भौतिक) मूल्यों के कारण तीन ग्रेड से भिन्न होने पर भी मूल उत्पाद के ही भाग हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सहयोजित मूल्य में भिन्नता होने का यह अभिप्राय नहीं है कि वे विचाराधीन उत्पाद से भिन्न वस्तुएं हैं, हालांकि विभिन्न ग्रेडों की विशिष्ट गुणक्षमताएं, उन्हें विशेष प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए उनके उपयोग को अधिक उपयुक्त बनाती हैं। इसलिए इससे ऐसा पता चलता है कि वे मात्र विभिन्न रूप की वस्तुएं हैं। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि धारा 9 के (1) में उल्लिखित परिभाषा के भीतर विभिन्न वस्तु से विभिन्न उत्पाद विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, उत्पादन प्रोटोटाइपिंग, कार्यों और उपयोग का स्पष्ट पता चलता है। इसलिए धारा 9 के (1) के प्रयोजनार्थ किसी वस्तु के विभिन्न रूप होने से वह भिन्न वस्तुएं नहीं मानी जा सकती हैं, हालांकि उनके रूप/ग्रेडस्तर पर उनकी तकनीकी गुणक्षमताओं में अंतर होता है। इसलिए प्राधिकारी का यह मानना है कि एलसीपीएमए के इस तर्क को कि अनुच्छेद 9 के (1) में उल्लिखित परिभाषा के भीतर तीन ग्रेड तीन विभिन्न वस्तुएं हैं, अनुपयुक्त हैं, और विचाराधीन उत्पाद के सभी रूप/ग्रेड जांच के अधिकार-क्षेत्र के भीतर हैं, माना जाए।

24. सीमा शुल्क विभाग के वर्गीकरण के संबंध में यह नोट किया जाता है कि ऐसी स्थिति जिसमें विचाराधीन उत्पाद का कोई निश्चित सीमा शुल्क वर्गीकरण नहीं है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह आवश्यक है कि एचएस कोड के कार्य-क्षेत्र को व्यापक बनाया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विचाराधीन उत्पाद के आयात, उपयुक्त रूप से पाटन-रोधी शुल्क के अध्यधीन होते हैं और मात्र एचएस कोड विनिश्चित करने से पाटन-रोधी शुल्क की अपवंचना नहीं की जाती है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि एचएस कोड के अंतर्गत सूचित किए गए किसी भी आयात को मात्र इसलिए पाटन-रोधी शुल्क के अध्यधीन नहीं रखा जाएगा कि पाटन-रोधी शुल्क तालिका के अंतर्गत एचएस कोड विनिश्चित किया गया है। इस संबंध में सावधानी वरतने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश उत्पाद के वर्गीकरण पर की जा रही है और न कि एचएस वर्गीकरण पर। ऐसे उत्पाद के किसी भी आयात को, जो कि विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के भीतर नहीं आता है, मात्र इस कारण से पाटन-रोधी शुल्क के अध्यधीन नहीं रखा जा सकता है कि शुल्क तालिका में उसका एचएस कोड विनिश्चित किया गया है। यह नोट किया गया था कि विचाराधीन उत्पाद का आयात, सीमा शुल्क के एक उप-शीर्ष (8 अंकीय) से अधिक उप-शीर्षों के अंतर्गत किया जाता है। रिकार्ड पर उपलब्ध प्रमाण को ध्यान में रखते हुए हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रदान की गई सूचना, वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र और एचएस कोड को विनिश्चित करने के उद्देश्य से तथा विशेष रूप से यह ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान मामले में

विचाराधीन उत्पाद का कोई निश्चित एचएस कोड नहीं है और इसका आयात, विभिन्न आईटीसी एचएस कोड में किया जा रहा है, प्राधिकारी ने सीमा शुल्क वर्गीकरण 3904 के अंतर्गत आने वाले विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

25. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा विभिन्न ग्रेडों में विनिर्मित वस्तुओं को संबद्ध देशों में विनिर्मित और/अथवा निर्यातित विभिन्न ग्रेडों की वस्तुओं के समान वस्तु माना जा सकता है, यह नोट किया जाता है कि भारतीय उद्योग द्वारा विनिर्मित और संबद्ध देशों से निर्यातित की जा रही संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। उनके भौतिक और रासायनिक लक्षणों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रोटोग्रामी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों जैसी विशेषताओं, कीमत, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से समान वस्तुएं हैं। उपभोक्ता उनको एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त कर सकते हैं। इसलिए प्राधिकारी का यह मानना है कि नियमावली में उल्लिखित परिभाषा के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तुएं, संबद्ध देशों से आयातित अथवा वहां विनिर्मित वस्तुओं के समान हैं।

### **घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार**

#### **घ. 1 निर्यातिकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

26. घरेलू उद्योग के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई निवेदन नहीं किया है।

#### **घ. 2 घरेलू उद्योग के विचार**

27. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (क) याचिका केमप्लास्ट सन्मार लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई है। याचिकादाता के अतिरिक्त भारत में पीवीसी पेस्ट रोसिन को एक और उत्पादक है जिसका नाम मेसर्ज फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है।
- (ख) याचिकादाता कंपनी ने संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं किया है और न ही उसका संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातिक/उत्पादक अथवा भारत में किसी आयातक के साथ कोई संबंध है।
- (ग) भारतीय उत्पादन में याचिकादाता के उत्पादन का प्रमुख अंशदान है। याचिकादाता का घरेलू उत्पादन, समान उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन का 50 प्रतिशत से भी अधिक भाग बनता है और आवेदन पत्र, घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त याचिकादाता कंपनी, पाटन-रोधी नियमावली में उल्लिखित परिभाषा के भीतर “घरेलू उद्योग” बनती है।

#### **घ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

28. आवेदन पत्र केमप्लास्ट सन्मार लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भारत में संबद्ध वस्तुओं का एक और उत्पादक कंपनी है, जिसका नाम मेसर्ज फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। उपलब्ध सूचना के अनुसार याचिकादाता कंपनी संबद्ध देशों में किसी भी निर्यातिक से (न प्रत्यक्ष रूप से और न ही अप्रत्यक्ष रूप से) अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयात से संबंधित नहीं है। याचिकादाता ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं किया है।

29. प्राधिकारी ने रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना की जांच करने के बाद यह निर्धारित किया है कि याचिकादाता कंपनी नियम 2 (ख) में उल्लिखित परिभाषा के भीतर घरेलू उद्योग बनती है और याचिका उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार घरेलू उद्योग के आधार के मानदंड को पूरा करती है।

### **इ. अन्य मुद्दे**

#### **इ. 1 निर्यातिकों/आयातकों/प्रयोक्ताओं/अन्य हितबद्ध पक्षकारों/अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन**

30. निर्यातकों/आयातकों/प्रयोक्ताओं/अन्य हितबद्ध पक्षकारों/अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

(क) विगत परिणामों से ऐसा पता चलता है कि एक निर्णय में डीजीएडी ने यह निर्णय दिया था कि कोरिया जनवादी गणराज्य में दो उत्पादक/निर्यातक हैं और जब यह पाया गया कि ये दोनों पाटन नहीं कर रहे हैं और घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं, तो कोरिया के खिलाफ जांच को समाप्त कर दिया गया था। इसके विपरीत इस तथ्य के बावजूद कि कोरिया जनवादी गणराज्य से सभी निर्यात, गैर-पाटित पाए गए हैं, कोरिया जनवादी गणराज्य के खिलाफ जांच को समाप्त नहीं किया गया था।

(ख) मूल जांच में जारी किए गए परिणामों से स्पष्ट पता चलता है कि संबद्ध वस्तुओं के तीन निर्यातकों को पाटन करते हुए नहीं पाया गया है। इसके अतिरिक्त कोरिया जनवादी गणराज्य और ताईवान से सभी निर्यातों से ऐसा स्थापित हुआ है कि वे गैर-पाटित हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी को इन तीनों निर्यातकों के खिलाफ जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए था और उन्हें वर्तमानजांच के कार्य-क्षेत्र से विशेष रूप से बाहर कर दिया जाना चाहिए था।

(ग) चावल पर मेक्सिकों-पाटन-रोधी उपायों में अपील निकाय ने मेक्सिको के इस तर्क को खारिज कर दिया था कि अनुच्छेद 5.8 में जांच को तभी समाप्त कर दिए जाने का प्रावधान है, जब कि “पाटन का देश-वार मार्जिन” न्यूनतम हो और पेनल के इस विचार की संपुष्टि हो कि अनुच्छेद 5.8 में “पाटन का मार्जिन” के भीतर किसी निर्यातक अथवा उत्पादक के पाटन का पृथक मार्जिन आता है, न कि पाटन का देश-व्यापक, मार्जिन जो कि अनुच्छेद 2.4.2. में “पाटन का मार्जिन” के पारिभाषिक शब्द के प्रयोग के अनुरूप हो।

(घ) मूल जांच के दौरान कोरिया जनवादी गणराज्य और ताईवान से संबद्ध वस्तुओं के जिन निर्यातकों को पाटन के लिए जिम्मेदार नहीं पाया गया था, उनको वर्तमान अंतिम निर्णयिक समीक्षा जांच में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था और इन निर्यातकों को वर्तमान अंतिम निर्णयिक समीक्षा जांच से बाहर कर दिया जाना चाहिए।

(ङ) यदि मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी को उसकी जांच करनी चाहिए। इससे पाटन-रोधी शुल्क के विद्यमान होने की पूर्व धारणा बन जाती है। यदि कुछ निर्यातकों के मामले में कोई पाटन-रोधी शुल्क नहीं होता है, तो उन पर समाप्ति की कोई धारा लागू नहीं की जा सकती है। इन निर्यातकों पर पाटन और क्षति होने की पुनरावृति की संभावना की जांच करने का स्तर उन निर्यातकों के भिन्न होना चाहिए जो मूल जांच में पाटन करने के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं।

(च) एचसीसी द्वारा किए गए आयात, वर्तमान निर्णयिक समीक्षा जांच का भाग नहीं होने चाहिए क्योंकि विगत जांच में निर्यातक के लिए शुल्क की शून्य मात्रा की सिफारिश की गई थी। मेक्सिको – बीफ और राईस के मामले में अपील निकाय की रिपोर्ट और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (5) पर विश्वास प्रकट किया गया है।

(छ) विगत जांच में न्यूनतम पाटन मार्जिन का निर्धारण किए जाने के कारण हानिवाह के आयातों की मात्रा को वर्तमान जांच में जांच के प्रयोजनार्थ बाहर रखा जाना चाहिए। इसलिए पाटन और क्षति के निरंतर जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृति होने की कोई संभावना नहीं है।

(ज) घरेलू उद्योग को अत्यधिक गोपनीयता के अपने दावे का प्रतिपादन करना चाहिए क्योंकि इससे प्रतिकारी आरोप लग रहे हैं।

(झ) शुल्क का अत्यधिक उपयुक्त रूप, यदि उसको निरंतर जारी रखने को कोई सिफारिश की जाती है, तो वह भारतीय रूपयों में बैंच मार्क कीमत है तथा कोई अन्य आधार नहीं होगा, क्योंकि ऐसे विभिन्न ग्रेड हैं, जिनमें से कुछ ग्रेडों का विनिर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है।

(ञ) पाटन-रोधी शुल्क, यदि कोई है, तो उसका परिकलन, सीमा शुल्क की तरह आयात कीमत के % के सम-मूल्य आधार पर किया जा सकता है, ताकि अपरिष्कृत और विनियम दर की अस्थिर स्थिति में प्रबंधन किया जा सके और शुल्क के ऐसे किसी भी अन्य रूप पर हम प्रतिवाद कर सकें कि हमारे अस्तित्व को बहुत दुर्बल बना देगा।

## छ. 2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

31. घरेलू उद्योग के आधार और उसके कार्य-क्षेत्र के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

(क) प्रश्नावली के उत्तरों के अगोपनीय वृत्तान्त विकट रूप से अपर्याप्त हैं। जहां तक कि जो सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है उसे भी प्रकट नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त हितबद्ध पक्षकारों ने दावा की गई गोपनीय सूचना के उपयुक्त और पर्याप्त अगोपनीय सारांश भी प्रस्तुत नहीं किए हैं। खाली प्रपत्र दिए गए हैं जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

(ख) सूचना को गोपनीय माने जाने के किसी भी दावे को वेद्ध होना चाहिए और वह पक्षकार के अधिकारों और कानूनी हितों के सुसंगत होना चाहिए।

(ग) सीईएसटीएटी ने बताया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय रूप से प्रस्तुत की गई किसी सूचना को यांत्रिकी रूप से माने जाने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि पक्षकार ने ऐसी इच्छा व्यक्त की है कि उसे गोपनीय माना जाए। नियमावली में निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वह इस बात से संतुष्ट होने पर कि उसकी आवश्यकता है अथवा सूचना का प्रदाता ऐसी सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है अथवा उसका सामान्य रूप से प्रकटन करने अथवा उसका सारांश के रूप में देने का प्राधिकार नहीं देना चाहता है, तो ऐसी सूचना की अनेदखी की जा सकती है।

(घ) एलसीपीएमए, पीवीसी रेसिन उपभोक्ताओं और आयातकों की एसोसिएशन है। उसने वर्तमान जांच में एक हितबद्ध पक्षकार होने का दावा किया है। तथापि, प्रयोक्ता एसोसिएशन ने प्रस्तुत किए गए अपने निवेदनों में यह बताया है कि उसके दो सदस्यों को छोड़ कर किसी भी अन्य सदस्य ने किसी भी प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना में हितबद्ध पक्षकारों को निर्दिष्ट प्राधिकारी को संबद्ध सूचना प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान किए गए हैं। एसोसिएशन ने वर्तमान जांच के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्रदान नहीं की है।

(ङ) वर्तमान जांच में केवल दो आयातकों से प्रश्नावलियों के उत्तर प्राप्त हुए हैं और आयातक एसोसिएशन के किसी भी अन्य सदस्य ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में योग्य बनने के लिए एलसीपीएमए के सदस्यों को प्रश्नावलियों के पृथक उत्तर प्रस्तुत करने चाहिए थे जिसे करने में वे विफल रहे हैं।

(च) फोरमोसा प्लास्टिक्स, एलजी केम और हानवाह केमिकल्स की निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विभिन्न उत्पादों के लिए बारंबार जांच की गई है और यह पाया गया है कि उनके निर्यातों में पाटन मार्जिन न्यूनतम है। जांच किए गए उत्पाद ऐसे उत्पाद हैं, जिन पर कोई भी उत्पादक, भारतीय बाजार में वास्तविक रूप से अन्य आपूर्तिकर्ताओं से भिन्न कीमत प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इन उत्पादों में अन्य निर्यातिकों द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में विशेष पाटन मार्जिन पाए जाने पर भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह पाया है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम है। तथापि चीन और आस्ट्रेलिया के अन्य जांच प्राधिकारियों ने उनके निर्यातों के संबंध में सकारात्मक पाटन मार्जिन पाया है।

(छ) समस्त उत्पादों में इन कंपनियों द्वारा पाटन के अनेक मामले होने से ऐसा स्पष्ट पता चलता है कि इन कंपनियों की कीमत संबंधी नीति, एक कीमत पर उत्पाद को बेचने की होती है, जिसके लिए बाजार की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसा विक्री कीमत के लिए नहीं बल्कि समायोजन करने के बाद निर्यातिकों को कारखाना-गत वसूली करने के लिए किया जाता है। यह अत्यधिक असंभव स्थिति है और इससे प्रश्नावली के उत्तर को विकट रूप से छलयोजित किए जाने का स्पष्ट पता चलता है।

(ज) यूरोप के मामले में इस समय उत्पाद पर निर्धारित मात्रा में पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाता है, जबकि पहले पाटन-रोधी शुल्क बैंच मार्क कीमत के रूप में लगाया गया था और बाद में समीक्षा में उसमें संशोधन कर उसे नियत शुल्क बना दिया गया था। विश्व व्यापार संगठन के पाटन-रोधी संबंधी करार में प्राधिकारियों को स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई है कि वे जैसा अनुरोध किया गया है, उस रूप में और तरीके से पाटन-रोधी शुल्क लगा सकते हैं।

(ज) हितबद्ध पक्षकार वर्ष 2004 के अंतिम जांच परिणाम की तुलना वर्ष के परिणाम से करते हैं। इन दोनों परिणामों में बड़ा अंतर व्याप्त है और इसलिए इस अवधि के दौरान स्थितियों में परिवर्तन हो सकता है। निर्यातकों को यह अधिकार था कि वे मूल जांच के समय उसको समाप्त करने की मांग कर सकते थे और उसके बाद उन्हें सांविधिक अपील करने का अधिकार था। निर्यातकों ने ऐसे अवसरों को गंवा दिया है और इसलिए वे अब अपनी चिंताओं के मुद्दों को नहीं उठा सकते हैं।

(ज) भारत प्रथा अनुसार आंशिक अंतरिम समीक्षा अथवा द्रुत निर्णायक समीक्षाएं नहीं करता है। भारत में मध्यावधि अथवा निर्णायक समीक्षाएं की जाती हैं जिनका संकेन्द्रण पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव पर होता है। यह नोट किया जाना चाहिए कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा शुरू की जा रही जांच प्रक्रिया, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की प्रथाओं से पर्याप्त रूप से भिन्न है। इसके अतिरिक्त कोई दायित्व नहीं होने के बावजूद निर्दिष्ट प्राधिकारी, क्षति और कारणात्मक संबंध जैसे प्राचलों की व्यापक जांच करता है और व्यापक परिणाम प्रदान करते हैं।

(ट) पहले निर्दिष्ट प्राधिकारी उसके बाद सीईएसटीएटी के समक्ष यह चुनौती दी गई थी कि एमटीआर, पाटन-रोधी शुल्क को हटाने अथवा उसको कम करने तक सीमित है, जबकि एसएसआर का अधिकार क्षेत्र, पाटन-रोधी शुल्क की अवधि को आगे बढ़ाने तक सीमित है। तथापि, अंतिम रूप से यह निर्णय लिया गया कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को एमटीआर अथवा एसएसआर में पाटन-रोधी शुल्क को बढ़ाने का अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही निर्दिष्ट प्राधिकारी एनएसआर का संचालन करते हैं, जिसका अधिकार-क्षेत्र पाटन मार्जिन का निर्धारण करने तक सीमित है और इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी एनएसआर में पाटन-रोधी शुल्क को पाटन मार्जिन की सीमा तक बढ़ाने की सिफारिश करते हैं और वे आईएम का निर्धारण नहीं करते हैं। तथापि, संयुक्त राज्य अमरीका के जांच प्राधिकारियों द्वारा संचालित प्रशासनिक समीक्षा, मध्यावधि समीक्षा और एसएसआर में विश्व व्यापार संगठन के करार के अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत निर्धारित सभी अपेक्षाएं निहित नहीं हो सकती हैं।

(ठ) घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका जांच अवधि के दौरान वास्तविक पाटन और जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति पर आधारित है। कोरिया और ताईवान के मामले में याचिका, वास्तविक पाटन मार्जिन और वास्तविक आर्थिक क्षति पर आधारित है और इसके अतिरिक्त चूंकि प्राधिकारी, करार के अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार इन आयातों के संबंध में पूरी जांच कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी कोरिया और ताईवान से छूट प्राप्त कंपनियों के संबंध में शुल्कों की सिफारिश करने के पूरे हकदार हैं।

(ड) घरेलू उद्योग ने हानवाह द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में सकारात्मक पाटन मार्जिन निर्धारित किया है।

(ढ) क्लासिक को अपने अधिकार का प्रयोग, अनुचित विवरण देने की बजाय समीक्षा करने अथवा वर्तमान जांच में भाग लेने के लिए करना चाहिए। वास्तव में पक्षकार को एक असहयोगी आयातक के रूप में घोषित कर दिया जाना चाहिए।

(ण) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सार्वजनिक नोटिस जारी किया था और विभिन्न पक्षकारों से उनके निवेदन आमंत्रित किए थे। कंपनी को अपने निवेदन प्रस्तुत करने से किसी ने नहीं रोका था। भारत में कोई भी पक्षकार किसी भी प्रकार का निवेदन करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने जांच शुरू किए जाने के चरण में पर्याप्त अवसर प्रदान किए थे। लेकिन पक्षकार ने जांच में भाग नहीं लेना उचित समझा। पक्षकार का स्पष्ट इरादा, जांच की प्रक्रिया में बाधा डालने का है, ताकि प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जा सके।

(त) शुल्क लगाए जाने से उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। डीओपी पर सुरक्षात्मक शुल्क के परिप्रेक्ष्य में महानिदेशक (सुरक्षा) ने निचले स्तर के उद्योग पर डीओपी की कीमत में वृद्धि के प्रभाव की जांच की है और यह निष्कर्ष दिया है कि ऐसा प्रभाव नगण्य होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि डीओपी और पेस्ट रेसिन का

प्रयोग एक साथ किया जाता है, महानिदेशक द्वारा निकाला गया निष्कर्ष, विचाराधीन उत्पाद के लिए भी उत्तम है। इसके अतिरिक्त पाटन-रोधी शुल्क से मात्र पाटन की प्रथा का निदान होता है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति होती है और इसलिए उपभोक्ता पर इसके प्रभाव का निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है।

(थ) कोई भी उत्पादक, किसी भी पक्षकार से सामग्री प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। प्राधिकारी ने बारंबार यह निर्णय दिया है कि पाटन-रोधी शुल्क का प्रयोजन भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्द्धा को बहाल करना है। पाटन-रोधी शुल्क संबंधी उपाय लागू करने से संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे।

### **ड. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

32. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को नोट किया है तथा नियमावली के अनुसार प्रकटन विवरण में उपयुक्त शीर्षों के अंतर्गत इन मुद्दों की जांच की है।

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एलसीपीएमए जो कि चमड़े के कपड़े के विनिर्माताओं की एक एसोसिएशन है, ने जांच के विभिन्न मुद्दों के संबंध में कुछ तर्क दिए हैं। विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं जो कि संबद्ध वस्तुओं के आयातक भी हैं, का एक निकाय होने के नाते एसोसिएशन, तथ्यों के आधार पर अपना निर्धारण करने में प्राधिकारी को सहायता करने के लिए समग्र आयातों पर बहुत उपयोगी सूचना प्रस्तुत कर सकती थी। तथापि, इस तथ्य के बावजूद निष्पक्षता और पारदर्शिता के हित में जांच के अन्य पहलुओं के संबंध में एलसीपीएमए के निवेदनों की जांच, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों के साथ जांच की गई है और जितना प्रासंगिक हो सका है उपयुक्त प्रमाणों के साथ उनका निदान, इन परिणामों में किया गया है।

34. प्राधिकारी का यह मानना है कि पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने का प्रयोजन, मांग-आपूर्ति की स्थिति अथवा घरेलू उत्पादकों की संख्या की ओर ध्यान दिए विना सामान्यतया पाटन की अनुचित प्रथाओं से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करना है, जिससे भारतीय बाजार में ऐसी खुली और उचित प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति बहाल की जा सके, जो कि सामान्यतया देश के हित में होती है। उपभोक्ता अभी भी आपूर्ति के दो अथवा उससे अधिक स्रोत बनाए रख सकते हैं।

35. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह मुद्दा उठाया है कि संबद्ध देशों से ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों को, जिन पर मूल जांच में शून्य शुल्क लगाया गया था, विश्व व्यापार संगठन के अपील निकाय की मेक्सिको-बीफ और राईस संबंधी रिपोर्ट में दिए गए परिणामों को ध्यान में रखते हुए इन समीक्षा जांच के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि इन उत्पादकों/निर्यातकों को समीक्षा जांच के अधिकार-क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जा सकता है। साथ ही उसने यह भी तर्क दिया है कि भारत में निर्णयिक समीक्षा में पाटन और क्षति मार्जिन का पूरा पुनःपरिकलन करना शामिल होता है।

36. जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने इस जांच की शुरूआत, लागू पाटन-रोधी शुल्कों को बढ़ाने के घरेलू उद्योग के अनुरोध की जांच करने के साथ-साथ इसको निरंतर जारी रखे जाने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए की थी। प्राधिकारी की यह सुसंगत पद्धति होती है कि वह मूल जांच के सभी पहलुओं की जांच करें, जिनमें घरेलू उद्योग का अधिकार-क्षेत्र, पाटन (पाटन मार्जिन सहित), घरेलू उद्योग की क्षति का विद्यमान रहना और क्षति मार्जिन शामिल हैं। इनके अतिरिक्त, प्राधिकारी इसकी भी जांच करते हैं कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति के फलस्वरूप पाटन के निरंतर जारी रहने, उसकी पुनरावृति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। हितबद्ध पक्षकार मामले के किसी भी पहलु के संबंध में मुद्दे उठा सकते हैं, जिनमें पाटन की मौजूदगी, पाटन मार्जिन, घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति, क्षति मार्जिन, शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन के निरंतर जारी रहना अथवा उसकी पुनरावृति होना और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना तथा पाटित आयातों और घरेलू उद्योग की क्षति के बीच कारणात्मक संबंध शामिल हैं। निर्धारण करते समय प्राधिकारी इस पर विचार करते हैं कि क्या उपायों के रूप में किसी प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता है।

37. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि मूल जांच में जिन नियातिकों पर शून्य शुल्क लगाया गया था, उन्हें निर्णायिक समीक्षा जांच के अधिकार-क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि भारत में पद्धति के अनुसार पूरी मध्यावधि और पूर्ण निर्णायिक समीक्षा की जाती है जिनका संकेन्द्रण पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव पर होता है और प्राधिकारी वास्तविक नियातिकों के संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण करते हैं और क्षति मार्जिन का परिकलन, उन्हीं सिद्धांतों पर किया जाता है जैसा कि मूल जांच में किया जाता है। शुल्क में अंतर हो सकता है जो कि समीक्षा अवधि के दौरान निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन पर निर्भर करता है। याचिकादाता द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि कोरिया और ताईवान के मामले में याचिका वास्तविक पाटन और वास्तविक आर्थिक क्षति मार्जिन पर आधारित है तथा इसके अतिरिक्त चूंकि प्राधिकारी करार के अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार इन आयातों के संबंध में पूरी जांच कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी कोरिया और ताईवान से छूट प्राप्त कंपनियों के संबंध में शुल्कों की सिफारिश करने के पूरे हकदार हैं। दूसरी ओर अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिनमें नियातिक और आयातक शामिल हैं, ने यह तर्क दिया है कि यदि पाटन और क्षति विद्यमान नहीं होती है, तो यह निरंतर नहीं हो सकती है अथवा उसकी पुनरावृति नहीं हो सकती है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी द्वारा की गई मूल जांच में यह पाया गया था कि तीन नियातिकों नामतः हानवाह केमिकल कार्पोरेशन, कोरिया जनवादी गणराज्य, एलजी केम कोरिया जनवादी गणराज्य और फोरमोसा प्लास्टिक कार्पोरेशन, ताईवान पाटन नहीं कर रहे थे और घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रहे थे और इन नियातिकों को वर्तमान निर्णायिक समीक्षा जांच के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि मूल जांच के दौरान उनके खिलाफ जांच को समाप्त कर दिया जाता। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इन नियातिकों के लिए पाटन की पुनरावृति और क्षति की संभावना की जांच का स्तर, ऐसे नियातिकों से भिन्न होना चाहिए जो मूल जांच में पाटन करने के लिए जिम्मेदार पाए गए थे।

38. मामले की जांच की गई है और यह नोट किया जाता है कि विश्व व्यापार संगठन के अपील निकाय ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि विश्व व्यापार संगठन के पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 5.8 अंतर्गत निर्धारित ऐसी अपेक्षा है कि जांच प्राधिकारी ऐसे नियातिक के खिलाफ जांच को समाप्त कर देंगे जिसका मूल जांच में मार्जिन न्यूनतम पाया गया है और उसके परिणामस्वरूप ऐसे नियातिक को निश्चयात्मक पाटन-रोधी उपायों से बाहर रखा जाना चाहिए तथा ऐसे नियातिक को प्रशासनिक और परिवर्तित परिस्थितियों की समीक्षा के अध्यधीन नहीं रखा जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब मूल जांच में किसी नियातिक पर पाटन करते हुए पाए जाने पर शून्य शुल्क लगाया जाता है और उसी नियातिक को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के लिए दोषी पाया जाता है, तो वर्तमान समीक्षा जांच अवधि में उसके खिलाफ पाए गए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को ध्यान में रखते हुए उस पर शुल्क लगाए जाने चाहिए। चूंकि विश्व व्यापार संगठन के पाटन-रोधी करार में विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को ऐसे पाटन को जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, रोकने के लिए शुल्क लगाए जाने की अनुमति है, अपील निकाय का उपरोक्त रिपोर्ट में दिए गए निर्णय से ऐसा माने जाने की आवश्यकता है कि ऐसे नियातिकों पर पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 2 के प्रावधान के भीतर पाटन और पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 3 में उल्लिखित परिभाषा के भीतर घरेलू उद्योग की क्षति के सकारात्मक परिणाम के बिना संबद्ध पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की अनुमति नहीं है। इसलिए जब तक प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में जो कि निर्णायिक समीक्षा जांच है, पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में उल्लिखित संबद्ध अपेक्षाओं का अनुसरण किया है, यह उपयुक्त होगा कि पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के बाद ऐसे नियातिकों, जिन पर शून्य पाटन-रोधी शुल्क लग रहा है, विशिष्ट पृथक पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण किए जाने पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाए।

39. इसलिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच करने के बाद ऐसा निर्णय लिया जाता है कि जैसा कि प्राधिकारी की पद्धति रही है कि वह पूरी जांच करें, जिसमें सभी सहयोगी नियातिकों जिनमें ऐसे नियातिक भी शामिल हैं, जिनका पहले मार्जिन न्यूनतम पाया गया था अथवा जिनका क्षति मार्जिन नकारात्मक था, के पाटन मार्जिन, क्षति और क्षति मार्जिन का निर्धारण करना शामिल है। यह भी नोट किया जाता है कि ऐसी स्थितियों में जिनमें नियातिकों को पहले न्यूनतम पाटन मार्जिन दिया गया था और जिनका अब न्यूनतम पाटन मार्जिन पाया गया है अथवा जिनका क्षति मार्जिन नकारात्मक

है, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इन कंपनियों द्वारा किए गए निर्यात से पाटन होने तथा घरेलू उद्योग को कोई क्षति की संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थितियों में जिनमें पहले पाटन मार्जिन न्यूनतम था, प्राधिकारी ने पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना के प्रयोजनार्थ अब निर्धारित पाटन पर विचार किया है।

40. गोपनीयता के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना की जांच, उसकी सुसंगत पद्धति और पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है गोपनीयता के दावे के स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय वृतान्त प्रदान करें।

41. पाटनरोधी शुल्क के रूप, उसकी मात्रा और मुद्रा के मूल्य वर्ग के संबंध में प्राधिकारी ने अमरीकी डालर में पाटन-रोधी शुल्क के उपयुक्त स्तर का निर्धारण करने के लिए उसकी सुसंगत पद्धति का अनुसरण किया है।

### च. बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

#### च.1 निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों/ अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

42. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के बारे में निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों/ अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) याचिकादाता ने पाटन मार्जिन को भी गोपनीय माना है।
- (ख) निर्दिष्ट प्राधिकारी को संबद्ध वस्तुओं की कीमतों का पता लगाने के लिए विभिन्न देशों में किए गए अध्ययनों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो कि आशोधित होते हैं और उपभोक्ता की आवश्यकतों के अनुरूप होते हैं।
- (ग) घरेलू उद्योग ने एक ही अवधि के लिए कोरिया जनवादी गणराज्य में पीवीसी पेस्ट रेसिन की विभिन्न घरेलू कीमतों का दावा किया है। जहां तक कि एक स्रोत से प्राप्त कीमतों में भी अंतर है। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि कीमतें, हैरीमन केमसल्ट द्वारा जारी की गई कीमतों से लगभग 75 प्रतिशत से भी अधिक हैं। जहां तक कि हैरीमन केमसल्ट ने एक ही अवधि के लिए दो भिन्न कीमतें सूचित की हैं और उनमें लगभग 20 प्रतिशत का अंतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग ने इसे मनगढ़त बनाया है, परिकल्पित किया है और चालाकी की है तथा अधिक पाटन मार्जिन का दावा किया है।
- (घ) घरेलू उद्योग ने हैरीमन केमसल्ट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट की प्रतियां प्रदान की हैं, जो कि दिनांक 9 दिसंबर, 2013 के ट्रेड नोटिस संख्या 1/2013 का उल्लंघन है। घरेलू उद्योग द्वारा विश्वास की गई इस रिपोर्ट को एक निजी परामर्शदात्री फर्म से प्राप्त किया गया है। जबकि यह रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और इसे किसी भी पक्षकार द्वारा शुल्क का भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में घरेलू उद्योग को कहा जाना चाहिए कि वह हमें हैरीमन केमसल्ट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराए ताकि हम उस पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकें।
- (ङ) जैसा कि याचिका में उल्लेख किया गया है, यूरोप में वीसीएम और पीसीएम पेस्ट रेसिन की कीमतें अविश्वसनीय हैं। याचिका के अनुसार यूरोप में वीसीएम, शेष विश्वभर की कीमतों की तुलना में 50 % अधिक प्रतीत होती हैं। यदि घरेलू उद्योग यूरोप के बाजार में शेष विश्व भर में पीसीएस पेस्ट की कीमतों से 70 % अधिक कीमतें प्राप्त कर रहा है, तो सभी उत्पादक यूरोप में सभी वस्तुओं को बेचना चाहेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि वीसीएम की लागत और निर्यातक देशों में घरेलू कीमतों के संबंध में घरेलू उद्योग के दावों में मूल त्रुटि है।

(च) संबद्ध देशों से पाटन के बारे में घरेलू उद्योग के दावे निराधार बढ़ाए हुए हैं और उनको खारिज कर दिए जाने की आवश्यकता है।

(छ) एलजीकेम लिमिटेड से पाटन के बारे में घरेलू उद्योग के दावे निराधार बढ़ाए हुए हैं और उनको खारिज कर दिए जाने की आवश्यकता है।

(ज) जहां तक कि हानवाह कार्पोरेशन भारत में निर्यात करने में लगा हुआ है। यह केवल एचसीसी के लिए वीजकों का प्रबंधन करने का कार्य कर रहा है और ऐसी प्रबंधन सेवाओं के लिए कमीशन प्राप्त करता है। हानवाह कार्पोरेशन की भारत में निर्यात विक्रियों के लिए एक व्यापारिक कंपनी के रूप में कोई भूमिका नहीं है।

(झ) हानवाह कार्पोरेशन, हानवाह केमिकल कार्पोरेशन से विचाराधीन उत्पाद की खरीदारी नहीं करता है और न ही उसे उपभोक्ताओं को बेचता है। इसका तात्पर्य यह है कि हानवाह कार्पोरेशन की भारत में निर्यात विक्रियों के लिए एक व्यापारिक कंपनी के रूप में कोई भूमिका नहीं है।

(ज) 74 निर्यात कारोबार में से 16 कारोबार, प्रबंधन प्रभारों का भुगतान किए जाने पर हानवाह कार्पोरेशन के माध्यम से किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भारत को किए गए 5305 मी.टन के निर्यात में से केवल 995 मी.टन ही हानवाह कार्पोरेशन के माध्यम से बेचे गए हैं, जो कि जांच अवधि के दौरान भारत को की गई संबद्ध वस्तुओं के कुल निर्यात का 20% से भी कम है। मई, 2014 के बाद हानवाह कार्पोरेशन के माध्यम से कोई निर्यात नहीं किया गया है।

(ट) पीवीसी सस्पेशन रेसिन के संबंध में हाल ही में निर्णायक समीक्षा निर्णय में उल्लेख है कि हानवाह कार्पोरेशन के माध्यम से एचसीसी द्वारा भारत को निर्यात के सभी कारोबार किए गए हैं और इस आशय के संयुक्त निवेदन के विचार को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है।

(ठ) एचसीसी के रिकार्ड में माल सूची का चलन, उसकी माल सूची के खाते में फैक्टरियों के बीच अंतर-अंतरण और बाह्य-अतरंग के रूप में दर्ज किया गया है। मूल्य का परिकलन, प्रारंभिक मूल्य और उत्पादन मूल्य की भारित औसत यूनिट कीमत से किया गया है।

(ड) एचसीसी को प्राधिकारी की ओर से कोई कमी संबंधी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि 7 महीनों से भी अधिक समय बीत गया है, कंपनी का यह मानना है कि उसकी सूचना संपूर्ण है।

(ढ) घरेलू उद्योग ने अत्यधिक ऊंचे स्तर पर पाटन मार्जिन का दावा किया है, जिससे पता चलता है कि सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और उनकी तुलना करने की विधि में त्रुटियां हैं। पाटन मार्जिन, निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए, न कि किसी अन्य आधार पर।

(ण) रूस के आयात के बारे में संचयी मूल्यांकन अनुचित है क्योंकि रूस से है और पाटन मार्जिन न्यूनतम से कम है। ऐसे न्यूनतम से कम पाटन मार्जिन और नगण्य आयात के ऐसे आधार सामान्यतया संबद्ध देश के बारे में जांच को समाप्त कर देने अथवा उक्त देश मूल की संबद्ध वस्तुओं के खिलाफ उपायों को रद्द करने के लिए पर्याप्त माने जाते हैं (इस संबंध में थाईलैंड और टर्की के मूल की कुछ लौह और स्टील रसियों और केबिल्स पर पाटन-रोधी उपायों को रद्द करने पर यूरोपीय यूनियन काउंसिल विनियमन 1279/2007 का संदर्भ ग्रहण किया जा सकता है)।

## च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

43. घरेलू उद्योग के आधार और कार्य-क्षेत्र के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विविध निवेदन निम्नानुसार है:-

(क) चीन एक गैर-अर्थव्यवस्था वाला देश है। विगत में यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा उसे ऐसा माना गया है। किसी भी देश ने व्यापक मूल्यांकन क्रिया-विधि और जांच करने के बाद चीन को बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश का दर्जा स्वीकृत नहीं किया है। भारत में भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन को एक गैर-अर्थव्यवस्था वाला देश माना है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 31 मई, 2002 के संशोधन के बाद व्यवहारिक रूप से चीन के खिलाफ शुरू की गई सभी जांच में चीन को एक गैर-अर्थव्यवस्था वाला देश माना है।

(ख) पाटन-रोधी नियमावली ने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं, जिन्हें बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण का दावा स्थापित करने के लिए पूरा किया जाना आवश्यक है। बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण का दावा करने वाले इच्छुक प्रत्येक नियर्तिक को ऐसी प्रत्येक शर्त को पूरा करना चाहिए।

(ग) वर्तमान मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण, बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में कीमत अथवा संरचित मूल्य के आधार पर इस कारण से नहीं किया जा सकता है कि संबद्ध सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

(घ) हानवाह केमिकल्स (एचसीसी) विशिष्ट पाटन मार्जिन प्राप्त करने का इसलिए हकदार नहीं है क्योंकि वह वर्तमान मामले में नियर्तिक नहीं है। इस मामले में नियर्तिक, हानवाह कार्पोरेशन (एचडब्ल्यूसी) है। इसके अतिरिक्त इस संबंध में प्रस्तुत उत्तर में यह उल्लेख किया गया है कि एचसीसी द्वारा विनिर्मित वस्तुओं के मामले में वाणिज्यिक बीजके एचडब्ल्यूसी द्वारा जारी की गई है, इसलिए एचडब्ल्यूसी, विचाराधीन उत्पाद का नियर्तिक है। इसलिए एचडब्ल्यूसी की क्यूआर के बिना एचसीसी को विशिष्ट पृथक पाटन मार्जिन स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

(ङ) एचसीसी ने यह दावा किया है कि उसने एचडब्ल्यूसी को कमीशन का भुगतान किया है। यदि एचडब्ल्यूसी विचाराधीन उत्पाद का नियर्तिक है, तो भारतीय उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक बीजक किसने जारी किए हैं। एचसीसी और एचडब्ल्यूसी के बीच विक्रियों और खरीददारी के कारोबार होने चाहिए। ऐसे मामलों में कमीशन नहीं हो सकती है। एचडब्ल्यूसी को कमीशन का भुगतान तभी किया जा सकता है जबकि एचसीसी द्वारा भारत को नियर्ति की वाणिज्यिक बीजके जारी की गई हों और ऐसी विक्रियों में एचडब्ल्यूसी द्वारा सहायता की गई हो। तथापि, वर्तमान मामले में एचडब्ल्यूसी ने भारतीय आयातकों को वाणिज्यिक बीजके जारी की हैं और इसलिए उसने एचसीसी से वस्तुएं खरीदी होनी चाहिए और उन्हें भारतीय आयातकों को बेचा होना चाहिए। ताईवान, चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका से पीवीसी संसपेशन ग्रेड में निर्णायिक समीक्षा जांच के अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी ने यह जांच की है कि एचडब्ल्यूसी, एचसीसी से संबद्ध वस्तुओं को खरीदें बिना भारतीय नियर्तिकों को बीजक दे रहा था। तथापि, जांच के दौरान ऐसा पाया गया था कि उक्त मामले में कोरिया के सीमा शुल्क विभाग ने एचडब्ल्यूसी को एक नियर्तिक तथा एचसीसी को एक उत्पादक के रूप में घोषित किया है।

(च) घरेलू उद्योग ने कोरिया जनवादी गणराज्य और यूरोप में विचाराधीन उत्पाद के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए हेरीमन केमसल्ट में उद्धृत कीमतों का हवाला दिया है। हेरीमन केमसल्ट विचाराधीन उत्पाद की कीमतों के बारे में नियमित रूप से सूचित करता है और ऐसी कीमतें सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त, सही और पर्याप्त सूचना का आधार बनती हैं। इसलिए कोरिया और यूरोप के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए इन कीमतों पर विचार किया जा सकता है।

(छ) घरेलू उद्योग ने पहले ताईवान के घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों के बारे में एक अध्ययन किया था जिसमें उसने ताईवान के घरेलू बाजार में कीमतों के प्रमाण एकत्र करने का प्रयास किया था। घरेलू उद्योग वर्ष 2012-13 की अवधि के लिए ताईवान के घरेलू बाजार में विक्री कीमत प्राप्त करने में सक्षम रहा था। याचिकादाता ने जांच अवधि के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए वीसीएम कीमत को समायोजित किया है।

(ज) सामान्य मूल्य और नियर्ति कीमत को ध्यान में रखते हुए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। इस संबंध में की गई तुलना को उचित तुलना माना जाना चाहिए। सामान्य मूल्य और नियर्ति कीमत दोनों का निर्धारण, कारखाना-गत स्तर पर किया गया है।

(झ) सामान्य मूल्य का निर्धारण, घरेलू उद्योग की लागत के आधार पर किया गया है जो कि व्यवसाय संबंधी संवेदी सूचना है। इसलिए घरेलू उद्योग के प्रकटन के फलस्वरूप सामान्य मूल्य का प्रकटन होगा। जहां तक कि नियर्तिकों ने यह दावा किया है कि सामान्य मूल्य और नियर्ति कीमत जैसी सूचना गोपनीय है।

(ज) घरेलू उद्योग ने केवल पाटित आयातों के खिलाफ संरक्षण का अनुरोध किया है और पाटन-रोधी शुल्क केवल तब लगाया गया है, जब घरेलू उद्योग ने सकारात्मक पाटन मार्जिन पाया है। बास्तव में घरेलू उद्योग ने यह पाए जाने पर कि पाटन मार्जिन न्यूनतम है, कोरिया/ताईवान के संबंध में अनेक कंपनियों द्वारा किए गए निर्यातों पर शुल्क की सिफारिश नहीं की थी।

(ट) घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न कार्य-प्रणालियां प्रदान की हैं, जिनमें से अध्ययन भी एक है। सभी कार्य-प्रणालियों ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन को सिद्ध कर दिया है। ताईवान और कोरिया के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए अध्ययन को प्रयुक्त किया गया है।

(ठ) प्राधिकारी पाटन मार्जिन और पृथक विशिष्ट मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ प्रचलित विनिमय दर को लागू करते हैं। ऐसी विनिमय दर से घरेलू उद्योग को संरक्षण प्राप्त हो गया होता है और उसके फलस्वरूप उसकी लाभप्रदता बढ़ गई होती। लेकिन इसके विपरीत घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है, जिससे यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को पाटन से नुकसान हो रहा है।

(ड) एलजी केम, कोरिया और एचसीसी, कोरिया ने अपने उत्तर प्रस्तुत किए हैं, लेकिन किसी ने भी अन्य संबद्ध देशों में अपने से संबंधित कंपनियों के बारे में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है। एचसीसी की चीन में हानवाह केमिकल (निंगबो) कंपनी लिमिटेड नामक एक कंपनी है, जो कि उसके पूर्ण स्वामित्वाधीन है। यह कंपनी संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करती है। इसी प्रकार एलजी केम, कोरिया की चीन में टिआन्जिन एलजी डीएजीयू केमिकल्स कंपनी लिमिटेड नामक एक सहायक कंपनी है। यह कंपनी भी संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करती है। वर्तमान जांच में इन उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह निर्धारण करना आवश्यकता है कि क्या पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप पाटन होने तथा घरेलू उद्योग को उससे क्षति होने की संभावना है। इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए किसी नियातक द्वारा संभावित पाटन का निर्धारण करना अत्यावश्यक है। भले ही निर्यातिक ने विचाराधीन उत्पाद के निर्यात नहीं किए हैं, तो भी ऐसा सुगमता से पता चल सकता है कि ऐसा लागू पाटन-रोधी शुल्क के कारण है तथा पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में ऐसी पूरी संभावना है कि निर्यातिक भारत में अपने निर्यात को पुनः शुरू कर देगा।

(इ) निर्दिष्ट प्राधिकारी को कंपनी द्वारा बना कर रखे गए रिकार्ड के आधार पर उत्पादन की लागत को अपनाने से पहले दो पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करना चाहिए। ऐसी पूर्ववर्ती शर्तों में से एक प्रमुख शर्त यह है कि ऐसी लागत, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के साथ सहयोगित लागत को उचित रूप से प्रतिविवित करे।

(ण) किसी भी प्रतिवादी निर्यातिक ने वीसीएम के मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न का पूर्ण उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

(त) हानवाह ने वीसीएम के मूल्यांकन से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की है और एलजी ने यह बताया है कि उसने किसी भी संबंधित पक्षकार से इनपुट की कोई खरीद नहीं की है। तथापि, ऐसे उत्तर को स्वीकार किया जाना कठिन है, क्योंकि एलजी बोहाई केमिकल्स कंपनी लिमिटेड, चीन नामक एलजी से संबंधित पक्षकार, वीसीएम की विनिर्माता कंपनी है।

(थ) वीसीएम एक व्यापारिक मद है और इसलिए प्रत्येक वीसीएम और पीवीसी उत्पादक के पास यह विकल्प होता है कि वह या तो वीसीएम को पीवीसी में परिवर्तित कर सकता है अथवा वीसीएम के रूप में उसे बाजार में बेच सकता है।

(द) प्रश्नावली के उत्तर में बहुत कमियां हैं और निर्यातिक ने जानवूझ कर संबद्ध सूचना प्रस्तुत नहीं करने का सतर्कता पूर्वक निर्णय लिया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वह प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर के संबंध में यदि कुछ मामूल स्पष्टीकरण प्राप्त करने आवश्यक हैं तो उन्हें प्राप्त करें। स्पष्टीकरण देने और कमियों को दूर करने के अवसरों का उपयोग, प्रश्नावली के पूरे उत्तर देने के लिए नहीं किया जा सकता है।

(न) हानवाह केमिकल कार्पोरेशन (एचसीसी) और हानवाह कार्पोरेशन (एचडब्ल्यूसी) दोनों ने कानूनी निवेदन किए हैं, लेकिन प्रश्नावली के उत्तर केवल हानवाह केमिकल कार्पोरेशन ने ही दिए हैं। हानवाह कार्पोरेशन (एचडब्ल्यूसी) की भारत में निर्यात विक्रियों के लिए एक व्यापारिक कंपनी के रूप में कोई भूमिका नहीं है। घरेलू उद्योग यह समझने में विफल है कि यदि प्रतिवादी पक्षकार यह दावा करता है कि हानवाह कार्पोरेशन एक व्यापारी कंपनी नहीं है और वह केवल बीजक का प्रबंध करने की एजेंसी है, तो उसे लिखित निवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में कैसे माना जा रहा है। चूंकि एचडब्ल्यूसी ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं, लेकिन उसने डब्ल्यूएस प्रस्तुत किया है, जिससे सूचना प्रस्तुत करने के प्रति पक्षकार की अनिच्छा का स्पष्ट पता चलता है और इसलिए उसे एक असहयोगी के रूप में माना जाना चाहिए।

### **च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

44. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 (1) (ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

- “(1) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातिक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (2) जब निर्यातिक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की विक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातिक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम विक्री मात्रा के कारण ऐसी विक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :

  - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातिक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा
  - (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, विक्री औंश सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ”।

45. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों और भारत में ज्ञात निर्यातकों और आयतकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं और उन्हें सलाह दी थी कि वे निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सूचना प्रस्तुत करें। तथापि, नीचे उल्लिखित उत्पादकों, निर्यातकों और संबंधित आयातकों को छोड़ कर, संबद्ध देशों के किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातिक और भारत में संबंधित आयातक ने प्रश्नावलियों के अपने उत्तर प्रस्तुत करके इस जांच में कोई सहयोग नहीं दिया है। निम्नलिखित कंपनियों ने प्रश्नावलियों के अपने उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

- (क) मेसर्ज एलजी केम लिमिटेड, कोरिया जनवादी गणराज्य
- (ख) मेसर्ज हानवाह केमिकल्स, कोरिया जनवादी गणराज्य

### **कोरिया जनवादी गणराज्य से उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाठन मार्जिन का निर्धारण**

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद नामतः पीवीसी पेस्ट रेसिन में विभिन्न ग्रेड निहित होते हैं, जिनकी तकनीकी विशेषताएं विभिन्न अनुप्रयोगों के अनुकूल होती हैं। कोरिया जनवादी गणराज्य में सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के विभिन्न ग्रेडों के लागत और कीमत अंतर बैंड को लगभग 15-20% की सीमा में नोट किया गया था। चूंकि भारत में निर्यातित और घरेलू बाजार में बेचे गए विशिष्ट ग्रेडों की सूचना उपलब्ध थी और उसकी जांच की

गई थी, पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए अलग-अलग ग्रेड की तुलना की गई है और सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में इसी प्रक्रिया को अपनाने का प्रस्ताव है।

### **एलजी केम लिमिटेड, कोरिया जनवादी गणराज्य**

47. मेसर्ज एलजी केम लिमिटेड, कोरिया जनवादी गणराज्य जो कि संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक/निर्यातक है, ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के 6 ग्रेड के \*\*\* मी.टन के सीधे और मेसर्ज यूनीफ्लास, यूएई के माध्यम से \*\*\* मी.टन के निर्यात किए हैं। चूंकि संबद्ध वस्तुओं के एक निर्यातक के रूप में मेसर्ज यूनीफ्लास, यूएई द्वारा कोई पृथक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए मेसर्ज एलजी केम लिमिटेड के केवल सीधे निर्यातों को पृथक मार्जिन का निर्धारण करने के लिए ध्यान में रखा गया है।

48. इसके अतिरिक्त जैसा कि दावा किया गया है, पीए 1302 को घरेलू बाजार में बेचा गया है और भारत को उनका निर्यात किया गया है, इसलिए इसे घरेलू और निर्यात विक्रियों दोनों से बाहर रखा गया है, क्योंकि यह एक कोपोलीमर है, जो कि विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के भीतर नहीं आता है।

### **सामान्य मूल्य**

49. मेसर्ज एलजी केम लिमिटेड, कोरिया जनवादी गणराज्य ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में \*\*\* कि.ग्रा. (\*\*\* मी.टन) संबद्ध वस्तुएं बेची हैं, जिनमें 15 ग्रेड नामतः एलके 170, एलपीओ 10 एएफ, एलपी 090, एलपी 170, एलपी 170 एल, एलपी 170 टी, पीबी 1200, पीबी 1202, पीबी 1302, पीबी 1752, पीबी 900, पीई 1311 शामिल हैं, जिनका मूल्य \*\*\* के आरडब्ल्यू है। भारत को विचाराधीन उत्पाद के 6 ग्रेड की कुल घरेलू विक्री \*\*\* कि.ग्रा. (\*\*\* मी.टन) है, जिनका मूल्य मूल्य \*\*\* के आरडब्ल्यू है।

50. समान मूल्य का ग्रेड-वार निर्धारण परिकलन करने के लिए, रियातता जांच सभी ग्रेडों के लिए अलग से की जाती है। “व्यापार का सामान्य समय” जांच उत्पादन की ग्रेड-वार लागत के आधार पर भारत में निर्यात किए गए उन छः ग्रेडों का सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए ग्रेड से ग्रेड हेतु भी माह-वार की गई है। जहां भी 80/20 जांच के फलस्वरूप लाभप्रद विक्री 80 प्रतिशत से कम होती है, वहां घरेलू विक्री में लाभ कमाने के लिए ही सामान्य मूल्य की गणना करने पर विचार किया गया है, अन्यथा सम्पूर्ण विक्री पर तब विचार किया जाता है जब लाभप्रद कारोबार 80 प्रतिशत से अधिक होता है। भाड़ा संबंधी खर्च, ऋण संबंधी खर्च और पैकिंग से संबंधित खर्च, जिनका सत्यापन किया गया है, के आधार पर समायोजन पर विचार किया गया है। विचारित भारित समायोजन क्रमशः \*\*\*\* के आरडब्ल्यू/किग्रा, \*\*\*\* के आरडब्ल्यू/किग्रा और \*\*\*\* के आरडब्ल्यू/किग्रा है। 6 ग्रेडों का भारित औसत सामान्य मूल्य को अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन के रूप में परिकलित किया गया है।

### **निर्यात कीमत**

51. मैसर्ज एलजी केम. लि. ने जांच की अवधि के दौरान भारत में 6 ग्रेडों (एलपी170, एलपी170जी, पीबी1202, पीबी1302, पीबी1752 और पीई1311) के संबद्ध वस्तुओं का \*\*\* किग्रा (\*\*\* मीट्रिक टन) निर्यात किया है। पीए 1302 (\*\*\* किग्रा), जो एक गैर-विचाराधीन उत्पाद है, पर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए विचार नहीं किया गया है। ग्रेड पीए 1302 को छोड़कर एलजी केम. लि. द्वारा भारत में कुल निर्यात में से, \*\*\* मी. का निर्यात भारत में मैसर्ज यूनिप्लस इंटरनेशनल ईस्ट, यूएई के माध्यम से किया गया है जो भारत में विचाराधीन उत्पाद का कुल निर्यात का 1.6 प्रतिशत होता है। मैसर्ज यूनिप्लस ईस्ट, यूएई ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इस कारण से मै. एलजी केम. लि. द्वारा केवल प्रत्यक्ष निर्यात पर विचार अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारण के लिए किया गया है।

52. “अमेरिकी डॉलर/मी.टन” इकाई में जांच की अवधि के दौरान निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के उपर्युक्त 6 ग्रेडों की सीआईएफ कीमतें क्रमशः \*\*, \*\*, \*\*, \*\*, \*\*, \*\* हैं और भारित औसत सीआईएफ कीमत \*\*\* अमेरिकी

डॉलर/मी.टन है। अन्तर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, रिम खर्चे, बैंक प्रभार, विदेशी बीमा, सीमा शुल्क एजेंट का शुल्क और पैकिंग खर्च के मद में समायोजन का सत्यापन और समायोजन किया गया है। “अमेरिकी डॉलर/मी.टन” में संबद्ध वस्तुओं के उपर्युक्त 6 ग्रेडों की एक्स-फैक्ट्री निर्यात कीमत क्रमशः \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* और \*\*\* होती है और भारित औसत एक्स-फैक्ट्री निर्यात कीमत की गणना \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी.टन के रूप में की जाती है।

### **पाटन मार्जिन**

53. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद अर्थात् पीवीसी पेस्ट रेसिन विभिन्न ग्रेडों से बने होते हैं जिसकी विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयुक्त होने के लिए तकनीकी विशेषताएं होती हैं। कोरिया में सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के विभिन्न ग्रेडों में लागत और कीमत में अंतर का बैंड 15-20 प्रतिशत तक नोट किया गया था। चूंकि भारत में निर्यात किए गए विशिष्ट ग्रेडों और घरेलू बाजार में बेची गई समान ग्रेडों की लागत और कीमत के संबंध में सूचना उपलब्ध थी और उसका सत्यापन किया गया था, पाटन मार्जिन का मूल्यांकन करने के लिए एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड की तुलना की गई है और सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में इस पद्धति को अपनाया गया है। कोरिया के लिए शेष/गैर-सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, सहयोग करने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के उत्तर के अनुसार सबसे अधिक सामान्य मूल्य और सबसे कम निर्यात कीमत को अपनाया गया है।
54. प्रत्यक्ष निर्यात के लिए पाटन मार्जिन की गणना लागत दर लागत आधार पर ग्रेड-वार और माह-वार की गई है। भारित औसत पाटन मार्जिन को \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी.टन (\*\*\* %) के रूप में परिकलित किया गया है।

### **हनवा केमिकल कारपोरेशन (एचसीसी), कोरिया जन गण**

#### **सामान्य मूल्य**

55. मै. हनवा केमिकल कारपोरेशन (एचसीसी), उत्पादक/निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की 12 ग्रेडों अर्थात् (ईएल 102, ईएल 103, ईएम 2070, ईएम 3090, केएच 10, केएच 31, केएच 60, केएल 10, केएल 31, केएल 701, केएम 31 और केएम 60) की कुल मात्रा \*\*\* मी.टन और \*\*\* केआरडब्ल्यू (अमेरिकी डॉलर \*\*\* ) मूल्य का घरेलू बाजार में बेचा है। इनमें 12 ग्रेडों में से अर्थात् 3 ग्रेड केएच31, केएल31 और ईएम3090 का निर्यात भारत में जांच की अवधि के दौरान \*\*\* अमेरिकी डॉलर के कुल सीआईएफ मूल्य के साथ \*\*\* मी.टन की कुल मात्रा का निर्यात किया गया था। उत्पादक/निर्यातक ने सभी 12 ग्रेडों के जांच की अवधि के लिए उत्पादन का ग्रेड-वार लागत (माह-वार) उपलब्ध कराया। भारत में निर्यात किए गए 3 ग्रेड घरेलू विक्री जांच की अवधि के दौरान अलग से की गई पर्याप्तता जांच को पूरा करते हैं। ओसीटी सत्यापन दर द्वारा उत्पादन की लागत का सत्यापन किए गए ग्रेड-वार के आधार पर ग्रेड-वार और माह-वार किया गया है। जहां भी 80/20 जांच के फलस्वरूप लाभप्रद बिक्री 80 प्रतिशत से कम होती है, वहां घरेलू विक्री में लाभ कमाने के लिए ही सामान्य मूल्य की गणना करने पर विचार किया गया है। अन्यथा सम्पूर्ण विक्री पर तब विचार किया जाता है जब लाभप्रद कारोबार 80 प्रतिशत से अधिक होता है। इस प्रकार से, सामान्य मूल्य की गणना ग्रेड-वार और माह-वार की गई है। दावा किए गए अन्तर्देशीय भाड़ा संबंधी खर्चे, ऋण संबंधी खर्चे और पैकिंग से संबंधित खर्चों का सत्यापन किया गया है और उसे अनुमति दी गई है। भारत में निर्यात किए गए 3 ग्रेडों का भारित औसत सामान्य मूल्य \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी.टन (केएच31), \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी.टन (केएल31) और \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी.टन (ईएम3090) होता है और समग्र औसत भारित औसत सामान्य मूल्य \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी.टन होता है।

#### **एक्स-फैक्ट्री निर्यात कीमत**

56. उत्पादक/निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान \*\*\* अमेरिकी डॉलर के सीआईएफ मूल्य पर भारत में 3 ग्रेडों केएच31, केएल31 और ईएम3090 का निर्यात किया है। हनवा कारपोरेशन को दिए गए कमीशन अन्तर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, हेनरिंग प्रभार, घरेलू ब्रोकरेज बैंक प्रभार, ऋण खर्च और पैकिंग लागत के मद में समायोजन का दावा किया गया है। उपर्युक्त 3 ग्रेडों का सीआईएफ क्रमशः \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* और \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी.टन है। 3 ग्रेडों के लिए एक्स-फैक्ट्री निर्यात कीमत की गणना क्रमशः \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* और \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी.टन के रूप में की जाती है। जांच की अवधि के दौरान भारत में निर्यात की गई कुल \*\*\* मी.टन में से, हनवा कारपोरेशन का \*\*\*

मी.टन के लिए दस्तावेज हैंडलिंग सर्विसेज का उपयोग एक सहमत निर्धारित हैंडलिंग प्रभार के आधार पर किया गया है। एक्स-फैक्ट्री निर्यात कीमत का मूल्यांकन करने के लिए निर्यात कीमत पर समायोजन के लिए उस पर भी विचार किया गया है। भारित औसत एक्स-फैक्ट्री निर्यात कीमत \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी.टन होता है।

57. पाटन मार्जिन के लिए, प्राधिकारी ने मासिक आधार पर पाटन मार्जिन के मूल्यांकन के लिए एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड की तुलना की है। तीन ग्रेडों अर्थात ईएम3090, केएच31 और केएल31 के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन का मूल्यांकन क्रमशः \*\*\*, \*\*\* और \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी.टन के रूप में किया गया है। भारित औसत पाटन मार्जिन की गणना \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी.टन (\*\*\* %) के रूप में की जाती है।

#### **कोरिया जन गण से गैर-सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन**

58. कोरिया जन गण से शेष उत्पादकों/निर्यातकों के लिए संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटन मार्जिन तय करने के लिए, कोरिया जन गण से सहयोगी निर्यातकों से उपलब्ध अधिकतम सामान्य मूल्य और न्यूनतम निर्यात कीमत को अपनाया गया है।

#### **चीन जन गण, ताइवान, मलेशिया, थाइलैंड, रूस और यूरोपियन यूनियन से उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण**

##### **सामान्य मूल्य**

59. पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में यह प्रावधान है कि:

“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात होने की स्थिति में, सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में कीमत अथवा संरचित मूल्य अथवा भारत सहित अन्य देशों को इस प्रकार के किसी तृतीय देश से कीमत के आधार पर अथवा जहां या संभव न हो, अथवा उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त अथवा देय कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर निर्धारण किया जाएगा। एक उपर्युक्त बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश का चयन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संबंधित देश के विकास के स्तर और प्रश्नगत उत्पाद को ध्यान में रखकर उचित रूप में किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई किसी विश्वसनीय सूचना पर उचित ध्यान दिया जाएगा। जहां भी उचित हो, किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश के संबंध में उसी प्रकार के किसी मामले में किए गए जांच की समय-सीमाओं का भी ख्याल रखा जाएगा। जांच से संबंधित पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त चयन में किसी प्रकार के किसी अनुचित विलंब के बिना सूचित किया जाएगा और उन्हें उनकी टिप्पणियां देने के लिए उचित समय अवधि दी जाएगी।”

60. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन को पाटनरोधी नियमावली के संबंध में निर्यातक देश अथवा अलग-अलग निर्यातकों द्वारा अनुमान के खंडन के अध्यधीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 के अनुसार, किसी गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन किया जा सकता है यदि चीन जन. गण. से निर्यातक पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में निर्धारित मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं और इसके विरुद्ध तथ्यों को सिद्ध करते हैं। चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों से अपेक्षित है कि वे इस प्राधिकारी को निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करने में सक्षम होने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वर्तवि प्रश्नावली के उत्तर में पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में यथा उल्लिखित सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करें कि क्या,

- कीमत, लागत और कच्चा माल सहित इनपुट्स, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, विक्री और निवेश के संबंध में चीन जन. गण. में संबंधित प्रतिष्ठानों के निर्णय मांग और आपूर्ति को दर्शाते हुए तथा इस संबंध में राज्य का बहुत अधिक हस्तक्षेप के बिना बाजार के सेकेतों के प्रतिक्रिया स्वरूप किए जाते हैं और क्या प्रमुख इनपुट्स की लागतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्य को परिलक्षित करते हैं;
- इस प्रकार के प्रतिष्ठानों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति में बहुत अधिक फेर-बदल हो सकता है जो परिसंपत्तियों के हास, अन्य बट्टे खाते में डाली गई राशि, लेन-देन, व्यापार और ऋण की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के विशेष संदर्भ में पूर्व के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से ली गई है;
- इस प्रकार के प्रतिष्ठान दिवालियापन और सम्पदा कानून के अध्यधीन हैं जो इन प्रतिष्ठानों के क्रियाकलाप के लिए कानूनी निश्चितता और स्थायित्व की गारंटी देते हैं और
- विनिमय दर में परिवर्तन बाजार दर से किया जाता है।

61. प्रारंभ किए जाने के चरण में प्राधिकारी ने चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानते हुए इस अनुमान से कार्रवाई शुरू की। प्रारंभ करने पर प्राधिकारी ने चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी कि वे प्रारंभ करने की सूचना का जवाब दें और अपने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का निर्धारण किए जाने से संबंधित सूचना भी प्रदान करें। प्राधिकारी ने इस नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 (3) में निर्धारित मानदंड के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को एमईटी प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं। प्राधिकारी ने चीन सरकार से यह भी अनुरोध किया कि वह अपने देश के उत्पादकों/निर्यातकों को यह सलाह दे कि वे संबंधित सूचना उपलब्ध कराएं। हालांकि चीन का कोई उत्पादक/निर्यातक ने कोई उत्तर नहीं दिया है।

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस प्राधिकारी द्वारा जारी की गई प्रारंभन सूचना के फलस्वरूप, चीन की किसी भी कंपनी ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। अतः प्राधिकारी ने चीन की कंपनियों को इस नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 को लागू नहीं किया है और इस नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार इस पर आगे कार्रवाई की है। इन नियमों के अनुसार, चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर किया जा सकता है:

क. किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत के आधार पर अथवा

ख. किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संरचित मूल्य के आधार पर अथवा

ग. भारत सहित अन्य देशों में ऐसे किसी तीसरे देश से कीमत।

घ. यदि सामान्य मूल्य का निर्धारण ऊपर में उल्लिखित विकल्पों के आधार पर किया जा सकता है तब निर्दिष्ट प्राधिकारी उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त अथवा देय कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकता है।

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि तीसरे देश की लागत और कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, घेरेलू विक्री अथवा तीसरे देश के निर्यात विक्री तथा तीसरे देश में इस प्रकार के उत्पादकों के उत्पादन की लागत और सहयोग के संबंध में पूर्ण और व्यापक आंकड़े अपेक्षित हैं। चूंकि, इन बाजारों में प्रचलित कीमतों और लागतों के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती है और इस बात के मद्देनजर भी कि, विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने तीसरे देश की उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की है, चीन जन. गण. के संबंध में सामान्य मूल्य इस नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के दूसरे परंतुक के संबंध में अन्य उचित आधार पर तय किया गया है। इस प्रकार से प्राधिकारी ने चीन जन. गण. को छोड़कर और कोरिया जन गण को छोड़कर सभी संबद्ध देशों से जांच की अवधि के दौरान आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य को निम्न प्रकार से संरचित किया है :

(क) उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर कच्चे माल का सर्वोत्तम उपयोगिता मानदंड पर विचार किया गया है।

(ख) कच्चे माल और उपयोगिताओं अर्थात् विजली की लागत का संदर्भ दूसरे स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर लिया गया है।

(ग) परिवर्तन लागत, एसजीए खर्च और ब्याज पर विचार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर किया गया है।

(घ) ब्याज को छोड़कर बिक्री की लागत का 5 प्रतिशत की अनुमति एक उचित लाभ के रूप में दी गई है।

64. तदनुसार, ताइवान, चीन जन. गण., मलेशिया, थाइलैंड और यूरोपियन यूनियन के लिए एक्स-फैक्ट्री स्तर पर परिकलित संरचित सामान्य मूल्य का क्रमशः \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी.टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी.टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी.टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी.टन और \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी.टन के रूप में निर्धारित किया गया है।

### निर्यात कीमत

65. चूंकि, कोरिया जन गण को छोड़कर संबद्ध देशों में से किसी देश से कोई भी निर्यातक ने किसी ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं कराई है जिसका उपयोग निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए किया जा सकता है, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के अनुसार भारत में आयात की सीआईएफ कीमत के आधार पर इन संबद्ध देशों से सभी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमतों का निर्धारण किया है। तदनुसार, चीन जन. गण. से निर्यात कीमतों का परिकलन समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह पर खर्च, अन्तर्रेशीय ढुलाई और बैंक प्रभार के लिए लागू समायोजनों के साथ उत्पाद की सीआईएफ कीमत के आधार पर किया गया है जिसे एक्स-फैक्ट्री निर्यात कीमत को तय करने के लिए उपयोग में लाया गया है। तदनुसार ताइवान, चीन जन गण, मलेशिया, थाइलैंड और यूरोप यूनियन के लिए निवल निर्यात कीमत का निर्धारण क्रमशः \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी.टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी.टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी.टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी.टन और \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी.टन के रूप में किया जाना प्रस्तावित है।

66. चूंकि, इन संबद्ध देशों के किसी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर देकर इसका जवाब नहीं दिया है और कोई ग्रेड-वार सूचना उपलब्ध नहीं है, प्राधिकारी इसे संभव नहीं पाते हैं कि वे ग्रेड और ग्रेड में तुलना में कर सकें और इसलिए उसकी तुलना करने तथा पाठन/क्षति मार्जिन का मूल्यांकन नहीं किया गया है और इस कारण से संबंधित पैराओं में यथाउल्लिखित डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार मूल्यांकित एक्स-फैक्ट्री निर्यात कीमत और संरचित सामान्य मूल्य अपनाकर भारित औसत दृष्टिकोण अपनाया गया है।

67. इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद के दौरान भी रूस से संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं हुआ है। मै. रस विनायल, रूस और रूस सरकार ने उसे प्रस्तुत किया है और यह उल्लेख किया है कि रूस ने संबद्ध वस्तुओं को उनके घरेलू बाजार द्वारा पूरा किया जा रहा है और भारत में निर्यात बहुत सीमित है। इस प्रकार से, रूस के लिए पाठन मार्जिन को न्यूनतम के रूप में माना गया है।

### पाठन मार्जिन का निर्धारण

68. उपर्युक्त में किए गए निर्धारण के अनुसार सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमतों पर विचार करते हुए, पाठन मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है :

देश	उत्पादक	निर्यातक	पाठन मार्जिन यूएस\$/एमटी	% में पाठन मार्जिन	% रेंज में पाठन मार्जिन
कोरिया जन गण	एलजी केम	एलजी केम	***	***	-(0-5)
	एलजी केम	एलजी केम को छोड़कर कोई अन्य	***	***	30-35
	एचसीसी	एचसीसी	***	***	-(0-5)
	एचसीसी	एचसीसी को छोड़कर कोई अन्य	***	***	30-35
	एलजी केम और एचसीसी को छोड़कर कोई अन्य	कोई	***	***	30-35

ताइवान	सभी उत्पादक	सभी निर्यातक	***	***	5-10
चीन जन गण	सभी उत्पादक	सभी निर्यातक	***	***	5-10
मलेशिया	सभी उत्पादक	सभी निर्यातक	***	***	15-20
थाईलैंड	सभी उत्पादक	सभी निर्यातक	***	***	5-10
यूरोपीय यूनियन	सभी उत्पादक	सभी निर्यातक	***	***	25-30

69. उपर्युक्त मूल्यांकन दर्शाता है कि संबद्ध वस्तुओं का प्रवेश पाइट कीमतों पर संबद्ध देशों से भारतीय बाजार में जारी है और यह भी पाटन का मार्जिन बहुत अधिक है।

#### छ. क्षति निर्धारण के लिए पद्धति और क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जांच

##### छ.1 निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों/अन्य पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

70. निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों/अन्य पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. घरेलू उद्योग के क्षति संबंधित सभी कारकों और आर्थिक मानदंडों में सुधार हुआ है। यह अनुमान इसे विल्कुल स्पष्ट करता है कि वर्तमान अथवा संभावित रूप से क्षति नहीं होगी। घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता का उपयोग और विक्री में वृद्धि हुई है। उत्पादकता में सुधार हुआ है।

ख. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में क्षति की जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है। साथ ही हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे वर्तमान जांच के प्रयोजन से डीजीसीआईएंडएस के अनुसार, आयात से संबंधित सूचना का संग्रह करें।

ग. याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है और संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

घ. भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग और आपूर्ति में बहुत अधिक अंतर है। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए क्षमता में वृद्धि के बाद भी, घरेलू उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। लेकिन इतने वर्षों के लिए शुल्कों का लाभ उठाने के बाद भी और इस देश में मांग का बहुत बड़े हिस्से को पूरा करने के लिए भी कुछ नहीं किए जाने के बाद, घरेलू उद्योग को इस तर्क के साथ बचकर निकलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि वे भारत में मांग और आपूर्ति के अंतर की स्थिति का ध्यान रखने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

ड. माल भंडार का स्तर का कोई संबंध वास्तविकता से होता हुआ प्रतीत नहीं होता है। जांच की अवधि में माल भंडार में वृद्धि हुई है। जबकि संबद्ध देशों से आयात के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। इस प्रकार से किसी भी स्थिति में माल के भंडार में वृद्धि के कारण समग्र देशों से आयात नहीं हुआ है।

च. पाटन के कारण कीमत में कोई क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग को क्षति होना विभिन्न स्रोतों पर शुल्कों के बाद भी जारी रहा है। यदि क्षति नाँचे और मैक्सिको जैसे अन्य स्रोतों से हुई होती, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा तक दिया जा रहा है, शुल्क को ऐसे स्रोतों पर लगाया जाता है और इस कारण से वर्तमान एसएसआर में संबद्ध देशों पर शुल्क को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। कीमत में कटौती जांच की अवधि के दौरान चीन जन गण, ताइवान और थाईलैंड से नकारात्मक रही है जिसका अर्थ यह होता है कि इन देशों से भी आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है। यूरोपीय यूनियन और कोरिया जैसे प्रमुख देशों से प्रमुख स्रोत अपारित दरों पर हुई थी। जैसा कि प्राधिकारी द्वारा विगत में देखा गया है।

छ. घरेलू उद्योग को क्षति अन्य कारकों से हो रही है:

- (i) आयातों के सभी प्रमुख स्रोतों पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा है लेकिन फिर भी घरेलू उद्योग दावा करता है कि उसे क्षति हो रही है।
- (ii) कंपनी कर्ज में डूबी हुई है और कंपनी द्वारा भारी ब्याज लागतों का वहन किया जा रहा है। यद्यपि पैट्रो केमिकल की कीमतें पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक नीचे आ गई हैं, फिर भी इससे स्थिति में सुधार नहीं हो सका है।

ज. याचिकाकर्ता को लगातार कोई क्षति नहीं हुई है और न ही कथित पाटन अथवा पाटन की संभावना के कारण क्षति की कोई संभावना नहीं है।

झ. घरेलू उद्योग द्वारा पाटन और क्षति के जारी रहने और उसके बार-बार होने की संभावना का एकमात्र आधार संबद्ध देशों में अत्यधिक क्षमता और भारतीय बाजार की आकर्षकता है जिसकी पुष्टि साक्ष्य द्वारा नहीं की गई है।

- i. चीन, ताइवान और थाइलैंड से कीमत की कटौती नकारात्मक रही है। रूस से आयात क्षति की पूरी अवधि और जांच की अवधि के दौरान शून्य रही है।
- ii. घरेलू उद्योग द्वारा तीसरे देश के निर्यात आंकड़ों पर विश्वास संभावना की स्थिति दर्शने के लिए किया गया है जिसमें कुछ मूलभूत कमियां हैं जो आपूर्ति किए गए आंकड़ों को अविश्वसनीय ही बनाता है। सर्वप्रथम ये आंकड़े विभिन्न उत्पादों और उप-शीर्षकों से संबंधित हैं जबकि वर्तमान एसएसआर में विचाराधीन उत्पाद की स्थिति अलग है। कम से कम 3 उप-शीर्षकों अर्थात् 390410, 390421 और 390422 से संबंधित आंकड़ों पर विश्वास किया गया है। दूसरा, ये आंकड़े विगत अवधि से संबंधित हैं और इन आंकड़ों को घरेलू उद्योग द्वारा अपनी स्थिति के अनुकूल उठाया गया है तथा हमारे तर्क पर बल देने के लिए इसे उठाया गया है कि इस कीमत में अनेक प्रकार के विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन मद्दें शामिल हैं, इन देशों में निर्यात कीमत असामान्य रूप से अलग-अलग है।
- iii. रूस से आयात क्षति की पूरी अवधि और जांच की अवधि के दौरान शून्य रहा है। शुल्कों को जारी रखने के लिए कोई औचित्य इस प्रकार के परिदृश्य में सिद्ध नहीं किया गया है। इससे केवल यह सिद्ध होता है कि रूस से विगत आयातों के साथ संभावना के अभाव को दिखाया जा रहा है। 2013 के दौरान रूस से विश्व को किए गए निर्यात के संबंध में सूचना घरेलू उद्योग द्वारा दी गई है। वह न तो जांच की अवधि से संबंधित है और न ही विचाराधीन उत्पाद से संबंधित है क्योंकि 3 उप-शीर्षकों जैसे 390410, 390421 और 390422 से संबंधित आंकड़ों पर घरेलू उद्योग द्वारा विश्वास किया गया है।
- iv. संबद्ध देशों के लिए विश्व निर्यात आंकड़े न तो जांच की अवधि के लिए हैं और न ही विचाराधीन उत्पाद के लिए हैं और इसे चयनित रूप में उपलब्ध कराया गया है। इन आधारों पर संभावना का दावा गलत है और उसे प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जाना चाहिए।

संबद्ध वस्तुओं की कीमत कच्चे/पैट्रो केमिकल कीमतों के अनुकूल हैं और कच्चे तेल की कीमतों में इसे एक वर्ष अथवा उसके लगभग में बहुत अधिक गिरावट देखी गई है। इसके फलस्वरूप, ईडीसी की कीमतों में कमी आई है जो संबद्ध वस्तुओं के लिए कच्चा माल है। इससे कैमप्लास्ट को बहुत अधिक लाभ हुआ है। हालांकि, इसका कोई लाभ उपभोक्ता उद्योग को नहीं दिया गया है क्योंकि कैमप्लास्ट का भारत में एकाधिकारवादी बाजार है और कैमप्लास्ट पाटनरोधी का दुरुपयोग कर रहा है।

झ. इसके प्रतिकूल यूएस डॉलर की कीमत में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और सस्ता आयात कोई वास्तविक नहीं रह गई है। कच्चे तेल की कीमत जिसका अर्थ यह है कि संबद्ध वस्तुओं के कच्चा माल की कीमत में बहुत अधिक गिरावट आई है। यह गिरावट जांच की अवधि के दौरान और जांच की अवधि के बाद के दौरान भी रही है। कैमप्लास्ट द्वारा तैयार सामानों की कीमत में कमी की तुलना में कच्चे माल की कीमतों में कमी के संबंध में लाभ को अत्यधिक गैर-आनुपातिक तरीके से दिया गया है।

ट. प्राधिकारी को कच्चे तेल की कीमतों और अमेरिकी डॉलर की दरों के साथ संबद्ध वस्तुओं पर किसी पाटनरोधी शुल्कों, यदि उसे जारी रखा जाना है, को जोड़ने के लिए एक तंत्र बनाना चाहिए ताकि उपभोक्ता उद्योग के हित का ध्यान रखा जा सके।

ठ. एक विशिष्ट फार्मा उद्योग के लिए वर्ष 1986 में डिजाइन किए गए 22 प्रतिशत आरओसीई का आधार जब ब्याज दर और कारपोरेट कर जैसे सभी मानदंड अलग-अलग थे, को वर्ष 2011 में 25 वर्षों के बाद उचित रूप में नहीं माना जा सकता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को उद्योग द्वारा अर्जित आरओसीई अपनाना चाहिए जब पाटन का उचित लाभ मार्जिन के रूप में और न कि 22 प्रतिशत आरओसीई के रूप में कोई आरोप नहीं था। नियोजित पूँजी पर 22 प्रतिशत लाभ घरेलू उद्योग को अनुचित सुरक्षा प्रदान करता है। माननीय सेसटेट ने ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग एवं अन्य बनाम नामित प्राधिकारी के मामले में तथा सेसटेट ने मै. हायोसंग कंपनी बनाम नामित प्राधिकारी के मामले में स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि 22 प्रतिशत आरओसीई को अपनाने से क्षति का निर्धारण भ्रमपूर्ण हो गया है। इसने कम कीमत पर बिक्री और क्षति के मार्जिन को बढ़ा दिया है।

ड. पीवीसी पेस्ट/एमल्सन रेसिन इंडिया की मांग और आपूर्ति में बहुत अधिक अंतर है। भारत में आयात आवश्यक है। इस उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की कोई कार्रवाई से डाउनस्ट्रीम उद्योगों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ढ. भारतीय उत्पादक 95 प्रतिशत से अधिक के क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहे हैं। घरेलू उद्योग पर मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

ण. घरेलू उद्योग का जांच की अवधि के दौरान हानि के संबंध में दावे में कोई औचित्य नहीं है। घरेलू उद्योग के विभिन्न संघटकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट कुछ और दर्शाती है।

त. घरेलू उद्योग क्षतिरहित कीमत अर्जित करने में सक्षम है और इस कारण से इस पर आयात के कारण कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

थ. घरेलू उद्योग का यह कथन कि संबद्ध देशों में बहुत अधिक क्षमता है, पूर्ण रूप से अतार्किक है।

द. पाटनरोधी शुल्क का आगे विस्तार जनहित में नहीं होगा क्योंकि उससे डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ध. पाटनरोधी शुल्क के नहीं लगाने के बाद भी हनवा कभी भी पाटन अथवा किसी अन्य अनुचित व्यापार प्रथा द्वारा भारतीय बाजार पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करता है।

प. वीसीएम की कीमतों में सुदूर-पूर्व के देशों में गिरावट आई है लेकिन कोरिया के उत्पादकों ने उस गिरावट का लाभ बाजार उपभोक्ताओं को नहीं दिया है।

फ. पीवीसी रेटिंग की कीमतें यूरोपीय यूनियन के उत्पादकों द्वारा कोरिया के उत्पादकों की तुलना में 20 प्रतिशत कम रखी गई है। पाटनरोधी शुल्क के कारण हम यूरोपीय यूनियन से आयात करने में सक्षम नहीं हैं।

ब. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रूपए की दर में लगातार कमी को ध्यान में नहीं रखा है।

भ. पाटनरोधी शुल्क से क्रॉस मुद्रा दर में परिवर्तन नहीं होता है। भारतीय रूपए की दर बढ़ी है जिसके फलस्वरूप क्लासिक लेमिटेक्स द्वारा निर्मित सामान की कीमत में वृद्धि हुई है और उससे निर्यात दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

म. पाटनरोधी शुल्क ने क्रॉस मुद्रा के दर में उतार-चढ़ाव पर विचार नहीं किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी अमेरिकी डॉलर और बस्तु की कीमतों के बीच इनवर्स अनुपात को मानने में असफल रहे हैं। 70 प्रतिशत सुरक्षा कैमप्लास्ट को दी गई है।

य. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस पर ज्यादा बल दिया है और स्थिर इनपुट कीमतों को मांगा है। कैमप्लास्ट ने इस प्राधिकारी को भ्रमित करने के लिए अनेक प्रकार के इनपुट कीमतों को घोषित करते हुए झूठ का पुलिंदा बनाया है।

कक. कोई एकीकृत उत्पादक की स्थापना केवल एथिलीन बेचने के लिए नहीं की गई है और कैमप्लास्ट को यह कच्चा माल तभी मिलता है जब यह किसी के पास अतिरिक्त मात्रा में हो। निम्न वित्तीय ताकत के साथ-साथ खरीदने की उच्च क्षमता कैमप्लास्ट को घोटे का प्रमुख कारण है।

खख. कैमप्लास्ट के पास इस उत्पाद की मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है।

गग. यदि कैमप्लास्ट विश्वस्तरीय उत्पाद बना रहा है तब उसे चीन, थाइलैंड, यूरोप आदि को निर्यात करना चाहिए तथा 20 प्रतिशत-70 प्रतिशत तक अतिरिक्त लाभ अर्जित करना चाहिए, यदि इन देशों के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कीमत सही हो। प्राधिकारी पिछले 15 वर्षों से कैमप्लास्ट का अनुचित रूप से पक्ष ले रहे हैं और इन देशों में से किसी में भी कोई व्यापार प्रतिबंध नहीं है।

घघ. पीवीसी रेसिन विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक मौलिक, रासायनिक महत्वपूर्ण उत्पाद है और इस कारण से भारत सरकार ने इस उत्पाद पर उच्चतम सीमा शुल्क से कम शुल्क लगाया है। पाटनरोधी शुल्क प्राधिकारी द्वारा 70 प्रतिशत तक शुल्क लगाकर पूर्ण रूप से इसे गलत किया गया है।

डड. प्राधिकारी पहले से ही निर्धारित धारणा से कार्य कर रहे हैं। यदि आधार वर्ष 2013-14 है जब तेल की कीमत 100 अमेरिकी डॉलर से अधिक थी, तो किस प्रकार से हुए इस स्थिति में इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं जब कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल 30 अमेरिकी डॉलर से कम है।

चच. कैमप्लास्ट को बिना आयात वाले देशों पर भी लगभग 15 वर्षों से संरक्षण दिया गया है। यदि कुछ वर्षों का अंतर नहीं हो, तो किस प्रकार से इन तथ्यों को सिद्ध किया जा सकता है।

छछ. पीवीसी एक वैश्विक माल है और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बिल्कुल पारदर्शी हैं। कोरिया और ताइवान के उत्पादक पीवीसी को भारत में कमतर कीमत पर क्यों बेचेंगे जब उन्हें अपने घरेलू बाजार में अधिक कीमत मिल सकती है? कैमप्लास्ट का दावा बिल्कुल आधारहीन है।

जज. यूरोप में पीवीसी की कीमत सबसे कम है लेकिन पाटनरोधी शुल्क के कारण इसे आयात करने की लागत बहुत अधिक हो गई है। चूंकि, कोरिया और ताइवान के उत्पादकों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लग रहा है, अतः वे बहुत अधिक लाभ पर इस उत्पाद को बेच पाने में सक्षम होते हैं क्योंकि उनकी प्रतिस्पर्द्धा पाटनरोधी शुल्क के कारण बाजार में बहुत अधिक हो गई है।

झझ. कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप क्लासिक द्वारा निर्मित अंतिम उत्पाद की कीमत में वृद्धि हुई है और इससे निर्यात बाजारों में विकास बाधित हुआ है।

जत्र. पाटनरोधी शुल्क लगाने के पीछे कोई आर्थिक लाभ नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी सामान्य व्यापारिक कीमत और पाटन प्रथाओं के बीच अंतर करने में असफल रहे हैं जिसके फलस्वरूप क्लासिक जैसे सामान्य व्यापारी को धन मिल रहा है।

टट. कैमप्लास्ट की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। कंपनी पीवीसी पेस्ट को भारतीय उपभोक्ताओं को अग्रिम आधार पर बेचता है जो यह दर्शाता है कि इसका क्रूण 0.56 विक्री माह है।

ठठ. कैमप्लास्ट के पास एक सप्ताह से अधिक का माल भंडार नहीं होता है और इस तथ्य द्वारा सिद्ध किया जा सकता है कि कैमप्लास्ट क्लासिक को एक सप्ताह के नोटिस पर एक ट्रक की आपूर्ति करने में भी सक्षम नहीं है।

डड. सबसे बड़े आयातक होने के बावजूद, क्लासिक को आयातक की प्रश्नावली का उत्तर तथा याचिका पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। यह अनुरोध किया जाता है कि सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण करने तथा उस पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए मौखिक सुनवाई से 40 दिन का समय दिया जाए।

ढढ. पाटन और क्षति की संभावना और उसके बार-बार होने का दावा केवल अनुमान पर आधारित है और इसका कोई संबंध इस मामले के तथ्यों की वास्तविकता से नहीं है और हम वर्तमान शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति के बार-बार होने की संभावना के किसी आरोप से इंकार करते हैं।

णण. घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। संबद्ध देशों सहित विभिन्न स्रोतों पर पाटनरोधी शुल्क अब से एक दशक से अधिक से प्रचलित है और घरेलू उद्योग को अभी भी घाटा हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि घरेलू उद्योग को क्षति का कारण कथित पाटन नहीं है बल्कि यह घाटा स्वयं अन्य कारणों से हो रहा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग अभी भी संबद्ध वस्तुओं के विभिन्न ग्रेडों की आपूर्ति नहीं कर रहा है और न ही वे घरेलू उद्योग की मांग का बहुत बड़ा हिस्सा पूरा कर सकते हैं और प्रयोक्ता उद्योग उसे गैर-जरूरी पाटनरोधी शुल्कों का भुगतान करने के बाद अन्य देशों से आयात करने के लिए मजबूर हैं।

तत. रूस से आयात पर विचार करने के बाद निर्णयिक समीक्षा रोक दी गई है और रूस को इस याचिका के विश्वेषण के बाद से ही संबद्ध देशों की सूची से बाहर कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि दस्तावेज से पाटन का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है और रूस से पीवीसी के आयात द्वारा कोई व्यापक क्षति के साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं।

## छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

71. घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. इस देश में उत्पाद की मांग, क्षति की पूरी अवधि के दौरान एक सकारात्मक गति को दर्शाता है।

ख. संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद, उन देशों, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता है, से काफी मात्रा में भारतीय बाजार में आयात होना जारी है।

ग. पाटित आयातों के बाजार हिस्से में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

घ. संबद्ध देशों से आयात से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। संबद्ध देशों से कीमत की कटौती बहुत अधिक होती है क्योंकि आयात का अवतरित कीमत घरेलू उद्योग के एनआईपी से बहुत कम है।

ङ. आयातों की अवतरित कीमत क्षति की पूरी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से बहुत कम है। जबकि क्षति की अवधि में बिक्री की लागत में 12% तक वृद्धि हुई है। फिर भी निवल बिक्री कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। घरेलू उद्योग को पाटित आयातों की बहुत अधिक निम्न कीमतों से प्रतिस्पर्द्धा करने के उद्देश्य वर्तमान जांच की अवधि तक 2012-13 से बिक्री की लागत से भी नीचे अपनी कीमतों को करना पड़ा था।

च. घरेलू उद्योग को कीमत में कमी के कारण लाभ प्रदाता में बहुत अधिक गिरावट तथा भारी घाटे का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद हो रहा है।

छ. घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि में नई क्षमताओं को नहीं जोड़ा है। हालांकि, बैट्री सेपरेटर रेसिन और सर्पेंशन रेसिन से लेकर पीवीसी पेस्ट तक क्षमताओं का आवंटन हुआ है और उससे विचाराधीन उत्पाद के लिए उपलब्ध प्रभावी क्षमता में वृद्धि हुई है।

ज. विचाराधीन उत्पाद की मांग उस मात्रा से अधिक है जितना घरेलू उद्योग उत्पादन और बिक्री कर सकता है। इस कारण से घरेलू उद्योग को इन वस्तुओं की बिक्री में उस सीमा तक कोई कठिनाई नहीं है कि इसकी कीमतें आयात की तुलना में प्रतिस्पर्द्धा हैं। चूंकि, घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतों को आयात की कीमतों के अनुरूप रखा, अतः बिक्री की मात्रा और उसके परिणामस्वरूप उत्पादन और क्षमता के उपयोग में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में मामूली गिरावट के साथ इस अवधि के दौरान सुधार हुआ है।

झ. घरेलू उद्योग के लाभ में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद सुधार हुआ है। हालांकि, लाभ प्रदाता में बहुत अधिक गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को 2012-13 में पुनः वित्तीय घाटे होने लगे। जब घाटों की सीमा 2012-13 में पहले से ही इतनी अधिक थी तब घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए घाटे में जांच की अवधि में और अधिक वृद्धि हुई।

ञ. कीमत में कमी और उस पर दबाव के फलस्वरूप लाभ में बहुत अधिक गिरावट हुई है और घरेलू उद्योग को 2012-13, 2013-14 और जांच की अवधि में वित्तीय घाटा उठाना पड़ा।

ट. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन एक सतत प्रक्रिया है जिसे रोका नहीं जा सकता है। इसके अलावा, या तो घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को आयात कीमतों में परिवर्तन के साथ जोड़ना होगा अथवा इसे आदेश नहीं मिलेगा। बहुत अधिक परिपक्व बाजार, विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिए जा रहे प्रचलित कीमतों की तुलना में उपभोक्ताओं के साथ बहुत अधिक जानकारी को देखते हुए, विदेशी उत्पादकों द्वारा की गई पेशकश का प्रभाव तत्काल घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ता है।

ठ. व्याज पूर्व-लाभ में भी 2011-12 में इसकी वसूली के बाद बहुत गिरावट आई और जांच की अवधि के दौरान घरेलू बिक्री के साथ इसकी कर-पूर्व लाभ घटकर क्रृणात्मक हो गया।

ড. घरेलू उद्योग के नकद लाभ में पूर्व के पाटन से आंशिक वसूली के बाद जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट आई। घरेलू उद्योग 2012-13 से नकद घाटा उठाता रहा है।

ঢ. निवेश पर आय में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद सुधार हुआ। हालांकि, इसमें 2012-13 में बहुत अधिक गिरावट आई जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई। घरेलू उद्योग को प्रस्तावित जांच की अवधि के दौरान क्रृणात्मक आय का सामना करना पड़ रहा है।

ণ. घरेलू उद्योग को हाल में पूर्व में पाटित सामानों से क्षति हुई थी और यह पूर्व-स्थिति में आने की प्रक्रिया में था। लेकिन इसे भारतीय बाजार में पाटन के फलस्वरूप पुनः क्षति उठानी पड़ रही है। यह संबद्ध देशों, जिन पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है, में निर्यातकों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन में वृद्धि के कारण पाटनरोधी शुल्क के औचित्य को खोने के कारण हुआ है।

ত. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है जबकि आयात के हिस्से में गिरावट आई है। हालांकि, पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के बावजूद, पाटित आयातों का बाजार हिस्सा बहुत अधिक रहा है।

थ. घरेलू उद्योग के रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई है। मजदूरी में मामूली वृद्धि हुई है। इसके अलावा, उत्पादकता में लगातार वृद्धि हुई। ये मानदंड अनेक अन्य मानदंडों पर निर्भर करते हैं और ये घरेलू उद्योग पर पाठन के प्रभाव को नहीं दर्शते हैं। कर्मचारियों की सेवा किराए पर लेना और उसे बर्खास्त करना घरेलू उद्योग के लिए अंतिम आश्रय की स्थिति है।

द. कीमत मानदंडों के संबंध में विकास क्रृष्णात्मक है और यह आरओसीई के लिए बहुत कम है।

ध. उद्योग के कार्य निष्पादों पर पाठित आयातों द्वारा बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन में लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध में बहुत अधिक गिरावट आई है। लगातार पाठन के फलस्वरूप घरेलू कीमतों पर दबाव बना है जिससे लाभ में कमी आई है।

न. घरेलू उद्योग के लाभ में कमी को अपरिणामी अथवा मामूली प्रतिकूल प्रभाव के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। जबकि लाभ, नकद धाटे और निवेश पर आय में सुधार होना चाहिए था, लेकिन उसमें गिरावट आई है। इससे केवल यह सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है और यह प्रतिकूल है।

प. घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न मानदंड सामूहिक रूप से और संचयी रूप से यह सिद्ध करते हैं कि घरेलू उद्योग को बहुत अधिक क्षति हुई है। इसके अलावा, पाठन और परिणामी क्षति के जारी रहने और उसके और अधिक होने की संभावना उस स्थिति में है जब वर्तमान पाठनरोधी शुल्क समाप्त हो जाए।

फ. मूल जांच में संबद्ध देशों के संबंध में पाठन मार्जिन न केवल न्यूनतम था बल्कि पर्याप्त भी था। वर्तमान जांच की अवधि के लिए पाठन मार्जिन बहुत अधिक है। पाठनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति इन नियांतिकों को भारत में विचाराधीन उत्पाद को पाठित करने के साथ बहुत बड़ा अवसर मिलेगा जिससे घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा समाप्त हो जाएगा।

ब. कोरिया जन गण से एलजी केम. लि. और हनवा केम. कारपोरेशन तथा ताइवान से फार्मोसा प्लास्टिक कारपोरेशन के संबंध में पाठन मार्जिन न्यूनतम थी और इसलिए शून्य की दर पर पाठनरोधी शुल्क की सिफारिश इन स्रोतों से होने वाले नियांत के संबंध में की गई थी। हालांकि, वर्तमान में इन नियांतिकों द्वारा किए जा रहे नियांत के संबंध में पाठन मार्जिन बहुत अधिक है। इस अवधि में की गई नियांत कीमत और सामान्य मूल्य का अनुमान स्पष्ट रूप से इस अवधि में पर्याप्त पाठन मार्जिन की मौजूदगी को दर्शाता है।

भ. संबद्ध देशों से आयात पाठनरोधी शुल्क के मौजूद रहने की स्थिति में रहते हुए भी बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शा रहा है। इसलिए, इसकी पूरी संभावना है कि पाठनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में मात्रा में वृद्धि होगी। वर्तमान में आयात की मात्रा की बढ़ती हुई गति पर विचार करने के बाद यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि पाठनरोधी शुल्क के समाप्त किए जाने की स्थिति में मात्रा में गिरावट आएगी।

म. संबद्ध देशों में उत्पादक संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए भारी क्षमता बनाए रखते हैं जो वर्ष 2014 के लिए विनिल्स पर आईएचएस रिपोर्ट से बिल्कुल स्पष्ट है।

य. पाठनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने के साथ मात्रा में और अधिक वृद्धि होनी तय है। इसके अलावा, जब उनके अन्य बाजार बंद हो गए हैं तब इसकी संभावना में और अधिक वृद्धि होगी।

कक. चीन और रूस के उत्पादक पाठित कीमतों पर तीसरे देशों को संबद्ध वस्तुओं का भारी मात्रा में नियांत कर रहे हैं। पाठनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, यह मात्रा संभवतः भारत में परिवर्तित हो जाएगी और वह ही बहुत अधिक पाठित कीमतों पर जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

खख. विचाराधीन उत्पाद के लिए भारतीय बाजार बहुत अधिक कीमत संवेदनशील है। उपभोक्ता कीमत को सबसे अधिक महत्व देते हुए अपने स्रोत के बारे में निर्णय लेते हैं। ऐसी स्थिति होने के कारण बाजार में संबद्ध देशों से इस प्रकार के कम कीमत पर आयातों की उपलब्धता से घरेलू उद्योग पर निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

गग. संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा मौजूदा पाठनरोधी शुल्क के बावजूद बहुत अधिक है। वास्तव में, बाजार का आयात हिस्सा जांच की अवधि के दौरान मामूली गिरावट के साथ कुछ वर्षों में बढ़ा है।

घघ. घरेलू उद्योग को पहले से ही भारी वित्तीय धाटा, नकद धाटा और निवेश पर क्रृष्णात्मक आय हो रही है। पाठनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, इससे संभवतः और अधिक अविजित पर्याप्त क्षति होगी।

उड. विचाराधीन उत्पाद की मांग में कोई कमी नहीं आई है। पर्याप्त क्षति घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से हो रही है। विनिर्माण की प्रक्रिया में कोई अधिक अंतर नहीं है।

चच. सूचीबद्ध ज्ञात अन्य कारक यह सिद्ध नहीं करते हैं कि इन अन्य कारकों द्वारा क्षति हुई है। ऐसी स्थिति में एकमात्र निष्कर्ष जिससे बचा जा नहीं सकता है, यह है कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध निर्यातकों और संबद्ध देशों से पाटित आयातों से हुई है।

छछ. संबद्ध देशों में उत्पादकों से आयात की मात्रा में वृद्धि होती रही है और यह बहुत अधिक हो गई है।

जज. आम तौर पर संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।

झझ. घरेलू उद्योग के लिए इसके उत्पाद की कीमत तय करने के लिए आरंभिक बिन्दु इनपुट्स की लागत और विदेशी उत्पादकों द्वारा दी जाने वाली कीमत है। इस प्रकार से, यदि विदेशी उत्पादकों द्वारा दी जाने वाली कीमत उस कीमत की तुलना में बहुत कम है जो घरेलू उद्योग अपनी लागत परिवर्तन के आधार पर तय करता है, घरेलू उद्योग के पास एकमात्र विकल्प उचित से कम कीमत की पेशकश करना होगा। पाटित आयातों द्वारा कीमत में हो रही कटौती घरेलू उद्योग को इसकी कीमतों में वृद्धि करने से रोक रहा है।

जज. लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ में कमी प्रत्यक्ष रूप से पाटित आयातों का परिणाम है।

टट. घरेलू उद्योग का विकास कीमत के मानदंड के अनेक मानदंडों के संबंध में ऋणात्मक हो गया।

ठठ. घरेलू उद्योग ने कभी भी मात्रा की क्षति का दावा नहीं किया है। संबद्ध देशों से आयात में पूर्ण रूप में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। संबद्ध आयात काफी हद तक घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव डाल रहा है और इसमें कटौती कर रहा है। कीमत में कटौती घरेलू उद्योग द्वारा पहले से रखी गई नियर्यातकों के बावजूद होती है। आयात कीमत में वृद्धि को रोक रहा है जो पाटित आयातों के न होने पर हुआ होता। घरेलू उद्योग को लाभ, निवेश पर आय और नकदी के प्रवाह के मामले में नुकसान हुआ है।

डड. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद, उन देशों, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा है, से पर्याप्त मात्रा में भारतीय बाजार में आयात का होना जारी है। आयात चीन से भारतीय बाजार में कृत्रिम रूप से अधिक कीमतों पर हो रहा है जिससे यह प्रतीत होता है कि पाटनरोधी शुल्क से बचा जा रहा है। भाड़ा जोड़ने के बाद चीन के सीमा शुल्क से नियर्यात भारतीय सीमा शुल्क में सूचित की गई कीमतों से कम कीमतों पर बहुत अधिक मात्रा में होता है। भारतीय सीमा शुल्क में सूचित की गई आयात कीमत कृत्रिम रूप से अधिक है और चीन के सीमा शुल्क में सूचित की गई कीमत वर्तमान प्रयोजन से संगत और विश्वसनीय है।

ढढ. पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के बावजूद पाटित आयातों का बाजार हिस्सा बहुत अधिक रहा है और पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ेगा। इसके अलावा, घरेलू उद्योग पर पाटन का प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ता है।

णण. यह तथ्य कि भारत में उपभोग भारतीय उत्पादकों के पास उपलब्ध क्षमताओं से अधिक है, अपने-आप में आयात न कि पाटन का औचित्य ठहराता है।

तत. घरेलू उद्योग प्रमुख विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की कीमत पेशकश पर विचार करने के बाद अपनी कीमतों का निर्धारण करने और अपनी लागत दृष्टिकोण पर ध्यान न देने के लिए बाध्य है। चूंकि, विदेशी उत्पादक पाटन का सहारा ले रहे हैं, अतः घरेलू उद्योग इस प्रकार की पाटित कीमतों का पालन करने के लिए बाध्य है।

थथ. यदि घरेलू उद्योग की कीमत की तुलना आयात कीमत से की जा सकती है तो घरेलू उद्योग का उत्पाद को उपभोक्ताओं के समक्ष वरीयता मिलती है। चूंकि, घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को आयात कीमतों से जोड़ने के लिए बाध्य है, अतः संबद्ध देशों और अन्य देशों से पाटन का घरेलू उद्योग पर एक प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ा है जो लाभ, निवेश पर आय और नकदी के प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में गिरावट से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है।

दद. कीमत में कटौती का निर्धारण करने का प्रयोजन इस बात का आकलन करना है कि क्या इस प्रकार से पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। इस बात का निर्धारण करना भी अपेक्षित है कि क्या आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है अथवा क्या आयातों के प्रभाव से अन्य प्रकार से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ता था। इसलिए, ऋणात्मक कीमत कटौती का आवश्यक रूप से यह मतलब नहीं होता है कि घरेलू उद्योग को कोई हानि नहीं होती है।

धध. भारी ब्याज लागत व्यापार क्रियाकलाप का हिस्सा होता है और इसे तदनुसार समाधान किए जाने की आवश्यकता होती है। वास्तव में नामित प्राधिकारी 22 प्रतिशत आरओसीई मंजूर करता है और इस कारण से क्या कंपनी का अधिक ब्याज अथवा कम ब्याज है, एनआईपी प्रभावित नहीं होती है। यदि ब्याज की लागत अधिक होती है तब लाभ कम होगा और यदि ब्याज की कीमत कम है तब लाभ ज्यादा होगा।

नन. एसएसआर अन्वेषण की जांच की अवधि के दौरान रिपोर्ट किए गए आयात की कम मात्रा की स्थिति में भी, पाटनरोधी शुल्क को जारी रखा जा सकता है। अनेक उदाहरण हैं जहां विदेशी प्राधिकारियों ने प्रथम और बाद की निणायिक समीक्षाओं में इस शुल्क को जारी रखा है।

पप. कञ्चे तेल की कीमत में गिरावट जांच की अवधि के बाद ही आई है और इस कारण से कञ्चे तेल की गति का वर्तमान जांच में कोई औचित्य नहीं है।

फफ. रूपए के अवमूल्यन से चयनित रूप से तैयार उत्पाद कीमतों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यह कञ्चे माल की कीमतों पर भी प्रभाव डालता है। वास्तव में सेसटेक ने अमेरिकी डॉलर की दर में वृद्धि के कारण भारतीय रूपए से अमेरिकी डॉलर में इस मुद्रा को संशोधित किया था। यदि अमेरिकी डॉलर की दर में वृद्धि इस शुल्क को भारतीय रूपए में परिवर्तित करने का कारण था तब वह शुल्क को भारतीय रूपए में परिवर्तित करने का कोई आधार नहीं बन सकता है। इसके अलवा, नामित प्राधिकारी ने डिजीटल प्लेट्स के मामले में शुल्कों को भारतीय रूपए में सिफारिश करने से इंकार किया था जिसमें स्पष्ट रूप से यह सिद्ध किया गया था कि अमेरिकी डॉलर में शुल्क से इस उद्योग को बहुत अधिक संरक्षण मिल रहा था।

बब. पीवीसी पेस्ट रेसिन की घरेलू कीमतों के संबंध में सूचना संबद्ध देशों में पीवीसी पेस्ट की कीमतों को दर्शाने के लिए हरिमन कंसल्ट रिपोर्ट तृतीय पक्ष की सूचना है और घरेलू उद्योग उसको प्रकट करने के लिए अधिकृत नहीं है। इस सूचना के लिए भुगतान अपने-आप में किसी भी व्यक्ति के साथ इस सूचना को नहीं देने के दायित्व के साथ इस सूचना का भुगतान करने वाले व्यक्ति तक इसकी पहुँच को सीमित कर देता है।

मम. वीसीएम और पीवीसी पेस्ट रेसिन कीमत यूरोप में बहुत अधिक है।

यय. उन निर्यातकों के लिए जिनके पास कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं है, वर्तमान मात्रा और कीमत अपने-आप में संभावना का सबसे बड़ा साक्ष्य है।

ककक. नामित प्राधिकारी लगातार 22 प्रतिशत लागू करते रहे हैं। प्राधिकारी ने उन मामलों में भी 22 प्रतिशत मंजूर किया जहां वास्तविक लाभ अपेक्षाकृत अधिक था।

खखख. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और घरेलू क्रियाकलाप के संबंध में अलग-अलग की गई सूचना को ही उपलब्ध कराया। इसलिए अलग उत्पाद के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किया गया कार्य निष्पादन पूर्ण रूप से तथ्य से परे है।

गगग. घरेलू उद्योग एनआईपी अर्जित करने में सक्षम नहीं है। इसे क्षति की कोई वधि के दौरान घाटा उठा पड़ रहा है।

घघघ. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों में अतिरिक्त धमताओं के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराया है।

डडड. पाठित आयातों के कारण कीमत में बहुत अधिक गिरावट हुई है। इस प्रकार से पक्षकार का यह तर्क सही नहीं है कि विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में गिरावट नहीं आई है।

चचच. वर्तमान मामले में जांच की अवधि सितंबर, 2014 में समाप्त हो गई और इसलिए कञ्चे तेल की वर्तमान कीमतों का कोई औचित्य नहीं है। किसी भी मामले में, कञ्चे तेल की कीमत का औचित्य विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन की लागत से अधिक नहीं है क्योंकि यह विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए कञ्चे माल नहीं है।

छछछ. कंपनी के पास माल भंडार नहीं है क्योंकि माल भंडार रखने में इसकी अपनी लागत होती है। कंपनी माल भंडार को यथासंभव सीमा तक बेच देती है। संगत तथ्य कंपनी द्वारा सृजित माल भंडार का स्तर नहीं है बल्कि घरेलू उद्योग पर पाटन का प्रतिकूल प्रभाव तथा उस कीमत, जिस पर घरेलू उद्योग अपने उत्पाद को बेचने के लिए बाध्य होता है, उस पर विचार किया जाना चाहिए।

जजज. जहां तक निर्यातकों का प्रश्न है, पाटनरोधी शुल्क का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है क्योंकि भारत सरकार निर्यात के प्रयोजन से आयात को छूट देती है। निर्यात के लिए पाटनरोधी शुल्क के छूट के बावजूद, यदि कंपनी को

विनिमय दर आदि में परिवर्तन के कारण निर्यात में नुकसान हो रहा हो, तो यह पूर्ण रूप से विभिन्न कारकों के कारण है जो वर्तमान मुद्रे से संबंधित नहीं हैं।

**झज्ज़र.** नामित प्राधिकारी ने क्रॉस मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव को माना है। एक बार लगाए गए पाटनरोधी शुल्क पांच वर्षों की अवधि तक लागू रहता है। इसकी समीक्षा समय-समय पर की जा सकती है। अन्य देशों ने हाल में विभिन्न उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क और सीबीडी लगाया है जो पाटन और अर्थिक छूट के वर्तमान स्तर से बहुत अधिक है और इस तथ्य के बावजूद कि वर्तमान मार्जिन बहुत कम है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि लगाया गया पाटनरोधी शुल्क तब तक लागू रहता है जब तक पक्षकार समीक्षा की आवश्यकता और शुल्क में संशोधन को सिद्ध नहीं कर दे।

**जबज.** प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह घरेलू उद्योग पर जैसा कि अब है और न कि आदर्श स्थितियों के अधीन होना चाहिए, पर विचार करे।

**ठट्ट.** केवल यह तथ्य कि घरेलू उद्योग इस देश में समग्र मांग को पूरा नहीं कर सकता है, का यह आशय नहीं है कि घरेलू उद्योग को नुकसान हो। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य आयात को रोकना नहीं है बल्कि घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करना है। हितैषी उत्पादक उचित दर पर इस उत्पाद को बेचकर भारतीय मांग को पूरा कर सकते हैं। विदेशी उत्पादकों से यह अपेक्षित नहीं था कि वे भारतीय मांग को पूरा करने के उद्देश्य से पाटन का सहारा लें।

**ठठठ.** घरेलू उद्योग का उत्पाद पूर्ण रूप से स्वीकार्य है और किसी भी पक्षकार को इस उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत नहीं है। पाटनरोधी शुल्क किसी कंपनी अथवा किसी उद्योग का पक्षपात नहीं करता है। यह केवल अनुचित व्यापार प्रथाओं का समाधान करता है।

**डडड.** भारत में अधिकांश उत्पाद पर वर्तमान में उच्चतम शुल्क से कम सीमा शुल्क लग रहा है। यह तथ्य कि इस उत्पाद पर उच्चतम सीमा शुल्क से कम सीमा शुल्क लग रहा है, का अर्थ यह नहीं होता है कि विदेशी उत्पादकों को माल पाटित करने की अनुमति दी गई है। इसके प्रतिकूल यह देखते हुए कि भारत सरकार ने सीमा शुल्क घटाया है, ये उत्पाद उच्चतर कीमत पर निर्यात करने के लिए पात्र हैं। उनसे यह अपेक्षित नहीं है कि वे पाटन का सहारा लें और भारतीय उद्योग को क्षति पहुँचाएं।

**ठठ.** पाटनरोधी शुल्क एक संरक्षण नहीं है।

**णणण.** कोरियाई और ताइवान के बाजार में विचाराधीन उत्पाद की मांग इन देशों में उत्पादकों के पास क्षमताओं से बहुत अधिक है। यह वे अतिरिक्त क्षमताएं हैं जिनका सृजन विदेशी उत्पादकों द्वारा किया गया है जो उन्हें पाटन का सहारा लेने के लिए बाध्य कर रहे हैं। जबकि वे अपने घरेलू बाजार में उस उत्पाद के लिए अपेक्षाकृत अधिक कीमत वसूल रहे हैं तब वे भारतीय बाजार में उस उत्पाद का निर्यात अपेक्षाकृत कम कीमत पर कर रहे हैं।

**ततत.** उपभोक्ताओं को किसी स्रोत से आयात करने से कुछ भी नहीं रोकता है। विदेशी उत्पादकों को इस उत्पाद को उस कीमत पर बेचने से कोई नहीं रोकता है जो पाटन की कीमत नहीं होती है। वास्तव में मांग और आपूर्ति के अंतर को देखते हुए, इन उत्पादकों के लिए भारतीय बाजार में उचित कीमत पर विक्री करने के लिए यह अपेक्षाकृत आसान होना चाहिए। यदि उत्पादकों ने पाटन का सहारा लिया है तब सरकार ने यह शुल्क नहीं लगाया होता और यदि उत्पादकों ने पाटन का सहारा लिया है तब उपभोक्ता अब लगाए गए शुल्क पर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं।

**थथथ.** पाटनरोधी शुल्क निर्यात के लिए आयात पर लागू नहीं होता है। ऐसी स्थिति होने पर इस प्रकार से वर्तमान पाटनरोधी शुल्क निर्यात बाजारों में कंपनी के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता था।

**ददद.** कैमप्लास्ट नकद आधार पर बेचता है और यह किसी भी प्रकार से एक अनुपयुक्त व्यापार नीति नहीं है। केवल इस कारण से कि कैमप्लास्ट की नीति नकद आधार पर उत्पाद को बेचना है, इसका यह अर्थ नहीं होता है कि कंपनी संरक्षण पाने की हकदार नहीं है। वास्तव में कंपनी, जो नकद आधार पर बेच रही है, की वित्तीय स्थिति खराब नहीं होगी। वास्तव में, इसकी वित्तीय स्थिति बेहतर होती।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

72. इस संबंध में हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और हानि की संभावना के पहलुओं की जांच करने के संबंध में कार्रवाई करने के पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच करने की कार्रवाई करता है।

73. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.1 और पाटनरोधी नियमावली का अनुबंध-II में दोनों (क) समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव और पाटित आयातों की मात्रा; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू

उत्पादों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच करने का प्रावधान है। पाटित आयातों के मात्रा प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह इस बात की जांच करे कि क्या पूर्ण रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। पाटित आयातों की कीमत के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह इस बात की जांच करे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से अन्य प्रकार से बहुत अधिक सीमा तक कीमतों पर दबाव बनेगा अथवा कीमत की वृद्धि में रुकावट आएगी जो अन्य प्रकार से काफी अधिक सीमा तक हुई होती।

74. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

“संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों का मूल्यांकन तथा विक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता का उपयोग में प्राकृतिक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव ढालने वाले सूचकांक; घरेलू कीमतों, पाटन के मार्जिन का आकार को प्रभावित करने वाले कारक, नकदी के प्रवाह, माल भंडार, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूँजीगत निवेश उगाहने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का मूल्यांकन शामिल होगा।”

75. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उत्पादों, क्षमता का उपयोग, विक्री की मात्रा, भंडार, लाभ प्रदत्ता, निवल विक्री प्राप्ति, पाटन का आकार और मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव ढालने वाले सूचकांकों पर विचार उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

76. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अनुसार, लगाए गए पाटनरोधी शुल्क, यदि इससे पूर्व में समाप्त नहीं किया गया हो, का इसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों के समाप्त होने तक प्रभाव नहीं ढालेगा वशर्ते कि यदि केंद्र सरकार एक समीक्षा में इस मत का हो कि इस प्रकार के सूत्र को समाप्त करने से संभवतः क्षति और पाटन जारी रहेगा अथवा बार-बार होगा, यह समय-समय पर इस अधिरोपण की अवधि को अगले पांच वर्षों की अवधि तक बढ़ा सकता है और इस प्रकार की आगे की अवधि ऐसे विस्तार के आदेश की तिथि से प्रारंभ होगी।

77. वर्तमान जांच लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है। नियम 23 में यह प्रावधान है कि नियम 11 के प्रावधान स्वयं विधि के अनुसार किसी समीक्षा की स्थिति में भी लागू होंगे। इसलिए प्राधिकारी ने अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 के प्रावधानों को विधि के अनुसार विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण किया है। इसके अलावा, चूंकि पाटनरोधी शुल्क विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लागू हैं, अतः प्राधिकारी इस बात पर विचार करते हैं कि क्या संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क पर घरेलू उद्योग को क्षति की जांच करते समय विचार किया जाना अपेक्षित है। प्राधिकारी ने इस बात की भी जांच की है कि क्या मौजूदा पाटनरोधी उपाय पाटन जिससे क्षति हो रही है, को निष्प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं।

### संचयी आकलन

78. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद का आयात एक ही समय में पाटनरोधी शुल्क की जांच के अध्यधीन आ रहा है तब नामित प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करेगा। यदि यह निर्धारित करता है कि:

“(क) प्रत्येक देश से आयातों की तुलना में स्थापित पाटन का मार्जिन नियति कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त 2 प्रतिशत से अधिक हो और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयातों का 3 प्रतिशत हो अथवा जहां अलग-अलग देशों का आयात 3 प्रतिशत से कम हो, संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयातों का 7 प्रतिशत से अधिक हो और (ख) आयातों का प्रभाव का संचयी आकलन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्द्ध की स्थितियों के आलोक में उपर्युक्त हो।”

79. इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि न्यूनतम पाटन मार्जिन और आयात की मामूली मात्रा के लिए मानदंड संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन की संभावना का निर्धारण करने के उद्देश्य से संगत नहीं है। हालांकि, संचयी आकलन के उद्देश्य से, संबद्ध देशों से उत्पादकों से पाटित न किए गए आयातों को क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से लिया गया है।

80. इसके अलावा, संबद्ध देशों से उत्पादकों द्वारा विनिर्मित समान परस्पर और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद की तुलना में समान वस्तु है। संबद्ध देशों से आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन करना उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात प्रत्यक्ष रूप से भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेशकश की गई समान वस्तुओं से प्रतिस्पर्द्धा करता है। साझा पक्षकार विभिन्न स्रोतों से और भारतीय घरेलू उद्योग एक-दूसरे के स्थान पर इन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, विक्री के माध्यम समान हैं।

81. वर्तमान क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध और क्षति की मौजूदगी की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभावों तथा इन कीमतों पर इसके प्रभावों तथा लाभप्रदता, यदि कोई हो, की जांच की है। प्राधिकारी ने इस नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग के रूप में मै. कैमप्लास्ट सनमार लि. से संबंधित सूचना पर विचार करने के बाद घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की जांच की है। तदनुसार, पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभाव की जांच नीचे दिए गए अनुसार की गई है:

### **पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव**

#### **मांग और बाजार हिस्सा**

82. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों और अन्य देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य के आकलन के लिए डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदत्त सौदा-वार आयात आकड़ों पर विचार किया है। विचाराधीन उत्पाद की मांग को सभी देशों से भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों और भारत में सभी घरेलू उत्पादकों की विक्रियों के रूप में निर्धारित किया गया है।

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई
घरेलू उद्योग की विक्रियां	एमटी	44,382	44,548	57,257	61,091
अन्य भारतीय उत्पादकों की विक्रियां	एमटी	11,490	11,906	11,906	11,906
कुल संबद्ध देश	एमटी	27,052	34,237	31,632	30,293
कोरिया गणराज्य	एमटी	7,565	8,476	10,277	13,212
ताइवान	एमटी	4,017	5,056	2,912	1,806
चीन जन.गण.	एमटी	4,015	2,082	307	152
मलेशिया	एमटी	2,809	5,350	7,415	4,183
थाइलैंड	एमटी	2,603	3,600	4,281	1,728
यूरोप	एमटी	6,043	9,673	6,440	9,213
देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू हैं	एमटी	1,016	6,585	7,263	6,467
अन्य देश	एमटी	1,862	780	1,560	3,535
कुल भारतीय मांग	एमटी	85,802	98,056	109,618	113,292

83. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु की मांग में क्षति अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि हुई है।

84. घरेलू उद्योग और संबद्ध देशों से आयातों का मांग में बाजार हिस्सा निम्नानुसार है:-

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई
मांग में कुल आयातों का हिस्सा	%	34.88%	42.43%	36.91%	35.57%
मांग में संबद्ध देश से आयातों का हिस्सा	%	31.53%	34.92%	28.86%	26.74%
मांग में अन्य देशों जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, से आयातों का हिस्सा	%	1.18%	6.72%	6.63%	5.71%
मांग में अन्य देशों से आयातों का हिस्सा	%	2.17%	0.79%	1.42%	3.12%
घरेलू उद्योग की मांग का हिस्सा	%	51.73%	45.43%	52.23%	53.92%
अन्य उत्पादकों का हिस्सा	%	13.39%	12.14%	10.86%	10.51%

85. उक्त आकड़ों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में 2012-13 में वृद्धि हुई है परंतु उसके बाद गिरावट आई है।

#### आयात मात्रा और संबद्ध देश का हिस्सा :

86. पाठित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाठित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में भारी वृद्धि हुई है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II (ii) में निम्नानुसार व्यवस्था है:

“पाठित आयातों की मात्रा की जाँच करते समय, उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाठित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में भारी वृद्धि हुई है”

87. क्षति अवधि के लिए आयात मात्राएं निम्नानुसार रही हैं:

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई
कुल आयात	एमटी	29,930	41,602	40,455	40,296
संबद्ध देश	एमटी	27,052	34,237	31,632	30,293
कोरिया गणराज्य	एमटी	7,565	8,476	10,277	13,212
ताइवान	एमटी	4,017	5,056	2,912	1,806
चीन जन.गण.	एमटी	4,015	2,082	307	152
मलेशिया	एमटी	2,809	5,350	7,415	4,183
थाइलैंड	एमटी	2,603	3,600	4,281	1,728
यूरोप	एमटी	6,043	9,673	6,440	9,213
ऐसे अन्य देशों से आयात जिनपर पाटनरोधी शुल्क लागू है	एमटी	1,016	6,585	7,263	6,467
अन्य देशों से आयात	एमटी	1,862	780	1,560	3,535
निम्न के संबंध में संबद्ध देशों से आयात					
कुल आयात	%	90.38%	82.30%	78.19%	75.18%
कुल मांग	%	31.53%	34.92%	28.86%	26.74%

88. उक्त से प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- क. संबद्ध देशों से आयातों में आधार वर्ष के बाद से वृद्धि हुई है।
- ख. कुल आयातों में से संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों का हिस्सा पीओआई सहित पूरी क्षति अवधि के दौरान काफी अधिक रहा है।
- ग. संबद्ध देश से समग्र रूप से आयात भारत में खपत के संबंध में काफी अधिक रहे हैं।

### **कीमत प्रभाव**

#### **पाइत आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव**

89. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जाँच कीमत कटौती, कम कीमत पर विक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल विक्री प्राप्ति (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के लिए पाइत आयातों के पहुंच मूल्य और घरेलू बाजार में घरेलू विक्री कीमत के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग के लिए निवल विक्री प्राप्ति को निर्धारित करने में, करों, छूटों, बट्टों और घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए कमीशन को समायोजित किया गया है। कम कीमत पर विक्री क्षति के आकलन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, इसलिए प्राधिकारी ने क्षतिरहित कीमत ज्ञात की है और कम कीमत पर विक्री की मात्रा ज्ञात करने के लिए उसकी तुलना पहुंच मूल्य के साथ की है। घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत पाठनरोधी नियमावली के अनुबंध III के अनुसार मूल्यांकित की गई है। यह स्थिति इस प्रकार है:-

#### **कीमत कटौती और कम कीमत पर विक्री**

90. प्राधिकारी ने शुल्क मुक्त आयातों के अंतर्गत पहुंच मूल्य का मूल्यांकन करने के बाद पाठनरोधी शुल्क के बिना कीमत कटौती और कम कीमत पर विक्री का निम्नानुसार विश्लेषण किया है:-

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई
निवल विक्री प्राप्ति (डीआई)	रु/एमटी	***	***	***	***
<b>संबद्ध देश</b>					
पहुंच कीमत	रु/एमटी	85,095	79,558	81,648	83,566
कीमत कटौती	रु/एमटी	***	***	***	***
कीमत कटौती %	%	***	***	***	***
रेंज	%	0-5	0-5	0-5	0-5
<b>कोरिया गणराज्य</b>					
पहुंच कीमत	रु/एमटी	87,199	80,921	82,327	83,764
कीमत कटौती	रु/एमटी	***	***	***	***
कीमत कटौती %	%	***	***	***	***
रेंज	%	0-5	0-5	0-5	0-5

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई
<b>ताइवान</b>					
पंहुच कीमत	रु/एमटी	83,614	83,071	79,855	88,242
कीमत कटौती	रु/एमटी	***	***	***	***
कीमत कटौती %	%	***	***	***	***
रेंज	%	0-5	-(0-5)	5-10	-(0-5)
<b>चीन जन. गण.</b>					
पंहुच कीमत	रु/एमटी	85,909	85,050	70,963	88,503
कीमत कटौती	रु/एमटी	***	***	***	***
कीमत कटौती %	%	***	***	***	***
रेंज	%	0-5	-(0-5)	15-20	-(0-5)
<b>मलेशिया</b>					
पंहुच कीमत	रु/एमटी	83,017	81,230	81,619	82,726
कीमत कटौती	रु/एमटी	***	***	***	***
कीमत कटौती %	%	***	***	***	***
रेंज	%	5-10	0-5	0-5	5-10
<b>शाईलैंड</b>					
पंहुच कीमत	रु/एमटी	89,672	86,744	88,177	86,091
कीमत कटौती	रु/एमटी	***	***	***	***
कीमत कटौती %	%	***	***	***	***
रेंज	%	-(0-5)	-(0-5)	-(0-5)	0-5
<b>यूरोप</b>					
पंहुच कीमत	रु/एमटी	81,899	71,748	77,577	82,193
कीमत कटौती	रु/एमटी	***	***	***	***
कीमत कटौती %	%	***	***	***	***
रेंज	%	5-10	10-15	5-10	5-10

91. उक्त आकड़ों से पता चलता है कि लागू पाटनरोधी शुल्क पर विचार किए बिना कीमत कटौती काफी अधिक है। विश्लेषण के बाद यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से समग्र रूप से संबद्ध वस्तु कीमतों से क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।

### कम कीमत पर बिक्री

92. कम कीमत पर बिक्री क्षति के आकलन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, इसलिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की क्षतिरहित कीमत ज्ञात की है और कम कीमत पर बिक्री की मात्रा जानने के लिए उसकी तुलना आयातित माल के पंहुच मूल्य के साथ की है। पाठित आयातों के कम कीमत पर बिक्री संबंधी प्रभावों की जाँच करने के लिए आयातों के पंहुच मूल्य की तुलना लागू पाटनरोधी शुल्क पर विचार किए बिना निर्धारित क्षतिरहित कीमत के साथ की गई है।

देश	क्षतिरहित कीमत	पंहुच मूल्य	कम कीमत पर बिक्री	कम कीमत पर बिक्री	कम कीमत पर बिक्री
	अम.डा. प्रति एमटी	अम.डा. प्रति एमटी	अम.डा. प्रति एमटी	%	रेंज %
कोरिया गणराज्य (समग्र)	***	1,358.68	***	***	20-25
ताइवान	***	1,431.32	***	***	10-15
चीन जन. गण.	***	1,435.56	***	***	10-15
मलेशिया	***	1,341.85	***	***	20-25
थाइलैंड	***	1,396.42	***	***	15-20
यूरोप	***	1,333.20	***	***	20-25

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान कम कीमत पर बिक्री सभी संबद्ध देशों के लिए सकारात्मक थी।

### पाठित आयातों के कीमत ह्रास और न्यूनीकरण प्रभाव

94. इस बात की जाँच करने के लिए कि क्या संबद्ध देश से पाठित आयातों की मौजूदगी के कारण घरेलू कीमतों में ह्रास या न्यूनीकरण हुआ है, घरेलू उद्योग की भारित औसत बिक्री प्राप्ति के रूझानों की तुलना बिक्री लागत और पंहुच मूल्यों के साथ की गई है।

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई
बिक्री लागत (डीआई)	रु./एमटी	***	***	***	***
रूझान	सूचीबद्ध	100	107	110	110
बिक्री कीमत (डीआई)	रु./एमटी	***	***	***	***
रूझान	सूचीबद्ध	100	95	96	100
संबद्ध देशों की पंहुच कीमत (आयात)	रु./एमटी	85,095	79,558	81,648	83,566
रूझान	सूचीबद्ध	100	93	96	98

**95.** उक्त सूचना के अनुसार प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान विक्री लागतों में भारी वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग कम कीमत पर आयातों के कारण अपनी विक्री कीमत में वृद्धि नहीं कर सका था। वास्तव में घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करने को बाध्य होना पड़ा था। इससे कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण प्रभाव प्रदर्शित होता है जिसके द्वारा घरेलू उद्योग विक्री कीमत में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि नहीं कर सका है, वास्तव में उसे लागत में वृद्धि के बावजूद अपनी विक्री कीमतें कम करनी पड़ी है।

#### घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंडों की जांच

**96.** पाटनरोधी नियमावली का अनुबंध-II यह अपेक्षा करता है कि क्षति के निधरण में इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्यपरक जांच अंतर्गत होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में पुनः यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत आर्थिक कारकों एवं संकेतकों की उद्देश्यपरक एवं पक्षपात रहित मूल्यांकन शामिल होगा जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, इनमें शामिल है विक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ या क्षमता उपयोग में संभावित एवं वास्तविक गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभाव मालसूची, रोजगार वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता शामिल है। घरेलू उद्योग से संबंधित क्षति संबंधी विभिन्न मापदंडों की निम्नानुसार चर्चा की गई है।

#### क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और विक्री

**97.** उत्पादन, विक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन निम्नानुसार है:-

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
रुक्षान	सूचीबद्ध	100	100	134	146
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
रुक्षान	सूचीबद्ध	100	100	130	137
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
रुक्षान	सूचीबद्ध	100	100	97	94
घरेलू विक्रियां	एमटी	44,382	44,548	57,257	61,091
रुक्षान	सूचीबद्ध	100	100	129	138

**98.** उक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2013-14 और जांच अवधि में क्षमताओं में वृद्धि की है। देश में विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है।

**99.** घरेलू उद्योग के उत्पादन और विक्री में इस पूरी अवधि में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने बताया है कि क्षमताओं में वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग ने अधिक उत्पादन का लक्ष्य रखा। यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग उस मात्रा से अधिक है जिसका घरेलू उद्योग उत्पादन और विक्री कर सकता है। अतः, घरेलू

उद्योग को आयातों की तुलना में उसकी कीमत के प्रतिस्पर्धी रहने तक उसकी वस्तु को बेचने में कोई कठिनाई नहीं है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि चूंकि घरेलू उद्योग ने आयात कीमतों के बराबर अपनी कीमतों रखी हैं इसलिए विक्री मात्रा और परिणामस्वरूप उत्पादन और क्षमता उपयोग में इस अवधि के दौरान सुधार हुआ है।

### मालसूची

100. नीचे दी गई सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति में वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई
औसत स्टाक	एमटी	***	***	***	***
रुक्षान	सूचीबद्ध	100	58	276	1,622

### लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह

101. लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्यनिष्पादन क्षति अवधि के दौरान निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई
विक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
रुक्षान	सूचीबद्ध	100	107	110	110
विक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
रुक्षान	सूचीबद्ध	100	95	96	100
लाभप्रदता	रु./एमटी	***	***	***	***
रुक्षान	सूचीबद्ध	100	(775)	(866)	(656)
घरेलू विक्री पर पीबीटी	लाख रुपये	***	***	***	***
रुक्षान	सूचीबद्ध	100	(777)	(1,117)	(903)
घरेलू विक्री पर पीबीआईटी	लाख रुपये	***	***	***	***
रुक्षान	सूचीबद्ध	100	0	(30)	(19)
नकद लाभ	लाख रुपये	***	***	***	***
रुक्षान	सूचीबद्ध	100	(582)	(807)	(650)
नियोजित पूँजी पर आय	%	***	***	***	***
रुक्षान	सूचीबद्ध	100	0	(28)	(17)

102. उक्त सूचना के अनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का लाभ/हानि और लाभप्रदता में पूरी क्षति अवधि के दौरान विकृति आई है। जबकि उत्पादन लागत और विक्री कीमत दोनों में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, उत्पादन लागत में वृद्धि विक्री कीमत से अधिक रही है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में क्षति अवधि के दौरान तेजी से गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को 2012-13 से वित्तीय घाटे होने शुरू हो गए थे। इसी प्रकार, नकद लाभ और नियोजित पूँजी पर आय में भी गिरावट का यही रूझान रहा है।

### **रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता**

103. नीचे दी गई सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के रोजगार की स्थिति और प्रदत्त मजदूरी में आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। उत्पादन प्रतिदिन और प्रतिकर्मचारी उत्पादन की दृष्टि से उत्पादकता में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई
कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***
रुझान	सूचीबद्ध	100	92	102	104
मजदूरी	लाख रूपये	***	***	***	***
रुझान	सूचीबद्ध	100	115	115	110
उत्पादन प्रतिदिन	एमटी/दिन	***	***	***	***
रुझान	सूचीबद्ध	100	100	130	137
प्रतिकर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचीबद्ध	100	109	127	132

### **पाठन की मात्रा**

104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस को छोड़कर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों का पाठन मार्जिन न केवल सकारात्मक है बल्कि काफी अधिक है।

### **वृद्धि**

105. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विक्री, उत्पादन और बाजार हिस्से की दृष्टि से घरेलू उद्योग की वृद्धि सकारात्मक थी। जबकि लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ के संबंध में वृद्धि नकारात्मक रही थी।

वृद्धि	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई
उत्पादन	%	-	0.37	29.58	5.30
घरेलू बिक्री मात्रा	%	-	0.37	28.53	6.70
बिक्री लागत घरेलू	%	-	6.92	2.88	0.28
बिक्री कीमत घरेलू	%	-	(5.35)	1.86	3.35
लाभ/हानि घरेलू	%	-	(874.58)	11.81	(24.27)
औसत स्टाक	%	-	(42.08)	375.65	488.73

### पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

**106.** प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में उत्पाद की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, घरेलू उद्योग ने क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश किया। तथापि, इन निवेशों के बावजूद, घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में काफी गिरावट आई है और आगे के निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

**107.** इसके अलावा, पीओआई के दौरान उक्त मात्रा और क्षति मापदंडों को निम्नानुसार सारांशीकृत और तालिकाबद्ध किया गया है:

### पीवीसी पेस्ट क्षति मापदंड

देश	कीमत कटौती	कम कीमत पर बिक्री
कोरिया गणराज्य	सकारात्मक	सकारात्मक
ताइवान	नकारात्मक	सकारात्मक
चीन जन. गण.	नकारात्मक	सकारात्मक
मलेशिया	सकारात्मक	सकारात्मक
थाइलैंड	सकारात्मक	सकारात्मक
यूरोपीय संघ	सकारात्मक	सकारात्मक
संबद्ध देश समग्र रूप से	सकारात्मक	सकारात्मक

मापदंड	आधार वर्ष से रूक्षान
उत्पादन	वृद्धि
घरेलू बिक्रियां	वृद्धि
क्षमता उपयोग	कमी
औसत स्टाक	वृद्धि
लाभ	कमी
पीबीआईटी	कमी
पीबीटी	कमी
नकद लाभ	कमी
निवेश पर आय	कमी
मांग में बाजार हिस्सा	
आयात	वृद्धि
घरेलू उद्योग	वृद्धि
कीमत ह्वास	सकारात्मक

108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्से और क्षमता में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, तथापि क्षमता उपयोग में कमी आई है। निवेश पर आय, पीबीआईटी, पीबीटी और नकद लाभ के कारण लाभप्रदता में कमी आई है। इसके अलावा, कीमत ह्वास और न्यूनीकरण से संबंधित अन्य कीमत मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यद्यपि कोरिया गणराज्य, मलेशिया, थाइलैंड, यूरोपीय संघ के लिए कीमत कटौती सकारात्मक है तथापि ताइवान, चीन जन. गण. के लिए वह नकारात्मक है, तथापि कीमत कटौती का संचयी मूल्यांकन सकारात्मक है। इसके अलावा, एनआईपी की तुलना में, कीमत कटौती को सभी देशों के लिए अलग-अलग और समग्र रूप से भी सकारात्मक पाया गया है।

### क्षति संबंधी निष्कर्ष

109. इस प्रकार यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से पाठित आयातों की मात्रा में समग्र रूप से भारी वृद्धि हुई है। आयात भारत में उत्पाद की खपत और उत्पादन के संबंध में भी काफी अधिक रहे हैं। इस प्रकार आयातों में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में वृद्धि हुई है। पाठित आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हुई है। पाठित आयातों का कीमत ह्वास और न्यूनीकरण के संबंध में काफी प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ा है। पाठित आयातों का प्रभाव ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी बढ़ गई होती। आयातों ने घरेलू उद्योग को उसकी लागत के अनुपात में उसकी कीमतों में वृद्धि करने से रोका है। घरेलू उद्योग काफी कम कीमत पर बिक्री से ग्रस्त है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठन मार्जिन काफी अधिक है। घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से पाठित आयातों ने मालसूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन को

**प्रतिकूलतः प्रभावित किया है।** घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, भारी कीमत कटौती और हास के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता इतनी कम हो गई है कि घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को पीओआई के दौरान नकद घाटा और निवेश पर नकारात्मक आय झेलनी पड़ रही है। प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

### कारणात्मक संबंध

110. प्राधिकारी ने इस बात की जाँच की है कि क्या अन्य ज्ञात कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है जो इस प्रकार हैं:-

### तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

111. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई के दौरान संबद्ध देशों से इतर देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर या तो पाठनरोधी शुल्क लागू हैं या वह न्यूनतम स्तर पर हैं।

### मांग में संकुचन और खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

112. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है। उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

### प्रौद्योगिकी में विकास

113. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्ष ने यह दर्शने वाला कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि प्रौद्योगिकी में ऐसे महत्वपूर्ण विकास हुए हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

### प्रतिस्पर्धा की स्थिति और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

114. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु मुक्त रूप से आयात योग्य है। घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है।

### घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य-निष्पादन

115. घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य-निष्पादन संगत नहीं है क्योंकि घरेलू और निर्यात बाजार की कीमत और लाभप्रदता को घरेलू उद्योग के लिए क्षति का आकलन करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा अलग-अलग किया गया है।

### अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन

116. घरेलू उद्योग के लिए दावा की गई क्षति विचाराधीन उत्पाद के संबंध में है। याचिकाकर्ता ने वह सूचना दी है जो केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित है। इस प्रकार, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में प्रदत्त वित्तीय सूचना घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेची गई समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति को दर्शाती है।

117. प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि यद्यपि ऊपर सूचीबद्ध ज्ञात अन्य कारक निर्धारित क्षति का कारण प्रतीत नहीं होते हैं तथापि निम्नलिखित मापदंडों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाठनरोधी शुल्क के समाप्त होने की दशा में पाठित आयातों के कारण हुई है।

**संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा काफी अधिक है।**

- क. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।
- ख. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाठनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद पाठित आयातों की भारी मात्रा इस स्रोत से जारी है। इससे पता चलता है कि यदि उपाय की अवधि समाप्त हो जाती है तो पाठन में तेजी आएगी और घरेलू उद्योग को आगे और क्षति होगी।

ग. लाभ, नियोजित पूँजी पर आय और नकद लाभ में गिरावट पाठित आयातों का प्रत्यक्ष परिणाम है।

घ. पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने से संबद्ध देश के निर्यातिक उनकी उच्च उत्पादन क्षमताओं और कम निर्यात कीमतों को देखते हुए बाजार पर आगे और कब्जा करने में समर्थ हो जाएंगे।

### **क्षति और कारणात्मक संबंध संबंधी निष्कर्ष**

118. इस प्रकार जॉच से पता चलता है कि रूस को छोड़कर संबद्ध देशों से पाठित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। कीमतों पर पाठित आयातों के प्रभाव के संबंध में भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में रूस को छोड़कर संबद्ध देशों से पाठित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री हुई है और ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में काफी अधिक हास और न्यूनीकरण करना था। घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से पाठित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, जॉच से पता चला है कि घरेलू उद्योग के कार्यनिपादन में लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय जेसे मापदंडों के संबंध में भारी गिरावट आई है। इस प्रकार, जॉच से पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाठित आयातों के कारण नुकसान उठाया है।

### **क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन**

119. क्षति के आकलन के संबंध में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए ग्रेड-वार क्षतिरहित कीमत का मूल्यांकन किया है और यदि घरेलू उद्योग के समान ग्रेड न हों तो वह दक्षिण कोरिया से एलजी कैमिकल और एचसीसी द्वारा निर्यातित ग्रेडों की तुलना समतुल्य ग्रेडों से ग्रेडवार क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए करने का प्रस्ताव करते हैं। तथापि, किसी भारित औसत आधार पर क्षति मार्जिन का निर्धारण करने का आकलन पर इस प्रकटन के लिए ग्रेडों की समतुल्यता की रूपरेखा में आने वाले निर्धारण संबंधी मुद्दों संबंधी उत्तर के आधार पर उचित ढंग से विचार किया जा सकता है।

120. प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की क्षतिरहित कीमत की तुलना पीओआई के दौरान क्षति मार्जिन निर्धारित करने के लिए संबद्ध देश से निर्यात के पंहुच मूल्य के साथ की गई है। दक्षिण कोरिया के सहयोगी निर्यातिकों द्वारा निर्यातित ग्रेडों और घरेलू उद्योग की समतुल्यता ग्रेड-वार क्षति मार्जिन के निर्धारण संभव करने के लिए निम्नानुसार है:

कोरिया (उत्पादक/निर्यातिक)	घरेलू उद्योग के ग्रेड
<b>एलजी कैमिकल</b>	
एलपी 170	121
एलपी 170 जी	121
पीबी 1302	120 और 124
पीबी 1752	121
पीई 1311	120
पीबी 1202	120 और 124
पीए 1302	सह-पालिमर, जो पीयूसी के दायरे से बाहर है, होने के कारण विचार नहीं किया गया
<b>एचसीसी</b>	
केएल 31	124
ईएम 3090	120
केएच 31	121

121. जॉन्च अवधि के दौरान संबद्ध देश के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन निम्नानुसार है:

देश	उत्पादक	निर्यातक	क्षति मार्जिन अम.डा./एमटी	% रूप में क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन % रेंज
कोरिया गणराज्य	एलजी कैम	एलजी कैम	***	***	15-20
	हानवा कैमिकल कार्पोरेशन	हानवा कैमिकल कार्पोरेशन	***	***	15-20
	अन्य	अन्य	***	***	35-40
ताइवान	सभी उत्पादक	सभी निर्यातक	***	***	10-15
चीन जन. गण.	सभी उत्पादक	सभी निर्यातक	***	***	10-15
मलेशिया	सभी उत्पादक	सभी निर्यातक	***	***	20-25
थाइलैंड	सभी उत्पादक	सभी निर्यातक	***	***	15-20
यूरोपीय संघ	सभी उत्पादक	सभी निर्यातक	***	***	20-25

122. पूर्वोक्त सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि जॉन्च अवधि के दौरान संबद्ध देशों के संबंध में क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है। तथापि, रूस के संबंध में, उपलब्ध तथ्यों के अनुसार, प्राधिकारी रूस से संभावित आयातों से पाटन और संभावित क्षति का कोई खतरा नोट नहीं करते हैं और इसलिए रूस से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करते हैं।

#### पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

123. वर्तमान जॉन्च संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायिक समीक्षा है। नियमों के अंतर्गत, प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को लागू रखना जरूरी है। इसमें इस बात की जॉन्च करना भी अपेक्षित है कि क्या लागू शुल्क क्षतिकारी पाटन को समाप्त करने के लक्षित प्रयोजन को सिद्ध कर रहा है।

124. प्राधिकारी नोट करते हैं वर्तमान जॉन्च में, रूस को छोड़कर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की निरंतर पाटन हो रहा है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी है, जो वस्तुतः संबद्ध देशों से पाटन और क्षति की संभावना को दर्शाता है। उक्त स्थिति को देखते हुए और जहां तक संबद्ध वस्तु की मांग और कीमत का संबंध है भारतीय बाजार में प्रचलित अनुकूल बाजार संबंधी दशाओं के कारण, प्राधिकारी के पास यह मानने का आधार है कि पाटनरोधी शुल्क को हटाने/समाप्त करने की स्थिति में संबद्ध देशों से पाटन में तेजी आ सकती है। निम्नलिखित विश्लेषण से पाटनरोधी शुल्क को हटाये जाने से पाटन और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के जारी रहने/और तेज होने की संभावना के बारे में दर्शाता है:

### (i) वर्तमान और पूर्व पाटन मार्जिन का स्तर

125. पूर्ववर्ती और वर्तमान जाँच में संबद्ध देशों के संबंध में पाटन मार्जिन का स्तर काफी अधिक है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री के स्तर को देखते हुए, पाटित आयातों की मात्रा में पाटनरोधी शुल्क हटाये जाने की स्थिति में आगे और वृद्धि होने की आशंका है। मूल जाँच के अंतिम जाँच परिणाम में पाटन मार्जिन सहयोगी निर्यातकों से इतर संबद्ध देशों के लिए लगभग 20-50 प्रतिशत की रेंज में निर्धारित किया गया था और मौजूदा निर्धारण अन्य सहयोगी निर्यातकों से इतर संबद्ध देशों के लिए वर्तमान जाँच में लगभग 5-30 प्रतिशत की रेंज में है।

### (ii) उपायों के अभाव में कीमत कटौती, हास, न्यूनीकरण

126. वह कीमत जिस पर संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयात की जा रही है उस कीमत से काफी कम है जिस पर वस्तुओं को घरेलू बाजार में बेचा जाता है। अतः पाटनरोधी शुल्क को हटाये जाने/उनकी समाप्ति पर इस बात की आशंका है कि इन देशों से निर्यातक उनके पास मौजूद काफी अधिक क्षमता को देखते हुए भारतीय बाजार में अपनी बिक्री करेंगे।

### (iii) संबद्ध देश में उच्च उत्पादन क्षमता

127. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त साक्ष्य संबद्ध देशों में निर्यातकों/उत्पादकों के पास अत्यधिक क्षमता की मौजूदगी को दर्शाते हैं।

### (iv) तीसरे देशों को निर्यातक के संबंध में पाटन मार्जिन

128. घरेलू उद्योग द्वारा रिकार्ड में प्रस्तुत साक्ष्य से पता चलता है कि संबद्ध देशों से उत्पादक/निर्यातक पाटित कीमतों पर तीसरे देशों को संबद्ध वस्तु की भारी मात्रा का निर्यात कर रहे हैं। प्राधिकारी ने जांच अवधि के बाद और तीसरे देशों के कीमत व्यवहार के संबंध में भी इसकी जांच की है।

#### प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां

#### घरेलू उद्योग द्वारा टिप्पणियां

129. घरेलू उद्योग ने प्रकटन के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं:

- हनवा केमिकल कारपोरेशन की प्रश्नावली का उत्तर अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।
- हनवा केमिकल कारपोरेशन इस कारण से अलग-अलग पाटन मार्जिन के लिए हकदार नहीं है कि वर्तमान मामले में निर्यातक हनवा केमिकल कारपोरेशन नहीं हैं। इस मामले में निर्यातक हनवा कारपोरेशन है। इसके अलावा, उत्तर में यह उल्लेख किया गया है कि हनवा केमिकल कारपोरेशन द्वारा उत्पादित सामानों के मामले में वाणिज्यिक बीजक हनवा कारपोरेशन द्वारा जारी किए गए थे। चूंकि निर्यात के लिए वाणिज्यिक बीजक हनवा कारपोरेशन द्वारा जारी किए गए थे, इसलिए हनवा कारपोरेशन संबंधित उत्पाद का निर्यातक है। इसके अलावा, यदि हनवा कारपोरेशन भारत में किए गए सभी निर्यात के लिए संबंधित निर्यातक हैं तब अलग-अलग पाटन मार्जिन हनवा कारपोरेशन के प्रश्नावली के उत्तर के बिना हनवा केमिकल कारपोरेशन को सोंपा नहीं जा सकता है। चूंकि हनवा कारपोरेशन द्वारा प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया गया है, अतः हनवा केमिकल कारपोरेशन अलग-अलग पाटन मार्जिन के लिए हकदार नहीं है। याचिकार्ता तदनुसार, अनुरोध करता है।
- यह भी उल्लेख किया जाता है कि हनवा केमिकल कारपोरेशन ने यह दावा किया है कि उसने हनवा कारपोरेशन को कमीशन का भुगतान किया है। यदि हनवा कारपोरेशन संबंधित उत्पाद का निर्यातक है जिसने भारतीय ग्राहकों को वाणिज्यिक बीजक जारी किया है, हनवा केमिकल कारपोरेशन और हनवा कारपोरेशन के बीच बिक्री और खरीद का लेन-देन होना है। ऐसे मामलों में कोई कमीशन नहीं हो सकता है। हनवा कारपोरेशन को कमीशन का भुगतान तभी किया जा सकता था जब भारत को निर्यात के लिए वाणिज्यिक बीजक हनवा केमिकल कारपोरेशन द्वारा जारी किया गया था और इस प्रकार की बिक्री में हनवा कारपोरेशन द्वारा सहायता दी गई थी। हालांकि, वर्तमान मामले में हनवा कारपोरेशन ने भारतीय आयतकों को वाणिज्यिक बीजक जारी किया है और इस कारण से हनवा कारपोरेशन हनवा केमिकल कारपोरेशन से इन वस्तुओं की खरीद अवश्य की होगी और भारतीय आयतकों को इसे बेचा होगा।

- ताइवान, चीन जन गण, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया जन गण, थाइलैंड और यूएसए से पीवीसी स्स्पेंशन ग्रेड में एसएसआर जांच के अंतिम जांच परिणाम में, प्राधिकारी ने इस बात की जांच की कि एचडब्ल्यूसी एचसीसी से संबद्ध वस्तुओं की खरीद किए बिना भारतीय नियर्तिकों को बीजक दे रहा था। हालांकि, यह नोट करना संगत है कि प्राधिकारी ने इस अन्वेषण में सत्यापन के दौरान यह पाया है कि कोरिया में सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने उस मामले में नियर्तिक के रूप में एचडब्ल्यूसी और उत्पादक के रूप में एचसीसी नामकरण किया। प्राधिकारी की यह टिप्पणी थी कि:

"एचसीसी से संबद्ध वस्तुओं की खरीद किए बिना भारतीय नियर्तिकों को बीजक देने से संबंधित एचडब्ल्यूसी के मुद्दे पर और इसलिए कोई अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण एचडब्ल्यूसी के माध्यम से एचसीसी द्वारा भारत के नियर्ति के लिए किया जाना चाहिए, यह सूचित किया गया है कि एचडब्ल्यूसी के माध्यम से भारत में एचसीसी द्वारा किया गया नियर्ति का लेन-देन कमीशन के लिए मूलवासी की ओर से कार्यरत एक एजेंट की प्रकृति में है। हालांकि, एचडब्ल्यूसी कमीशन एजेंट के रूप में कोरिया सरकार के पास पंजीकृत नहीं है। मौके पर सत्यापन के दौरान सत्यापन दल को यह दिखाया गया था कि एचडब्ल्यूसी द्वारा भारत में नियर्ति की गई संबद्ध वस्तुओं के संबंध में, एचडब्ल्यूसी को बिक्री संबंधी दस्तावेज का रख-रखाव करने तथा समुद्री बीमा और बैंक प्रभारों को शामिल करने के लिए एचसीसी से कमीशन मिला। कोरिया के सीमा शुल्क अधिकारियों ने एचडब्ल्यूसी के नाम का उल्लेख नियर्तिक के रूप में और एचसीसी के नाम उत्पादक के रूप में दिया है। जब घरेलू उद्योग ने इस मुद्दे को उठाया कि एचडब्ल्यूसी तब तक इन वस्तुओं का नियर्ति नहीं कर सकता था जब तक यह एचसीसी से इन वस्तुओं की खरीद नहीं की होती, एचसीसी ने यह उल्लेख करते हुए अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों से एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करवाया कि एचसीसी और एचडब्ल्यूसी के बीच लेन-देन को बिक्री और खरीद के रूप में नहीं माना जा सकता है और उन्हें एचडब्ल्यूसी द्वारा एचसीसी को दी गई कीमत के लिए सेवाओं के रूप में माना जाए। प्राधिकारी ने खरीद और बिक्री के रूप में एचसीसी और एचडब्ल्यूसी के बीच लेन-देन को मानते हुए एचसीसी के निवल एक्स-फैक्ट्री में नियर्ति कीमत का आकलन किया है। यदि इसे बिक्री और खरीद लेन-देन के रूप में माना जाए तब कथित तौर पर पाटन मार्जिन निवल नियर्ति कीमत का (-) \*\*\*% होता है।"

- इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि प्राधिकारी ने खरीद और बिक्री के रूप में एचसीसी और एचडब्ल्यूसी के बीच लेन-देन को मानते हुए एचसीसी के निवल एक्स-फैक्ट्री में नियर्ति कीमत का आकलन किया है। दूसरे शब्दों में प्राधिकारी ने एचडब्ल्यूसी से प्रश्नावली के उत्तर के बिना एचसीसी से पाटन मार्जिन का निर्धारण किया। वर्तमान मामले में भी स्थिति एक जैसी बनी हुई है।
- इस प्रकार से हनवा केमिकल कारपोरेशन इस कारण से अलग-अलग पाटन मार्जिन के लिए हकदार नहीं है कि वर्तमान मामले में नियर्तिक हनवा केमिकल कारपोरेशन नहीं बल्कि एचडब्ल्यूसी है जिसके द्वारा वाणिज्यिक बीजक जारी किया गया है। अतः अलग-अलग पाटन मार्जिन एचडब्ल्यूसी की प्रश्नावली के उत्तर के बिना एचसीसी को नहीं दी जा सकती।
- कानूनी अनुरोध हनवा केमिकल कारपोरेशन (एचसीसी) और हनवा कारपोरेशन (एचडब्ल्यूसी), दोनों द्वारा दायर किए गए थे। हालांकि, प्रश्नावली का उत्तर केवल हनवा केमिकल कारपोरेशन द्वारा दायर किया गया था। हितबद्ध पक्षकार ने यह तर्क दिया कि यद्यपि हनवा केमिकल कारपोरेशन भारत में नियर्ति में शामिल है, अतः यह केवल एचसीसी के लिए बीजक का रख-रखाव करने में शामिल है और इसे रख-रखाव सेवा के लिए कमीशन प्राप्त होता है। एचडब्ल्यूसी का भारत में नियर्ति बिक्री के लिए एक व्यापारिक कंपनी के रूप में कोई भूमिका नहीं है। घरेलू उद्योग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि यदि परस्पर विरोधी हितबद्ध पक्षकार हनवा कारपोरेशन को एक व्यापारी के रूप में दावा नहीं करता है और केवल बीजक रखने वाली एजेंसी के रूप में दावा करता है तब इसे किस प्रकार से लिखित अनुरोध दायर करने के लिए एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से भारत में पाटनरोधी शुल्क के अन्वेषण पर हनवा कारपोरेशन के हित को दर्शाता है जो कमीशन प्राप्त करने वाली किसी एजेंसी को नहीं मिल सकता।
- एचडब्ल्यूसी ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है बल्कि लिखित अनुरोध दायर किया है। यह सूचना प्रदान करने के लिए उस पक्षकार की अनिच्छा को स्पष्ट रूप से दर्शाया और इस कारण से इसे गैर-सहयोगी के रूप में माना जाना चाहिए।
- वर्तमान मामले में एलजी केम, कोरिया और एचसीसी, कोरिया से उत्तर प्राप्त हुए थे। हालांकि, उन्होंने अन्य संबद्ध देशों में संबंधित कंपनियों के संबंध में सूचना प्रस्तुत नहीं की है। एचसीसी चीन में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक

कंपनी, हनवा केमिकल (निंगबो) कारपोरेशन लि. है जो संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करती है। उसी प्रकार से, एलजी केम चीन में भी एक सहायक कंपनी, अर्थात् तियानजिन एलजी दागू केमिकल्स कारपोरेशन लि. है जो भी संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करती है। इन उत्पादनों/निर्यातिकों ने वर्तमान अन्वेषण में प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। सुनवाई के दौरान यह तर्क दिया गया था कि संबंधित पक्षकारों ने निर्यात नहीं किया है और इस कारण से प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। याचिकाकर्ता यह अनुरोध करता है कि चूंकि, वर्तमन जांच एक अंतिम निर्णायिक जांच है, अतः प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह निर्धारण करे कि क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति होने की संभावना होगी। अतः प्राधिकारी के लिए किसी निर्यातिक द्वारा संभावित पाटन का निर्धारण करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। यद्यपि, निर्यातिक ने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, इसका स्पष्ट आशय यह हो सकता है कि ऐसा तागू पाटनरोधी शुल्क के कारण हुआ है। पाटनरोधी शुल्क के समाप्त किए जाने की स्थिति में इस बात की पूरी संभावना है कि निर्यातिक भारत में अपना निर्यात फिर शुरू कर देंगे।

### **एलजी केम और हनवा केमिकल्स द्वारा किसी प्रकार का पाटन नहीं करने का बार-बार दावा किया जाना**

- एलजी केम और हनवा केमिकल्स ने विभिन्न उत्पादों के लिए भारत में नामित प्राधिकारी द्वारा अन्वेषण करने की बात बार-बार की है और यह पाया गया है कि उनका निर्यात में पाटन मार्जिन न्यूनतम है। विगत जांच, जहां निर्दिष्टप्राधिकारी ने इन निर्यातिकों की जांच की है और शून्य अथवा मामूली पाटन पाया है। उनकी सूची नीचे दी गई है (वास्तव में सभी मामलों में, निम्न पाटन मार्जिन के एक अपवाद को छोड़कर, न्यूनतम पाटन मार्जिन):
  1. हनवा - 9 मामले (वर्तमान मामले सहित)
    - क. कास्टिक सोडा - 3 जांचे – सभी में किसी प्रकार का पाटन नहीं देखा गया
    - ख. पीवीसी सस्पेंशन बेसिन - 2 मामले – कोई पाटन नहीं
    - ग. सोडियम सायनाइड – मूल मामले में कोई पाटन नहीं, अंतिम समीक्षा में 3.71 प्रतिशत
    - घ. पीवीसी पेस्ट रेसिन – कोई पाटन नहीं
  2. एलजी केम - 4 मामले (वर्तमान मामले सहित)
    - क. पीवीसी सस्पेंशन रेसिन – मूल मामला – कोई पाटन नहीं
    - ख. पीवीसी पेस्ट रेसिन – कोई पाटन नहीं
    - ग. फिनाइल समीक्षा मामला – कोई पाटन नहीं
  3. फॉर्मोसा -4 मामले (वर्तमान मामले सहित)
    - क. पीवीसी सस्पेंशन रेसिन – मूल मामला – कोई पाटन नहीं
    - ख. पीवीसी पेस्ट रेसिन – कोई पाटन नहीं
    - ग. कास्टिक सोडा अंतिम समीक्षा – कोई पाटन नहीं
- उपर्युक्त सूचीबद्ध उत्पादन उत्पाद ऐसे हैं कि कोई भी उत्पादक भारतीय बाजार में अन्य आपूर्तिकर्ताओं से बहुत अधिक कीमत प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार से, जब निर्दिष्ट प्राधिकारी को इन उत्पादों में अन्य उत्पादकों द्वारा किए गए निर्यात के संबंध में बहुत अधिक पाटन मार्जिन मिला, तब नामित प्राधिकारी ने यह पाया कि इन कंपनियों के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम है। यह इस पर विचार करते हुए और भी आश्वर्यजनक है कि चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसी अन्य जांचों प्राधिकारियों ने उनके निर्यात के संबंध में धनात्मक पाटन मार्जिन पाया है।
- इन कंपनियों द्वारा समग्र उत्पादों का कोई पाटन बार-बार नहीं होने के मामले तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किया गया निर्धारण कि इन कंपनियों में पाटन मार्जिन शून्य के करीब है। यह दर्शाता है कि इन कंपनियों की कीमत निर्धारण नीति बाजार का ध्यान रखे बिना एक कीमत पर इस उत्पाद को बेचना है। इसके अलावा, यह बिक्री कीमत के लिए नहीं है, यह समायोजन करने के बाद निर्यातिक को एक्स-फैक्ट्री राजस्व प्राप्ति के लिए है। जैसा कि प्रश्नावली

के उत्तर में दावा किया गया है। यह अत्यधिक असंभव स्थिति है और यह स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि इन कंपनियों द्वारा दायर की गई प्रश्नावली के उत्तर में बहुत अधिक घालमेल किया गया है।

- लागतों का कारक यद्यपि वह निर्यातिक द्वारा रखे गए अभिलेखों पर निर्भर हो सकता है, फिर भी उसका यह आशय नहीं होता है कि नामित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हुए बिना कि वह विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और विक्री से जुड़ी लागत को उचित रूप में दर्शाता है, निर्यातिक के उत्पादन की लागत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। पूर्व की दो स्थितियां निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस कंपनी द्वारा रखे गए अभिलेखों के आधार पर उत्पादन की इस प्रकार की लागत को मानने के पूर्व संतुष्ट किया जाना चाहिए। पूर्व की ऐसी स्थितियों में एक प्रमुख स्थिति यह शामिल है कि इस प्रकार की लागत विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और विक्री से जुड़ी लागतों को उचित रूप में दर्शाए।
- इस अपेक्षा/बाध्यता के निर्वहन में, नामित प्राधिकारी ने निर्यातिक की प्रश्नावली में निम्नलिखित निर्धारण किया है:

"..... (छ) किसी भी स्थिति में कोई भी समान संबंधित आपूर्तिकर्ता अथवा गुप्त रूप से खरीदा जाता है, कृपया विचारित सामग्री की कीमत निर्धारण का आधार का उल्लेख करें। यह भी विस्तार से बताएं कि किस प्रकार से आप यह मानते हैं कि विचारित कीमत निर्धारण उचित बाजार कीमत को दर्शाता है अथवा उसका प्रतिनिधित्व करता है। एक समान अथवा तुलनीय इनपुट उत्पाद के लिए स्वतंत्र पक्षकारों से खरीद कीमत का भी उल्लेख करें। इसके अलावा, गुप्त रूप से अथवा किसी संबद्ध आपूर्तिकर्ता से खरीदे गए मद की उत्पादन की लागत का उल्लेख करें।"

- यह देखा जाएगा कि विदेखा उत्पादक से यह अपेक्षित है कि वह निम्नलिखित सूचना उस स्थिति में उपलब्ध कराएँ जब किसी सामग्री की खरीद संबंधित आपूर्तिकर्ता से किया गया हो अथवा गुप्त रूप से उत्पादित हो:

  - i. विचारित सामग्री के कीमत निर्धारण का आधार।
  - ii. इस प्रकार से निर्यातिक यह मानते हैं कि विचारित कीमत निर्धारण उचित बाजार कीमत को दर्शाता है।
  - iii. एक समान अथवा तुलनीय इनपुट उत्पाद के लिए स्वतंत्र पक्षकारों से खरीद कीमतों का उल्लेख करें।
  - iv. गुप्त रूप से अथवा किसी एक संबद्ध आपूर्तिकर्ता से खरीदी गई मद के उत्पादन की लागत का उल्लेख करें।

- इस संबंध में उत्तर देने वाले निर्यातिकों द्वारा दायर किए गए उत्तरों को नोट करना महतवपूर्ण है। उत्तर देने वालों निर्यातिकों के प्रश्नावली के कुछ उत्तरों से संगत सार नीचे दिया गया है:

  - क. हनवा केमिकल कारपोरेशन  
जैसा कि ऊपर में उल्लेख किया गया है प्रमुख इनपुट, वीसीएम गुप्त रूप से एचसीसी द्वारा उत्पादन किया जाता है। इस कारण से यह प्रश्न लागू नहीं होता है।
  - ख. एलजी केम  
जैसा कि ऊपर उत्तर (अ) में उल्लेख किया गया है, कोई भी सामग्री संबंधित पक्षकारों से नहीं खरीदी गई है। इसलिए यह प्रश्न लागू नहीं होता है।

- निर्यातिकों/उत्पादकों द्वारा दायर किए गए उत्तरों से यह देखा जाएगा कि:

  - क. उन्होंने जानबूझकर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना देने से बचने का प्रयास किया है। वास्तव में उत्तर देने वाले किसी भी निर्यातिकों ने वीसीएम के मूल्यांकन के संबंध में प्रश्न का पूर्ण रूप से उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी कृपया इस प्रकार की सूचना देने के लिए अथवा अन्य प्रकार से यह मानने लिए उत्तर देने वाले निर्यातिकों को निदेश दें कि उत्तर देने वाले निर्यातिकों ने संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है और सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना लागू होती है।
  - ख. हनवा में वीसीएम के मूल्यांकन से संबंधित सूचना देने से बचने का प्रयास किया है। दूसरी ओर एलजी ने उल्लेख किया कि वे किसी संबंधित पक्षकार से इनपुट्स नहीं खरीदते हैं। हालांकि, इस प्रकार के उत्तर को स्वीकार करना मुश्किल है क्योंकि एलजी का संबंधित पक्षकार नामतः तियानजिन एलजी बोहाई केमिकल्स कं. लि., चीन वीसीएम का निर्माता है।
  - वीसीएम व्यापार किए जाने वाली एक वस्तु है और इसलिए प्रत्येक वीसीएम और पीवीसी उत्पादक के पास या तो वीसीएम को पीवीसी में परिवर्तित करने अथवा वीसीएम के रूप में बाजार में बेचने का विकल्प होता है।

याचिकाकर्ता प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वह उस पर ध्यान दे और समय वीसीएम की बाजार कीमत पर विचार करें।

- पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.1 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क(5) का संदर्भ लेते हुए, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि अंतिम समीक्षा अन्वेषण लागू पाटनरोधी शुल्क के निम्नलिखित परिणामों की जांच करने के लिए है:
  - कि पाटन होना जारी है, यदि हां तो क्या यह पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त किए जाने पर जारी रहने की संभावना है।
  - उन मामलों में, जहां पाटन जारी नहीं था, क्या पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में पाटन फिर से होगा;
  - क्या घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी रहा और यदि हां तो क्या घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने की संभावना है।
  - उस मामले में, जहां घरेलू उद्योग को लगातार क्षति नहीं उठानी पड़ी है, क्या घरेलू उद्योग को क्षति पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में फिर से होने की संभावना है।
  - वर्तमान मामले में जांच की अवधि में रूस से आयात शून्य है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि वहां भी जहां पाटन मार्जिन शून्य है, पाटनरोधी शुल्क को रूस से पाटन की स्पष्ट संभावना को देखते हुए जारी रखने की आवश्यकता है। निम्नलिखित मानदंडों का संदर्भ यह सिद्ध करने के उद्देश्य से लिया गया था कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से पाटन और क्षति फिर से होगी:
    - इस उत्पाद से संबंधित पूर्व के सभी अन्वेषणों में निर्धारित पाटन मार्जिन
    - भारत में कोई नियर्ति नहीं
    - विदेशी उत्पादकों के पास मुक्त रूप से बेचने योग्य वर्तमान और संभावित क्षमताएं
    - तीसरे देशों में नियर्ति के संबंध में पाटन मार्जिन
  - निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विगत में इस तथ्य के बावजूद पाटनरोधी शुल्क जारी रखा है कि आयात इस आधार पर शून्य था कि पाटन होने की संभावना थी। निम्नलिखित मामलों का संदर्भ इस आधार पर लिया गया था:
    - ✓ सोडियम फॉर्मेलिहाइड सल्फो जाइलेट (एसएफएस)
    - ✓ जिंक ऑक्साइड
    - ✓ डक्टाइल आयरन पाइप
  - घरेलू उद्योग को मौजूद पाटनरोधी शुल्क के बावजूद लगातार क्षति उठानी पड़ी है जिसे निम्नलिखित से देखा जा सकता है।
    - पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा फिर से होने की संभावना है
    - पाटनरोधी शुल्क प्राधिकारी की सतत प्रथा के अनुसार पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित मात्रा के रूप में ही लगाया जा सकता है (शुल्क का निर्धारित रूप) ताकि पाटनरोधी शुल्क वर्धन न हो जाए। इस दावे के लिए निम्नलिखित निर्णय का उल्लेख किया गया था:
      - कोरिया से एनबीआर के मामले में, माननीय सेसटेट ने एक निर्यातक, मै. कुम्हो पैट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर अपील (2004 (170) ई. एल. टी. 274) के आधार पर निर्धारित शुल्क के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विधिवत सिफारिश की गई परिवर्तनीय पाटनरोधी शुल्क में संशोधन किया।
      - मैट्कोक के मामले में, सेसटेक ने 2000 (116) ई. एल. टी. 67 के अपने निर्णय के माध्यम से परिवर्तनीय से बदलकर निर्धारित पाटनरोधी शुल्क संशोधित किया।
      - विट्रीफाइड फाइलों के मामले में सेसटेक ने नामित प्राधिकारी के शुल्क की निर्धारित मात्रा लगाने के निर्णय को सही ठहराया है।
    - शुल्क अमेरिकी डॉलर के रूप में लगाया जाना चाहिए क्योंकि रूपए में बहुत अधिक अवमूल्यन हुआ है। यह चीन से मैट्कोक के मामले में अमेरिकी डॉलर के रूप में शुल्क को परिवर्तित करते समय सेसटेट के निर्णय के शामिल तर्क द्वारा भी समर्थित है।

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा टिप्पणियां

130. हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं:

- I. हनवा केमिकल कारपोरेशन, कोरिया
- डीजीएवी ने हनवा कारपोरेशन के कार्य तथा इससे संबंधित खर्चों की सूचना देने की पद्धति को 26 दिसंबर, 2007 को जारी अंतिम जांच परिणाम में स्वीकार किया। संगत निर्णय नीचे संलग्न है (अंतिम जांच परिणाम का पृष्ठ: 36-37):

#### **"ख.2) निर्यात कीमत – हनवा केमिकल कारपोरेशन**

जांच की अवधि के दौरान, मै. हनवा केमिकल कारपोरेशन (एचसीसी) ने \*\*\*\* लेन-देन के प्रति भारत में संबद्ध वस्तुओं का \*\*\*\* मी.ट. का निर्यात किया है। जांच की अवधि के दौरान एचसीसी ने पीवीसी सम्पेशन के केवल 3 ग्रेड की विक्री की है। भारत में सभी निर्यात सीआईएफ शर्त पर और देखते ही एलसी अथवा उपयोग आधार पर होता है। दो लेन-देन को छोड़कर सभी विक्री इसके संबद्ध व्यापारी अर्थात् मै. हनवा कारपोरेशन (एचडब्ल्यूसी) के माध्यम से की जाती है।

एचडब्ल्यूसी इन पक्षकारों के बीच सेवा संविदा के अंतर्गत भारत में माल भेजने पर निर्धारित कमीशन के भुगतान के प्रति एचसीसी और भारतीय ग्राहकों के बीच एक कमीशन एजेंट के रूप में कार्य करता है। यह कमीशन राशि में दस्तावेज रखने और दस्तावेज भेजने की शर्त, समुद्री बीमा खर्च और \*\*\* प्रति मी.ट. अमेरिकी डॉलर से कम उप एजेंट के कमीशन शामिल होते हैं। भारतीय ग्राहक को यूनिट कीमत एचडब्ल्यूसी की बीजक कीमत होती है। एचसीसी एचडब्ल्यूसी कमीशन को छोड़कर एचडब्ल्यूसी को बीजक भेजता है।

निर्यात लेन-देन के प्रति निर्यातक ने अंतर्देशीय दुलाई खर्चे, समुद्री भाड़ा खर्चे और बंदरगाह पर उतराई संबंधी खर्चे और एचडब्ल्यूसी को भुगतान की गई कमीशन का वहन किया है जिसका सत्यापन कंपनी के अभिलेख से किया गया था। समुद्री बीमा और उप एजेंट के कमीशन में एचडब्ल्यूसी का कमीशन शामिल है और इसलिए बीजक की कीमत से किसी प्रकार की कटौती अपेक्षित नहीं है।"

- सूचना देने की उपर्युक्त पद्धति को भी महानिदेशक पाठनरोधी शुल्क द्वारा पीवीसी पेस्ट मामले के लिए स्वीकार किया गया था (अंतिम जांच परिणाम 2 मई, 2011 को दिया गया था)।
- भारत में संबद्ध वस्तुओं के किए गए निर्यात लेन-देन में से कुछ में, हनवा केमिकल कारपोरेशन (एचसीसी) ने हनवा कारपोरेशन (एचडब्ल्यूसी) को दस्तावेज रखने संबंधी शुल्क का भुगतान किया है।
- यद्यपि हनवा कारपोरेशन भारत में निर्यात में शामिल था, इसलिए कृपया नोट करें कि हनवा कारपोरेशन हनवा केमिकल कारपोरेशन के लिए रख-रखाव करने संबंधी बीजक के लिए ही जिम्मेदार है और इसे दस्तावेज रखने से संबंधित सेवा के लिए कमीशन प्राप्त होता है। यह उल्लेखनीय है कि हनवा कारपोरेशन हनवा केमिकल कारपोरेशन से न तो विचाराधीन उत्पाद की खरीद करता है और न ही उसे ग्राहक को बेचता है। इसका मतलब यह हुआ कि हनवा कारपोरेशन की भारत में निर्यात विक्री के लिए एक व्यापारिक कंपनी के रूप में कोई भूमिका नहीं है।
- \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी.ट. दस्तावेज रखने संबंधी शुल्क में एचडब्ल्यूसी द्वारा एचसीसी को दी गई निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं:
  1. कोरिया जन गण से निर्यात से संबंधित दस्तावेज तैयार करना।
  2. समुद्री बीमा के लिए शुल्क/खर्च
  3. निर्यात प्राप्ति के प्रति अंतर्देशीय भुगतान से संबंधित बैंक शुल्क

एचडब्ल्यूसी को एचसीसी की ओर से निर्यात भुगतान भी प्राप्त होता है और यह विल्कुल उस राशि का भुगतान एचसीसी को कर देता है। यह नोट करना यहां संगत होगा कि निर्यात बीजक, पैकिंग सूची और अवतरण का बिल एचसीसी के नाम से था। इसके अलावा, भारतीय बंदरगाहों पर स्वीकार किए गए प्रविष्टियों के बिल भी एचसीसी के रूप में निर्यातिक के नाम दर्शाता है। इस कारण से एचसीसी की उत्पादक तथा निर्यातिक के रूप में स्थिति के बारे कोई संदेह नहीं हो सकता है।

- वास्तव में 74 निर्यात लेन-देन में से, केवल 16 लेन-देन एचडब्ल्यूसी के माध्यम से रख-रखाव शुल्क के भुगतान के प्रति किया गया था। इसके अलावा, भारत में निर्याति के \*\*\* मी.ट. में से, \*\*\* मी.ट. केवल एचडब्ल्यूसी के माध्यम से

बेची गई थी, जो जांच की अवधि के दौरान भारत में निर्यात किए गए कुल संबद्ध वस्तुओं का \*\*\* प्रतिशत से भी कम होता है। यह भी नोट करना संगत होगा कि एचडब्ल्यूसी के माध्यम से मई, 2014 के बाद कोई निर्यात नहीं किया गया था। एचसीसी ने भारत में जांच की अवधि के बाद के निर्यात से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई है जिसमें निर्यात का कोई लेन-देन एचडब्ल्यूसी के माध्यम से नहीं किया गया है।

- इसके अलावा, सत्यापन के समय प्राधिकारी को यह दर्शाया गया था कि एचडब्ल्यूसी ने दस्तावेज रख-रखाव शुल्क के लिए एचसीसी से \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी.ट. वसूलकर उचित से अधिक लाभ अर्जित कर रहा है। इसके अलावा, यह दर्शाया था कि यदि एचडब्ल्यूसी के माध्यम से लेन-देन पर ध्यान नहीं दिया गया होता तब इसके फलस्वरूप ऋणात्मक पाटन मार्जिन में वृद्धि हुई होती। अतः पाटनरोधी अन्वेषण के उद्देश्य से कोई गलत कारण भी हो सकता है।
- उपर्युक्त को देखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि एचसीसी के पाटन मार्जिन की गणना करने के लिए सभी 74 निर्यात लेन-देन पर विचार किया गया है।

II. लेदर क्लॉथ एंड प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन (एलसीटीएंडए), पॉलीनोवा इंडस्ट्रीज लि., मयूर यूनिकोर्ट्स, केपीएल इंटरनेशनल लि., जास प्लास्टिक्स इंडिया लि. और जास इंडस्ट्रीज लि. की ओर से टिप्पणियां:

- जैसा कि प्रतीत होता है, प्रकटन के फलस्वरूप पाटनरोधी शुल्कों, यदि वर्तमान उपायों को जारी रखा जाए, के क्षेत्र में गैर-विचाराधीन उस मदों को लगातार शामिल करना पड़ेगा। आईआईटी, दिल्ली की रिपोर्ट पर विवाद खड़ा हो गया है और प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह प्रश्नगत उत्पाद मामले की पुष्टि करने के लिए एक अन्य जांच आयोजित करे। प्राधिकारी द्वारा एक बार फिर निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया जाए:
- घरेलू उद्योग निम्नलिखित उत्पादों का विनिर्माण नहीं करता है:
  - i. उच्च के मूल्य का पीवीसी पेस्ट रेसिन
  - ii. जांच पद्धति डिन – 75201/आईएसओ-6452 द्वारा परीक्षण के माध्यम से 0.5 एमजी से कम के फॉर्मिंग लक्षण वाले विशिष्ट रूप से ऑटोमोटिव उपयोग के लिए निम्न फॉग मूल्य का पीवीसी पेस्ट रेसिन:

### **उच्च के मूल्य का पीवीसी पेस्ट रेसिन**

- पीवीस रेसिन का के मूल्य वाहनों के लिए विभिन्न सीट कवर, फर्नीचर अपहोस्टरी, फुटवियर और अन्य उत्पादों के लिए ओर्डरएम विनिर्माताओं जैसे अंतिम ग्राहक द्वारा अपेक्षित विनिर्देशनों से संबंधित पीवीसी लेदर कपड़े की यांत्रिक लक्षणों का निर्धारण करता है।
- जैसे ही पीवीसी लेदर क्लॉथ निर्माण में के मूल्य बढ़ता है, पीवीसी लेदर का कड़ापन भी बढ़ जाता है। लेदर क्लॉथ में विभिन्न प्रकार के विनिर्देशन होते हैं जैसे व्हील्स के विशिष्ट प्रकार के लिए टेवर अव्रेशन, साइकिलों का वजन और संख्या; #8 डक क्लॉथ का उपयोग करते हुए वाइजन बिक अव्रेशन, मार्टिन डेल अव्रेशन टेस्ट, लचीलापन टेस्ट जैसे बेली फ्लैक्स का 2,00,000 साइकिल, शट्रा फ्लैक्स टेस्ट 5,00,000 साइकिल।
- ब्रेकिंग शक्ति, टियर शक्ति और टूटने पर लम्बाई में कमी जैसे यांत्रिक लक्षणों में वृद्धि पर पीवीसी रेसिन के के मूल्य द्वारा वृद्धि होने का प्रभाव पड़ता है।
- पीवीसी रेसिन का उच्च के मूल्य को निम्न के मूल्य की तुलना में उच्च डिग्री के तापमान पर प्रोसेस किया जाना अपेक्षित होता है। पीवीसी रेसिन का निम्न के मूल्य पीवीसी निर्माण में उच्च के मूल्य के रेसिन के रूप में समान यांत्रिक लक्षण प्राप्त नहीं कर सकता है। इस बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है जो निम्न के मूल्य के पीवीसी को उच्च के मूल्य के पीवीसी में लेदर क्लॉथ के निर्माण में परिवर्तित कर सकता है। उदाहरण के लिए ब्रेकिंग स्ट्रैथ को निम्न के मूल्य के पीवीसी के निर्माण में प्लास्टिसाइजर को कम कर कुछ स्तर तक बढ़ाया जा सकता है परन्तु उत्पाद लम्बाई/लचीलेपन में असफल होगा।

नोट: पीवीसी रेसिन के मोलिक्युलर वजन का प्रतिनिधित्व के मूल्य करता है। ऐसे ज्ञात वृद्धिकारी कोई भी चीज नहीं है जो पीवीसी रेसिन के मोलिक्युलर वजन को 67 के मूल्य से बढ़ाकर 77 कर सके और इसलिए विभिन्न के मूल्य के इन रेसिन एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किए जा सकते हैं।

- यदि इन रेसिनों को एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है तब मैं केमप्लास्ट के लिए विदेशी निर्माताओं द्वारा विभिन्न के मूल्य के रेसिन और 65 के के सहित 124 रेसिन ग्रेड, 68 के के 120 ग्रेड और 77 के के 121 ग्रेड का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मैं, केमप्लास्ट इस बात का बेहतर उत्तर दे सकता है कि क्यों वे विभिन्न के मूल्य वाले रेसिनों के तीन विभिन्न ग्रेडों का निर्माण करते हैं जबकि उनका उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है।

#### **विशेष रूप से ऑटोमोटिव के लिए निम्न फॉग मूल्य का पीवीसी रेसिन**

- केमप्लास्ट द्वारा निर्मित रेसिन के साथ निर्मित लेदर क्लॉथ फॉग टेस्ट में कभी सफल नहीं रहा। केमप्लास्ट रेसिन के सभी ग्रेड फॉगिंग टेस्ट में असफल होते हुए गए हैं और वे उन मानकों के कहीं भी आस-पास नहीं हैं क्योंकि ग्लास प्लेट पर बहुत बड़ी तेल की बूंद बन जाती है और इसलिए यह ऑटोमोटिव उद्योग के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह उत्पाद फॉगिंग मूल्य के लिए उनके टेस्ट पद्धति ऐसा एर्ड – जे1756 के अंतर्गत सफल नहीं होते हैं।
- इसलिए एलसीपीएमए के सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि उपर्युक्त जांच पद्धति के अनुसार निम्न फॉग लक्षण वाले पीवीसी रेसिन का आयात करना होता है जिसके बिना समग्र ऑटोमोटिव उद्योग को आपूर्ति रुक जाएगी।
- यह स्पष्ट है कि एलसीपीएमए सदस्यों ने जांच की अवधि के दौरान इन रेसिनों का आयात उपर्युक्त अमेरिकी डॉलर 1800.00 प्रति मी.ट. पर किया है जबकि सामान्य उद्देश्य वाले पीवीसी रेसिन की कीमतें 1200.00 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.ट. था। यह दर्शाता है कि विशिष्ट पीवीसी रेसिन की कीमतें सामान्य उद्देश्य वाले पीवीसी रेसिन की कीमत से 50 प्रतिशत अधिक है और किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार के आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। ऑटोमोटिव उद्योग के लिए इन रेसिनों विशेषकर आयात किए गए रेसिन न तो तकनीकी रूप से और न ही वाणिज्यिक रूप से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पीवीसी ग्रेड के प्रतिस्थापनीय हैं और निम्न फॉग वाले रेसिन को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किए जाने की आवश्यकता है।
- इन रेसिन के मूल निर्माता मैं, सोल्वे और मैं, विनोलिट ने अपनी लैब में तथा स्वतंत्र एजेंसी द्वारा इन रेसिनों की जांच आईएसओ – 6452 और डीआईएन – 75201 जांच पद्धति से करवाई और जांच के परिणाम को नीचे दर्शाया गया है:

ग्राम में वजन की माप	मि.ग्रा. में परिवर्तन	
सोल्विन 373 एनडी	0.0002 ग्रा.	0.2 मि.ग्रा. (क्षेत्र में)
केमप्लास्ट रेसिन-121	0.0457 ग्रा.	45.7 मि.ग्रा. (क्षेत्र से बाहर)
केमप्लास्ट रेसिन-124	0.0334 ग्रा.	33.4 मि.ग्रा. (क्षेत्र से बाहर)

- पूर्व के अन्वेषण के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आईआईटी, नई दिल्ली को जांच के लिए पीवीसी रेसिन का विशिष्ट ग्रेड का नमूना भेजा था लेकिन आईआईटी, नई दिल्ली द्वारा जारी रिपोर्ट पूर्ण नहीं थी और न ही सही थी जिसका विरोध एलसीपीएमए द्वारा दिनांक 14.02.2013 के पत्र के माध्यम से तथा यूरोपीय निर्माताओं द्वारा किया गया था।
- यह मुद्दा अभी भी सुलझा नहीं है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसकी समीक्षा करें (आईआईटी, नई दिल्ली के साथ किए गए पत्राचार की प्रति हमारे अनुरोध और प्राधिकारी के साथ हुई बैठक में पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है)। प्राधिकारी इन अन्वेषणों को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को गंभीर अन्याय से बचाने के लिए इस प्रकार की अपेक्षित जांच करवाई जा सके।
- घरेलू उद्योग ने प्रकटन विन्दु सी-2 (एच) के अनुसार अनुरोध किया है कि उनके द्वारा निर्मित ग्रेड ऑटोमोटिव उद्योग के लिए उपयुक्त निम्न फॉगिंग रेसिन हैं जो बिल्कुल गलत और असत्य हैं। यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया मैं, केमप्लास्ट से शपथ-पत्र और जांच रिपोर्ट की पुनः पुष्टि करवाएं कि उनके द्वारा निर्मित रेसिन ऑटोमोटिव उद्योग द्वारा यथा अपेक्षित डीआईएन – 75201/आईएसओ – 6452 जांच पद्धति द्वारा परीक्षण कर 0.5 मि.ग्रा. से कम के फॉगिंग लक्षणों (ग्रेवी मैट्रिक) के निम्न फॉग लक्षणों को पूरा करता है और इस बात की पुष्टि करता है कि ये ग्रेड आयातित ग्रेडों 373 एन डी और 375 एम डी के समतुल्य हैं और इन रेसिनों को मैं, केमप्लास्ट के कथन की सत्यता का सत्यापन करने के लिए जांच विधि आईएसओ – 6452 और डीआईएन – 75201 (एसजीएस इंडिया जैसे) के

साथ फॉग लक्षणों की जांच करने के लिए जांच उपकरण से लैस किसी जांच लैब में पुनः जांच के लिए भेजा जा सकता है।

- यदि इस पहलू का सही-सही अन्वेषण नहीं किया जाता है और मै. केमप्लास्ट द्वारा बनाई जा रही पीवीसी रेसिन की विशेष ग्रेडों को अलग करने का निर्णय लिया जाता है और इनका आयात ऑटोमोटिव उद्योग द्वारा यथा अपेक्षित पीवीसी लेदर क्लॉथ के विनिर्माण के लिए यूरोप से आवश्यक रूप से किया जाना अपेक्षित है तब पीवीसी लेदर क्लॉथ के घरेलू विनिर्माताओं को बहुत अधिक कठिनाई होगी। यह प्राकृतिक न्याय के कानूनों के भी विरुद्ध होगा।
- इन दोनों पहलुओं का सत्यापन एलसीपीएमए के एक सदस्य के संयंत्र में प्राधिकार से एक दल के दौरे के दौरान किया गया था। हालांकि, यदि किसी कारण से ऑटोमोटिव के लिए निम्न फॉग रेसिन को विचाराधीन उत्पाद से अलग नहीं किया जाता है तब हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे घरेलू उद्योग को क्षतिरहित कीमत तथा संदर्भ कीमत से अधिक कीमत के निम्न फॉग वाले पीवीसी रेसिन के समतुल्य कीमत को पाटनरोधी शुल्क से अलग करने की कार्रवाई की जाएगी।

### यूरोपीय निर्माताओं के भाग न लेने के कारण कठिनाई

- पीवीसी लेदर क्लॉथ के घरेलू निर्माताओं को बहुत अधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें जांच में पीवीसी रेसिन के यूरोपीय यूनियन के निर्माताओं के भाग न लेने के कारण घाटा हो रहा है क्योंकि वे भारत को अपने प्रमुख बाजार के रूप में नहीं समझते हैं।
- चूंकि, ये आंकड़े यूरोपीय यूनियन निर्माताओं द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, अतः तीसरे पक्ष के आंकड़ों द्वारा पाटन मार्जिन की गणना की जाती है जो पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं है और गैर-स्तरीय ग्रेडों सहित विभिन्न ग्रेडों की विभिन्न कीमतों का एक औसत लिया जाता है जो अपेक्षाकृत बहुत कम औसत कीमत होती है और इसके फलस्वरूप वास्तविक उपभोक्ताओं को अनुचित कठिनाई होती है।
- यह अनुरोध किया जाता है कि तीसरे पक्ष के आंकड़ों के बजाए प्रत्येक ग्रेड के पाटन मार्जिन की गणना के लिए सदस्य आयातकों द्वारा यथा प्रदत्त पृथक रूप से पीवीसी रेसिन के विभिन्न ग्रेडों के वास्तविक आयात आंकड़ों पर विचार किया जाता है।
- हाल में सोल्वे ने संबद्ध वस्तुओं की कीमत प्रस्तुत की है जिसका उपयोग प्राधिकारी द्वारा ग्रेड-वार कीमतों हेतु किया जाए। निर्यातिक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और हमारे निर्यात के आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से आयात किए गए इस प्रकार की उच्च कीमत वाले उत्पादों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं हो सकते हैं।

### अस्थिर कद्दा तेल की कीमतों तथा भारतीय रूपए के विनिमय दर के कारण पीवीसी रेसिन की कीमतों में उत्तर-चढ़ाव

- पीवीसी रेसिन की कीमतों (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू) कच्चे तेल की कीमतों के उत्तर-चढ़ाव से जुड़ी हुई हैं:

ब्यौरा	जांच की अवधि के दौरान कीमत	वर्तमान कीमत
कच्चा तेल	103-3अमेरिकी डॉलर	39-41 अमेरिकी डॉलर
पीवीसी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें	1200-1250 अमेरिकी डॉलर	950-1000 अमेरिकी डॉलर
पीवीसी की घरेलू कीमत	90-96 रुपए	78.50 रुपए
भारतीय रूपए से अमेरिकी डॉलर में विनिमय दर	59-62 रुपए	67-68 रुपए

- पाटनरोधी शुल्क की गणना जांच की अवधि में प्रचलित कीमत के आधार पर की जाती है जो ऊपर में दिए गए अनुसार वर्तमान अवधि के दौरान बहुत अधिक बदल गया है। पाटनरोधी शुल्क की अवधि के दौरान अगले पांच वर्षों में ऐसी ही प्रवृत्ति रहेगी।
- विन्दु वी10-XXVI में नोट किया गया है कि अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर जांच की अवधि के दौरान प्रचलित 61.65 रुपए के रूप में ली गई है। वर्तमान विनिमय दर 67.50 रुपए है (आयात के लिए सीमा शुल्क अधिसूचना के

दिनांक 07.04.2014 के अधिसूचना संख्या 48/2016 के अनुसार)। विनिमय दर में इस वृद्धि से पाटनरोधी शुल्क की राशि में प्रत्यक्ष वृद्धि होती है और इसलिए यह अनुरोध भारतीय रूपए में अथवा मूल कीमत के प्रतिशत के रूप में पाटनरोधी शुल्क, यदि कोई हो, पर विचार करने की आवश्यकता दर्शाता है (यथा मूल्य के रूप में और कञ्जे तेल की कीमतों और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण शुल्क लगने की कठिनाई से बचने के लिए)।

### **केमप्लास्ट सेनमर के उत्पादन की उच्च लागत**

- मै. केमप्लास्ट पीवीसी रेसिन का उत्पादन बहुत पुरानी प्रौद्योगिकी से कर रहा है और उसके उत्पादन की लागत अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं से अधिक है और वास्तव में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पहलू का सत्यापन यूरोपियन यूनियन के भाग न लेने के कारण किया जा सकता है और हमें पाटनरोधी शुल्क के कारण हानि उठानी पड़ रही है, इसलिए हमारा विनिमय अनुरोध है कि पीवीसी पेस्ट रेसिन के एक अन्य घरेलू निर्माता मै. फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लि. के उत्पादन की लागत का सत्यापन करने की व्यवस्था करें।
- जब मै. फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लि. को आयात के कारण क्षति और घाटा नहीं होता है तब क्यों केवल केमप्लास्ट को यह क्षति और घाटा उठाना पड़ता है।

### **मै. केमप्लास्ट सेनमर भारत में पीवीसी लेदर क्लॉथ के वास्तिक उपभोक्ताओं और निर्माताओं की अपेक्षा पूरी नहीं करता है**

- भारत में पीवीसी लेदर क्लॉथ का निर्माण करने वाले लघु उद्योग को पीवीसी रेसिन व्यापारियों के माध्यम से स्थानीय बाजार से खरीदार पड़ता है और इसके लिए बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि घरेलू उद्योग वास्तविक उपभोक्ताओं की मांग पूरी नहीं कर पाता है। यह अधिक कीमत इस जांच का भाग नहीं है और इस पर विचार किया जाना चाहिए।
- भारत में पीवीसी पेस्ट रेसिन की कुल खपत वार्षिक रूप से लगभग 12,50,000.00 मी.ट. है जबकि घरेलू उद्योग की क्षमता 50 प्रतिशत मात्र है और शेष पीवीसी रेसिन का आयात पाटनरोधी शुल्क की अधिक लागत के साथ किया जाना होता है और इस तथ्य के बावजूद कि मै. केमप्लास्ट ने कम आपूर्ति के कारण वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा यथा अपेक्षित सामग्री की आपूर्ति करने से इंकार कर दिया है। यह पीवीसी लेदर क्लॉथ के स्थानीय निर्माताओं के लिए बहुत अधिक कठिनाई पैदा करता है।
- आपका ध्यान प्रकटन के बिन्दु संख्या 92 की ओर आकर्षित किया जाता है जो इस प्रकार है: "घरेलू उद्योग का उत्पादन और विक्री सम्पूर्ण अवधि में बढ़ी है। घरेलू उद्योग की पूँजी में गिरावट आई है। एक स्थान पर वे क्षमता के उपयोग में गिरावट दर्शा रहे हैं और दूसरे स्थान पर वे लिख रहे हैं कि क्षमता उपयोग में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। लेकिन वास्तव में घरेलू उद्योग को सामग्री का अभाव रहा है और इसने वास्तविक उपभोक्ताओं को अपेक्षित मात्रा में आपूर्ति करने से इंकार किया है जो पीवीसी लेदर क्लॉथ के घरेलू उद्योग के उत्पादन पर प्रभाव डालता है। हमने अपने अनुरोध में मै. केमप्लास्ट के साथ हमारे सदस्यों द्वारा भेजे गए मेल की प्रतियों के साथ-साथ इसके संबंध में साध्य संलग्न किए हैं।"

### **वर्तमान शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति की कोई संभावना नहीं है**

- पीवीसी पेस्ट रेसिन का घरेलू उद्योग पाटन और क्षति संभावित नहीं है और इन शुल्कों को बंद किया जाना अपेक्षित है। संबद्ध वस्तुओं का सतत आयात दो प्रमुख कारणों से होता है (क) मांग और आपूर्ति में अंतर है इस प्रकार से आयात आवश्यक है, (ख) कुछ विशिष्ट ग्रेडों का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है, इस प्रकार वे ऐसी विशिष्ट ग्रेडों का आयात करने के बाध्य नहीं हैं। यह भी देखे जाने की आवश्यकता है कि ऐसे विशिष्ट ग्रेडों का आयात अपेक्षाकृत बहुत अधिक कीमतों पर किया जाता है। घरेलू उद्योग को कोई क्षति अपेन स्वयं के कारणों से हो सकती है और वर्तमान पाटनरोधी शुल्क जारी रखना इसका हल नहीं है। इस प्रकार से, हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वह संबद्ध देशों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की सिफारिश करें।

### **यदि शुल्क को जारी भी रखा जाना हो तो प्राधिकारी को वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क के किसी निर्धारित रूप के लिए घरेलू उद्योग के अनुरोध को अस्वाकीर करना चाहिए।**

- जहां तक भारत में संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं द्वारा पूरी जांच के दौरान तथा विगत में भी उठाया गया एक गंभीर मुद्दा कुछ विशिष्ट उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर करने की आवश्यकता है और उसे अभी तक नहीं किया गया है जिसने प्रतिस्पर्द्धी बाजार में उपभोक्ताओं की स्थिति को कमज़ोर बनाया है। यह पहले ही प्राधिकारी को

दर्शाया गया है कि ऑटोमोटिव और उच्च के मूल्य के लिए निम्न फॉग जैसी विशिष्ट ग्रेडों का आयात नियमित ग्रेड की तुलना में 50% अधिक कीमत पर किया गया है।

- फिर भी उपभोक्ताओं को बहुत अधिक पाटनरोधी शुल्क देना पड़ा था। चूंकि घरेलू उद्योग निर्माण नहीं कर रहा है, वे किसी भी तरीके से ऐसे ग्रेडों के आयातों के बारे में संबंधित नहीं हैं जो घरेलू उद्योग द्वारा किसी कल्पना से उत्पादित ग्रेडों के स्थान पर परस्पर उपयोग किए जाते हैं।
- उपर्युक्त को देखते हुए, निर्धारित शुल्क की घरेलू उद्योग की धारणा का विरोध किया गया है, यदि इन शुल्कों को जारी रखे जाने की आवश्यकता है। हमारा विनम्र अनुरोध है कि किसी निर्धारित रूप में शुल्क हेतु किसी निर्णय से उपभोक्ता उद्योग पूर्ण रूप से अप्रतिस्पर्द्धी हो जाएगा और परस्पर ग्रेडों की कीमतों में अंतरों को किसी भी प्रकार से शुल्क के ऐसे प्रकार के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा। शुल्क का संदर्भ रूप पहले संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद पर लगाया गया था और हम अनुरोध करते हैं कि प्राधिकारी यदि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना आवश्यक भी पाते हैं तो इस अंतिम निर्णयक समीक्षा में भी शुल्क का संदर्भ रूप की ही सिफारिश करें।

### **अनुरोध:**

- आवेदक को संबद्ध देशों से सतत आयातों के कारण न तो कोई लगातार क्षति हर्दी है और न ही आवेदक वर्तमान उपायों के समाप्त होने की स्थिति में क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना सिद्ध करने में सक्षम हो पाया है;
- उच्च के मूल्य (77 और उससे अधिक) के पीवीसी पेस्ट रेसिन तथा ऑटोमोटिव उद्योग के लिए विशेष रूप से निम्न फॉगिंग विनिर्देशन जिसका निर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है, को शामिल करने अथवा लगातार शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है और ऐसे ग्रेडों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर किए जाने की आवश्यकता है।
- घरेलू उद्योग ने इसकी पुष्टि की है कि वे ऑटोमोटिव उपयोग के लिए निम्न फॉग वाले पीवीसी रेजिन का निर्माण नहीं करते हैं। इन पीवीसी रेजिन का निर्माण विशिष्ट प्रौद्योगिकी से किया जाता है और घरेलू उद्योग के पास यह प्रौद्योगिकी नहीं है और केवल 3-4 प्रमुख निर्माता विश्व में इन प्रकारों में पीवीसी का निर्माण कर सकते हैं। इनका निर्माण मुख्य रूप से इमल्शन उत्पादन प्रक्रिया से किया जाता है और घरेलू उद्योग के पास यह प्रोसेस नहीं है। इन श्रेणियों के निर्माण की लागत सामान्य उद्देश्य वाले ग्रेड के विनिर्माण की लागत से अलग है क्योंकि निम्न फॉग-ऑटोमोटिव ग्रेड पीवीसी रेजिन के निर्माण के लिए उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है और यह आयातक द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़ों से स्पष्ट है कि विशिष्ट ग्रेड की कीमत 1800 अमेरिकी डॉलर है जबकि सामान्य उद्देश्य वाली ग्रेड की कीमत उससे कम है। घरेलू उद्योग के पास ऐसी ग्रेड की उत्पादन और विक्री का कोई रिकार्ड नहीं है। अतः ऐसी ग्रेडों, जिसका नियमित रूप से आयात किया जाता है, को विचाराधीन उत्पाद से बाहर किया जाना चाहिए।
- हमने जांच की अवधि से वर्तमान अवधि में कच्चे तेल की कीमतों तथा भारतीय रूपए की विनिमय दर में बहुत अधिक उत्तर-चढ़ाव देखा है और इसका सीधा प्रभाव पीवीसी के निर्माण के लिए अपेक्षित कच्चे माल की कीमत पर पड़ता है। अतः पाटनरोधी शुल्क पर विचार भारतीय रूपए में बेंचमार्क के रूप में किया जाना चाहिए ताकि घरेलू उद्योग तथा पीवीसी लेदर क्लॉथ के निर्माता इस प्रकार की अधिक दिक्कतों से बच सकें।
- वैकल्पिक तौर पर, किसी पाटनरोधी शुल्क, यदि कोई हो, की गणना कच्चे तेल की कीमत तथा विनिमय दर में उत्तर-चढ़ाव का ध्यान रखने के लिए सीमा शुल्क जैसे आयात कीमत का % के रूप में यथा मूल्य आधार पर की जा सकती है, तथा किसी अन्य रूप में शुल्क जो हमारे बने रहने की स्थिति को बहुत कमज़ोर बना देगा, का हमारा विरोध दर्ज होना करना चाहिए।

**III. इनोवीन बेल्जियम एस.ए.**

- मै. इनोवीन बेल्जियम एस.ए. ने भारत में ईयू से संबद्ध वस्तुओं के एक निर्यातिक के रूप में दिनांक 11.04.2016 के पत्र के माध्यम से इसका विरोध किया है कि गतिशील वस्तु तथा फॉगिंग दो अलग-अलग गुण हैं।
- इसके अलावा, यूनिट कीमत के साथ संबद्ध वस्तुओं का कुल निर्यात पर विवरण बिना किसी साक्ष्य आदि के बहुत-बाद के चरण में दिया गया है।

#### **IV. एससीजी कार्य निष्पादन केमिकल्स कं. लि. ("एससीजी")**

- मै. एससीजी कार्य निष्पादन केमिकल्स कं. लि. ने टिप्पणी की है कि मै. हनवा और मै. एलजी ने मै. एससीजी की कीमतों में कटौती की और उसे कम से कम 50 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.ट. तक मै. एससीजी की कीमतों से कम पर बेचा। मै. एससीजी ने मै. हनवा और मै. एलजी की पाटन कीमतों के विरुद्ध अनेक आदेश, गँवा दिये और फिर भी मै. हनवा और मै. एलजी पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगा है।
- V. प्राधिकारी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण नहीं किया है और वे केवल कैमप्लास्ट के आंकड़ों पर निर्भर रहे हैं और उन्होंने डी जी सी आई एंड इस के आंकड़ों का स्वतंत्र रूप से उल्लेख नहीं किया है। कैमप्लास्ट द्वारा नकदी में छूट देने, पहुंच मूल्य का निर्धारण करने के लिए मूल सीमाशुल्क को शामिल नहीं करने, आशोधित कीमतों में कमी होने, यदि निर्यातिक देश की कीमतें अधिक होती हैं तो कैमप्लास्ट द्वारा निर्यात नहीं करने, कैमप्लास्ट की उच्च खरीद कीमत होने जैसे मुद्दों का निदान नहीं किया गया है।

#### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

131. वाष्पहीनता और कम फॉर्मिंग के लक्षणों की जांच करने के संबंध में प्राधिकारी का यह मानना है कि उक्त ग्रेड के उत्पादकों/निर्यातिकों ने विचाराधीन उत्पाद, पाटन अथवा क्षति के पहलू का प्रतिवाद करते हुए जांच में भाग नहीं लिया था। इसके अतिरिक्त, प्रयोक्ताओं को अपीलीय निकाय सेस्टेट के समक्ष पहले आई आई टी की परीक्षण रिपोर्ट पर प्रतिवाद करने की आवश्यकता थी। आई आई टी की रिपोर्ट ने कम वाष्पहीनता तथा कम फॉर्मिंग के लक्षणों के पहलू को कैसे स्पष्ट किया और विचाराधीन उत्पाद में संबद्ध वस्तुओं के ग्रेड को भी शामिल किया गया है।

132. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक/निर्यातिक की क्षमता में मै. एच सी सी द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर घेरेलू उद्योग के साथ-साथ मै. एच. सी सी द्वारा किए गए निवेदनों को प्राधिकारी नोट करते हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एच सी सी को कोरिया के सीमाशुल्क द्वारा जारी किए गए निर्यात परमिट और वाणिज्यिक बीजक और लदान बिल में एक निर्यातिक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। तथापि, जांच अवधि में मै. एच सी सी द्वारा किए गए निर्यात के \*\*\* मी.ट. में से \*\*\* मी.ट. के लिए वर्तमान निर्णायिक समीक्षा में हानवा कॉर्पोरेशन की सेवाओं को प्रयुक्त किया गया है तथा कारखानागत निर्यात कीमत का आकलन करने के लिए \*\*\* अम.डॉ./मी.ट. को कमीशन के रूप में समायोजन करने पर विचार किया गया है तथा साथ ही दिनांक 2 मई, 2011 के मूल परिणामों में भी जिसमें प्राधिकारी ने मै0 एच सी सी और मै0 हानवा कॉर्पोरेशन के बीच इसी प्रकार की व्यवस्था से कारखानागत निर्यात कीमत का आकलन करने के लिए समायोजन किया था। इसके अतिरिक्त उपरोक्त कारोबार के संबंध में जिनमें हानवा कॉर्पोरेशन ने साखपत्र का प्रबंधन किया है, महानिदेशक प्रणाली आंकड़ा ने एच सी सी को एक निर्यातिक के रूप में अभिज्ञात किया है। मै0 हानवा कॉर्पोरेशन के \*\*\* मी.ट. से संबंधित कारोबार के लिए कारखानागत निर्यात कीमत के लिए कमीशन का समायोजन करने के बावजूद भी पाटन मार्जिन निरंतर न्यूनतम बना हुआ है। इसलिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक और निर्यातिक, दोनों के रूप में एच सी सी के लिए पाटन मार्जिन/क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है तथा एच सी सी द्वारा अपनाए गए निर्यात के किसी अन्य माध्यम के लिए पाटनरोधी शुल्क की अधिशेष श्रेणी की सिफारिश की है। दक्षिण कोरिया में पीवीसी पेस्ट रेजिन के उत्पादक/निर्यातिकों के स्थल का दौरा करने पर वीसीएम के मूल्यांकन की ध्यानपूर्वक जांच की गई है। संबद्ध पाटनरोधी शुल्क नियमावली के अनुसार, पीवीसी पेस्ट रेजिन की कारखानागत लागत का मूल्यांकन करने के लिए लेखा बहियों में दर्ज वीसीएम के उत्पादन की लागत पर विचार किया गया है।

133. विचाराधीन उत्पाद के ग्रेडों में अंतर होने के संबंध में प्राधिकारी का यह मानना है कि ऐसे विचाराधीन उत्पाद जिसे कुछ तकनीकी प्राचलों और अनुप्रयोगों के आधार पर विभिन्न ग्रेडों से भिन्न है, उनकी लागत और कीमत में भी अंतर है। कोरिया जैसे सहयोगी निर्यातिकों के मामले में लागत और कीमत में व्याप्त इस अंतर को 15-20 प्रतिशत के बीच नोट किया गया है। इसलिए प्राधिकारी ने सहयोगी निर्यातिकों के लिए पाटन मार्जिन का मूल्यांकन करने के लिए अलग-अलग ग्रेड का विशेषण किया है जोकि वास्तविक और उपयुक्त है। जैसा कि प्रकटन विवरण में उल्लेख किया गया है, विभिन्न ग्रेडों में समानता को ध्यान में रखते हुए क्षति मार्जिन के लिए भी अलग-अलग ग्रेड के आधार पर उनकी तुलना की गई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घेरेलू उद्योग ने अपने द्वारा विनिर्मित ग्रेडों के संबंध में

यह बताया है कि उनकी लागत का अंतर कम है। ऐसे मामले में भी प्राधिकारी का यह मानना है कि अलग-अलग आधार पर ग्रेडों का विश्लेषण करना अवास्तविक नहीं है।

134. पाटनरोधी शुल्क के रूप और मूल्य वर्ग के संबंध में प्राधिकारी का यह मानना है कि क्रियान्वयन और प्रभावकारिता को ध्यान में रखते हुए डॉलर के रूप में नियत शुल्क की सुसंगत रूप से सिफारिश की गई है तथा उसे लगाया गया है।

135. कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव होने के संबंध में प्राधिकारी का यह मानना है कि विभिन्न तत्वों जैसे कि जांच के विभिन्न पहलुओं के लिए उपयुक्त रूप से जांच अवधि में अधिप्राप्त किया गया कच्चा माल/संबद्ध वस्तुओं की लागत और कीमतों में व्याप्त अंतर पर विचार किया गया है। आशोधित कीमत में गिरावट, कैमप्लास्ट के उत्पादन की उच्च लागत, पहुंच मूल्य का निर्धारण और डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों को अपनाने से संबंधित मुद्दों के संबंध में प्राधिकारी का यह मानना है कि कैमप्लास्ट, पाटनरोधी नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग की अपेक्षा को पूरा करता है। जांच अवधि के दौरान एनआईपी का निर्धारण, संबद्ध नियमानुसार किया गया है तथा यह प्राधिकारी की सुसंगत प्रक्रिया के अनुसार लागत की कमी के मुद्दों का निदान करता है। असहयोगी निर्यातिकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, संबद्ध पाटनरोधी नियमावली के अनुसार किया गया है, जिसके ब्यौरे संबद्ध पैराओं में दिए गए हैं। असहयोगी निर्यातिकों के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर आधारित भारित औसत आयात कीमतों पर मूल सीमाशुल्क को लागू करके पहुंच मूल्य निर्धारित किया गया है, क्योंकि निर्यातिकों से उत्तर प्राप्त न होने तथा आयातकों से सीमित उत्तर प्राप्त होने को ध्यान में रखते हुए यह व्यापक है और वेहतर उपलब्ध सूचना है। एन एस आर का निर्धारण कारखानागत स्तर पर किया गया है जोकि छूट और करों का निवल है।

136. कोरिया जन.गण. से निर्यातिकों द्वारा पाटन पर मै0 एस सी जी परफोरमेंस कैमिकल्स कंपनी लि0 की टिप्पणियों के संबंध में कि उनकी कीमतें थाइलैंड की कीमतों से कम हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक निर्यातिक के लिए विशेष रूप से निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन उस निर्यातिक के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर आधारित होता है। ऐसा ही कोरिया जन.गण. से सहयोगी निर्यातिकों के लिए किया गया है।

137. रूस से आयात नहीं होने की स्थिति में पाटन के खतरे और संभावित क्षति का संभावित विश्लेषण करने के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं तथापि, विश्व व्यापार एटलस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 में सीमाशुल्क के वर्गीकरण सं. 390422 के अंतर्गत भारत को कम मात्रा में निर्यात किए हुए प्रतीत होते हैं। जांच अवधि के दौरान भारत से भिन्न अन्य देशों को इस शीर्ष के अंतर्गत निर्यातों की औसत कीमत से यह सिद्ध नहीं होता है कि यदि भारत की ओर निर्यात कर दिए जाते हैं तो घरेलू उद्योग को उससे संभावित क्षति नहीं होगी।

138. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जांच अवधि पश्चात तृतीय देशों को संबद्ध वस्तुओं की कीमतों से ऐसा पता चलता है कि जांच अवधि की तुलना में उनमें 13.42 प्रतिशत की गिरावट आई है। मुख्य कच्चा माल अर्थात वीसीएम की कीमतों से भी यह पता चलता है कि इस तदनुरूपी अवधि के दौरान तृतीय देशों को ऐसी कीमतों में 21 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसलिए, संबद्ध वस्तुओं और कच्चे माल, दोनों में ही वैश्विक गिरावट आने का स्पष्ट पता चलता है। ऐसी स्थिति में समीक्षा के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्कों को निरंतर जारी रखने की वजाए निर्यातिक विशिष्ट विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए प्राधिकारी का यह मानना है कि उपयुक्त तथ्य और कीमत की प्रवृत्ति से ऐसा स्थापित नहीं होता है कि रूस से पाटन के निरंतर जारी रहने और उससे परिणामी क्षति होने की संभावना है।

### निष्कर्ष

139. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों, प्रदत्त सूचना और किए गए निवेदनों तथा इस परिणाम में दर्ज प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों तथा पाटन के निरंतर जारी रहने और उससे परिणामी क्षति होने तथा पाटन और क्षति के निरंतर रहने/पुनरावृत्ति होने की स्थिति के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष निम्नानुसार है:

- (1) रूस को छोड़कर संबद्ध देशों से तथा कोरिया जन.गण. से मै0 एल जी कैमिकल्स और मै0 एच सी सी संबंधित उत्पाद का पूर्णरूपेण तथा भारत में उत्पादन/खपत दोनों की दृष्टि से निरंतर पाटन हो रहा है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

- (2) आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आयातों से घरेलू कीमतों का मूल्यह्रास और न्यूनीकरण हो रहा है।
- (3) घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ, नकदी प्रवाह और मालसूचियों के रूप में गिरावट आयी है।
- (4) रूस को छोड़कर संबद्ध देशों तथा कोरिया जन.गण. से मै0 एल जी कैमिकल्स और मै0 एच सी सी से पाटित आयात निरंतर घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं।
- (5) यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो रूस को छोड़कर संबद्ध देशों तथा कोरिया जन.गण. से मै0 एल जी कैमिकल्स और मै0 एच सी सी से विचाराधीन उत्पाद का निरंतर पाटन /गहन होने की संभावना है।

### सिफारिशें

140. उपरोक्त निष्कर्ष देने पर प्राधिकारी का यह विचार है कि रूस को छोड़कर संबद्ध देशों और कोरिया जन.गण. से मै0 एल जी कैमिकल्स और मै0 एच सी सी के संबंध में पाटनरोधी शुल्क के उपायों को निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है। इसलिए प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर नीचे शुल्क तालिका में निर्धारित रूप और तरीके से निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है।

141. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी रूस को छोड़कर संबद्ध देशों तथा कोरिया जन.गण. से मै0 एल जी कैमिकल्स और मै0 एच सी सी से के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से कम मार्जिन के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नीचे तालिका के कॉलम 8 में निर्दिष्ट राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

### शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष/ उप शीर्ष	*वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातिक देश	उत्पादक	नियातिक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3904	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	कोरिया जन. गण.	कोरिया जन. गण.	हान्वाह कैमिकल कॉर्पोरेशन	हान्वाह कैमिकल कॉर्पोरेशन	0	मी.ट.	अम.डॉ.
2	3904	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	कोरिया जन. गण.	कोरिया जन. गण.	मै0 एलजी कैम. लि0	मै0 एलजी कैम. लि0	0	मी.ट.	अम.डॉ.
3	3904	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	कोरिया जन. गण.	कोरिया जन. गण.	क्र. सं. 1 और 2 से भिन्न कोई अन्य	क्र. सं. 1 और 2 से भिन्न कोई अन्य	379	मी.ट.	अम.डॉ.

4	3904	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	कोरिया जन. गण.	संबद्ध देशों से इतर कोई देश और वे देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	कोई	कोई	<b>379</b>	मी.ट.	अम.डॉ.
5	3904	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	संबद्ध देशों से इतर कोई देश और वे देश जिन पर किसी अन्य अधिसूचना के तहत पाटनरोधी शुल्क लागू है	कोरिया जन. गण.	कोई	कोई	<b>379</b>	मी.ट.	अम.डॉ.
6	3904	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	कोई	कोई	<b>88</b>	मी.ट.	अम.डॉ.
7	3904	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	चीन जन. गण.	संबद्ध देशों से इतर कोई देश और वे देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	कोई	कोई	<b>88</b>	मी.ट.	अम.डॉ.
8	3904	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	संबद्ध देशों से इतर कोई देश और वे देश जिन पर अन्य कोई अधिसूचना के तहत पाटनरोधी शुल्क लागू है	चीन जन. गण.	कोई	कोई	<b>88</b>	मी.ट.	अम.डॉ.
9	3904	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	मलेशिया	मलेशिया	कोई	कोई	<b>214</b>	मी.ट.	अम.डॉ.
10	3904	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	मलेशिया	संबद्ध देशों से इतर कोई देश और वे देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	कोई	कोई	<b>214</b>	मी.ट.	अम.डॉ.
11	3904	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन*	संबद्ध देशों से इतर कोई देश और वे देश जिन पर अन्य कोई अधिसूचना के तहत पाटनरोधी शुल्क लागू है	मलेशिया	कोई	कोई	<b>214</b>	मी.ट.	अम.डॉ.
12	3904	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	ताइवान	ताइवान	कोई	कोई	<b>101</b>	मी.ट.	अम.डॉ.

13	3904	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	ताइवान	संबद्ध देशों से इतर कोई देश और वे देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू हैं	कोई	कोई	<b>101</b>	मी.ट.	अम.डॉ.
14	3904	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	संबद्ध देशों से इतर कोई देश और वे देश जिन पर अन्य कोई अधिसूचना के तहत पाटनरोधी शुल्क लागू हैं	ताइवान	कोई	कोई	<b>101</b>	मी.ट.	अम.डॉ.
15	3904	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	थाइलैंड	थाइलैंड	कोई	कोई	<b>111</b>	मी.ट.	अम.डॉ.
16	3904	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	थाइलैंड.	संबद्ध देशों से इतर कोई देश और वे देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू हैं	कोई	कोई	<b>111</b>	मी.ट.	अम.डॉ.
17	3904	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	संबद्ध देशों से इतर कोई देश और वे देश जिन पर अन्य कोई अधिसूचना के तहत पाटनरोधी शुल्क लागू हैं	थाइलैंड	कोई	कोई	<b>111</b>	मी.ट.	अम.डॉ.
18	3904	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	यूरोपीय यूनियन	यूरोपीय यूनियन	कोई	कोई	<b>298</b>	मी.ट.	अम.डॉ.
19	3904	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	यूरोपीय यूनियन	संबद्ध देशों से इतर कोई देश और वे देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू हैं	कोई	कोई	<b>298</b>	मी.ट.	अम.डॉ.
20	3904	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	संबद्ध देशों से इतर कोई देश और वे देश जिन पर अन्य कोई अधिसूचना के तहत पाटनरोधी शुल्क लागू हैं	यूरोपीय यूनियन	कोई	कोई	<b>298</b>	मी.ट.	अम.डॉ.

\* कृपया नोट करें : 1. ब्लैंडिंग रेजिन, 2. पीवीसी पेस्ट रेजिन के कोपालिमर्स, 3. बैटरी सेपरेटर रेजिन और 4. 60 से कम के-मूल्य के पीवीसी पेस्ट रेजिन, इन सिफारिशों के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं।

## निष्कर्ष

142. इस अधिसूचना के प्रयोजन से आयातों का अवतरित मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य होगा तथा इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल होते हैं।

## आगे की प्रक्रिया

143. इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना से उत्पन्न होने वाले केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)

New Delhi, the 26th April, 2016

## FINAL FINDINGS

**Subject: Sun Set Review of the Anti-Dumping Investigation concerning imports of “Poly Vinyl Chloride (PVC) Paste/ Emulsion Resin” originating in or exported from Korea RP, Taiwan, China PR, Malaysia, Thailand, Russia and European Union.**

**No. 15/19/2014-DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

### A. Background of the case

1. Whereas in the matter of imports of Poly Vinyl Chloride Paste Resin also known as Emulsion PVC Resin (hereinafter referred to as the subject goods), falling under sub- heading 3904 22 10 of the Customs Tariff Act, 1975, originating in, or exported from, People's Republic of China, Republic of Korea, Malaysia, Russia, Taiwan and Thailand imported into India, the Designated Authority in its preliminary findings vide notification No.14/36/2009- DGAD, dated the 11th June, 2010, had recommended imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from, and whereas, on the basis of the aforesaid findings of the Designated Authority, the Central Government had imposed provisional anti-dumping duty on the subject goods vide notification No. 77/2010-Customs, dated 26th July, 2010. And whereas, the Designated Authority, issued its final findings vide notification No. 14/36/2009–DGAD, dated 2nd May, 2011 and the Ministry of Finance imposed definitive anti-dumping duty vide Notification No.66 /2011-Customs dated 26th July, 2011.
- (2) Separately, in another investigation, the Designated Authority vide notification No.15/27/2008-DGAD, dated the 31st March, 2009, had initiated sunset review in the matter of anti-dumping duty on imports of subject goods originating in or exported from European Union imposed vide notification of Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 104/2004–Customs, dated the 7th October, 2004, and extended the same by notification No. 115/2009-Customs dated 6th October,2009. The Designated Authority vide notification No. 15/27/2008-DGAD, dated the 26th April, 2010, after conducting Sunset Review had recommended continued imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from European Union, which was imposed by the Ministry of Finance vide Notification No. 70 /2010- Customs dated 25th June, 2010 and amendment notification no.8/2012 dated 16.01.2012.
- (3) And whereas, Leather Cloth and Plastics Manufacturers Association (LCMPA) filed an appeal before CESTAT, challenging the continued imposition of antidumping duty on imports of product under consideration recommended vide final findings dated 26th April, 2010 and imposed vide Customs Notification No.70/2010-Customs dated 25th June, 2010 and amendment vide notification no 8/2012 dated 16.01.2012. 6.
- (4) And whereas the Hon'ble CESTAT vide its order dated 6th July, 2012 set aside the final findings dated 26th April 2012 , the Customs notification No.70/2010- Customs dated 25th June, 2010 and amendment notification no.8/2012

dated 16.01.2012 and remanded the matter back to Designated Authority for fresh decision after granting opportunity of hearing to the interested parties.

- (5) The Designated Authority vide notification No. 15/27/2008-DGAD dated 4th April 2013, after granting opportunity of hearing recommended imposition of anti-dumping duty has recommended the continued imposition of definitive anti-dumping duty on all imports of the subject goods, originating in, or exported from the European Union; which was imposed by the Ministry of Finance vide Notification No. 15/2013-Customs (ADD) dated 3<sup>rd</sup> July, 2013.
- (6) Whereas, M/s. ChemplastSanmar Ltd has filed a duly substantiated application before the Authority, in accordance with the Act and the Rules, contending likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from Korea RP, Taiwan, China PR, Malaysia, Thailand, Russia and European Union and consequent injury to the domestic industry and have requested for review, extension of period, modification of the existing anti dumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.
- (7) Whereas in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated a Sunset review investigation vide Notification No 15/19/2014-DGAD dated 27<sup>th</sup> April, 2015 to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
- (8) The present Sunset Review is initiated on imports of the subject goods from the exporting countries mentioned in Para (1) and (2) above i.e. People's Republic of China, Republic of Korea, Malaysia, Russia, Taiwan, Thailand and European Union (herein after referred to subject countries).
- (9) In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government has extended the existing anti-dumping duty on "Poly Vinyl Chloride Paste Resin" levied vide notification No 15/2013-Customs (ADD) against imports from European Union, dated the 3rd July, 2013; upto 25th day of July, 2016 through a notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 26/2015-Customs (ADD), dated the 1st June, 2015 and Corrigendum dated 28th March, 2016. Separately, the Ministry of Finance extended the anti-dumping duty on "Poly Vinyl Chloride Paste Resin" against imports from Korea RP, Taiwan, People's Republic of China, Malaysia, Thailand and Russia imposed *vide* Notification No. 66/2011-Customs, dated the 26th July, 2011; upto 25th day of July, 2016 through a Notification No. 25/2015-Customs (ADD) dated 1<sup>st</sup> June, 2015.

## **B. Procedure**

- (10) The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

i. The Authority sent copy of the initiation notification dated 27<sup>th</sup> April, 2015 to the embassy of the subject countries in India, known exporters from the subject countries and known importers, as per available information. The known interested parties were requested to file questionnaire responses and make their views known in writing within the prescribed time limit. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to embassy of the subject countries along with a list of known exporters/producers, with a request to advise the exporters/producers from the subject countries to respond within the prescribed time.

ii. Copy of the non-confidential version of the application filed on behalf of the applicant was made available to the known exporters and the embassies of the subject country in accordance with Rule 6(3) of the Rules.

iii. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the sunset review to the following known producers/exporters in the subject countries and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules:

- a) Tianjin Chemical Plant, China PR
- b) Tianjin Bohai Chemical Industries, China PR
- c) Shenyang Chemicals Co. Ltd, China PR
- d) Formosa Plastic Corporation, Taiwan
- e) LG Chem Ltd., Korea RP
- f) Hanwha Chemicals, Korea RP
- g) Kaneka Paste Polymers SDN, Malaysia
- h) Vinythai Public Company Limited, Thailand
- i) OOO Polymer- Chemie, Russia
- j) VistolitGmBH& Co, Denmark

k) EVC Business Centre, UK

l) VastoliteGmBH& Co, Germany

m) Solvin SA, Belgium

n) VinnolitGmbh& Co, Germany

o) Alscondel, Spain

iv. In response to the initiation of the subject investigation, following producers/exporters from the subject countries have responded by filing questionnaire response

- M/s LG Chem, Korea RP (“M/s LG”)
- M/s Hanwa Chemicals, Korea RP (“M/s HCC”)

v. Further M/s RusVinyl, producer from Russia filed a letter dated 27<sup>th</sup> January, 2016 raising certain issues on the investigation. However, the company did not file the questionnaire response. The issues raised by the company are however considered in the present investigation to the extent found appropriate. An email dated 21<sup>st</sup> January, 2016 in continuation of its email of October, 2016 was also received at the belated stage of investigation from SCG Performance Chemicals Co Ltd, Thailand (“M/s SCG”), an exporter of the subject goods produced by its 100% subsidiary, i.e. M/s. TPC Paste Resin Co. Ltd., Thailand, requesting for a possible participation in investigation. The Authority in the disclosure had stated that both the above producer and exporter of the subject goods did not register themselves as an interested party as was required to be done. Neither did they file any submissions/data on normal value and exports made by them despite an extension in time provided with notice hosted on the Dept. of Commerce’s website. The exporter did therefore not avail opportunity provided to them in a timely manner. The Authority provided the disclosure statement to the exporter for their comments.

vi. Market Economy Treatment (MET) questionnaire was also forwarded to the known producers/exporters in China PR and the Embassy of China PR in India with the request to provide relevant information to the Authority within the prescribed time limit. While for the purpose of initiation, the normal value in China PR was considered based on the cost of production of the subject goods in India, duly adjusted, the Authority informed the known producers/exporters from China PR that it proposes to examine the claim of the applicant in the light of Para 7 and Para 8 of Annexure I of Anti-dumping Rules, as amended. The exporters/producers of the subject goods from China PR were, therefore, requested to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned to enable the Authority to consider whether market economy treatment can be granted to the cooperative exporters/producers in China PR. However, none of the producers/exporters from China PR have filed MET questionnaire response rebutting the non-market economy treatment to China PR.

vii. Questionnaires were sent to the following known importers/users/associations of subject goods in India calling for necessary information in accordance with the Rules:

Akzo Nobel Coatings India Pvt. Limited 62P HoskoteIndl Area Pilgumpa Karnataka 562 114	Alleppey Co Ltd Post Box No.2602, Tac House Alleppey Kerala
Anabond Essex India P Ltd 1F Dev Regency, 1 <sup>st</sup> Main Road Gandhinagar, Chennai 20	Creative World 11-12, 2nd Floor, NarimanIndlEst New Link Road Village ChincholiMalad (W) Bombay
D C Mills (P) Ltd P.B.No.160, Kalavoor Alleppey Kerala	DRG Leather P Ltd Karai pudur Thrissur
EftecShroff India Limited Excel Est, SVivekanand Road Goregaon Bombay 400 062	Fenner Conveyor Belting Pvt Ltd Madurai-Dindigul Road, Nagari, VadipattiTaluk, Madurai 625 221, Tamilnadu
Fenoplast Ltd 165 166 Nandigaon Village Medak District Andhra Pradesh	Halol Leather Cloth Ltd 7-A, Dharamsi Cross Street Bhendi Bazar Bombay 400003
Henkel Teroson India (P)Ltd 74, Indl. Devp Colony Mehrauli Road Gurgaon Haryana	Hindusthan Seals Ltd Bikaner Building, 3rd Floor 8/1, Lal Bazar Street Calcutta
International Conveyore Ltd	Jasch Industries Ltd

E-39, MIDC, Industrial Area, Chikathana, Aurangabad 431210	5105 Blk D - Gali 1 - KrishanNgr Karol Bagh New Delhi 110 005
Kerafibertex International P Ltd 53-57 Kinfra Industrial Park, Kisumagiri P.O Kakkandu, Cochin 682030	Kerala Balers Ltd P O Box 28 3, Alleppey Kerala
MayurUniquoters Ltd Rotary Bhawan Church Road Jaipur	Oswal Cable Products A 93/1 WazirpurIndust Area- 52 WazirpurIndust Area New Delhi 110 052
PhirozeSethna P Ltd 101-A, Road No.16 WagleIndl.Estate Thane	Polmann India Ltd Maker Chmbs-V Nariman Point Bombay 400 021
Polynova Industries Ltd 92-101, Kundaim Industrial Estate, PanjiPonda Road, Kundaim, Goa-403110	Premier Polyfilm Ltd 305 Elite Hs 36 Community Centre Kailash Colony New Delhi
RotoScreentech Ltd 301, Silver Chamber Tagore Road Rajkot 360002	Shivam Textiles A 1/126 JanakPuri- New Delhi 110 058
SielTizit Ltd 58 Motilal Gupta Road BarishaInd 700008 Calcutta	Sneha Vinyl Products P Ltd Industrial Dev Area Renigunta 517520 AP
SRF Limited Viralimalai 621316, Tamilnadu, India	Texon Industries P Ltd 19 Marshalls Road Egmore Chennai 8
Travancore Cocotuft P Ltd Coir Park, Thiruvizha, Cherthala-688 539, Kerala	Yash Marketing Agencies 1/2 Chitra-Ami Apartment, Ashram Road, Ahmedabad 380009
Valley Velvette (P) Ltd 1/2 Chitra-Ami Apartment, Ashram Road, Ahmedabad 380009	Om Vinyls Pvt Ltd 4- Ground Floor, VyaparBhavan, 49, P D'Mello Road. CarnakBunder, Mumbai-400009
Gomti Exports 410, 121/127 - MandviNavjivan, Mumbai-400003	RMG Polyvinyl India Limited 302, Elite House, 36, Community Centre, Zamroodpur, New Delhi 110048
Veekey Vinyl 4283 (A)/4 Jai Mata Market, Tri Nagar, New Delhi-110035	United Decorative Private Ltd 46/3, Site-IV, UPSIDC Industrial Area, Sahibabad-201010, Gaziabad UP.
B.B. Trading Co. B -10, Shoe Market, Delhi 110035,	Incom Cables Pvt Ltd 'A-1/73 Safdarjang Enclave, New Delhi 110029
Kundan Rice Mills Ltd. D-16,City Chambers PrashantVihar, Delhi 110085	'Lucky Plast Ltd. 6-B/3 N.E.A. Old Rajinder Nagar, New Delhi
Mansfield Cable Co., B 41, Sector-6, Noida 201301	Marvel Vinyls Limited G-73, Connaught Circus, New Delhi 110001
Nouvelle Credits Pvt.Ltd. 4316/17-3rd Floor,Saini Market, BahadurGarh Road, New Delhi 110006	'Orient Overseas Private Limited, C-15,Sma Co-Op Industrial Estate, 'G.T.Karnal Road, Delhi 110033
Oswal Vinyl Industries Ltd. 2/49,Roop Nagar, Delhi 110007	Paramount Communications Ltd. M-4, Bahubali. 59/17, New Rohtak Road New Delhi
Poonam Plastic Produts 76, ShahzadaBaghExtn. Old Rohtak Road, Delhi 110035	R.K.Industries C-595, DSIDC Industrial Park, Narela, Delhi 110040
'R.K.Trading Company 2nd Floor,Saini Market, 3007,Bahadur Garh Road, Delhi 110006	R.S. Overseas Pvt. Ltd. F-31 - Bhagawant Singh Market. BahadurGarh Road, Delhi
Rallison Electricals Pvt. Ltd.	'Responsive Industries Ltd

Plot No.164(1310), Vpo. 'Manpura, Tehsil Nalagarh, Distt., Solan	Mahagaon Rd,Betegaon, Boisar East, 'Tal-Palghar, Dist-Thane, 'Maharashtra
Ritzy International Pvt.Ltd. D-832, New Friends Colony, New Delhi 110065	Royale Industries G-1085, DSIDC Industrial Complex, Narela, Delhi
S. K. Traders K.No.358, Street No.2, Kusak Road-2, Saroop Nagar, Delhi	'S.L.F.(India) Limited 6, Sehgal Colony, Court Lane, Delhi 110054
S.R.Polychem 4311/5-Jai Mata Market, Trinagar, Delhi 110035	SheelPolytex 10761-62, Jhandewalan Road, Nabi Karim, New Delhi 110055
SheelVinyls H-41, Green Park Extn., New Delhi 110016	Shiv Shakti Industries D-7, Kh.No.30/23, Nangli Poona Extension, Delhi 110036
'Sunny Chemicals Pvt Ltd. C-151, PreetVihar, Delhi	Supreme Electricals 'D-33, Bali Nagar, New Delhi
'Sushi Chem Plastic Industries 72-B, ShahzadaBaghExtn., 'Old Rohtak Road, Delhi	Terra India F-118,Ashok Vihar, Phase-I, Delhi 110052
Trishla Vinyl Tubes Ltd. 4.A Race Course Trishla House, Dehradun 248001	'Ultimate Industries Ltd. E-260,Greater Kailash-II, New Delhi
'VeekayPolycroats Ltd. Flatno 7d, 7th Floor, Hansalaya Building, 15 , Barakhamba Road, New Delhi	Vima International Products 307/3 ShahzadaBagh Old, Rohtak Road, Delhi 110035
Akshat Plastics Pvt. Ltd., 4648/15, Jai Mata Market, Trinagar, New Delhi 110035	'Vipin Polymers Pvt.Ltd. 193, Bhagirathi Appmts, 'Sector-Ix, Rohini, Delhi
Arinits Sales Pvt. Ltd., 603, Nirmal Tower, 26 Barakhamba Road, New Delhi 110001	Bansal Chemicals (India) F/14, Mahaveer Chambers, 103, NyniappaNaicken Street, Chennai 600003

viii. In response to the above notification, following importers filed questionnaire/ submissions

- a. M/s MayurUniquoters Ltd
- b. M/s Polynova Industries Ltd.
- c. M/s Jasch Industries Ltd.

ix. Further, the M/s Leather Cloth and Plastics manufacturers' Association (LCPMA) has filed response to the petition.

x. M/s Athena Associates also made submissions on behalf of M/s MayurUniquoters Ltd. M/s Polynova Industries Ltd., M/s Jasch Industries Ltd., LCPMA, M/s KPL International Ltd. and M/s Jasch Plastics India Ltd. after oral hearing held on 02.02.2016.

xi. One of the importers KlassikLamitex Private Ltd. ("M/s Klassik") filed its response at the belated stage of the proceedings. The Authority has informed all the known importers mentioned in the domestic industry's petition to file the questionnaire responses. Further the questionnaires and Initiation of the investigation was available on the website. As per the initiation notification, any party wishing to participate can get itself registered as an interested party.

xii. M/s. Klassic through letter dated 18.03.2015 had requested for non- imposition of existing anti- dumping duty in PVC resin after its expiry in June 2015, on the grounds that despite falling VCM prices globally, high prices for PVC resin prevailing in India, non- consideration dynamic cost structure of products globally, Foreign Exchange Rate factors including cross currency rates, advance impact on user industry especially employment, monopolistic protection to a few producers, emergence of inverted duty structure, under invoicing of imports by derived industry etc., prior to initiation of the sunset review.

xiii. The importer participated in the oral hearing held on 02.02.2016 and provided submissions and the imports data as per the questionnaire which has been appropriately correlated with the data provided by the producer/exporter from South Korea and the DGCI&S data. The submissions made by the importer earlier vide its letter date 18.03.2015 as stated above have been broadly repeated further emphasizing the high protection to Domestic Industry not based on global price data, the huge demand supply gap in the country, non-integrated facility of M/s. Chemplast leading to high cost and unreasonable quantum of anti-dumping duty which if was correct would have encouraged M/s Chemplast to export to countries having high domestic prices which is not the case.

xiv. The Authority notes that the submissions of the importer in its letter dated 18.03.2015 prior to the SSR initiation indicate his knowledge of the forth coming sunset review. Further, in view of questionnaires, and initiation being gazetted and available in public domain on website of Dept. of Commerce, submissions/data in the present ongoing sunset review could have been filed well by him within the stipulated time.

xv. Further M/s Bansal Chemical Ltd filed a letters dated 8<sup>th</sup> June 2015 stating that they have not imported the product under consideration since 2008 and will not import in future and therefore should not be considered as a leading exporter of product under consideration.

xvi. Exporters, producers and other interested parties who have not responded to the Authority nor supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating.

xvii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange for details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigation, which was received by the Authority.

xviii. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry. The NIP has been determined by the Authority for various grades of the product under consideration in terms of the principles laid down under Annexure II to the Anti-dumping Rules.

xix. The period of investigation for the purpose of the present review is October 2013- September 2014 (12 months). However, injury analysis covered the periods April, 2011-12, 2012-13, 2013-14 and POI.

xx. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 2<sup>nd</sup> February, 2016. The parties, who presented their views in oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

xxi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation have been considered by the Authority, wherever found relevant, in this finding.

xxii. Verification to the extent deemed necessary was carried out in respect of the information & data submitted by the domestic industry, cooperative exporters and one of the importer/ user industries.

xxiii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xxiv. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.

xxv. In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts were disclosed by the Authority on 15<sup>th</sup> April, 2016 to the known interested parties. Interested parties were requested to file comments to the disclosure statement by 20.04.2016. However keeping in view the submission made by M/s KlassikLamitex and M/s SCG Performance Chemical Co. Ltd., the Authority has granted them one additional day, i.e. 21.04.2016 to file comments on the disclosure statement. Further, comments received on the disclosure statement, to the extent considered relevant by the Authority, have been considered in this final finding.

xxvi. The average exchange rate of 1US\$ = Rs 61.65 prevailing during the POI has been adopted by the Authority in this finding.

xxvii. “\*\*\*” represents information furnished by an interested party/other party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

### C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

11. The product under consideration, in the original investigation is Poly Vinyl Chloride Paste Resin" also called "Emulsion PVC Resin" and referred to as PVC paste resin (hereinafter also referred to as the subject product or the subject goods). There are primarily two types of PVC resins, namely PVC Paste Resin and PVC Suspension Resin. It was clarified in the initiation notification itself that PVC Suspension Resin is excluded from the ambit and scope of this investigation. The PVC Paste Resin is produced from Vinyl Chloride Monomer (VCM). VCM is produced using EDC, which in turn requires chlorine as one of the major products. The subject goods is produced and sold in the form of white/off-white powder. The properties of the subject goods are described in terms of K value, inherent viscosity, particle size retention, heat loss, initial BFB etc.
12. The subject goods fall under Chapter 39 of the Act under subheading no. 3904. However, the Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation

#### C.1 Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties

13. Following submissions have been made by the exporters/importers/users/other interested parties/ other parties
  - a. The Authority should reconsider the scope of PUC and like article in the current investigation as apart from the original investigation and remove certain items not falling within the ambit of the PUC. It is within the prerogative of the DA to re-examine the PUC in an SSR investigation.
  - b. The DI does not manufacture any resin by emulsion process but only by suspension and micro-suspension process. Since resin manufactured by suspension process is admittedly out of the scope of PUC, what remains is only resin manufactured by micro-suspension process and not by emulsion process. DI is confusing the authorities by coining multiple names for the same products i.e. emulsion grade and paste resin.
  - c. The goods produced by petitioner are only a small sub set of products in respect of which duty is sought to be continued. Domestic industry manufactures only grades 124 (K Value 65), 120 (K Value 68) and 121 (K Value 77). None of the grades manufactured by Domestic Industry qualify as low fogging resin. In the specification sections of products, Chemplast does not talk about fogging properties at all.
  - d. Domestic industry itself on its website and also in its petition and through its product catalogue depicts that different grades of PVC paste resin manufactured by it has different properties and they are suitable for different uses and one grade cannot be substituted for another grade. Domestic industry itself sells these grades at different prices. This in itself a sufficient proof which DI cannot dispute that different grades are distinct products and they are technically and commercially not substitute of each other.
  - e. Domestic industry does not manufacture (1) PVC paste resin of High K Value and (2) PVC paste resin of low fogging especially for the automotive application.
  - f. leather cloth manufactured with resins manufactured by Chemplast has never passed the Fog test. All the grades of Chemplast resin have been found to be failing on fogging test and are nowhere near the standards as huge oil droplets are formed on the glass plates & hence not suitable for automotive Industry at all. It is therefore essential for LCPMA members that PVC resin with LOW FOG property has to be imported, without which the domestic supply to the entire automotive industry will come to a standstill.
  - g. Comparison with special grades like 373 ND and 375 MD imported from EU will clearly show that the subject goods produced by Chemplast are not like article to the specialty grades like 373 ND and 375 MD imported from subject countries including EU and there is no justification for allowing low fogging grades within the scope of PUC and ambit of anti dumping duties. The Authority may note that the price variance in specialty grade and the general purpose PVC has been in the range of 20% to 28% this alone shows there is no justification for continued consideration of these grades in the PUC bucket. The Low Fog resins for automotive application in particular imported are neither technically nor commercially substitutable to the PVC grades produced by the domestic industry and Low Fog resins needs to be excluded from the scope of PUC.
  - h. The domestic Industry is manufacturing non plasticized PVC paste resin of K-value between 65 and 77 as evident from their own product catalogue. Further domestic industry is clearing its products under 39042110 and no other classification. Therefore for the purposes of review PUC should be non plasticized PVC paste resin of K-value between 65 and 77 falling under CTH 39042110.
  - i. The Automotive companies have adopted an international standard SAE J- 1756 to test the fogging property. The paste resin manufactured by the Domestic Industry fails all fogging tests and unsuitable to meet the specific requirements of the automotive manufacturers. Request made to compare the same with special grades from EU.
  - j. The DI is manufacturing non-plasticized PVC paste resin of K-value between 65 and 77. High K-value resin cannot be substituted by a low K-value resin. PVC paste resin of K-value higher than 77 should be excluded from PUC.

- k. Members of LCPMA cannot execute orders of leather cloth with specifications using the PVC paste resin manufactured by the DI.
- l. Orders for High K-value, low fogging paste resin were placed by members of LCPMA with the DI post-POI as well as before whom the DI was unable to supply. We have tried to manufacture the leather cloth with the grades supplied by DI and with the grades imported and got it tested. The one in which top coat is made with imported PVC of higher K value with low fogging passes the test and the one in which top coat is made with Chemplast PVC Resin fails the test.
- m. It the discretion of the Authority, let the testing be done by any recognised and independent agency of Authority's choice by giving emphasis to a correct sample testing process right from sample collection to credibility and facilities available with the testing agency to carry out the required tests. We are also ready to bear the expenses for such testing.
- n. LCPMA members have placed orders for supply of (1) PVC paste resin of High K Value and (2) PVC paste resin of low fog which Chemplast is unable to supply and has not responded till date. It is already explained that LCPMA members cannot execute the orders for automotive industry with the existing graders manufactured by Chemplast and thus are constrained to import.
- o. DI should be asked to provide K-value wise production and sale details as the interested parties are unaware of the grades the DI can actually manufacture and sell.
- p. Minuscule requirements or lack of commercial volume is not an argument against supply of certain grades. Admittedly the demand for specialty grades is minuscule, but the same is substantial for the downstream users.
- q. The product manufactured by domestic industry is not like article to imported products.
- r. There is a need to review the scope of PUC as there is no justification for continued inclusion of High K Value resins and Low Fogging resins in particular for the auto motive sector from the scope of PUC which are not manufactured and supplied by the DI. DI tried to mislead the Authority by equating test of volatility to low fogging test when the resin produced by the DI could never pass the low fogging test and unfortunately the test conducted at IIT Delhi also talked about volatility and not low fogging properties. Thus, there is a case for reconsideration of scope of PUC and there is nothing in the Rule bars such a consideration by the Authority.
- s. Volatility test and low fogging test are not the one and the same. Low fogging test is a different test all together as per international standards prescribed for automobile interiors and Delhi IIT did not even have the facility to test low fogging property.
- t. A verification visit was undertaken to the premises of one of the users/importers i.e. MayurUniquoters, in Jaipur on 09-10 April, 2016 to verify the data/basis of their submissions. It was reiterated that the volatility content and fog property of PVC resin are two different properties and it cannot be concluded that PVC resin with volatile content less than 0.5% has low fogging characteristics. Further it was mentioned that different grades of PVC having different K volumes are used in coating of different layers in footwear, automatic and general applications. There are no known additives which can change K volume or fog characteristics. If plasticizer added to PVC paste resin is reduced to increase K value, it also reduces elongation/flexibility.
- u. The Trade Representation of the Russian Federation in the Republic of India submitted that there is no import of the product under consideration from Russia into India during the period of investigation from 2011 to 2014. There were two companies producing the subject goods in Russia namely "JSC Chimprom", Volgograd and "Usolyechimprom Ltd." Only the latter company dispatched the subject goods to India. Both companies have terminated their commercial activity in 2009 and 2014 respectively. Therefore, there is irrelevance of findings on Russian capacities of PVC production, as companies in Russia related to the production and export of the PVC products covered by the subheading 3904; however the only subject of investigation is the PVC Paste/Emulsion Resin, so the findings on capacities could be misleading and lead to incorrect conclusions on possibility of resumption of shipments of subject goods into India market. Russian producers of PVC suspension Resin, which is beyond the scope of the present investigation, are mainly focused on markets of CIS region, Middle East, the European Union, Africa.

## C.2 Views of Domestic Industry

- 14. The domestic industry has made the following submissions with regard to the issue of the product under consideration
  - a. Since the present investigation is an SSR, the scope of the PUC is the same as that of original investigations.
  - b. PVC resin is broadly classified into two categories – PVC Paste Resin and PVC Suspension Resin. PVC Paste Resin is produced from Vinyl Chloride Monomer (VCM). The PUC is produced and sold in the form of white/off-white powder. It is offered in different grades by the DI and foreign producers which merely differ in terms of the associated properties, which are achieved through control on process parameters and use of

specified additives. These different grades do not mean different products. All grades of PVC Paste Resin are within the scope of product under consideration.

- c. The goods produced by DI are like article to the goods imported from subject countries. There is no material difference in the production process employed by the foreign producers and that employed by DI. However, every manufacturer fine-tunes its production process as per the necessities and available facilities.
- d. DI manufactures the subject goods having a K-value as low as 61 and as high as 85 which is evidenced by the product brochures. After the due verification, the Authority concluded in the previous investigations that DI is capable of producing high, low and medium K value of PUC.
- e. After testing the volatile content of the PUC produced by DI and those imported by the user association, LCPMA at IIT Delhi, the Authority concluded that both of them have similar volatile content. Further, internal lab tests conducted by DI showed that the sampled PUC manufactured by DI had K-values as low as 61 with a maximum of 82. Therefore, DI can produce a wide range of subject goods having extremely varying K-values.
- f. DA has consistently adopted the same scope of PUC in the SSR investigations unless strong reasons for modifications are put forth by the interested parties along with credible evidence to substantiate the same. In the instant case, there have been four investigations with the same PUC. Therefore unless the opposing interested parties brings out credible evidences apart from those which the Authority has already examined in the previous investigations, the claim of modification of scope of PUC cannot be accepted. Nothing new has been brought out by the interested parties so there is no reason for altering the determination earlier reached.
- g. The difference in manufacturing process does not render two products produced through two different processes as two different articles. The resin produced by DI using its process and resin produced by emulsion process are interchangeably used. PVC Paste resin that can be manufactured by either Emulsion Process or Micro suspension process is the PUC for the present investigation. Hence, PVC resin is also called as Emulsion resin or Micro suspension resin or Dispersion resin. That the same product is called by 4 different names does not make it four different products.
- h. The grades manufactured by DI include 120, 121, 123, 124 and 128. The DA has examined about low fogging application in the earlier investigation and held that the grades manufactured by DI qualify as low fogging resin.
- i. The PUC comprises of a number of product types which varies significantly in terms of associated properties. There is no requirement under the WTO Agreements or in Indian Laws that the PUC must be an internally homogenous product. The PUC can have various types, grades or forms, which differ significantly in terms of associated costs and prices. Different grades/ form/type of the product do not mean different products. Different grades of a product are alike as far as their essential physical and technical characteristics are concerned. They are also alike as far as their functions and uses are concerned. The fact that different product types are meant for different end applications does not mean that they constitute different article, particularly when different types of product perform the same functions.
- j. Repeated investigation has shown that the goods supplied by DI are like article to the imported products.
- k. DI has never declined supply of PUC if the orders are placed on a regular basis. If the demand for the PUC is so minuscule and pertinent, the consumers can import the product. There is no ban on imports.

### C.3 Examination of the Authority

- 15. The Authority notes the submissions made and holds that product under consideration is ‘Poly Vinyl Chloride Paste Resin’ also called “Emulsion PVC Resin” and referred to as PVC paste resin (hereinafter also referred to as the subject product or the subject goods). There are primarily two types of PVC resins, namely PVC Paste Resin and PVC Suspension Resin. All grades of Poly Vinyl Chloride Paste Resin”, also called “Emulsion PVC Resin” and referred to as PVC paste resin is subject matter of present investigation and are within the scope of product under consideration. However PVC Suspension Resin, PVC Blending Resin, co-polymers of the PVC Paste Resin and Battery Separator Resins are excluded from the ambit and scope of this investigation as per the product under consideration in the original findings.
- 16. With regard to paste resin and emulsion resin being different products, it is noted that PVC Paste/Emulsion Resin can be produced through two processes i.e. micro suspension and emulsion polymerisation. While, the goods produced through these two processes are the same, there are some differences in the physical and chemical characteristics of different grades. The assumption that the scope of the product under consideration is restricted to PVC Paste Resin produced through a particular process is not correct. The PVC paste resin can though be produced through two different processes, the same does not imply that resultant product is different from the considered product under consideration. The domestic industry produces the subject goods by adopting the micro suspension process. The difference in the process employed does not lead to different products, unless the resultant grades of

products themselves differ in terms of essential product properties. It is possible that each producer may have its own process to manufacture the product; but the difference in the production process would be immaterial as long as the resultant product's (comprising of various grades) properties for various grades are the same. In view of the same, the Authority holds that both PVC paste and PVC emulsion resin are covered in the scope of the product under consideration in the present investigations and both are within the scope of the product under consideration and measures. The aspect of variation in properties at grade level are appropriately considered while undertaking comparison for assessment of dumping and injury as feasible.

17. With regard to the contention of LCPMA that none of the grades manufactured by Domestic Industry qualify as low fogging resin, the matter was examined in the previous investigations and after taking into account the contention of the various interested parties comprising of domestic industry and LCPMA, it was earlier decided by the Designated Authority to examine their samples by IIT Delhi especially about the fact whether the domestic industry makes products belonging to K value higher than 78 and also if their products have low fogging characteristics.
18. Both the parties were asked to send the samples and based on sample results which was duly conveyed to both the parties, it was noted by the Designated Authority in the previous investigation that after examination of samples reports (including the conclusions given by the above institution) that domestic industry samples of subject goods included PVC paste resin carrying higher K value ( of more than 78) while none of the samples of the LCPMA had K values higher than 78, and all the samples (from both parties) had low fogging characteristics.
19. In view of the above, the Authority held in the previous investigation that the contention of LCPMA that the domestic industry does not produce those grades of PVC paste resin having K value above 78 and low fogging characteristics is not correct. IIT Delhi through its test results and further clarification confirmed that the domestic industry has produced those grades of PVC paste resin having low fogging characteristics and K value above 78.
20. The contending parties have argued that test of volatility and fogging are different tests and that the test done by IIT Delhi did not test the low fogging property. They have further contended that despite anti dumping duty, the users continue to import low fogging grade of product under consideration from European Union by paying anti dumping duty at much higher prices as this grade required as per specifications of automotive sector are not produced by the domestic industry. In this regard, test reports by producers in European Union of such grades have been submitted.
21. The Authority notes that the domestic industry has submitted internal lab tests conducted by the domestic industry in the month of December 2015 to show that the sampled subject goods manufactured by the Domestic Industry had K-values as low as 61 with a maximum of 82.
22. As no new findings of IIT Delhi modifying its earlier reports were brought by the opposing interested party to the Designated Authority, the Authority has not considered the claim of the interested parties to exclude PVC paste resin having K value above 78 and low fogging characteristics from the scope of the product under consideration. However, keeping in view that different intrinsic properties of a grade cannot be altered by a user by certain additives like plasticizer etc., a grade to grade comparison appears appropriate.
23. Regarding claim made that the domestic industry itself on its website through its product catalogue depicts that different grades of PVC paste resin manufactured by it has different properties and they are suitable for different uses; the Authority, on a perusal of the copies of the catalogues of three PVC paste resin grades, namely, 120, 121 and 124 being produced by M/s. ChemplastSanmar Limited, notes that the catalogues show that all the three grades are suitable for manufacturing leather cloth. Though these different grades have different properties but they do not constitute different articles within the meaning of Section 9A(1). It is therefore confirmed that the three grades differ in terms of associated technical (chemical/ physical) values of the product properties with the three grades being part of the basic product. The Authority notes that difference in associated values does not render them different articles from the product under consideration though specific properties of different grades make the usage more conducive for a particular type of application. It therefore merely implies a different form of an article. The Authority notes in this regard that different article within the meaning of Section 9A(1) implies distinctly different product characteristics, manufacturing process, production technology, functions & uses. Therefore, different forms of an article do not for the purposes of Section 9A(1) imply different articles though there are variations in technical properties at the form/ grade level. Hence, the Authority holds that the contention of LCPMA that the three grades are three different articles within the meaning of Section 9A(1) is inappropriate, and all forms/ grades of the product under consideration are within the scope of investigation.
24. As regards custom classification, it is noted that in a situation where the product under consideration does not have dedicated customs classification, the Authority considers that it is necessary to provide wider scope of the HS code in order to ensure that the imports of the product under consideration are appropriately subjected to anti dumping duty and the anti dumping duty is not evaded by merely specifying the HS code. It is however clarified that this does not imply that any import reported under that HS code shall be subjected to anti dumping duty merely because the HS code has been specified under anti dumping duty table. For sake of abundant caution, it is clarified that anti dumping duty being recommended is on the product description and not on HS classification. Any imports of a product not within the scope of the product under consideration should not be subjected to anti dumping duty merely

because the HS code has been specified under duty table. It was noted that product under consideration is imported under more than one customs subhead (8 digit). Having regard to the evidence on record, information provided by the interested parties, scope of the product under consideration in the present case and objective of specifying the HS codes, and in particular considering that the product under consideration does not have a dedicated HS code in the present case and is being imported under different ITC HS codes, the Authority has recommended anti dumping duty on imports of product under consideration falling under customs classification 3904.

25. In order to determine whether goods produced by the domestic industry in various grades can be considered like article to the goods produced and/or exported from the subject countries of various grades, it is noted that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and exported from subject countries in terms of physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable, with the consumers using the two interchangeably at various grades level. The Authority, therefore holds that the subject goods produced by the domestic industry is like article to that imported or produced in subject countries within the meaning of the Rules.

#### **D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

##### **D.1 Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties**

26. None of the parties raised any submissions with regard to domestic industry.

##### **D.2 Views of domestic industry**

27. Following submissions have been made by the domestic industry
  - a. The petition had been filed by ChemplastSanmar Limited. Apart from the Petitioner there is one more producer of PVC Paste Resin in India, i.e. M/s Finolex Industries Limited.
  - b. Petitioner Company has neither imported nor is related to any exporter/producers of subject goods in subject countries or importers in India.
  - c. Production of the Petitioner constitutes a major proportion in Indian production; domestic production of the petitioner account for significantly more than 50 percent of total Indian production of the like product; and the application has been made by or on behalf of the domestic industry. Further, the petitioner company constitutes “domestic industry” within the meaning of the Anti-Dumping Rules.

##### **D.3 Examination of the Authority**

28. The application for the sunset review has been filed by M/s. ChemplastSanmar Limited. There is one more producer namely M/s Finolex Industries Limited, of the subject product in India. As per the information available, the petitioner company is not related (neither directly nor indirectly) to any exporter in the subject countries or importer of product under consideration in India. The petitioner has not imported the subject goods from subject countries during period of investigation.
29. The Authority after examining the information on record has determined that the petitioner company constitutes domestic industry within the meaning of the Rule 2(b) and the petition satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

#### **E. Other Issues**

##### **E.1 Submissions made by the Exporters/Importers/ users/ other Interested Parties/ other parties**

30. Following submissions have been made by the exporters/importers/users/other interested parties/ other parties
  - a. Previous findings show that in one of the Findings DGAD concluded that there are two producers/exporters from Korea RP and when both of them were found not to be dumping or causing injury to the Domestic Industry, investigation against Korea was terminated. On the contrary with same facts, investigation against Korea RP was not terminated despite the fact all exports from Korea RP were found undumped.
  - b. Findings issued in the original investigation clearly shows that three exporters of subject goods were found not to be dumping. Further all exports from Korea RP and Taiwan were established to be un-dumped. The Designated Authority should have terminated investigation against these three exporters and should have been excluded them specifically from the scope of the present investigation.
  - c. In *Mexico-Anti-Dumping Measures on Rice*, the Appellate Body rejected Mexico’s argument that Article 5.8 requires the termination of the investigation only when the “country-wide margin of dumping” is *de minimis*, and confirmed the Panel’s view that the term “margin of dumping” in Article 5.8 refers to the individual margin of dumping of an exporter or producer rather than to a country-wide margin of dumping, to be consistent with the use of the term “margins of dumping” in Article 2.4.2.

- d. Inclusion of exporters of subject goods from Korea RP and Taiwan, who were found not dumping during the original investigation should not have been included in the present Sunset Review investigation and these exporters should be excluded from the present Sunset Review investigation.
- e. The Designated Authority must examine the fact that in case the existing Anti-dumping Duty ceases to exist. This presupposes existence of Anti-dumping Duty. In case there is no Anti-dumping Duty in respect of some exporters no clause of cessation can be made applicable to them. The level of test of likelihood of recurrence of dumping and injury to these exporters should be different from those exporters who were found to be dumping in the original investigation.
- f. Imports by HCC should not be a part of the current SSR investigations as the zero quantum of duty was recommended for the exporter in the previous investigation. Reliance was placed on Appellate Body report in Mexico – Beef and Rice and Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1975.
- g. Volume of imports of Hanwha should be excluded from the purpose of examination in the current investigation due to determination of de minimis dumping margin in the previous investigation. Therefore, there is no likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.
- h. The DI to cover their claim of excessive confidentiality has been raising a counter allegation.
- i. The most appropriate form of duty, if any is recommended to be continued, is bench mark price in terms of Indian Rupees and no other basis as there are different grades out of which some are not manufactured by the Domestic Industry.
- j. Anti-Dumping Duty, if any, may be calculated on ad-valoram basis as % of the import price like customs duty to take care in the volatility in crude and exchange rate and register our opposition to any other form of duty which will render our survival itself very fragile.

## **E.2 Submissions made by Domestic Industry**

- 31. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing and scope of the domestic industry
  - a. Non-confidential version of questionnaire responses is grossly inadequate. Even information that is publicly available has not been disclosed. Further the interested parties have not filed proper and sufficient non confidential summary of the information claimed confidential. Blank formats have been given which is in direct violation to principles of natural justice.
  - b. Any claim to treat the information as confidential must be *bona fide* and germane to the rights and legitimate interests of the party.
  - c. The CESTAT stated that DA is not required to mechanically treat the information provided by a party as confidential merely because that party has desired it to be kept confidential. The rules confer discretion upon DA to consider the request for confidentiality made by a party and if it is satisfied that the same is not warranted or that the supplier of the information is unwilling to make information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.
  - d. LCPMA is the association of PVC Resin consumers and importers. It claimed to be an interested party in the current investigation. The user association has filed its submissions however, apart from two of its members; none of the members of the user association has filed any QR. The notice of initiation provides opportunities to interested parties to provide relevant information to the Designated Authority. The Association has not provided any information" whatsoever with regard to the present investigations.
  - e. Only two importer questionnaires were received in the current investigation and no other members of the importer association filed responses. Thus, to qualify as an interested party, members of the LCPMA were required to file separate questionnaire responses which they have failed to do.
  - f. Formosa Plastics, LG Chem and Hanwha Chemicals have been repeatedly investigated by DA for different products and it has been found that DM in their exports is de-minimus. The products investigated are such that no producer is able to fetch a price materially different from other suppliers in Indian market. Thus, even when DA found significant DM in respect of exports made by other exporters in these products, the DA found that the DM is de-minimus. However, other investigating authorities such as China and Australia have found positive DM in respect of their exports.
  - g. Repeated instances of no dumping by these companies across the products imply that these companies pricing policy is to sell the product at one price, regardless of the market. Further, this is not for selling price, this is for ex-factory realization to the exporters after making of the adjustments. This is highly impossible situation and clearly points at grossly manipulated QR.

- h. The product is attracting fixed quantum of ADD at present in case of Europe, where ADD was earlier imposed in the form of benchmark price and was later modified to fixed duty in review. The WTO Agreement on AD explicitly permit authorities to impose ADD in the form and manner requested.
- i. The interested parties are comparing the Final Findings of 2004 with that of 2011. There is a long gap between the two findings and therefore the situation between the periods may have undergone a change. The exporters had a right to demand termination at the time of original investigation and thereafter had a right of statutory appeal. Having lost those opportunities, the exporters cannot now raise these concerns.
- j. India by practice does not conduct partial interim review or expedited sunset reviews. The midterm or sunset reviews conducted in India focuses on existence, degree and effect of dumping. It must be noted that the investigation process that is being undertaken by the DA is substantially different from other WTO member countries' practices. Further, despite no obligation, the DA examines and renders elaborate findings on parameters such as injury and causal link.
- k. It was earlier challenged before the DA and thereafter CESTAT that MTR is limited to withdrawal or reduction of ADD whereas scope of SSR is limited to mere extension to ADD. However, it was finally held that the DA is entitled to enhance the ADD in a MTR or SSR. Also, the DA conducts NSR, the scope of which is limited to determination of DM and therefore the DA recommends ADD to the extent of DM in NSR and does not even determine the IM. However the administrative review, the partial interim review and the SSR conducted by the US investigating authorities may not involve all the requirements laid down under Article 2 & 3 of the WTO Agreement.
- l. The petition filed by DI was based on actual dumping during POI and actual injury to the DI during POI. The petition in case of Korea and Taiwan was based on actual dumping margin and actual material injury and further since the Authority is undertaking full investigation in respect of these imports consistent with requirements of Article 2 & 3 of the Agreement, it follows that the DA is fully entitled to recommend duties in respect of exempted companies from Korea and Taiwan.
- m. The domestic industry has determined positive dumping margin with regard to exports by Hanwha.
- n. Klassik should have exercised its right to seek a review or right to participate in the present investigation rather than making abusive statements. The party should in fact be declared as non cooperative importer.
- o. DA issued a public notice and invited submissions from various parties. Nothing prevented the company for filing the submissions. Any party in India is free to file any kind of submissions. Also, the Authority provided adequate opportunity at the stage of initiation but the party preferred not to participate. The intention of party is clearly to hamper the process of investigation so no additional time should be given to such parties for filing QR.
- p. The consumers are not going to be adversely impacted by imposition of duty. In the context of safeguard duty on DOP, the DG (safeguards) has investigated the impact of increase in price of DOP on the downstream industry and has concluded that the impact shall be negligible. Given that DOP and paste resin are consumed together, the conclusion drawn by the DG holds good for PUC as well. Also, the ADD merely addresses a practice of dumping which has caused injury to DI and so its impact on the consumer is not required to be determined.
- q. Any producer is free to source the material from any party they wish to. The Authority has repeatedly held that the purpose of ADD is to eliminate injury caused to DI by the unfair trade practices of dumping to re-establish open and fair competition in the Indian market. Imposition of AD measures would not restrict imports from the subject countries.

### **E.3 Examination of Authority**

- 32. The Authority has noted the submissions made by the domestic industry and interested parties and these issues have been examined under appropriate headings in this disclosure statement in accordance with the Rules.
- 33. The Authority notes that LCPMA, as an association of the Leather Cloth manufacturers, has made certain arguments in respect of various aspects of the investigation. Being a body representing the users of the product under consideration who are also importers of the subject goods, the association could have provided very useful information on entire imports to help the Authority in making its determination based on facts. However, notwithstanding the fact, in the interest of fairness and transparency, LCPMA's submission with regard to the other aspects of the investigation examined along with the arguments made by other interested parties and have been addressed in these findings to the extent they are relevant with appropriate evidence.
- 34. The Authority holds that the purpose of imposing anti-dumping duties irrespective of demand-supply situation or number of domestic producers, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade

practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

35. Some of the interested parties have raised the issue that those producers/exporters from the subject countries that were awarded zero duty in the original investigation should be excluded from the scope of these review investigations in view of the findings in WTO Appellate Body report Mexico-Beef and Rice. The domestic industry has contended that these producer/exporters cannot be excluded from the scope of the review. They have further contended that in India the sunset review includes a complete recalculation of the dumping and injury margins.

36. With regard to initiation notification, it is noted that the Authority initiated the investigation to review the need for continuation as well as to examine the request of domestic industry for enhancement of anti-dumping duties, in force. It is a consistent practice of the Authority to review all the aspects of the original investigation including scope of the domestic industry, dumping (including dumping margin), existence of injury to the domestic industry, injury margin. In addition to this, the Authority undertakes an examination of whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. Interested parties can raise issues on any aspect with respect to any aspect of the case, including the existence of dumping, dumping margin, material injury to the domestic industry, injury margin, likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of revocation of duties, and causal link between the dumped imports and the injury to the domestic industry. During determination, the Authority considers whether a modification in the form of measures is required.

37. The domestic industry has claimed that Exporters which were awarded zero duty in the original investigation should not be excluded from the sunset review as India by practice conducts full midterm and full sunset reviews which focus on existence, degree and effect of dumping and the Authority determines dumping margin in respect of actual exports, and dumping margin and injury margin are calculated on the same lines as is done in the original investigations. The duty is varied depending on dumping margin and injury margin determined during the review period. It has also been contended by the petitioner that the petition in case of Korea and Taiwan is based on actual dumping and actual material injury and further since the Authority is undertaking full investigation in respect of these imports consistent with requirements of Article 2 & 3 of the Agreement, it follows that the Authority is entitled to recommend duties in respect of these companies. On the other hand, it has been contended by the other interested parties comprising exporters and importers that in case the dumping and injury does not exist, it cannot continue or recur. It has also been contended by them that in the original investigation carried out by the Authority, it was found that the three Exporters i.e. Hanwha Chemical Corporation Korea RP, LG Chem Korea RP and Formosa Plastic Corporation, Taiwan, were not dumping or causing injury to the domestic industry and these exporters should not come in the preview of present sunset review as investigations should have been terminated against them during original investigations. It has also been contended by them that the level of test of likelihood of recurrence of dumping and injury to these exporters should be different from those exporters who were found to be dumping in the original investigation.

38. The matter has been examined and it is noted that the WTO Appellate Body clarified in its report that Article 5.8 of the WTO ADA requires an investigative Authority to terminate the investigation in respect of an exporter found to have a de minimis margin in an original investigation and that the exporter consequently must be excluded from definitive anti-dumping measures and such exporters cannot be subject to administrative and changed circumstances reviews. The Authority notes that where an exporter awarded zero duty in an original investigation is found to be dumping and the same is found to be causing injury to the domestic industry, then duties must be imposed considering the dumping margin and injury margin found in the present review investigation period. Since the WTO Agreement on anti dumping (ADA) allows WTO members to impose duties to counteract dumping which is injuring the domestic industry, the Appellate Body decision in the aforementioned report needs to be construed as not permitting imposition of anti dumping duty on such exporters without a positive finding of dumping within the meaning of Article 2 of the ADA and injury to the domestic industry within the meaning of Article 3 of the ADA. Therefore, so long as the Authority has followed the relevant requirements of Article 2 and Article 3 of the ADA, even when the present investigation is a sunset review investigation, it is appropriate to recommend anti dumping duty on such exporters after following the requirements of Article 2 and 3 of ADA and by determining individual dumping margin and injury margin for the such exporters who are attracting zero anti-dumping.

39. Therefore, after examining the contentions of various interested parties it is held that it has been the practice of the Authority to conduct full investigation including determination of dumping margin injury and injury margin in respect of all the cooperating exporters including those who were earlier awarded de-minimis dumping margin or whose injury margin was negative. It is also noted that in those situations where the exporters were earlier awarded de-minimis dumping margin and have now been found to have de-minimis dumping margin or whose injury margin is negative, it is concluded that exports made by these companies are unlikely to be dumped and injure the domestic industry. Further, in those situations, where the dumping margin was de-minimis earlier, the Authority has considered the dumping margin now determined, for the purpose of likelihood of dumping and injury in the event of revocation of anti-dumping duty.

40. As regards confidentiality; the Authority notes that information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim as per its consistent practice and AD Rules. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
41. As regards the form, quantum and currency denomination of the anti dumping duty, the Authority has followed its consistent practice in fixing appropriate level of the duty in US\$ terms.

#### **F. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN**

##### **F.1 Submissions made by exporters, importers and other interested parties/ other parties**

42. Following submissions have been made by the exporters, importers and other interested parties/ other parties with regard to normal value, export price and dumping margin
  - a. The petitioner has treated even dumping margin as confidential.
  - b. Designated Authority should not take cognizance of the studies in various countries to ascertain the prices of the subject goods which are doctored and made to suit the requirements of the customer.
  - c. Domestic Industry has claimed different domestic prices of PVC Paste Resin in Korea RP for the same period. Even prices from same source differ. Study conducted by Domestic Industry shows prices almost 73% higher than what has been claimed to be issued by Harriman Chemsult. Even Harriman Consult has reported two different prices for the same period and variation is almost 20. Domestic Industry appear to be fabricated, concocted, manipulated and has been prepared to claim high dumping margins.
  - d. DI has not provided copies of report issued by Harriman Chemsult which is in violation of Trade Notice No. 1/2013 dated 9<sup>th</sup> Dec. 2013. Report relied upon by Domestic Industry is sourced from a private consulting firm. This report is publically available and can be obtained by any party after payment of fee. Under such circumstances Domestic Industry should be asked to provide copies of Report issued by Harriman to us so that we may file our comments on the same.
  - e. VCM and PVC Paste Resin prices in Europe as mentioned in the petition are unreliable. As per the petition VCM in Europe almost 50% higher than what has been appearing in rest of the world. In case domestic market in Europe is fetching almost 70% higher prices of PVS paste than rest of the world, all producer would like to sell the goods to Europe. There appears to be basic flaw in the claims of the Domestic Industry with regard to cost of VCM and domestic prices in exporting countries
  - f. Claims of the Domestic Industry with regard to dumping from subject countries is baseless inflated and needs to be rejected.
  - g. Claims of the Domestic Industry with regard to dumping from LG Chem Ltd., are baseless inflated and needs to be rejected.
  - h. Even though Hanwha Corporation is involved in the exports to India, it is only involved in handling invoices for HCC and receives commission for handling service. HWC has no role as a trading company for the export sales to India.
  - i. Hanwha Corporation does not purchase the product under investigation from Hanwha Chemical Corporation nor resell it to customer. It means Hanwha Corporation does not have any role as a trading company for the export sales to India.
  - j. Out of 74 exports transaction, only 16 transactions were made through HWC against the payment of handling charges. Further, out of 5305 MT of exports to India, 995 MT was sold through HWC, which is less than 20% of the total subject goods exported to India during POI. No exports were made through HWC after May' 2014
  - k. In the recent sunset review finding of PVC Suspension resin, all the transaction of exports to India by HCC were made through HWC and this view was of joint submission was well accepted the Authority.
  - l. HCC records the inventory movement between the factories as transfer-in and transfer-out in its inventory ledger. The value is calculated by the weighted average unit price of beginning value and production value.
  - m. No deficiency letter received from the Authority by HCC. Since more than 7 months have elapsed, the company presume that the information is complete.

- n. DI have claimed exorbitant levels of dumping margins which shows there are fallacies in the claim of normal value, export price and the method of comparison. Dumping margins should be based on the data filed by the exporters and not otherwise.
- o. The cumulative assessment in regard to Russian import is unreasonable, as imports from Russia is insignificant and dumping margin de minimis. Such grounds as de minimis dumping margin and insignificance of import are usually a sufficient warranty for termination of investigation in regard of a subject country or for repealing the measure on goods originating from that country (ex: EU Council Regulation 1279/2007 on repealing the anti-dumping measures on certain iron and steel ropes and cables originating in Thailand and Turkey).

#### **F.2 Submissions made by Domestic Industry**

- 43. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing and scope of the domestic industry
  - a. China is a non-market economy. It has been treated so by European Union and United States in the past. No country has granted market economy country status to China after following detailed evaluation procedure and examination. In India also, the Designated Authority has treated China as non-market economy. The Designated Authority has treated China as non-market economy in practically all the investigations initiated against China after the amendment dated 31<sup>st</sup> May, 2002.
  - b. AD Rules have prescribed certain conditions that have to be satisfied in order to establish the claim of market economy treatment. Each and every condition must be fulfilled by an intending exporter in order to claim market economy treatment.
  - c. In the present case, Normal Value cannot be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available
  - d. Hanwha Chemicals (HCC) is not entitled for individual DM because they are not the exporter in the present case. The exporter in this case is Hanwha Corporation (HWC). Further, the response has stated that the commercial invoices in case of goods produced by HCC were issued by HWC so HWC is the exporter of PUC. So, individual DM cannot be assigned to HCC without QR of HWC.
  - e. HCC has claimed to have paid commission to HWC. If HWC is the exporter of the PUC, who has issued commercial invoice to Indian customers, there has to be sales and purchase transactions between HCC and HWC. There cannot be a commission in such cases. Commission to HWC could have been paid only when the commercial invoices for exports to India were issued by HCC and such sales were assisted by HWC. However, in the instant case, HWC has issued commercial invoice to Indian importers and therefore it must have purchased the goods from HCC and sold the same to Indian importers. In the final findings of SSR Investigation in PVC Suspension Grade from Taiwan, China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Malaysia, Thailand and USA, the Authority examined that HWC was raising invoice on Indian Exporters without purchasing the subject goods from HCC. However, during verification, it was found that the Korean customs authorities in that case named HWC as exporter and HCC as producer.
  - f. DI has referred to the prices quoted in the HarimanChemsult report for determining normal value of PUC in Korea RP and Europe. HarimanChemsult regularly reports the prices of PUC and such prices constitute reasonable, accurate and adequate information for determination of normal value. Therefore these prices may be considered for determination of normal value of Korea and Europe.
  - g. DI had earlier got a study done about the prices of PUC in the domestic market of Taiwan where they attempted to collect evidence of the prices in the domestic market of Taiwan. DI has been able to get the selling price in the domestic market of Taiwan for the period 2012-13. The petitioner has adjusted the VCM price for determination of normal value for the period of investigation.
  - h. Dumping margin has been determined considering the normal value and export price. The comparison made must be considered fair comparison. Both the normal value and export price have been determined at ex-factory level.
  - i. The normal value is determined on the basis of the cost of DI which is business sensitive information. So disclosure of DM would result in disclosure of normal value. Even the exporters have claimed information such as normal value and export price as confidential.
  - j. DI has sought protection only against dumped imports and ADD has been imposed only when the DA has found positive DM. In fact, DA did not recommend duty on exports made by number of companies in respect of Korea/Taiwan on finding that the DM is de-minimus.
  - k. DI has provided various methodologies for determination of normal value, study being one of them. All the methodologies proved dumping of PUC from subject countries. The study was used to determine normal value of Taiwan and Korea.

- i. The Authority applies prevailing exchange rates for the purpose of determination of DM and IM. The exchange rate would have protected DI and would have resulted in improvement in profitability. On the contrary, the profitability of DI has declined, which shows that DI is suffering from dumping.
- m. LG Chem, Korea and HCC, Korea have responded however, none has furnished information pertaining to related companies in other subject countries. HCC has a wholly owned subsidiary in China, Hanwha Chemical (Ningbo) Co. Ltd. which produces subject goods. Similarly, LG Chem has a subsidiary in China as well i.e. Tianjin LG DAGU Chemicals Co. Ltd. which also produces the subject goods. These producer/exporters have not filed QR in the present investigation. The current investigation being an SSR investigation, DA is required to determine whether cessation of ADD would lead to likely of dumping and injury to DI. Therefore, it is important for DA to determine likely dumping by an exporter. Even though the exporter has not exported PUC, it can be easily implied that this is due to ADD in force and in the event of cessation of ADD the exporter would in all likelihood resume its exports to India.
- n. Two conditions precedent must be satisfied before DA can adopt the cost of production on the basis of records maintained by the company. Such conditions precedent includes a major condition that such costs should reasonably reflect the costs associated with production and sale of PUC.
- o. None of the responding exporters have fully replied to the question with regard to valuation of VCM.
- p. Hanwa didn't provide information related to valuation of VCM and LG stated that they do not purchase inputs from any related parties. However, it is difficult to accept such response since the related party of LG namely Tianjin LG Bohai Chemicals Co Ltd, Chins is a manufacturer of VCM.
- q. VCM is a tradable commodity and hence every VCM and PVC producer has option to either convert VCM to PVC or sell in the market as VCM.
- r. There are vital defects in the QR and the exporter has cautiously decided not to provide relevant information. The DA is obliged to seek clarification only with regard to QR filed and if some minor clarifications are required. The opportunities for clarification or rectifying deficiencies cannot be used to file complete QR.
- s. The legal submissions are filed by both Hanwha Chemical Corporation (HCC) and Hanwha Corporation (HWC) however; the QR is only filed by Hanwha Chemical Corporation. HWC has no role as a trading company for the export sales to India. DI fails to understand that if the opposing interested party claims Hanwha Corporation as not a trader and only invoice handling agency then how it is being treated as an interested party to file written submissions. As HWC has not filed a QR but has filed WS clearly indicated the unwillingness of the party to provide information and therefore should be considered as non cooperative.

### **F.3 Examination of the Authority**

44. Under section 9A (1) (c) normal value in relation to an article means:
  - (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or
  - (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either
    - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
    - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);
45. The Authority sent questionnaires to the known exporters and importers from the subject countries, and India, advising them to provide information in the form and manner prescribed. However, barring below mentioned producers, exporters and related importers, none of the producer/exporter from subject countries and importers from India have co-operated in this investigation by filing their Questionnaires' responses. The questionnaire response has been filed by the following companies:
  - a. M/s LG Chem, Korea RP
  - b. M/s Hanwa Chemicals, Korea RP

## **DUMPING MARGIN DETERMINATION FOR PRODUCERS AND EXPORTERS FROM KOREA RP**

46. The Authority notes that the product under consideration i.e. PVC paste resin comprises of various grades which have technical characteristics to suit to different applications. The cost and price variation band amongst different grades of co-operative producers/exporters in Korea RP were noted to be in range of almost 15-20%. Since information on specific grades on cost and price exported to India and identical ones sold in domestic market were available and verified, a grade to grade comparison to evaluate dumping margin has been undertaken and adopted in case of cooperative producers/exporters.

### **LG CHEM LTD., KOREA RP**

47. M/s LG Chem Ltd., Korea RP, one of the producers/exporters of the subject goods has exported \*\*\* MT of 6 grades of the product under consideration during POI to India directly and \*\*\* MT through M/s Uniplas, UAE. As a separate response has not been filed by M/s Uniplas, UAE as an exporter of the subject goods, only direct exports of M/s LG Chem have been considered for individual determination.

48. Further PA1302 claimed as a grade of the subject goods sold in the domestic market and also exported to India has been excluded both from domestic and export sales as the same being a copolymer is not within the scope of the product under consideration.

#### **Normal value**

49. LG Chem Ltd., Korea RP has sold \*\*\* Kg (\*\*\* MT) of the subject goods during the POI in the domestic market, comprising of 15 grades, i.e. LK170, LP010F, LP090, LP170, LP170G, LP170L, LP170T, PB1120, PB1200, PB1202, PB1302, PB1752, PB900, PE1311 for a value of \*\*\* KRW. The total domestic sale of 6 grades of PUC exported to India is \*\*\* Kg (\*\*\* MT) for a value of \*\*\* KRW.

50. For computing the normal value, grade-wise, the sufficiency test is undertaken separately for all grades. The “ordinary course of trade” test has been carried out month-wise as well for grade to grade to determine the Normal Value of those 6 grades exported to India on the basis of grade wise cost of production. Wherever 80/20 test leads to less than 80% profitable sales, to calculate normal value only the profit making domestic sales have been considered or else the entire sales is considered if profitable transactions are more than 80%. The adjustments on account of freight expenses, credit expenses and packing expenses as verified have been considered. The weighted average adjustments considered are \*\*\* KRW/Kg, \*\*\* KRW/Kg and \*\*\* KRW/Kg respectively. The weighted average normal value of 6 grades has been computed as \*\*\* US\$/MT.

#### **Export Price**

51. M/s LG Chem Ltd. has exported \*\*\* Kg (\*\*\* MT) of subject goods of 6grades (LP170, LP170G, PB1202, PB1302, PB1752 and PE1311) to India during POI. PA 1302 (\*\*\* Kg), which is a Non-PUC has not been considered for the dumping margin and injury margin determination. Out of total exports to India by LG Chem Ltd., excluding grade PA 1302, \*\*\* MT has been exported to India through M/s Uniplas International Est, UAE, which constitutes 1.6 % of total exports of PUC to India. M/s Uniplas International Est, UAE, has not filed Exporters Questionnaire response and therefore only direct exports by M/s LG Chem Ltd., have been considered for individual dumping margin determination.

52. The CIF prices of the above 6 grades of the subject goods exported during POI in unit “US\$/MT” are \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, respectively, and weighted average CIF price is \*\*\* US\$/MT. The adjustments on account of Inland Freight, Ocean Freight, Credit Expenses, Bank Charges, Overseas Insurance, Customs Agent Fee and packing Expenses have been verified and adjusted. The ex- factory export price of the above six grades of the subject goods in “US\$/MT” comes \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, and \*\*\* respectively and the weighted average ex- factory export price is computed as \*\*\* US\$/MT.

#### **Dumping Margin**

53. The Authority notes that the product under consideration i.e. PVC paste resin comprises of various grades which have technical characteristics to suit to different applications. The cost and price variation band amongst different grades of co-operative producers/exporters in Korea were noted to be in range of 15-20 %. Since information on specific grades on cost and price exported to India and identical ones sold in domestic market were available and verified, a grade to grade comparison to evaluate dumping margin has been undertaken and adopted in case of cooperative producers/exporters. For residual/ non cooperative producers/exporters for Korea, the highest Normal Value as per cooperating producers/exporters response and least export price has been adopted.

54. The Dumping Margin for direct exports has been calculated grade-wise and month-wise on a transaction- to-transaction basis. The weighted average dumping margin has been computed as \*\*\* US\$/MT (\*\*\* %).

### **HANWHA CHEMICAL CORPORATION (HCC), KOREA RP**

#### **Normal Value**

55. M/s. Hanwa Chemical Corporation (HCC), the producer/exporter, during the POI has sold 12 grades of the subject goods i.e. (EL102, EL103, EM2070, EM3090, KH10, KH31, KH60, KL10, KL31, KL701, KM31 and KM60) in the domestic market for a total quantity of \*\*\* MT and value of \*\*\* KRW (US\$ \*\*\*). Out of these 12 grades i.e. 3 grades KH31, KL31 and EM3090 were exported to India for a total quantity of \*\*\* MT with a total CIF value of \*\*\* US\$ during POI. The producer/exporter provided grade wise cost of production (monthwise) for POI of all the 12 grades. The domestic sales of 3 grades exported to India meet the sufficiency test separately during the POI. The OCT has been carried out grade wise and month wise on the basis of the grade wise verified cost of production undertaken by the verification team. Wherever 80/20 test leads to less than 80% profitable sales, to calculate normal value only the profit making domestic sales have been considered or else the entire sales is considered if profitable transactions are more than 80%. The 'Normal Value' has thus been computed grade wise and month wise. Adjustments on Inland Freight, Credit Expense and Packing Cost claimed were verified and allowed. The weighted average Normal Value of the 3 grades exported to India comes to \*\*\*\$/MT (KH31), \*\*\*\$/MT (KL31) and \*\*\* \$/MT (EM3090) and the overall weighted average Normal Value being \*\*\* \$/MT.

#### **Ex-factory Export Price**

56. The Producer/ Exporters has exported \*\*\* MT of 3 grades KH 31, KL 31 and EM 3090 to India during POI at a CIF value of \*\*\* USD. Adjustments an account of commission paid to Hanwha corporation, Inland Freight, Ocean Freight, Marine Insurance, Handling Charges, Domestic brokerage bank Charges, credit expense & packing cost have been claimed. The CIF of the above 3 grades is \*\*\*, \*\* and \*\*\* \$/MT respectively. The ex-factory export price for the 3 grades is computed as \*\*\*, \*\* and \*\*\* \$/MT respectively. Out of the total \*\*\* MT exported to India during POI, for \*\*\* MT document handling services of Hanwha Corporation have been used on an agreed fixed handling charge. The same has been also considered for adjustment on export price to evaluate ex-factory export price. The weighted average ex-factory export price comes to \*\*\* \$/MT.

57. Dumping Margin the Authority has undertaken grade to grade comparison for evaluation of dumping margin on a monthly basis. The individual dumping margin for the 3 grades i.e. EM 3090, KH 31 and KL 31 is evaluated as \*\*\*, \*\*\* and \*\*\* \$/MT respectively. The weighted average Dumping Margin is computed at \*\*\* \$/MT (\*\*%).

#### **DUMPING MARGIN FOR NON- COOPERATING PRODUCERS AND EXPORTERS FROM KOREA RP**

58. For working out dumping margin in respect of subject goods for the residual producers and exporters from Korea RP, highest normal value and least export price as available from cooperative exporters from Korea RP have been adopted.

#### **DUMPING MARGIN DETERMINATION FOR PRODUCERS AND EXPORTERS FROM CHINA PR,**

#### **TAIWAN, MALAYSIA, THAILAND, RUSSIA AND EUROPEAN UNION**

##### **Normal Value**

59. **Para 7 of Annexure I of the AD Rules provides that**

*"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated Authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."*

60. The Authority notes that China has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the AD Rules. As per Paragraph 8 of Annexure I of the AD Rules, the presumption of a non-market economy can be rebutted, if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. The co-operating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Authority to consider the following criteria as to whether:

- the decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand

and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

- the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
- such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
- the exchange rate conversions are carried out at the market rate.

61. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption by treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting presumption of nonmarket economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested Government of China to advise the producers/exporters in their country to provide the relevant information. However, none of the Chinese producers/exporters have filed any response.

62. The Authority notes that consequent upon the initiation notice issued by the Authority, none of the Chinese companies have filed exporter's questionnaire response. Therefore, the Authority has not applied Para 8 of Annexure 1 to the Rules to the Chinese companies and has to proceed in accordance with Para 7 of Annexure- I to the Rules. According to these Rules, the normal value in China PR can be determined on any of the following basis:

- a. On the basis of the price in a market economy third country, or
- b. The constructed value in a market economy third country, or
- c. The price from such a third country to other countries, including India.
- d. If the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include reasonable profit margin.

63. The Authority notes that for determination of normal value based on third country cost and prices, the complete and exhaustive data on domestic sales or third country export sales, as well as cost of production and cooperation of such producers in third country is required. Since no information with regard prices and costs prevalent in these markets could be accessed and also the opposing interested parties have provided no information with regard to an appropriate market economy third country, the normal value in respect China PR has been worked out on other reasonable basis, in terms of second proviso of Para 7 of Annexure 1 to the Rules. Thus, the Authority has constructed the normal value for the product under consideration imported during the POI from all subject countries excluding Korea RP and excluding China PR as follows:

- (a) The best utilisation norm of the raw materials based on the best information available has been considered.
- (b) Cost of raw materials and utilities, i.e. power has been referenced on the basis of international prices available through secondary sources.
- (c) Conversion cost, SGA expenses and interest have been considered on the basis of the best information available.
- (d) 5% of cost of sales excluding interest has been allowed as a reasonable profit.

64. Accordingly, the Constructed Normal Value computed at ex-factory level for Taiwan, China PR, Malaysia, Thailand and Europe Union have been determined as \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT and \*\*\* US\$/MT respectively.

#### **Export Price**

65. As none of the exporters from any of the subject countries except Korea RP has provided any information that can be used for determination of the export price, the Authority has determined the export prices for all exporters from these subject countries on the basis of CIF price of imports into India as per DGCI&S. Accordingly, export prices from the China PR are have been calculated on the basis of CIF price of product with applicable adjustments for Ocean freight, Marine insurance, Port expenses, Inland transportation and Bank Charges, have been made to arrive at the ex-factory export price. Accordingly, the net export price for Taiwan, China PR, Malaysia, Thailand and Europe Union are determined as \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT and \*\*\* US\$/MT respectively.

66. Since none of the producers/exporters from these subject countries has responded by filing the questionnaire response and no grade wise information is available, the Authority does not find it feasible to undertake grade to grade comparison and therefore has not undertaken the same for comparison and evaluation of Dumping/Injury margin and

therefore has adopted a weighted average approach by adopting constructed Normal Value and ex- factory export price evaluated as per DGCI&S data as mentioned in concerned paragraphs.

67. The Authority further notes that there have been no imports of the subject goods from Russia during POI and even Post POI. M/s. RusVinyl, Russia and the Government of Russia have submitted the same and mentioned that subject goods in Russia are being largely catered to their domestic market and exports to India is very limited. Thus dumping margin for Russia has been treated as de minimis.

#### **Determination of Dumping Margin**

68. Considering the normal values and net export prices as determined above, the dumping margins have been determined as follows:

Countries	Producer	Exporter	Dumping Margin US\$/MT	Dumping Margin in %	Dumping Margin in % Range
Korea RP	LG Chem	LG Chem	***	***	-(0-5)
	LG Chem	Any other than LG Chem	***	***	30-35
	HCC	HCC	***	***	-(0-5)
	HCC	Any other than HCC	***	***	30-35
	Any other than LG Chem and HCC	Any	***	***	30-35
Taiwan	All producers	All Exporters	***	***	5-10
China PR	All producers	All Exporters	***	***	5-10
Malaysia	All producers	All Exporters	***	***	15-20
Thailand	All producers	All Exporters	***	***	5-10
European Union	All producers	All Exporters	***	***	25-30

69. The above evaluation indicates that the subject goods continue to enter the Indian market, from subject countries, at dumped prices and that the margin of dumping is significant enough.

#### **METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK**

##### **G.1 Submissions made by the exporters, importers and Other Interested Parties/ other parties**

70. Following are the submissions made by exporters, importers and other interested parties/ other parties:

- There is improvement in all the injury factors and economic parameters of the DI. The inference makes it crystal that there is no current or likely injury. The capacity, production, capacity utilization and sales of the domestic industry have increased. Productivity has improved.
- Volume of imports from subject countries has declined over the injury investigation period. Also, we request the Authority to collect import information as per DGCI&S for the purpose of present investigation.
- Market share of the petitioner has increased in the POI as compared to base year and that of the subject countries have declined.
- There is a huge demand supply gap for the subject goods in India. Even after the increase in capacity carried out by the DI, it is not sufficient to meet the needs of the domestic users. But having taken benefit of duties for so many years and nothing been done to meet even the substantial part of demand in the country, the DI shouldn't be allowed to get away with this argument that they are not liable to take care of the demand supply gap situation in India.
- The inventory level appears to be of no nexus to the reality. Inventories increased in the POI when the market share of imports from subject countries has declined. Thus, in any case increase in inventory is not attributable to imports from subject countries.

- f. There is no price injury on account of dumping. The injury to the DI has continued even after duties on various sources. If the injury were due to other sources like Norway and Mexico as contended by the DI, duty is imposed on such sources hence there is no justification for continuation of duties on subject countries in the present SSR. Price undercutting has been negative from China PR, Taiwan and Thailand during the POI meaning thereby no injury has been caused because of imports from these countries also. The major sources from countries like EU and Korea etc were at un-dumped rates as found by the Authority in the past.
- g. Injury to the DI is being caused by other factors.
  - i. All major sources of imports are attracting AD duty but still DI claims injury being caused to it.
  - ii. Company is debt ridden and huge interest costs are borne by the company. Even though the petrochemical prices have heavily come down over the years, it couldn't improve the situation.
- h. There is no continued injury to the petitioner nor is there any likelihood of injury on account of alleged dumping or alleged likelihood.
- i. The only ground for likelihood of continuation and recurrence of dumping and injury by the DI is excess capacity in subject countries and attractiveness of the Indian market which has not been substantiated by evidence.
  - i. Price undercutting from China, Taiwan and Thailand has been negative. Imports from Russia has been nil throughout the injury period and POI.
  - ii. The third country export data relied upon by the DI to show a case of likelihood has some fundamental flaws in it which alone makes the data supplied by the unreliable. First of all, the data pertains to a wide range of products and subheading whereas the case of PUC in the present SSR is different. At least data pertaining to three subheadings i.e 390410, 390421 and 390422 have been relied upon. Secondly, the data pertains to an old period and the data have been picked as per the choice of the DI to suit their case, buttressing our argument that the price includes a wide range of PUC and non PUC items, the export price between countries abnormally varies.
  - iii. Imports from Russia has been nil throughout the injury period and POI. No justification for continuation of duties is established in such scenarios. This alone proves absence of likelihood red with past imports from Russia. Some information on export from Russia to world during 2013 is provided by the DI. The same is neither for POI nor for PUC as the data pertaining to 3 sub-headings such as 390410, 390421 and 390422 have been relied upon by the DI.
  - iv. The world export data for subject countries are neither for POI nor for PUC and it has been provided selectively. Likelihood is falsely claimed on these bases and the same should be rejected by the Authority.
- j. the price of subject goods are amenable to crude/petrochemical prices and the crude prices have seen significant down falls in the past one year or so. This has resulted in reduction in prices of EDC which is the raw material for the subject goods. This has been to the huge benefit of Chemplast. However, no benefit of this has been passed on to the user industry since Chemplast enjoys a monopolistic market in India and Chemplast is misusing anti-dumping.
- k. On the contrary, the US dollar has appreciated significantly and cheap imports are not any reality. Price of crude meaning thereby raw material price of subject goods have declined significantly. The decline has been there through the POI and during the period thereafter. There has been a highly disproportionate passing on of benefits in terms of reduction in raw material prices vis-à-vis reduction in price of finished goods by Chemplast.
- l. the Authority to work out a mechanism to associate any anti-dumping duties, if at all to be continued, on subject goods with the price of Crude and USD rates so that the interest of user industry is taken care of.
- m. Basis of 22% ROCE designed in the year 1986 for a specific Pharma industry when all parameters like interest rate and corporate tax were different cannot be termed as reasonable after 25 years in the year 2011. Designated Authority should adopt ROCE earned by the Industry when there was no allegation of dumping as reasonable profit margin and not 22% ROCE. 22% Return on capital employed gives undue protection to the domestic industry. Hon'ble CESTAT in the case of **Bridge Stone Tyre Manufacturing & others vs. Designated Authority and CESTAT in M/S Hyosung Co. vs. Designated Authority**, clearly shows that adoption of 22% ROCE has coloured the injury determination. It has inflated the price underselling and injury margin.
- n. There is a huge gap between demand and supply of PVC Paste/Emulsion Resin India. An import into India is imperative. Any move to impose Anti-dumping Duty on this product will adversely affect competitiveness of the downstream industries.
- o. Indian producers are operating at more than 95% capacity utilization. There is no volume effect on the Domestic Industry.
- p. There is no justification in claim of the Domestic Industry with regard to the losses during the Period of investigation. Audit Reports of the various constituents of the Domestic Industry show otherwise.

- q. The Domestic Industry is able to earn the Non-injurious Price hence not adversely affected due to imports.
- r. Assertion of the Domestic Industry that there is huge surplus capacity in the subject countries is totally illogical.
- s. Further extension of Anti-dumping Duty will not be in Public Interest as the same will adversely affect the downstream industry.
- t. Even after no imposition of anti-dumping duty, Hanwha never tries to capture the Indian market by dumping or any other unfair trade practice.
- u. VCM prices have fallen in far east countries but the Korean producers have not passed on the reduction to Indian consumers.
- v. EU producers prices of PVC Resin are 20% cheaper than that of Korean producers. Due to Anti-dumping duty we are unable to import from EU.
- w. The Designated Authority has not taken into account the continuous depreciation of Indian rupee vs USD.
- x. Anti-dumping duty does not account for cross currency rate changes. Indian rupee has appreciated which has resulted in increase in price of good manufactured by KlassikLamitex thereby affecting export obligations
- y. Anti-dumping duty has not taken into account cross currency rate fluctuations. The Designated Authority has failed to recognize the inverse ratio between USD and commodity prices. Protection of up to 70% has been accorded to Chemplast.
- z. The Designated Authority has out way and assumed static input prices. Chemplast has woven a web of lies by declaring a huge range of input prices to confuse the Authority.
- aa. No integrated producer is set up for selling ethylene alone and chemplast get this raw material only if there is surplus with someone. The high cost of buying coupled with poor financial strength is the main cause of losses to Chemplast.
- bb. Chemplast does not have capacity to meet the demand of the product.
- cc. If Chemplast is making world class products then they should export to China, Thailand, Europeetc and earn 30%-70% additional profits if the prices determined by Authority for these countries are correct. The Authority is unduly favouring Chemplast for last 15 years and there is no trade barriers in any for the countries.
- dd. PVC resin is a basic chemical important product for manufacturing sector and that is why the Government of India has imposed lower than peak custom duty on the product. This has been totally distorted by Anti-dumping duty Authority by imposing tariff of upto 70%.
- ee. The Authority is approaching at a pre-determined mind. If the base year is 2013-14 when oil was above USD 100 how can they come to a conclusion in a situation when crude oil is below USD 30 per barrel.
- ff. Chemplast has been given protection for almost 15 years even on countries with no imports. Unless there is a gap of few years how can facts be established.
- gg. PVC is a global commodity and international prices are quite transparent. Why would Korean and Taiwan producers sell PVC in India at lower prices when they can fetch higher prices in their domestic market? Totally baseless claim of Chemplast.
- hh. The cost of PVC in Europe is lowest but due to Anti-dumping duty the cost of importing it has become exorbitant. Since Korea and Taiwan producers are not attracting Anti-dumpingduty, they are able to sell the product at huge profits because their competition has been priced out of the market due to Anti-dumping duty.
- ii. Increase in raw material prices has led to increase in price of final product manufactured by Klassik and it has hampered the growth in the export markets.
- jj. No economic benefit behind imposition of Anti-dumping duty. The Designated Authority has failed to distinguish between normal commercial pricing and dumping practices which has resulted in punishing normal business such as Klassik.
- kk. Poor financial situation of Chemplast. The company sells PVC paste on advance basis to Indian customers which are reflective that its debtors are 0.56 months of sales.
- ll. Chemplast does not have more than one week inventories and it is borne out by the fact that Chemplast is not even able to supply one truck at week's notice to Klassik.
- mm. Despite being the largest importers, the Klassik was denied the opportunity to file importer questionnaire response and comments on the petition. Requested to give 40 days time from Oral hearing to inspect the public file and provide comments on the same.

nn. The claim of likelihood and recurrence of dumping and injury are merely based on conjectures and have no nexus to the reality of the facts of the case and we deny any charge of likelihood of recurrence of dumping and injury in the event of expiry of present duties.

oo. There is no causal link between the alleged dumping and injury to the DI. The AD duties on various sources including the subject countries is prevalent for more than a decade now and the DI is still making losses meaning there by the reason for injury to the DI are not alleged dumping but self inflicted other reasons. Moreover, the DI is yet not supplying various grades of subject goods nor they can meet any substantial portion of domestic demand and the user industry is forced to import the same from other countries but after paying unwarranted AD duties.

pp. The sunset review considering Russian import should have been stopped and Russia should have excluded from the list of subject countries right after the analysis of the Petition because from the document consists no evidence of dumping and a lack of evidence of material injury caused by import of PVC from Russia.

## G.2 SUBMISSIONS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY

71. Following are the submissions made by the domestic industry in this regard:

- a. The demand of the product in the Country shows a positive movement throughout the injury period.
- b. Despite the imposition of ADD on the subject goods, imports continue to enter the Indian market in significant volumes from countries attracting ADDs.
- c. The market share of the dumped imports has increased over the period.
- d. The imports from the subject countries are undercutting the prices of DI. Price underselling by subject countries is very high, as landed price of imports is much below the NIP of DI.
- e. The landed price of imports is significantly below the cost of production of DI, throughout the injury period. Whereas the cost of sales increased over the injury period by 12%, there is no increase in net selling price. DI had to lower its prices even below the cost of sales from 2012-13 to the current POI in order to compete with extremely low prices of dumped imports.
- f. DI is suffering significant deterioration in profitability and huge losses due to price suppression. This is despite the existing ADD.
- g. DI has not added fresh capacities over the injury period. However, there has been a re-allocation of capacities from battery separator resin & suspension resin to PVC Paste thereby increasing effective capacity available for PUC.
- h. Demand for PUC is higher than what DI can produce and sell. Therefore, DI does not have any difficulties in selling the goods so long as its prices are competitive vis-à-vis imports. Since DI kept its prices matching to the import prices, the sales volumes and consequently production and capacity utilization improved over the period with a marginal decline in capacity utilization of DI during POI.
- i. The profits of DI improved after imposition of ADD. The profitability however plummeted and DI started suffering financial losses once again in 2012-13. Even when the extent of losses was already so high in 2012-13, the losses suffered by DI further increased in the POI.
- j. The price depression and suppression has led to steep decline in profits and DI suffered financial losses in the 2012-13, 2013-14 and the POI.
- k. Production of PUC is a continuous process which cannot be stopped. Furthermore, either DI must align its prices with the changes in the import prices, or must lose the order. Given highly matured market, significant knowledge with the consumers with regard to prevailing prices being offered by different suppliers, the impact of offer made by the foreign producers immediately comes onto DI's prices.
- l. Profit before interest also declined significantly after its recovery in 2011-12, with PBT on domestic sales plunging into negative values during POI.
- m. The cash profits of DI declined significantly during POI after minor recovery from previous dumping. DI has been suffering cash losses since 2012-13.
- n. ROI improved after imposition of ADD. However it steeply declined in the 2012-13 causing injury to DI. DI is faced with negative returns during the POI.
- o. DI had recently suffered injury from previously dumped goods and was on the course of recovery. But it is once again suffering injury as a result of dumping in the Indian market. This is due to the ADD losing its relevance due to increase in dumping of subject goods from exporters in subject countries which are exempt from ADD.
- p. Market share of DI has increased whereas that of imports has declined. However, despite ADD in existence, the market share of dumped imports remained significant.

- q. Employment level of DI has increased. Wages have shown normal increases. Further, productivity has consistently increased. These parameters are dependent on a number of other parameters and not reflective of impact of dumping on the domestic industry. Hiring & firing of employees is the last resort situation for DI.
- r. Growth in terms of the price parameters is negative and minuscule for the ROCE.
- s. The performance of industry has been severely affected by dumped imports. Performance of DI has significantly deteriorated in respect of profit, cash profits and ROI. Persistent dumping has resulted in depression of domestic prices causing erosion of profits.
- t. Decline in profits of DI should not be regarded as inconsequential or insignificant adverse impact. Whereas profits, cash profits and ROI should have improved, the same has rather declined. This alone clearly establishes that the performance of DI is getting very severely impacted and is adverse.
- u. The various parameters relating to DI collectively and cumulatively establish that DI has suffered material injury. Further, dumping and consequent injury is likely to continue and intensify further, should the current ADD ceases.
- v. The dumping margins with respect to the subject countries in original investigation was not only above de-minimus but also substantial. The dumping margin for the current investigation period is substantially high. In the event of cessation of ADD, these exporters will get a greater opportunity to dump PUC into India, taking away the market share of DI.
- w. Dumping margin in respect of LG Chem Ltd. and Hanwha Chemical Corporation from Korea RP and Formosa Plastics Corporation from Taiwan were de-minimus and therefore ADD at the rate of nil were recommended in respect of exports from these sources. However, DM in respect of exports being made by these exporters at present is significantly high. The estimates of normal value and export price made for this period clearly show existence of significant dumping margin in this period.
- x. The imports from subject countries are showing the increasing trend even in the presence of ADD so there is all the probability that the volume would increase in the event of revocation of ADD. Considering the pace of increasing volume of imports at present, there is no reason to believe that the volume will decline in the event of revocation of ADD.
- y. Producers in subject countries maintain huge capacities to produce subject goods, which is evident from the IHS report on Vinyls for the year 2014.
- z. With the revocation of ADD, the volume is bound to increase further. Moreover, this probability would further intensify when their other markets have closed down.
- aa. The Chinese and Russian producers are exporting huge volume of subject goods to third countries at dumped prices. In the event of revocation of ADD, these volumes are likely to get diverted to India and that too at significant dumped prices causing injury to DI.
- bb. The Indian market for the PUC is highly price sensitive. The consumers decide their source, with the price being the foremost consideration. Such being the case, availability of such low priced imports from subject countries in the market would definitely cause an adverse impact over DI.
- cc. The market share of subject countries is quite significant in spite of the existing ADD. In fact the market share of the imports has increased over the years with a mild decline during POI.
- dd. DI is already suffering huge financial losses, cash losses and negative ROI. It is likely to suffer further insurmountable material injury in the event of cessation of ADD.
- ee. There is no contraction in demand of PUC. Material injury is being caused to DI from dumped imports. There is no significant difference in the manufacturing process.
- ff. Listed known other factors do not establish that injury has been caused by these other factors. Such being the case, the only inescapable conclusion is that the injury to DI has been caused by the dumped imports from subject exporters and subject countries.
- gg. The volume of imports from producers in subject countries has been increasing and is significantly high.
- hh. Imports from subject countries in general, are undercutting the prices of DI.
- ii. The starting points for DI to price its product are – cost of inputs and price offered by foreign producers. Thus, if price offers by the foreign producers are too low compared to the price that DI works out based on its cost changes, the only option with DI is to offer a sub-optimal price. Price undercutting being caused by the dumped imports is preventing the domestic industry from increasing its prices.
- jj. Deterioration in profits, return on capital employed and cash profits is directly a result of dumped imports.

- kk. The growth of DI became negative with regard to a number of price parameters.
- ll. DI never claimed volume injury. Imports from subject countries have increased substantially in absolute terms. Subject imports are undercutting and underselling the prices of DI to a significant extent. The price undercutting is in spite of low prices already kept by DI. Imports are preventing the price increases that would have occurred in the absence of dumped imports. DI industry has deteriorated in terms of profits, return on investments and cash flow.
- mm. Despite the imposition of ADD, imports continue to enter the Indian market in significant volumes from countries attracting ADD.. The imports are entering the Indian market from China at artificially higher prices which appear to avoid ADD. The exports from China customs after adding freight shows prices significantly below the prices reported in the Indian customs. The import price reported in Indian customs is artificially higher and the price reported in China customs is relevant and reliable for the present purposes.
- nn. Despite ADD in existence, the market share of dumped imports remained significant and in the event of cessation of ADD, the market share of the imports from subject countries would increase. Also, there is adverse price effect of dumping on DI.
- oo. The fact that consumption in India is higher than the capacities with the Indian producers may justify imports per se but not the dumping.
- pp. DI is forced to set its prices considering the price offers of the leading foreign suppliers and disregard its cost consideration. Since the foreign producers are resorting to dumping, DI is forced to follow such dumped prices.
- qq. If the DI price is comparable to the import price, DI product gets a preference before the consumers. Since DI is forced to align its prices to import prices, dumping from subject countries and other countries have had an adverse price effect on DI, which is clearly established by deterioration in performance of DI in respect of profits, ROI and cash flow.
- rr. The purpose of determining price undercutting is to assess whether such dumped imports are causing injury to DI. It is required to determine whether imports are undercutting the domestic prices or whether the effect of imports was to otherwise depress or suppress the prices of DI in the market. Therefore negative price undercutting does not necessarily mean no injury to DI.
- ss. Huge interest costs are part of business operations and are required to be addressed accordingly. In fact, the DA grants 22% ROCE and therefore whether the company has high interest or low interest, the NIP does not get impacted. If the interest cost is high, the profit shall be low. And if interest cost is low, profit shall be high.
- tt. Even in the event of low volumes of imports reported during the POI of a SSR investigation, ADD can be continued. There are a number of instances where foreign authorities have continued the duty in the first and subsequent sunset reviews.
- uu. The crude price has declined only after POI and therefore movement of Crude has no relevance in the present investigation.
- vv. Devaluation of Rupee does not selectively impact the finished product prices. It impacts the raw material prices as well. In fact, the CESTAT had modified the currency from INR to US\$ only because of appreciation of US\$. If appreciation of US\$ was the reason for converting the duties to INR, the same cannot become a ground for converting duties to INR. Further, DA had declined to recommend duties in INR in the matter of digital plates wherein it was clearly established that the US\$ duty was overprotecting the industry.
- ww. The information regarding domestic prices of PVC Paste Resin is based on Harriman Chemsult to indicate the prices of PVC paste in subject countries. It is third party information.
- xx. Hariman Consult reports are the third party information and DI is not authorized to disclose the same. The payment for the information itself limits its access to the person paying for the information with the obligation of not sharing it with anybody.
- yy. VCM and PVC Paste Resin prices in Europe are much higher.
- zz. For exporters having no ADD, the present volume and price itself is the biggest evidence of likelihood.
- aaa. DA has been applying 22% consistently. Authority granted 22% in those cases also where the actual return was higher.
- bbb. DI provided information segregated only in respect of PUC and domestic operations. So the performance reported in the Annual Report with regard to different product is entirely immaterial.
- ccc. DI is not able to earn the NIP. It is suffering losses throughout the injury period.
- ddd. DI has provided evidence regarding surplus capacities in subject countries.

eee. There was significant price decline because of dumped imports. Thus, the contention of the party is incorrect that there prices of PUC have not declined.

fff. The investigation period in the present case ended in September 2014 and therefore the present crude oil prices has no relevance. In any case, the crude oil price has no relevance to the cost of production of PUC as it is not the raw material for production of PUC.

ggg. The company does not hold inventories since holding inventories has its own cost. The company liquidates inventories to the extent possible. The relevant point is not the level of inventories created by company but the adverse impact of dumping on DI and the prices at which DI is forced to sell its product.

hhh. As far as the export obligations are concerned, ADD cannot have any adverse effect, as GOI exempts import for export purposes. Despite exemption of ADD for export, if the company is suffering in exports because of changes in exchange rate, etc., it is due to entirely different factors unrelated to the present issue.

iii. DA has recognized the cross currency rate fluctuations. ADD once imposed remains in force for the period of 5 years. It can be reviewed from time to time. Other countries have recently extended ADD and CVD on several products which are significantly higher than the present level of dumping and subsidization despite the fact that the present margins are much lower. It is thus evident that the ADD imposed once remains in force unless party establishes the need for review and revision of duty.

jjj. The Authority is required to consider DI as it exists, and not under ideal conditions.

kkk. The mere fact that DI cannot cater to entire demand in the country does not mean that the DI should suffer. The purpose of ADD is not to restrict imports but to provide level playing field to DI. The foreign producers could meet the Indian demand by selling the product at reasonable price. The foreign producers were not required to resort to dumping in order to meet the Indian demand.

lll. DI product is well accepted and no party has any complaints about the quality of the product. ADD is no favor to a company or an industry. It merely addresses unfair trade practices.

mmm. Majority of products in India are at present having customs duty below peak duties. The fact that the product is attracting less than peak duty do not imply that the foreign producers are given a license to dump the material. On the contrary, given that the GOI has reduced the customs duty, these producers are eligible to export at a higher price. They are not required to resort to dumping and cause injury to the Indian industry.

nnn. The ADD is not a protection.

ooo. The demand for PUC in Korean and Taiwanese market is far above the capacities with the producers in these countries. It is these surplus capacities created by the foreign producers which are forcing them to resort for dumping. While they are charging a higher price for the product in their home market, they are exporting the product in Indian market at a lower price.

ppp. Nothing prevents the consumers from importing from any source. Nothing prevents foreign producers for selling the product at a price which does not constitute dumping price. In fact, given demand-supply gap, it should be easier for these producers to sell at fair prices in the Indian market. If the producers have not resorted the dumping, the Govt. would have not impose the duties. And if the producers have resorted to dumping, the consumer cannot now blame for the duty imposed.

qqq. The ADD does not apply on imports for exports. Such being the situation, how the present ADD could not have adversely impacted the growth of the company in the export markets.

rrr. Chemplast chooses to sell on cash basis and it is no way an inappropriate business policy. Merely because Chemplast has a policy to sell on cash basis, it does not imply that the company is not entitled to protection. In fact, the company selling on cash basis will not have poor financial position. In fact, it would have better financial position.

### **Examination by the Authority**

72. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.

73. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting

by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

74. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry Para (iv) of Annexure-II of the Anti-dumping Rules states as follows:

*"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."*

75. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the rules supra.

76. According to Section 9A (5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.

77. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties in force. Rule 23 provides that provisions of Rule 11 shall apply, mutatis mutandis in case of a review as well. The Authority has, therefore, determined injury to the domestic industry considering, mutatis mutandis, the provisions of Rule 11 read with Annexure II. Further, since anti-dumping duties are in force on imports of the product under consideration, the Authority considers whether the existing anti-dumping duties on the imports of subject goods from subject countries are required to be considered while examining injury to the domestic industry. The Authority has examined whether the existing antidumping measure is sufficient or not to counteract the dumping which is causing injury.

### Cumulative Assessment

78. Annexure II to the Anti Dumping Rules provides that in case the imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:-

*"(a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual countries is less than three percent, the imports cumulatively accounts for more than seven percent of the imports of like article and (b) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles."*

79. In this regard, the Authority notes that criteria for de minimis dumping margin and negligible volume of imports are not relevant for the purpose of determining likelihood of dumping margin from subject countries. However, for the purpose of cumulative assessment, un-dumped imports from producers from subject countries have been taken out for the purpose of injury analysis.

80. Further, the goods manufactured by the producers from the subject countries are like articles inter se and in comparison to the product manufactured by the domestic industry. A cumulative assessment of the effects of imports from the subject countries is appropriate since the exports from the subject countries directly compete with the like goods offered by the domestic industry in the Indian market. Commons parties are using the goods from the different sources and from the Indian domestic industry interchangeably, and the channels of sale are similar.

81. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The Authority has examined injury to the domestic industry by considering information relating to M/s. ChemplastSanmar Limited constituting domestic industry under the Rules. Accordingly, the volume and price effect of dumped imports have been examined as follows:

### Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic Industry

#### Volume Effect

#### Demand and market share

82. The Authority has considered the transaction-wise import data provided by DGCI&S for the assessment of volume and value of imports from the subject countries and other countries. Demand for the product under consideration

has been determined as the imports of the product under consideration into India from all countries and sales of all domestic producers in India.

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Sales of domestic industry	MT	44,382	44,548	57,257	61,091
Sales of Other Indian producer	MT	11,490	11,906	11,906	11,906
Total Subject Countries	MT	27,052	34,237	31,632	30,293
Korea RP	MT	7,565	8,476	10,277	13,212
Taiwan	MT	4,017	5,056	2,912	1,806
China PR	MT	4,015	2,082	307	152
Malaysia	MT	2,809	5,350	7,415	4,183
Thailand	MT	2,603	3,600	4,281	1,728
Europe	MT	6,043	9,673	6,440	9,213
Countries attracting anti-dumping duty	MT	1,016	6,585	7,263	6,467
Other Countries	MT	1,862	780	1,560	3,535
Total Indian Demand	MT	85,802	98,056	109,618	113,292

83. The Authority notes that demand for the subject goods has shown consistent increase over the injury period.

84. The market share in demand of domestic industry and imports from subject countries are as under

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Share of Total Imports in Demand	%	34.88%	42.43%	36.91%	35.57%
Share of Imports from Subject Country in Demand	%	31.53%	34.92%	28.86%	26.74%
Share of Imports from other countries attracting ADD in Demand	%	1.18%	6.72%	6.63%	5.71%
Share of Imports from Other Countries in Demand	%	2.17%	0.79%	1.42%	3.12%
Share of DI Demand	%	51.73%	45.43%	52.23%	53.92%
Share of Other Producer	%	13.39%	12.14%	10.86%	10.51%

85. The above data indicates that the market share of the domestic industry has increased. The market share of subject countries increased in 2012-13 but declined thereafter.

#### **Import volumes and share of subject country:**

86. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure II (ii) of the anti dumping rules provides as under:

*“While examining the volume of dumped imports, the said Authority shall consider whether there has been significant increase in the dumped imports either in absolute terms or relative in production or consumption in India”*

87. The import volumes for the injury period are as under:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Total Imports	MT	29,930	41,602	40,455	40,296
Subject Countries	MT	27,052	34,237	31,632	30,293
Korea RP	MT	7,565	8,476	10,277	13,212
Taiwan	MT	4,017	5,056	2,912	1,806
China PR	MT	4,015	2,082	307	152
Malaysia	MT	2,809	5,350	7,415	4,183
Thailand	MT	2,603	3,600	4,281	1,728
Europe	MT	6,043	9,673	6,440	9,213
Imports from other countries attracting ADD	MT	1,016	6,585	7,263	6,467
Imports from other countries	MT	1,862	780	1,560	3,535
Imports from subject countries in relation to					
Total Imports	%	90.38%	82.30%	78.19%	75.18%
Total demand	%	31.53%	34.92%	28.86%	26.74%

88. From the above, the Authority notes that:

- a. The imports from subject countries have increased since base year.
- b. The share of imports of the product under consideration from subject countries out of the total imports is quite huge throughout the injury period including the POI.
- c. Imports from subject country as a whole have remained significant in relation to consumption in India.

## PRICE EFFECT

### Price effect of dumped imports and impact on domestic industry

89. The impact on the prices of the domestic industry on account of imports of the subject goods from the subject countries have been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed value of imports from the subject country. A comparison for subject goods during the period of investigation was made between the landed value of the dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission incurred by the domestic industry have been adjusted. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out a non-injurious price and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic industry in terms of Annexure III of the Anti-dumping Rules. The position is as follows:

### Price Undercutting and Underselling

90. The Authority has made price undercutting and price underselling analysis without anti-dumping duty after evaluating the Landed Value of inputs under the duty free imports as below:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Net Sales Realisation (DI)	Rs./MT	***	***	***	***
<b>Subject Countries</b>					
Landed Price	Rs./MT	85,095	79,558	81,648	83,566
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price undercutting %	%	***	***	***	***

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Range	%	0-5	0-5	0-5	0-5
<b>Korea RP</b>					
Landed Price	Rs./MT	87,199	80,921	82,327	83,764
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price undercutting %	%	***	***	***	***
Range	%	0-5	0-5	0-5	0-5
<b>Taiwan</b>					
Landed Price	Rs./MT	83,614	83,071	79,855	88,242
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price undercutting %	%	***	***	***	***
Range	%	0-5	-(0-5)	5-10	-(0-5)
<b>China PR</b>					
Landed Price	Rs./MT	85,909	85,050	70,963	88,503
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price undercutting %	%	***	***	***	***
Range	%	0-5	-(0-5)	15-20	-(0-5)
<b>Malaysia</b>					
Landed Price	Rs./MT	83,017	81,230	81,619	82,726
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price undercutting %	%	***	***	***	***
Range	%	5-10	0-5	0-5	5-10
<b>Thailand</b>					
Landed Price	Rs./MT	89,672	86,744	88,177	86,091
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price undercutting %	%	***	***	***	***
Range	%	-(0-5)	-(0-5)	-(0-5)	0-5
<b>Europe</b>					
Landed Price	Rs./MT	81,899	71,748	77,577	82,193
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price undercutting %	%	***	***	***	***
Range	%	5-10	10-15	5-10	5-10

91. The above data indicates price undercutting, without taking into account the antidumping duty in force, is significant. It is noted after the analysis that the prices of subject goods from subject countries as a whole are undercutting the prices of domestic industry during the injury period.

#### Price Underselling

92. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out non-injurious prices of the subject goods and compared the same with the landed values of the imported goods to arrive at the extent of price underselling. For examining the underselling effects of the dumped imports the landed value of imports, without taking into account the antidumping duty in force, has been compared with the Non Injurious Price determined

Country	Non-Injurious Price	Landed Price	Price Underselling	Price Underselling	Price Underselling
	US\$ per MT	US\$ per MT	US\$ per MT	%	% Range
Korea RP (overall)	***	1,358.68	***	***	20-25
Taiwan	***	1,431.32	***	***	10-15
China PR	***	1,435.56	***	***	10-15
Malaysia	***	1,341.85	***	***	20-25
Thailand	***	1,396.42	***	***	15-20
Europe	***	1,333.20	***	***	20-25

93. The Authority notes that during the POI, the price underselling was positive for all the subject countries.

**Price suppression and depression effects of the dumped imports:**

94. To examine whether the domestic prices are suppressed or depressed due to the presence of dumped imports from subject country the trend of weighted average sales realization of the domestic industry has been compared with the cost of sales and the landed values.

Particular	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Cost of Sales (DI)	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	110	110
Selling price (DI)	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	96	100
Landed Price (Imports) Subject Countries	Rs./MT	85,095	79,558	81,648	83,566
Trend	Indexed	100	93	96	98

95. From the above information, the Authority notes that there was significant increase in cost of sales over the injury period. However, the domestic industry was unable to increase its selling price due to low price imports. Infact the domestic industry was forced to reduced its prices. This shows price suppression and price depression effect whereby the domestic industry has not been able to increase the selling price commensurate with increase in the cost of sales and infact had to reduce its selling prices despite increase in cost.

**Examination of Economic Parameters relating to Domestic Industry**

96. Annexure II to the Antidumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

**Capacity, production, capacity utilization and sales**

97. Performance of the domestic industry with regard to production, sales, capacity and capacity utilization are as follows:

Particular	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	134	146
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	130	137
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	97	94
Domestic Sales	MT	44,382	44,548	57,257	61,091
Trend	Indexed	100	100	129	138

98. It is seen from the above table that the domestic industry enhanced capacities in the year 2013-14 and POI. The demand for the product under consideration in the Country has increased significantly over the injury period.

99. The production and sales of the domestic industry have increased throughout the period. Capacity utilization of the domestic industry has declined. The domestic industry explained that with the increase in the capacities, the domestic industry has targeted more production. It is noted that the demand for the product under consideration is higher than what the domestic industry can produce and sell. Therefore, the domestic industry does not have any difficulties in selling the goods so long as its prices are competitive vis-à-vis imports. The domestic industry has contended that since the domestic industry kept its prices matching to the import prices, the sales volumes and consequently production and capacity utilization improved over the period.

### **Inventories**

100. From the information given below, the Authority notes that the inventory position of domestic industry has increased during period of investigation.

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Average Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	58	276	1,622

### **Profits, return on investment and cash flow**

101. Performance of the domestic industry with regard to profits, return on investment and cash flow over the injury period was as follows:

Particular	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	110	110
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	96	100
Profitability	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(775)	(866)	(656)
PBT on Domestic Sales	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(777)	(1,117)	(903)
PBIT on Domestic Sales	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	0	(30)	(19)
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(582)	(807)	(650)
ROCE	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	0	(28)	(17)

102. From the above information, the Authority notes that Profit/Loss and profitability of domestic industry has deteriorated throughout the injury period. Whereas both cost of production and selling price increased over the period, the increase in the cost of production was more than the increase in selling price. Resultantly, the profitability of the domestic industry steeply deteriorated over the injury period. The domestic industry started suffering financial losses since 2012-13. Similarly, the cash profits and return on capital employed also followed the same declining trend.

### **Employment, wages and productivity**

103. From the information given below, the Authority notes that the employment position of the domestic industry and wages paid have increased during period of investigation as compared to base year. Productivity in terms of production per day and production per employee has increased over the period.

Particular	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Number of employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	92	102	104
Wages	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	115	110
Productivity Per Day	MT/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	130	137
Productivity Per Employee	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	127	132

**Magnitude of dumping**

104. The Authority notes that the dumping margin of the imports of the subject goods from the subject countries except Russia is not only positive but also significant.

**Growth**

105. The Authority notes that the growth of domestic industry in terms of sales, production, and market share was positive whereas growth in respect of profits, return on investment and cash profits was negative.

Growth	Units	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Production	%	-	0.37	29.58	5.30
Domestic Sales Volume	%	-	0.37	28.53	6.70
Cost of sales domestic	%	-	6.92	2.88	0.28
Selling price domestic	%	-	(5.35)	1.86	3.35
Profit/Loss domestic	%	-	(874.58)	11.81	(24.27)
Average stock	%	-	(42.08)	375.65	488.73

**Ability to raise Capital Investment**

106. The Authority notes that given rising demand of the product in the country, the domestic industry has made investments in enhancing capacity. However, despite these investments, the performance of the domestic industry has deteriorated considerably and further investment may get adversely affected.

107. Further, the above volume and injury parameters during POI are summarized and tabulated as below:

**PVC Paste Injury Parameters**

Countries	Price undercutting	Price underselling
Korea RP	Positive	Positive
Taiwan	Negative	Positive
China PR	Negative	Positive
Malaysia	Positive	Positive
Thailand	Positive	Positive
European Union	Positive	Positive
Subject countries as a whole	Positive	Positive

Parameters	Trend since base year
Production	Increase
Domestic sales	Increase
Capacity utilization	Decrease
Average stock	Increase
Profits	Decrease
PBIT	Decrease
PBT	Decrease
Cash Profits	Decrease
ROI	Decrease
Market share in Demand	
Imports	Increase
Domestic industry	Increase
Price suppression	Positive

108. The Authority notes that though production, sales, Market share of Domestic Industry and capacity during the period of injury have increased, the capacity utilization has decreased. Profitability on account of ROI, PBIT, PBT, and cash profits has decreased. Also there has been adverse impact on other price parameters related to price suppression and depression. While price undercutting is Positive for Korea RP, Malaysia, Thailand, European Union, it is negative for Taiwan, China PR, however on cumulative assessment the price undercutting is positive. Further on comparison with NIP, the price underselling is noted to be positive for all countries individually and even collectively.

#### **Conclusion on injury**

109. It is thus seen that there has been a significant increase in the volume of dumped imports from subject countries in absolute terms. The imports have remained significant in relation to consumption and production of the product in India. Imports have thus increased both in absolute terms and in relation to production and consumption in India. The dumped imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market. Dumped imports have had significant adverse price effect in terms of price suppression and depression. Effect of dumped imports has been to prevent price increase which otherwise would have occurred, to a significant degree. Imports have prevented the domestic industry from raising its prices in proportion to cost increases. The domestic industry is suffering significant price underselling. The dumping margin determined by the Authority is quite significant. With regard to consequent impact of dumped imports on the domestic industry, it is noted that dumped imports from subject countries have adversely impacted the performance of the domestic industry in respect of inventories, profits, cash profits and return on investment. Inventories with the domestic industry increased. Further, as a result of significant price undercutting and suppression, profitability of the domestic industry deteriorated so significantly that the domestic industry was suffering significant financial losses. Further, the domestic industry suffered cash losses and negative return on investment during the POI. The Authority holds that the domestic industry has suffered material injury.

#### **Causal Link**

110. The Authority examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry as follows:

##### **Volume and prices of imports from third countries**

111. The Authority notes that during POI, imports of the subject goods from countries other than the subject country are either attracting anti-dumping duty or are de minimis.

##### **Contraction of demand and changes in the pattern of consumption**

112. The Authority notes that there is no contraction in the demand during injury period. Demand for the product has increased over the injury period.

##### **Developments in technology**

113.The Authority notes that none of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the DI.

#### **Conditions of competition and trade restrictive practices**

114.The Authority notes that the subject goods are freely importable. The domestic industry is the sole producer of the subject goods.

#### **Export performance of the domestic industry**

115.The export performance of the domestic industry is not relevant since price and profitability in the domestic and export market has been segregated by the Authority for the purpose of assessing injury to the domestic industry.

#### **Performance of other products**

116.Claimed injury to the domestic industry is on account of product under consideration. The petitioner has provided information which pertains only to the product under consideration. Thus, the financial information provided with regard to product under consideration clearly shows the position of the domestic industry with regard to like article produced and sold by the domestic industry.

117.The Authority concludes that while the known other factors listed above do not appear to have caused the injury determined, the following parameters show that injury to the domestic industry is caused by the dumped imports in the event of cessation of anti dumping duty.

- a. The volume of imports of the subject goods from the subject country is quite significant.
- b. Imports of the subject goods from the subject countries are undercutting domestic industry's prices.
- c. Despite the existence of anti-dumping duties in force on the imports of the subject goods from the subject country, significant volume of dumped imports continues from this source. This indicates that should the measures be allowed to expire, dumping will intensify and cause further injury to the domestic industry.
- d. Deterioration in profits, return on capital employed and cash profits is a direct consequence of dumped imports.
- e. In case of cessation of anti dumping duties the subject country exporters shall be able to further capture the market in view of their high production capacities and low export prices.

#### **Conclusion on Injury and Causation**

118.The investigation has thus shown that the volume of dumped imports from subject countries except Russia has increased. With regard to the effect of the dumped imports on prices, there has been significant price undercutting and underselling effect by the dumped imports from subject countries except Russia as compared with the price of like product in India, and the effect of such imports was to suppress and depress prices to a significant degree. With regard to consequent impact of the dumped imports from subject countries on the domestic industry, the investigation has shown that performance of the domestic industry has deteriorated significantly in terms of parameters such as profits, cash profits and return on investment. The investigation has thus shown that the domestic industry has suffered injury from the dumped imports of subject goods from subject countries.

#### **Magnitude of Injury and Injury Margin**

119.As regards injury assessment, the Authority has evaluated grade wise non-injurious price for the Domestic Industry and also proposes to undertake grade to grade Injury Margin determination by comparing exported grades by LG Chemical and HCC from South Korea with the equivalent grades if not identical of the Domestic Industry. However assessment to undertake Injury Margin determination on a weighted average basis could be appropriately considered based on response regarding any determination issues faced in mapping equivalence of grades to this disclosure.

120.The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during POI. The equivalence of the grades exported by the cooperative exporters from South Korea and Domestic Injury are as under to enable grade wise Injury Margin determination.

Korea (producer/exporter)	Domestic Industry's Grade
<b>LG Chemical</b>	
LP 170	121
LP 170 G	121
PB 1302	120 & 124
PB 1752	121
PE 1311	120
PB 1202	120 & 124
PA 1302	Not considered being a Copolymer which is excluded from PUC
<b>HCC</b>	
KL 31	124
EM 3090	120
KH 31	121

121. The injury margin determined for subject country, during POI is as follows:

Countries	Producer	Exporter	Injury Margin US\$/MT	Injury Margin in %	Injury Margin in % Range
Korea RP	LG Chem	LG Chem	***	***	15-20
	Hanwha Chemical Corporation	Hanwha Chemical Corporation	***	***	15-20
	Others	Others	***	***	35-40
Taiwan	All producers	All Exporters	***	***	10-15
China PR	All producers	All Exporters	***	***	10-15
Malaysia	All producers	All Exporters	***	***	20-25
Thailand	All producers	All Exporters	***	***	15-20
European Union	All producers	All Exporters	***	***	20-25

122. From the aforesaid information, the Authority notes that during POI, the injury margin in respect of subject countries is positive and significant. However, in respect of Russia, in view of available facts, the Authority does not note any threat of dumping and likely injury on possible imports from Russia and therefore discontinues the levy of anti-dumping duty on imports of the subject goods from Russia.

#### **LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY**

123. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties imposed on the imports of subject goods from subject countries. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of antidumping duty is warranted. This also requires examination whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping.

124. The Authority notes that in the present investigation, there is continuous dumping of the subject goods from subject countries except Russia, causing continued injury to the domestic industry, which ipso facto indicates likelihood of dumping and injury from subject countries. In view of the above position and due to favorable market conditions prevailing in the Indian market as far as demand and price for the subject goods are concerned, the Authority holds that in the event of revocation/cessation of anti-dumping duties, dumping may intensify from subject countries. The following analysis shows the likelihood of continuation/intensification of dumping and injury to the domestic industry in the event of revocation of anti-dumping duties:

**(i) Level of current and past dumping margin**

125. The level of dumping margin in respect of subject countries in the earlier as well as present investigations is significant. Given the level of price undercutting and price underselling effects from the imports of subject goods from subject countries, the volume of dumped imports is likely to increase further in the event of revocation of anti-dumping duty. The dumping margin in the original investigation final findings were determined in the range of about 20%- 50% for subject countries other than cooperative exporters; and in the present determination, they are in the range of about 5%- 30% for subject countries other than cooperative exporters.

**(ii) Price undercutting, suppression, depression in the absence of measures**

126. The prices at which subject goods are being imported from subject countries are substantially lower than the price at which the goods are being sold in the domestic market. Therefore, in the event of revocation/cessation of the anti-dumping duties, it is likely that exporters from these countries may channelize their sales in the Indian market in view of the significant capacities being held by them.

**(iii) Huge production capacity in the subject country**

127. The evidence provided by the domestic industry, shows existence of excessive capacities with the exporters/producers in subject countries.

**(iv) Dumping margin in respect of exports to third countries**

128. The evidence submitted by the domestic industry on record shows that the producers/ exporters from subject countries are exporting huge volume of subject goods to third countries at dumped prices. The Authority has examined this post POI and third countries price behaviour as well.

**Comments on Disclosure**

**Comments by Domestic Industry**

129. The domestic industry has submitted the following comments to the disclosure:

- Questionnaire response of Hanwha Chemical Corporation should be rejected.
- Hanwha Chemicals Corporation is not entitled for individual dumping margin for the reason that the exporter in the present case is not Hanwha Chemicals Corporation. The exporter in this case is Hanwha Corporation. Further, the response has stated that the commercial invoices in case of goods produced by Hanwha Chemicals Corporation were issued by Hanwha Corporation. Since commercial invoice for exports were issued by Hanwha Corporation, Hanwha Corporation is the exporter of the product concerned. Further, if Hanwha Corporation is the exporter concerned for all the exports made to India, individual dumping margin cannot be assigned to Hanwha Chemical Corporation without questionnaire response of Hanwha Corporation. Since there is no questionnaire response by Hanwha Corporation, Hanwha Chemical Corporation is not entitled for individual dumping margin. Petitioner requests accordingly.
- It is also pointed out that Hanwha Chemicals Corporation has claimed to have paid commission to Hanwha Corporation. If Hanwha Corporation is the exporter of the product concerned, who has issued commercial invoice to Indian customers, there has to be sales and purchase transactions between Hanwha Chemical Corporation and Hanwha Corporation. There cannot be a commission in such cases. Commission to Hanwha Corporation could have been paid only when the commercial invoices for exports to India were issued by Hanwha Chemical Corporation and such sales were assisted by Hanwha Corporation. However, in the instant case, Hanwha Corporation has issued commercial invoice to Indian importers and therefore Hanwha Corporation must have purchased the goods from Hanwha Chemical Corporation and sold the same to Indian importers.
- In the final findings of SSR Investigation in PVC Suspension Grade from Taiwan, China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Malaysia, Thailand and USA, the Authority examined that HWC was raising invoice on Indian Exporters without purchasing the subject goods from HCC. However, it is pertinent to note that the Authority in this investigation found during verification that the Korean customs authorities in that case named HWC as exporter and HCC as producer. The Authority observed:

*"On the issue of HWC raising invoice on Indian exporters without purchasing the subject goods from HCC and therefore no separate dumping margin should be determined for exports to India by HCC through HWC, it has been reported that the transaction of exports made by HCC to India through HWC is in the nature of an agent acting on behalf of the principal for a commission. However, HWC is not registered with the Korean Government as Commission Agent. During the on the spot verification, it was shown to the verification team that in respect of the subject goods exported to India by HWC, HWC received the commission from HCC for handling the sales documents and covering the marine insurance and bank charges. The Customs Authorities of Korea have named HWC as exporter and HCC as producer. When the domestic industry raised the issue that HWC could not have exported the goods unless it has purchased the goods from HCC, HCC submitted a certificate from their statutory auditors stating that the transaction between HCC and HWC are not treated as sales and purchases and they are treated as the services for a price rendered by HWC to HCC. The"*

*Authority has assessed the net ex-factory export price of HCC treating the transactions between HCC and HWC as one of purchase and sale. If it is treated as a sale and purchase transactions, the dumping margin reportedly comes to (-) \*\*\*% of the net export price."*

- It is thus evident that the Authority has assessed the net ex-factory export price of HCC treating the transactions between HCC and HWC as one of purchase and sale. In other words, the Authority determined dumping margin for HCC without a questionnaire response from HWC. The situation continues to be same in the present case as well.
- Thus, Hanwha Chemicals is not entitled for individual dumping margin for the reason that in the present case the exporter is not HCC but HWC as commercial invoices are issued by it. Therefore, individual dumping margin cannot be assigned to HCC without questionnaire response of HWC.
- The legal submissions are filed by both Hanwha Chemical Corporation (HCC) and Hanwha Corporation (HWC). However, the questionnaire response was filed only by Hanwha Chemicals Corporation. The interested party argued that even though Hanwha Corporation is involved in the exports to India, it is only involved in handling invoices for HCC and receives commission for handling service. HWC has no role as a trading company for the export sales to India. The domestic industry fails to understand that if the opposing interested party claims Hanwha Corporation as not a trader and only invoice handling agency then how it is being treated as an interested party to file written submissions. This clearly shows the interest of Hanwha Corporation on the anti-dumping duty investigation in India which no agency receiving commission would have.
- HWC has not filed a questionnaire response but has filed written submissions. This clearly indicated the unwillingness of the party to provide information and therefore should be considered as non cooperative.
- In the current case, responses were received from LG Chem, Korea and HCC, Korea. However, they have not furnished information pertaining to related companies in other subject countries. HCC has a wholly owned subsidiary in China, Hanwha Chemical (Ningbo) Co. Ltd. which produces subject goods. Similarly, LG Chem has a subsidiary in China as well i.e. Tianjin LG DAGU Chemicals Co. Ltd. which also produces the subject goods. These producer/exporters have not filed questionnaire response in the present investigation. It was argued during the hearing that the related parties have not exported and therefore have not filed questionnaire response. Petitioner submits that current investigation being a sunset review investigation, the Authority is required to determine whether cessation of anti-dumping duty would lead to likely of dumping and injury to the domestic industry. Therefore, it is important for the Authority to determine likely dumping by an exporter. Even though the exporter has not exported the product under consideration, it can be easily implied that this is due to anti-dumping duty in force. In the event of cessation of anti-dumping duty, the exporter would in all likelihood resume its exports to India.

#### **REPEATED CLAIMS OF NO DUMPING BY LG CHEM AND HANWHA CHEMICALS**

- LG Chem and Hanwha Chemicals have repeatedly been investigated by the Designated Authority in India for different products and it has been found that dumping margin in their exports is de-minimus. Past investigations where the Designated Authority has investigated these exporters and has found no or negligible dumping are listed below (in fact, de-minimus dumping margin in all cases, barring one exception of low dumping margin):-

1. Hanwha – 9 cases (including present case)
  - a. Caustic soda – three investigations – all showed no dumping
  - b. PVC suspension resin two cases – no dumping
  - c. Sodium cyanides – no dumping in original case, 3.71% in sunset review
  - d. PVC Paste Resin – no dumping
2. LG Chem – 4 cases (including present case)
  - a. PVC suspension resin original case – no dumping
  - b. PVC Paste resin – no dumping
  - c. Phenol review case – no dumping
3. Formosa – 4 cases (including present case)
  - a. PVC suspension resin original case – no dumping
  - b. PVC Paste resin – no dumping
  - c. Caustic soda sunset review – no dumping

- Products listed above are such that no producer is able to fetch a price materially different from other suppliers in Indian market. Thus, even when Designated Authority found significant dumping margin in respect of exports made

by other exporters in these products, the DA found that the dumping margin in respect of these companies are de minimus. This is all the more surprising considering that other investigating authorities such as China and Australia have found positive dumping margin in respect of their exports.

- Repeated instances of no dumping by these companies across the products and the determination made by the Designated Authority that dumping margin in these companies are very close to zero implies that these companies pricing policy is to sell the product at one price, regardless of the market. Further, this is not for selling price, this is for ex-factory realization to the exporters after making of the adjustments, as have been claimed in the questionnaire responses. This is highly impossible situation and clearly points at grossly manipulated questionnaire responses having been filed by these companies.
- Elements of costs even though might be based on the records kept by the exporter, nevertheless does not imply that the Designated Authority is bound to adopt the cost of production of the exporter without satisfaction whether the same reasonably reflect the cost associated with production and sale of the product under consideration. Two conditions precedent must be satisfied before the Designated Authority can adopt such cost of production on the basis of records maintained by the company. Such conditions precedent includes a major condition that such costs should reasonably reflect the costs associated with production and sale of the product under consideration.
- In discharge of this requirement/obligation, the Designated Authority has prescribed as follows in the exporter's questionnaire.

“.....(g) In case any material is purchased from related supplier or captively produced, please state the basis of pricing of the material considered. Elaborate how you consider that the pricing considered is reflective and representative of a fair market price. Provide purchase prices from independent parties for an identical or comparable input product. Also provide cost of production of the item procured captively or from an affiliated supplier.

- It would be seen that the foreign producer is required to provide the following information in case any material is purchased from related supplier or captively produced –
  - i. the basis of pricing of the material considered
  - ii. how exporter considers that the pricing considered is reflective and representative of a fair market price
  - iii. provide purchase prices from independent parties for an identical or comparable input product.
  - iv. provide cost of production of the item procured captively or from an affiliated supplier.
- It is important to note the replies filed by the responding exporters in this regard. Following are the relevant extracts from the some of the questionnaire responses of the responding exporters.

- a. Hanwa Chemical Corporation

*As stated above, the major input, VCM is captively produced by HCC. Therefore, this question is not applicable.*

- b. LG Chem

*As explained above answer (e) none of the material are purchased from related parties. Therefore the question is not applicable.*

- It would be seen from the responses filed by the exporters/producers that
  - a. they have intentionally avoided the information sought by the Designated Authority. In fact, none of the responding exporters have fully replied to the question with regard to valuation of VCM. The Authority may kindly direct the responding exporters to provide such information or otherwise hold that the responding exporters have not supplied the relevant information and apply best available information.
  - b. Hanwa has avoided providing information related to valuation of VCM. LG on the other hand stated that they do not purchase inputs from any related parties. However, it is difficult to accept such response since the related party of LG namely Tianjin LG Bohai Chemicals Co Ltd, Chins is a manufacturer of VCM.
- VCM is a tradeable commodity and hence every VCM and PVC producer has option to either convert VCM to PVC or sell in the market as VCM. The petitioners request the Authority to take note of that and consider market price of VCM while determining elements of cost for computing normal value.
- Referring to Article 11.1 of AD Agreement and Section 9A(5) of Customs Tariff Act, 1975, the domestic industry submitted that sunset review investigation is to examine the following results of the anti dumping duty in force:

- Whether dumping continues, if so, whether it is likely to continue on the revocation of anti dumping duties;
- In case where dumping did not continue, whether the dumping would recur in the event of revocation of anti dumping duties;
- Whether the Domestic Industry continued to suffer injury and if so, whether injury to the domestic industry is likely to continue;
- In case where the Domestic Industry has not suffered continued injury, whether injury to the Domestic Industry is likely to recur in the event of revocation of anti dumping duties.
- In the present case, imports from Russia in the POI are nil. The domestic industry submitted that even where the dumping margin is zero, anti-dumping duty needs to be continued in view of clear likelihood of dumping from Russia. Following parameters were referenced in order to prove that the cessation of anti-dumping duty would recurrence of dumping and injury
  - *Dumping margin determined in all previous investigations relating to the product*
  - *No exports to India*
  - *Freely disposable present and potential capacities with the foreign producers*
  - *Dumping margin in respect of exports to third countries*
- The Designated Authority has in the past continued anti-dumping duty despite the fact that imports were nil on the ground that there was likelihood of dumping. The following cases were referenced on this point.
  - ✓ *Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS)*
  - ✓ *Zinc oxide*
  - ✓ *Ductile iron pipes*
- The domestic industry has suffered continued injury despite anti-dumping duty in existence as can be seen from the following
  - There is the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.
  - Anti dumping duty may be imposed only as fixed quantum of anti dumping duty (fixed form of duty) as per the consistent practice of the Authority so that ADD does not become futile. For this claim, following decisions were cited:
    - 👉 in the case of NBR from Korea, the Hon'ble CESTAT modified variable anti-dumping duty recommended by Designated Authority to fixed duty based on the appeal filed by an exporter, M/s. Kumho Petro-Chemicals Co. Ltd. [2004(170)E.L.T. 274]
    - 👉 in the case of Metcoke, the CESTAT, vide their decision 2000(116) E.L.T. 67 modified the anti-dumping duty from variable to fixed.
    - 👉 in the case of Vitrified files, the CESTAT upheld the decision of the Designated Authority to impose fixed quantum of duty.
    - 👉 decision of the CESTAT in the matter of Metcoke from China.

#### **Comments by Interested Parties:**

130. Following are the comments of interested parties to the disclosure statement:

I. Hanwha Chemical Corporation, Korea

- DGAD accepted the reporting method of Hanwha Corporation's function and its related expenses in the final finding issued on December 26, 2007. The relevant sentence is attached below (page 36-37 of final finding):

#### **“ b.2 ) Export Price-Hanwha Chemical Corporation**

During the POI, M/s Hanwha Chemical Corporation (HCC) has exported \*\*\*\*\* MT of the subject goods to India against \*\*\*\*\* transactions. During the POI, HCC has sold only three grades of PVC Suspension. All exports to India are on CIF term and LC at sight or usance basis. All sales except two transactions are through its affiliated trader viz. M/s Hanwha Corporation (HWC).

HWC acts as a commission agent between HCC and Indian Customers against payment of fixed commission on the shipments to India under a service contract between the parties. The Commission amount takes care of documentation and negotiation of shipping documents, ocean insurance expense and sub-agent's commission less than US\$ \*\*\*\*\* per

MT. The unit price to the Indian customer is the invoice price of HWC. HCC raises the invoice to HWC excluding the HWC commission.

Against the export transactions, the exporter has incurred inland transport expenses, ocean freight expenses and port handling expenses, and commission paid to HWC which were verified from the records of the company. Ocean insurance and subagent's commissions are included in HWC's commission and hence no deduction is required from the invoice value."

- The above reporting method was also accepted by the DGAD for PVC Paste Case (The final finding released on May 2, 2011)
- In some of the export transactions of subject goods made to India, Hanwha Chemical Corporation (HCC) has paid handling of document charges to Hanwha Corporation (HWC).
- Even though Hanwha Corporation involved in the exports to India, please note that Hanwha Corporation is just responsible for handling invoice for Hanwha Chemical Corporation and receives commission for document handling service. It may be noted that Hanwha Corporation does not purchase the product under investigation from Hanwha Chemical Corporation nor resell it to customer. It means Hanwha Corporation does not have any role as a trading company for the export sales to India.
- Document handling charges of \*\*\* USD per MT includes following services provided by HWC to HCC:
  - i. Preparation of documents related to exports out of Korea, RP;
  - ii. Charges/expenses for overseas insurance;
  - iii. Banking Charges related to inward remittances against export receipts.

HWC only receives the export remittances on behalf of HCC and remits exactly the same to HCC. It will be pertinent to note that the Export Invoice, Packing List as well as Bill of Lading were in the name of HCC. Further, the Bill of Entries cleared at Indian Ports also shows the name of exporter as HCC. Hence, there cannot be iota of doubt about the status of HCC as Producer as well as exporter.

- Factually, out of 74 exports transaction, only 16 transactions were made through HWC against the payment of handling charges. Further, out of \*\*\* MT of exports to India, \*\*\* MT was only sold through HWC, which is even less than \*\*\*% of the total subject goods exported to India during POI. It will also be pertinent to note that no exports were made through HWC after May' 2014. HCC has also provided the information related to POST POI exports to India, wherein, no transaction of exports has been made through HWC.
- Additionally, at the time of verification, it was demonstrated to the Authority that HWC is making more than reasonable profits by charging \*\*\* USD per MT from HCC against documents handling charges. It was further demonstrated that if the transactions through HWC were ignored that it will only result in enhancement of negative dumping margin. Therefore, there cannot be any mala fide reason for the purposes of Anti-Dumping Investigation.
- In view of the above, it is requested to consider all the 74 exports transactions for computation of Dumping Margin of HCC.

II. Comments on behalf of Leather Cloth and Plastics Manufacturers Association (LCPMA), Polynova Industries Ltd, MayurUniquoters, KPL International Ltd, Jasch Plastics India Ltd and Jasch Industries Ltd.:

- The disclosure as it appears would lead to continued inclusion of certain non PUC items in the scope of anti-dumping duties if the present measures are continued. The IIT Delhi Report is disputed and the Authority is requested to conduct another test for confirming product issue in question. Following points may kindly be once again perused by the Authority;
  - The domestic industry does not manufacture the following products;
    - i. PVC paste resin of high K Value;
    - ii. PVC paste resin of low fog values especially for automotive application with a fogging characteristics (gravimetric) of less than 0.5 mg by testing by test method din-75201 / iso-6452.

#### **PVC paste resin high k value**

- K value of PVC resin determines the mechanical properties of PVC leather cloth relating to specifications required by Final customer such as OEM manufacturers of various seat covers for vehicles, furniture upholstery, footwear and other products.
- As K-value increases in the PVC leather cloth formulations the toughness of PVC leather also increases. There are various types of specifications in leather cloth such as Taber abrasion for specific Types of wheels, weights and

number of cycles; Wyzenbeek abrasion using # 8 Duck cloth; Martindale abrasion test; Flexibility tests such as 2,00,000 cycles of Bally flex, Satra Flex test 5,00,000 cycles.

- Increase in Mechanical properties such as Breaking Strength, Tear strength and reduction in Elongation at break etc are influenced by increase by K value of the PVC resin.
- The High K value of PVC Resin is required to be processed at higher degree of temperature in comparison to low K value. The low K Value PVC resin cannot achieve the same Mechanical properties as high K Value resin in PVC formulation. There are no additives that can convert low K value PVC in to High K Value PVC in Leather cloth formulation. For example breaking strength can be increased to some level by reducing plasticizer in formulation with low K value PVC but the product will fail in Elongation/ Flexibility.

**Note:** K Value is a representation of Molecular weight of PVC resin. There no such known additive that will increase the molecular weight of PVC resin from 67K Value to 77 and therefore these Resins of difference K values are not interchangeable.

- In case these resins have interchangeability there was no need for M/s. Chemplast to manufacture Resin Grade 124 with 65k, grade 120 of 68k and grade 121 of 77k and wide range of different k value by the overseas manufacturers. Therefore M/s. Chemplast can reply better why they manufacture three different grades of Resins with different k values if they are interchangeable.

#### Pvc Resin Of Low Fogg Value Specifically For Automotives

- Leather cloth manufactured with resins manufactured by Chemplast has never passed the Fog test. All the grades of Chemplast resin have been found to be failing on fogging test and are nowhere near the standards as huge oil droplets are formed on the glass plates & hence not suitable for automotive Industry at all as the product do not pass under their Test method SAE-J1756 for fogging values .
- It is therefore essential for LCPMA members that PVC resin with LOW FOG property as per above test method are to be imported, without which the domestic supply to the entire automotive industry will come to a standstill.
- This is evident that LCPMA members have imported these Resins during POI at above USD 1800.00 / MT while the general purpose PVC Resin prices were at the range of USD 1200.00 / MT. This shows that specialty PVC Resin prices are higher by 50% than general purpose and such imports under any circumstance can cause any injury to domestic industry. These resins for automotive application in particular imported are neither technically nor commercially substitutable to the PVC grades produced by the domestic industry and Low Fog resins needs to be excluded from the scope of PUC.
- The original manufacture of these resin M/s. Solvay and M/s.Vinnolit got the testing of these resins in their lab as well as by independent agency with Test method ISO-6452 and DIN-75201 and test results shown are as under;

Weight measure in gram:	Conversion in mg:
Solvin 373 ND	0.0002gr      0.2mg (in spec)
Chemplast Resin-121	0.0457gr      45.7mg (out of scope)
Chemplast Resin-124	0.0334gr      33.4mg (out of scope)

- During previous investigation the Designated Authority had send the samples of specialty grades of PVC Resin for examination to IIT, New Delhi but the report issued by IIT New Delhi was incomplete and incorrect which was protested by LCPMA vide letter dated 14.2.2013 as well as by European manufacturers.
- This issue is still open and we request before you for a review (copy of letter and correspondence with IIT, New Delhi already submitted with our submission and meeting with the Authority). The Authority may extend the investigations to conduct such required test to avoid serious injustice to the users of the subject goods.
- The domestic industry has submitted as per disclosure point C 2 (h) that the grade manufactured by them are log fogging resins for suitable for automotive industry, which is totally incorrect and false. It is requested to please obtain a re-confirmation with affidavit and test report from M/s Chemplast that the resins manufactured by them meet the low fog properties of FOGGING CHARACTERSTICS (GRAVIMETRIC) OF LESS THAN 0.5MG BY TESTING BY TEST METHOD DIN-75201 / ISO-6452 as required by automotive industries and to confirm that these grades are equivalent to imported grades 373 ND and 375 MD or these resins can be sent for Re-Testing to any test laboratory equipped with testing equipment to undertake the test of fog properties with test method ISO-6452 and DIN-75201 (Like SGS India) to verify the correctness of the statement of M/s. Chemplast.
- It will be a great hardship to the domestic manufacturers of PVC Leather cloth if this aspect is not correctly investigated and concluded to exclude the specialty grades of PVC Resin being not manufactured by M/s. Chemplast and

are essentially required to be imported from Europe for manufacture of PVC Leather Cloth as required by Automotive Industry. This will be also against the laws of Natural Justice.

- These both aspects were verified during the visit of a team from the Authority in the plant of one of the member of LCPMA. However if due to any reason the low fog resin for automotive are not excluded from the product under consideration, we request the Authority to kindly make a reference price equivalent to non-injurious price to domestic industry and the Low fog PVC Reins of price higher than the reference price to be excluded from the Anti- Dumping duty.

#### **Hardship Due To Non-Participation Of European Manufacturers**

- The domestic manufacturers of PVC Leather cloth are suffering with great hard ship and losses due to nonparticipation of EU manufacturers of PVC Resin in investigation as they do not consider India as their major market.
- Since the data is not provided by EU manufacturers, dumping margins are calculated by third party data which not fully reliable and an average is taken of different prices of different grades including nonstandard grades which gives very lower average price and results in undue hardship to actual users.
- It is requested to consider the **actual import data of different grades of PVC Resin separately as provided by member importers** for the calculation of dumping margin of **each grade** rather than third party data.
- Solvay has lately filed price of subject goods which may kindly be used by the Authority for the grade wise prices. The information provided by the exporter and data of our imports would show that the DI can never get impacted by such high priced products imported from subject countries.

#### **Volatility In Prices Of Pvc Resin Due To Volatile Crude Prices And Ex. Rate Of Indian Rupee**

- The prices of PVC Resin (International as well as Domestic) are linked to the movement of crude prices.

Particulars	Price during POI	Current Price
Crude	USD 103 – 93	USD 39 – 41
International Prices of PVC	USD 1200 – 1250	USD 950 – 1000
Domestic Price of PVC	Rs. 90 – 96	Rs. 78.50
Exchange Rate of INR to USD	Rs. 59 – 62	Rs. 67 – 68

- The Anti-Dumping duty is calculated based on prices prevailing in POI which has changed a lot during current period as above. This will have similar trend in next five years during the period of A.D.D.
- It is noted at point B10-XXVI exchange rate of USD is adapted as INR 61.65 as prevailing during POI. The current exchange rate is INR 67.50 (As per Customs Notification No.48/2016 dated 7.4.2016 for imports). This increase in exchange rate directly increase the amount of Anti-Dumping duty and therefore and this requested shows the need to consider Anti-dumping duty, if any, in INR or as the percentage of basic price (As ad valorum and to save the hard ship of under incident of duty due to volatility in crude prices and Exchange rate).

#### **High Cost Of Production Of Chempalst Sanmar**

- M/s. Chemplast is producing PVC Resin with very old technology and their cost of production is higher than international manufactures and it is really unfortunate that this aspect cannot be verified due to nonparticipation of EU manufactures and we have to suffer losses due to ADD therefore it is humbly requested to kindly arrange to verify the cost of production of another domestic manufacturer of PVC Paste Resin **M/s. Finolex Industries Ltd.**
- When M/s. Finolex Industries Ltd. does not have the injury and losses due to imports then why only Chemplast has this injury and suffers the loss?

#### **M/s. Chemplast Sanmar Do Not Fulfill the Requirements Of Actual Users And Manufacturers of PVC Leather Cloth In India**

- Small scale industry manufacturing PVC Leather cloth in India has to buy PVC Resin from local market through traders paying hefty premiums as the domestic industry do not fulfill the demand of actual users. This premium is not part of this investigation and may please be considered.
- The total consumption of PVC Paste Resin in India is about 12,50,000.00 MT Annually while the capacity of domestic industry is just about 50% and rest of PVC Resin is to be imported with high cost of ADD and in spite of that the M/s. Chemplast **has refused** to supply material as required by actual users due to short supply. This is a great hardship to the local manufactures of PVC Leather cloth.

- Your attention is drawn at Point No.92 of Disclosure reads as “The production and Sales of domestic industry has increased in the throughout the period. **Capitalisation of Domestic industry has declined. At one place they are showing decline in capacity utilization and other place they write capacity utilization has increased over the period.** But infact DI always have scarcity of material and refused to supply to actual users the required quantities which affect the production of domestic industry of PVC Leather cloth. We have enclosed evidences in support of this with the copies of mails exchanged by our members with M/s. Chemplast in our submissions.

**There is no likelihood of dumping and injury in the event of revocation of present duties.**

- DI of PVC paste resin is not vulnerable to dumping and injury and the duties are required to be discontinued. The continued imports of the subject goods are due to two predominant reasons a) there is demand supply gap thus imports are essential, b) certain speciality grades are not produced by DI, thus, they are forced to import such special grades. It is also needs to be seen that such speciality grades are imported at much higher prices. The injury any to DI could be due to self-inflicted reasons and continuation of present AD duties is not the solution to it. Thus, we request the Authority to recommend discontinuation of existing AD duties on subject goods from subject countries.

**The Authority should reject the request of the DI for any fixed form of AD duty in the present case, if at all the duties have to be continued.**

- A serious issue as far as the consumers of the subject goods in India raised throughout this investigation and also in the past is the need for exclusion of certain speciality products from the scope of PUC and the same is not yet done which has weakened the position of users in the competitive market. It is already shown to the Authority that the speciality grades like low fog for automotive and high k value have been imported at a price more 50% higher than the regular grade.
- Still the users were subjected to very hefty AD duties. Since the DI is not manufacturing they are not concerned in any manner what so ever about the imports of such grades which are not interchangeable to the grades produced by the DI by any figment of imagination.
- In view of the above the proposition of the DI for a fixed duty is disputed if the duties are required to be continued. We humbly submit any decision for a fixed form of duty will render the user industry completely uncompetitive and price differences inter se grades will not be taken into consideration under such form of duty in no manner. Reference forms of duty were earlier imposed on PUC from subject countries and we request the Authority to recommend only reference form of duty in this SSR also, if at all the Authority finds it essential to continue the AD duty.

**• Prayer:**

- there is no continued injury to the applicant on account of continued imports from subject countries nor has the applicant been able to prove any likelihood of continuation or recurrence of injury in the event of expiry of present measures;
- The inclusion or continued inclusion of PVC Paste resin of High K Value (77 and above) and Low Fogging specification in particular for the automotive industry which are not manufactured by the DI is of no justification and such grades needs to be excluded from the scope of PUC;
- DI confirmed that they do not make Low Fog PVC Resin for Automotive applications. These PVC Resin's are made with special technology and DI does not have this technology and only 3-4 leading makers in the world can make these types of PVC. These are manufactured mainly with Emulsion production process and DI does not have this production process. The cost of manufacturing these grades is different than the cost of manufacturing general purpose grade as high technology is required for manufacturing of Low Fog –automotive grade PVC Resin and this is evident from the import data submitted by importer that the price of speciality grade is US\$ 1800 while the general purpose is much less than that. DI does not have such grade in their production /sales records. So such grades as regularly imported should be excluded from PUC.
- We have seen the large volatility and price movements in crude from POI to current period as well as in the Exchange Rate of INR and this directly impact the cost of raw materials required for manufacturing of PVC. Therefore the ADD should be considered as a BENCHMARK IN INR to avoid such great hardship to the Domestic USER Industry and manufacturers of PVC Leather cloth.
- Alternatively an Anti-Dumping Duty, if any, may be calculated on ad-valoram basis as % of the import price like customs duty to take care in the volatility in crude and exchange rate and register our opposition to any other form of duty which will render our survival itself very fragile.

**III. INOVYN Belgium S.A.**

- M/s. INOVYN Belgium S.A. in the capacity of an exporter of the subject goods to India from EU through letter dated 11.04.2016 has contested that volatile content and fogging are two different properties.

- Further a statement on total exports of the subject goods with unit price has been provided at an extremely belated stage with no evidence etc.

**IV. SCG Performance Chemicals Co. Ltd. (“SCG”)**

- M/s. SCG Performance Chemicals Co. Ltd. commented that M/s. Hanwha and M/s LG cut M/s SCG’s prices and sell lower than M/s SCG’s prices by at least USD 50/MT. M/s SCG has lost many orders against dumping prices of M/s. Hanwha and M/s LG and yet there is no ADD on M/s. Hanwha and M/s LG.

V. The Authority has not followed principles of natural justice, has depended upon the data of chemplast only and not referenced the DGCIS data independently. Issues like cash discounts by chemplast, non inclusion of basic custom duty to determine landed value, fall in crude prices, non export by chemplast if prices in exporting countries are high, high purchase cost of chemplast have not been addressed.

**Examination by Authority**

131. As regards the test on volatility and low fogging characteristics the Authority holds that the producers/exporters of the said grades did not participate in the investigation contesting on the aspect of PUC, dumping or injury. Further the users need to have contested the test report of IIT earlier before CESTAT, the appellate body. The report of IIT has clarified the aspect of low volatility and low fogging characteristics and the PUC includes the low fogging grade of subject goods also.

132. The Authority notes the submissions made by the domestic industry as well as by M/s. HCC on the data submitted by M/s. HCC in the capacity as a producer/ exporter of the subject goods. The Authority notes that HCC is mentioned as an exporter in the commercial invoice, bill of lading and export permit issued by Korean Customs. However, in the current sunset review, for \*\*\* MT out of \*\*\* MT of exports by M/s. HCC in POI,M/. Hanwha Corporation’s services have been utilised, and an adjustment of \*\*\* \$/MT as commission has been considered to arrive at ex- factory export price as also done earlier in the original findings dated 2<sup>nd</sup> May, 2011, wherein also, the Authority had provided such an adjustment to arrive at the ex- factory export price with a similar arrangement between M/s. HCC and M/s. Hanwha Corporation. Further, in respect of the above transactions wherein Hanwha Corporation has handled the letter of credit, the DG Systems data identify HCC as an exporter. For the transactions related to \*\*\* MT involving M/s. Hanwa Corporation, despite the adjustment of commission for ex-factory export price the dumping margin continues to be de minimis. The Authority has therefore determined the dumping margin/ injury margin with HCC both as producer and exporter of the subject goods, and for any other channel of exports adopted by HCC, residual category of ADD has been recommended. The valuation of VCM was carefully examined during the visit to the producer/exporters of PVC Paste Resin in South Korea. The cost of production of VCM as reflected in the books of accounts has been considered for evaluating ex-factory cost of PVC Paste Resin, as per relevant ADD rules.

133. As regards difference in grades of PUC, the Authority holds that the PUC which is differentiated in various grades on the basis of certain intrinsic technical parameters, and applications have difference in cost and price. In case of cooperative exporters in South Korea, this difference in cost and price is noted in the range of 15-20%. The Authority therefore has undertaken grade to grade analysis for evaluation of dumping margin for cooperative exporters, which is realistic and appropriate. In view of equivalence of various grades as illustrated in the disclosure, the comparison has been undertaken on grade to grade basis for injury margin as well. The Authority notes that Domestic Industry has mentioned that in respect of grades manufactured by them, the cost difference is low. In such a case also the Authority holds that grade to grade analysis is not unrealistic.

134. As regards form and denomination of ADD, the Authority considers that fixed duty in dollar from has been consistently recommended and levied keeping in view ease of implementation and efficacy.

135. As regards price fluctuation of raw materials, the Authority holds that all variation in costs and prices of various elements viz raw materials/subject goods are captured in the POI appropriately for different aspects of investigation. The Authority in respect of issues related to crude price fall , high cost of production of chemplast, determination of landed value and DGCIS data adoption holds that Chemplast fulfills the requirement as domestic industry as per AD rules. NIP has been determined during POI as per relevant rules addressing cost inefficiencies issues as per Authority’s consistent practice. The Normal value of non-cooperative exporters has been determined as per relevant AD rules as detailed in relevant paras . Landed value has been determined by applying basic custom duty on weighted average import prices based on DGCIS data for non cooperative exporters as the same is comprehensive and the best available information in view of no response from exporters and limited response from importers . The NSR has been determined at ex factory level net of discounts and taxes.

136. As regards the comments of M/s SCG Performance Chemicals Co. Ltd. on the dumping by exporters from Korea RP with their prices being lower than that from Thailand, the Authority notes that the dumping margin determined specifically for an exporter is based on that exporter’s normal value and export price. The same is done for cooperative exporters from Korea RP.

137. As regards likelihood of dumping and injury, the Authority notes that there are no imports from Russia during the POI and post POI. However as per the World Trade Atlas data, a small quantity of exports is reflected to India in 2015 under the Customs classification of 390422. The average prices of exports under this head to countries other than India during POI do not establish a likelihood of injury to the domestic industry in the event of its diversion to India.

138. The Authority further notes that in post POI the prices of the subject goods to 3<sup>rd</sup> countries show a decline of 13.42% as compared to that in POI. The prices of main raw material i.e. VCM also show a decline by 21% to 3<sup>rd</sup> countries during this corresponding period. Therefore a global decline of both subject goods and raw materials prices is evident. Under such situation, exporter specific analysis under a review may be warranted rather than the continuance of anti-dumping duties. Therefore the Authority holds that the above facts and the price trend do not establish the likelihood of continuance of dumping and consequential injury from Russia.

### **Conclusion**

139. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in this finding and on the basis of the above analysis of the state of continuation of dumping and consequent injury and likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:

- i. There is continued dumping of the product concerned from the subject countries except Russia, and M/s LG Chemicals and M/s HCC from Korea RP, both in absolute terms and in relation to production/consumption in India causing injury to the domestic industry.
- ii. Imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry. Further, imports are suppressing and depressing the domestic prices.
- iii. The performance of the Domestic Industry has deteriorated in terms of profits, return on investments, cash flow and inventories.
- iv. The dumped imports from the subject countries except Russia, and M/s LG Chemicals and M/s HCC from Korea RP continue to cause injury to the domestic industry.
- v. Dumping of the product under consideration from the subject countries except Russia, and M/s LG Chemicals and M/s HCC from Korea RP is likely to continue/intensify should the current antidumping duty be revoked.

### **Recommendations**

140. Having concluded as above, the Authority is of the view that the anti-dumping measures are required to be continued in respect of the subject countries except Russia, and M/s LG Chemicals and M/s HCC from Korea RP. Therefore, Authority considers it necessary to recommend continued imposition of the following definitive anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries in the form and manner as described in the duty table given below.

141. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries except Russia, and M/s LG Chemicals and M/s HCC from Korea RP so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the anti-dumping duty equal to the amount indicated in Col. 8 of the table below is recommended to be imposed by the Central Government on the imports of the subject goods, originating in or exported from subject countries.

**DUTY TABLE**

Sl. No.	Heading / Sub heading	*Description of goods	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	3904	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Korea RP	Korea RP	Hanwha Chemical Corporation	Hanwha Chemical Corporation	0	MT	US \$
2.	3904	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Korea RP	Korea RP	M/s LG Chem Ltd.	M/s LG Chem Ltd.	0	MT	US\$
3.	3904	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Korea RP	Korea RP	Any other than Sl. No. 1 & 2		379	MT	US \$

4.	3904	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Korea RP	Any country other than the subject countries and countries attracting ADD	Any	Any	379	MT	US \$
5.	3904	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Any country other than the subject countries and countries attracting ADD under any other notification	Korea RP	Any	Any	379	MT	US \$
6.	3904	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	China PR	China PR	Any	Any	88	MT	US \$
7.	3904	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	China PR	Any country other than the subject countries and countries attracting ADD	Any	Any	88	MT	US \$
8.	3904	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Any country other than the subject countries and countries attracting ADD under any other notification	China PR	Any	Any	88	MT	US \$
9.	3904	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Malaysia	Malaysia	Any	Any	214	MT	US \$
10.	3904	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Malaysia	Any country other than the subject countries and countries attracting ADD	Any	Any	214	MT	US \$
11.	3904	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Any country other than the subject countries and countries attracting ADD under any other notification	Malaysia	Any	Any	214	MT	US \$

12.	3904	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Taiwan	Taiwan	Any	Any	101	MT	US \$
13.	3904	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Taiwan	Any country other than the subject countries and countries attracting ADD	Any	Any	101	MT	US \$
14.	3904	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Any country other than the subject countries and countries attracting ADD under any other notification	Taiwan	Any	Any	101	MT	US \$
15.	3904	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Thailand	Thailand	Any	Any	111	MT	US \$
16.	3904	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Thailand	Any country other than the subject countries and countries attracting ADD	Any	Any	111	MT	US \$
17.	3904	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Any country other than the subject countries and countries attracting ADD under any other notification	Thailand	Any	Any	111	MT	US \$
18.	3904	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	European Union	European Union	Any	Any	298	MT	US \$
19.	3904	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	European Union	Any country other than the subject countries and countries attracting ADD	Any	Any	298	MT	US \$

20.	3904	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Any country other than the subject countries and countries attracting ADD under any other notification	European Union	Any	Any	298	MT	US \$
-----	------	---------------------------------	--	----------------	-----	-----	-----	----	-------

\*Please note: 1. Blending resin; 2. Co-polymers of PVC paste resin; 3. Battery separator resin and 4. PVC paste resin of K value below 60 are excluded from the scope of these recommendations.

142. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

#### **Further Procedure**

143. An appeal against the order of the Central Government arising out of this Final Findings Notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

A. K. BHALLA, Addl. Secretary & Designated Authority